



ड्रग्स के
मकड़जाल में
फंसता बॉलीवुड



सावरकर रूपी उजालों पर
कालिख पोतने की कोशिशें



मील का
पत्थर 1 अरब
टीका

मूल्य 30/-

नवंबर, 2021

डायलॉग इंडिया

परिवर्तन की चाह.. संवाद की चाह



चीन और पाकिस्तान

हालात बिगाड़ने की जिद



धरती के अस्तित्व को खतरा



CLAT 2022

How to Crack CLAT 2022 in the First Attempt?

CLAT- UG & PG

CLAT Comprehensive Program 2022-2023

Live Lectures

Recording of Live Lectures

Doubt Sessions

Regular Mock Tests

Very Impressive Results

Fully updated Assignment

One to One Mentoring Sessions

English / हिन्दी
Medium
Hostel Facility

Study
Material &
Test Series

New ONLINE/OFFLINE Batches in English/Hindi medium

starts from 12th Nov.2021 & 26th Nov-2021

CAREER LAW

A Premium Institute for CLAT

India's Best Law Institution

Powered By:



EDUCATIONAL SOCIETY

A Legacy of 25 Years

H.O. : 301/A,37,38,39, Ansal Building, Behind Safal Dairy, Commercial Complex, Mukherjee Nagar, Delhi-9

Contact : 9891186435, 9811069629, 9015912244, 011-27654588

Website : www.careerplusonline.com / www.careerplusgroup.com



धरती के अस्तित्व को खतरा



मील का पत्थर 1 अरब टीका नहीं बल्कि सभी पात्र लोगों का पूरा टीकाकरण है



टाटा विनीत के हुए 'महाराजा'



क्या पार्टियों में अब आंतरिक लोकतंत्र बढ़ेगा ?



सावरकर रूपी उजालों पर कालिख पोतने की कोशिशें



ड्रस के मकड़ जाल में फंसता बॉलीवुड



किसान आंदोलन : क्या करे आमजन



धार्मिक पर्यटन एवं नायकों की मूर्ति पूजा



स्व. डॉ. मदन मोहन अग्रवाल जी की मूर्ति का अनावरण

हमारे बारे में

डायलॉग इंडिया

वर्ष 13 अंक-3

वर्ष- 13

अंक- 3

संपादक

अनुज कुमार अग्रवाल

प्रबंध संपादक

डॉ. सारिका अग्रवाल

विशिष्ट संपादक

अमित त्यागी

विशेष संवाददाता

शरीफ भारती, आदित्य गोयल,

डॉ. यशवंत चौधरी, डॉ. अर्चना पाटिल

उप संपादक

नेहा जैन

मुख्य प्रबंधक (डिजिटल मीडिया)

सम्यक अग्रवाल

मुख्य प्रबंधक (विज्ञापन, वितरण एवं प्रसार)

विजय कुमार

जन सम्पर्क अधिकारी

पंकज कुशवाहा

ब्यूरोचीफ

उत्तर प्रदेश - एस.पी. सिंह

मध्य प्रदेश - संजीव चोकोटिया

राजस्थान - रामस्वरूप रावतसरे

बिहार - नंद शर्मा

दिल्ली - जितेन्द्र तिवारी

डिजाइन एवं ग्राफिक्स

विकास, मनीष, दीपक, रजत

मुख्य कार्यालय : 301/ए, 37-38-39

अंसल बिल्डिंग, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स

मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन : 011-27652829, 08860787583

फैक्स : 011-27654588

ई-मेल : dialogueindia@yahoo.in

dialogueindia.in@gmail.com

ई-पत्रिका : www.dialogueindia.in

स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक अनुज कुमार अग्रवाल द्वारा
स्टेलेंट प्रिंट एन पैक, ए-1, डीएसआईडीसी कॉम्प्लेक्स,
झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली से मुद्रित एवं 301,
37-38-39, अंसल बिल्डिंग, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स,
मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 से प्रकाशित

© सर्वाधिकार सुरक्षित

नवंबर, 2021 माह के लिए प्रकाशित

- डायलॉग इंडिया में प्रकाशित सभी लेख एवं सामग्री लेखकों के स्वयं के हैं, इससे प्रकाशक व सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।
- किसी भी विवाद की स्थिति में हमारा न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।



Exclusive Online/Offline Coaching For

IAS/PCS



Extremely Qualified and Experienced Faculty

Admission Open For Foundation Courses of IAS/PCS

New Batches Starting From

12th & 26th Nov. 2021

MUKHERJEE NAGAR, DELHI

9811069629  www.careerplusonline.com



Exclusive Online/Offline Coaching For

CTET



Extremely Qualified and Experienced Faculty

Admission Open for CTET

New Batches Starting From

12th & 26th Nov. 2021

MUKHERJEE NAGAR, DELHI

9811069629  www.careerplusonline.com

लगड़बग्घे वाली बात

द

र्द जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो दवा हो जाता है। पिछले दो वर्षों के झंझावत झेलने के बाद सभी इंसानों का यही हाल हो गया है। मुसीबतों के पहाड़ एक के बाद एक टूट पड़ने को बेचैन हैं। एक आफत से निकलो तो दूसरी सामने खड़ी होती है। आदमी ठीक से हंसना व अंदर से मुस्कुराना भूल गया है। यह कहना कठिन होता जा रहा है कि भारत समेत दुनिया को कौन ज्यादा सता रहा है? चीन-अमेरिका व्यापार युद्ध, कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी का बढ़ता तापमान, भूकंप, भारी बारिश, जलते जंगल, पिघलते ग्लेशियर, दरकते पहाड़, घटती धरती, जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती बीमारियां, टूटती सप्लाइ चैन, बढ़ती महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी, अमीर-गरीब के बीच बढ़ती खाई, असमय मौतें, अराजक होता समाज व सरकारों के बीच बढ़ती हथियारों की होड़, इस्लामिक आतंकवाद, कट्टरता व घृणा। मगर भारत के लिए ये सभी मुद्दे विकराल समस्या बनते जा रहे हैं। और इन समस्याओं में से अधिकांश के पीछे चीन और अमेरिका ही हैं। अमेरिका के दक्षिण एशिया से भाग खड़े होने के बाद से चीन बुरी तरह भारत पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। बेपटरी होता सीमा विवाद, भारत चीन (तिब्बत) सीमा पर बढ़ता सैन्य जमावड़ा, कश्मीर में हिंदुओं पर बढ़ती हिंसा, बांग्लादेश में हिन्दू मंदिरों पर हमले और देश में बढ़ते साम्प्रदायिक विभाजन के पीछे चीन ही है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश व

अफगनिस्तान के कट्टर इस्लामिक तत्वों को शह देकर भारत पर दबाव बना रहा है। भारत के पड़ोसी देशों भूटान, म्यांमार, श्रीलंका व मालदीव में भी चीन की सक्रियता बड़ी चेतावनी व खतरे की घंटी बन चुकी है। उससे भी ज्यादा भारत के किसान आंदोलन व सेकूलर राजनीतिक दलों पर चीन का स्पष्ट प्रभाव दिख रहा है। वह देश को अराजकता व ग्रहयुद्ध की ओर ले जाने की कोशिश में है। अमेरिका-चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध, कोरोना महामारी व जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी दुनिया की तरह भारत की अर्थव्यवस्था भी गहरे संकट में है। कोयले की आपूर्ति में कमी व महंगे होते पेट्रोलियम पदार्थों ने भीषण ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है जिस कारण महंगाई व बेरोजगारी नई ऊंचाइयों पर है। केरल और उत्तराखंड की हाल ही में हुई भीषण तबाही ने बता दिया है प्रकृति नित अपना भयावह रूप दिखा रही है और बता रही है कि आने वाला समय और चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है।

इतना सबके बाद भी व्यक्ति, समाज व सरकारें कोई भी बदलने को तैयार नहीं। शक्तिशाली राष्ट्र अभी भी संसाधनों पर कब्जे व शक्ति संतुलन के लिए हथियारों की होड़ में लगे हैं। लोकप्रिय व संवेदनशील नेतृत्व का स्थान कुटिल व धूर्त आत्मकेंद्रित नेता लेते जा रहे हैं और निर्णय प्रक्रिया भ्रष्ट व लालची कारपोरेट घरानों व कुटिल नोकरशाहों के हाथ गिरवी रखी जा रही है। ऐसे में लोकतंत्र मायने खोता जा रहा है। कोरोना काल के बाद से निरंकुश व बदहवास सत्ताओं द्वारा आम जनता पर मनमाने निर्णय थोपने की तो जैसे बाढ़ सी आ गयी है। राजनीति अभी भी नस्लवाद, धार्मिक कट्टरता, जातिवाद व मुफ्त रेवड़ी बांटने के खेल में व्यस्त है। विश्व अराजकता व अंधकार के धूमिल युग में प्रवेश कर चुका है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं मायने खो चुकी हैं। जीडीपी आधारित विकास ने पिछले सौ सालों में धरती को लील लिया है। मगर वैकल्पिक नीतियों को अपनाने में बड़ी हीलाहवाली हो रही है। दुनिया की जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों से कहीं अधिक हो चुकी है। हम जितना उपभोग कर रहे हैं उसका आधा भी पुनरुत्पादित नहीं कर पा रहे हैं। मगर न होड़ कम हो रही है न दौड़। जीवाश्म ईंधनों, मांसाहार व विलासिता के साधनों के अंधाधुंध उपयोग से बढ़ते पृथ्वी के तापमान ने मौसम व फसल चक्र को

अनिश्चित, अनियमित व विनाशकारी बना दिया है और जीव व वनस्पति के अस्तित्व पर ही खतरा खड़ा हो गया है। सच तो यह है कि स्थितियां हाथों से निकल चुकी हैं और आने वाला समय बड़ी तबाही व विनाश लेकर आने वाला है यह तय हो चुका है। अब तो बस यही देखना है कि कब तक गाड़ी खिंच सकती है और आने वाले भविष्य में कितने लोग बचेंगे और कितने संसाधन। ऐसे में प्रस्तावित जी-20 देशों की शिखर बैठक व सीओपी-26 के मंथन से बहुत कुछ स्पष्ट होना तय है।

भारत में आगामी कुछ महीनों में पांच राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं किंतु आश्चर्यजनक रूप से उपरोक्त किसी मुद्दे को राजनीतिक बहस में स्थान ही नहीं मिल रहा है। पंजाब में खालिस्तान, जाट सिख, हिंदू, दलित व किसान आंदोलन के मुद्दे के बीच राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने व उनके नयी पार्टी बनाने व भाजपा से गठजोड़ करने का ऐलान करने और नवजोत सिंह सिद्धू व नए मुख्यमंत्री चरनजीत सिंह चन्नी के बीच बढ़ती खाई ने मुकाबला बहुकोणीय कर दिया है। अब यह लगभग निश्चित है कि वहां मिलानजुली सरकार ही बनेगी। उत्तरप्रदेश में योगी का असर व प्रभाव गहरा है मगर समाजवादी पार्टी खासी आगे बढ़ती जा रही है। यहां पर बीएसपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ओवैसी आदि भाजपा की बी टीम के रूप में अधिक कार्य कर रहे हैं। अंततः आखिरी समय में हिंदू - मुस्लिम की ही राजनीति होनी यहां तय है। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं ने तस्वीर धुंधली कर दी है। गोवा में भाजपा का पलड़ा भारी दिख रहा है और मिजोरम में भाजपा व कांग्रेस गठबंधनों में कांटे की लड़ाई है।

राजनीति कुछ भी करवट ले ले इससे कोई खास अंतर नहीं पड़ने वाला क्योंकि असली अंतर तो प्रकृति के करवट लेने से आएगा और प्रकृति बहुत तेजी से करवटें बदल रही है, जनता व राजनेता इस सच्चाई को समझे या न समझे। कुल मिलाकर हमारी कहानी उसी लगड़बग्घे वाली है जो उसी डाली को काट रहा था जिस पर बैठा था।

अनुज अग्रवाल
संपादक



धरती के अस्तित्व को खतरा

● रंजना मिश्रा

कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि आइसबर्ग का टूटना एक प्राकृतिक बात है, समय-समय पर बर्फ के बने बड़े-बड़े आइसबर्ग अक्सर टूटते रहते हैं, वहीं अधिकतर वैज्ञानिक इसे ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा मानते हैं। तेजी से पिघलते ग्लेशियर पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन को समाप्त भी कर सकते हैं अतः यह खतरा बहुत बड़ा और गंभीर है। दुनिया पर इस समय बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, न सिर्फ महामारी कहर बरपा रही है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के कारण वह वक्त भी करीब आता जा रहा है, जब एक समय पृथ्वी पानी में समा जाएगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि भविष्य में दुनिया के खत्म होने का एक बहुत बड़ा कारण ग्लेशियर हो सकते हैं।

पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पर वैज्ञानिक लोग अक्सर शोध और सेमिनार करते रहते हैं। इन सेमिनारों में कुछ देर के लिए इस विषय पर चर्चा होती है, लेकिन इस पर कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता। परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग ने दुनिया में अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है और अब दुनिया के लिए रेड अलार्म भी बज गया है। दरअसल अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग टूटा है, जिसका आकार दिल्ली से 3 गुना ज्यादा बताया जा रहा है। अगर ऐसे ही आकार के आइसबर्ग टूटेंगे तो इस धरती पर तबाही आना तय है। लगातार बर्फ पिघल रही है और समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन इसे इतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा जितना कि लेना चाहिए।

यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बताया है कि दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग ए-76 टूटने के बाद अब वेडेल सागर में तैर रहा है। वैज्ञानिकों के लिए ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इन ग्लेशियरों के पिघलने का कारण है ग्लोबल वार्मिंग।

यदि पूरी दुनिया के ग्लेशियर पिघल गए तो पृथ्वी का तापमान लगभग 60° सेंटीग्रेड तक बढ़



जाएगा, इतने अधिक तापमान में इंसानों का रहना मुश्किल हो जाएगा, वो आसानी से इस गर्मी को झेल नहीं पाएंगे। इसका दूसरा परिणाम यह होगा कि दुनिया में शुद्ध पीने के पानी का संकट उत्पन्न हो जाएगा। शुद्ध पानी का स्टॉक खत्म हो जाने से इंसानों को पीने के पानी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि जल ही जीवन है, इसलिए जल समाप्त तो जीवन समाप्त है, इसलिए जल समाप्त तो जीवन समाप्त।

हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा जितनी जरूरी है, पृथ्वी का स्वस्थ रहना भी उतना ही आवश्यक है। पृथ्वी पर इस समय करीब दो लाख ग्लेशियर हैं, ये प्राचीन काल से पृथ्वी पर बर्फ का एक विशाल भंडार बने हुए हैं, ऐसे में ग्लेशियरों के पिघलने से जमीन पर रहने वाले दुनिया के उन लोगों पर असर पड़ता है, जिनके लिए ग्लेशियर ही पानी का प्रमुख स्रोत हैं, जैसे हिमालय के ग्लेशियर, आसपास की घाटियों में रहने वाले 25 करोड़ लोगों को उन नदियों का पानी देते हैं, जो आगे जाकर करीब 165 करोड़ लोगों के लिए भोजन, ऊर्जा और कमाई का जरिया बनती हैं।

आईपीसीसी की रिपोर्ट में एक रिसर्च के हवाले से चेतावनी दी गई है कि एशिया के ऊंचे पर्वतों के ग्लेशियर अपनी एक तिहाई बर्फ को खो सकते हैं और यह स्थिति तब होगी जब

इंसान ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने में कामयाब हो जाएगा और दुनिया के तापमान की बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित कर दिया जाएगा, यानी दुनिया का बढ़ता यही तापमान ग्लोबल वार्मिंग है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बढ़ने से पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन भी होता है।

नेचर में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक वर्ष 1980 के बाद से समुद्र का जलस्तर औसतन 9 इंच बढ़ गया है और इस वृद्धि का लगभग एक चौथाई हिस्सा ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के पिघलने के कारण हुआ है। अंटार्कटिका में जितनी बर्फ मौजूद है, यदि वो पिघल जाए तो समुद्रों का जलस्तर 200 फुट तक बढ़ सकता है। इसकी बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग, जिससे आइसबर्ग पिघलते हैं और फिर टूटकर समुद्र में गिर जाते हैं। पोस्टडैम इंस्टिट्यूट फॉर क्लाइमेट इंपैक्ट रिसर्च का कहना है कि पिछले 100 वर्षों में दुनिया के समुद्र तल में 35% की बढ़ोतरी ग्लेशियरों के पिघलने की वजह से हुई है और यह सिलसिला आगे भी जारी है। अनुमान

लगाया जा रहा है कि भविष्य में ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र का बढ़ना 30 से 50 सेंटीमीटर तक सीमित रहेगा, क्योंकि अब इन ग्लेशियरों के पास कम ही बर्फ बची है, इसकी तुलना अगर ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ की चादर से करें तो इनके पिघलने से समुद्र तल कई दर्जन मीटर तक बढ़ सकता है, दूसरे शब्दों में तेजी से पिघलते ग्लेशियरों और टूटते आइस शेल्फ पृथ्वी के बिगड़ते स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा लक्षण हैं और इसके लिए जरूरी है कि दुनिया इस विषय को सिर्फ सेमिनार और गोष्ठियों तक ही सीमित न रखे बल्कि इसका विस्तार आम लोगों के बीच होना चाहिए।

इस समय दुनिया के सभी देश इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि कार्बन उत्सर्जन में कमी आनी चाहिए। कार्बन उत्सर्जन का मतलब है, पृथ्वी के वातावरण में मौजूद अधिक कार्बन डाइऑक्साइड, यह इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये ग्रीनहाउस गैस है जो वातावरण में मौजूद गर्मी को रोककर रखती है फिर इससे ही पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है।

तटीय और पर्वतीय क्षेत्रों की ले सुध

■ अजीत द्विवेदी

देश के पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश, पहाड़ी नदियों का उफन कर बहना और भूस्खलन कोई नई बात नहीं है। पहाड़ में रहने वाले इसके आदी होते हैं और वे पहाड़, जंगल व मौसम की पारंपरिक समझ और तैयारियों से सदियों से खुद को बचाते आए हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं सामान्य से ज्यादा होने लगी हैं और पहाड़ के लोग खुद को बचा नहीं पा रहे हैं? इसका दो शब्दों में जवाब है- जलवायु परिवर्तन! चाहे पर्वतीय इलाका हो या तटीय इलाका, सब जलवायु परिवर्तन का शिकार हैं और हर साल जान-माल का भारी नुकसान झेल रहे हैं। पर्वतीय और तटीय इलाकों की पारिस्थितिकी की नजाकत को समझे बगैर अंधाधुंध विकास और जंगल, पहाड़ की कटाई ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि इस इलाके के लोगों को मौसम का अतिरिक्त अनिवार्य रूप से झेलना पड़ रहा है।

सामान्य से अधिक बारिश, नदियों का उफनना और भूस्खलन अब कभी कभार होने वाली घटना नहीं है, बल्कि हर साल और कई बार साल में दो-तीन बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अभी लौटते मॉनसून की बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन की वजह से लगभग आधा उत्तराखंड तबाह है। इसी साल फरवरी में उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही हुई थी। ग्लेशियर टूटने से अचानक नदियों का पानी बढ़ गया था और कई गांव बह गए थे। दर्जनों लोगों की मौत हुई और सैकड़ों पशु बह गए। सैकड़ों घर टूटे। केदारनाथ की भीषण त्रासदी की यादें भी ज्यादा पुरानी नहीं हैं। देश का पर्वतीय इलाका एक दिन में इस हालत

में नहीं पहुंचा है। दशकों पहले जब विकास के नाम पर जंगलों की कटाई शुरू हुई और पहाड़ी नदियों का दोहन करने के लिए पनबिजली की बड़ी बड़ी परियोजनाएं लगनी शुरू हुईं, बांध बना कर नदियों का रास्ता मोड़ा जाने लगा, प्राकृतिक सौंदर्य को भुनाने के लिए पहाड़ काट कर रिसॉर्ट बनाए जाने लगे तभी इसकी शुरुआत हो गई थी। चिपको आंदोलन शुरू करने वाले सुंदरलाल बहुगुणा और उनके साथियों ने उसी समय भांप लिया था कि विकास के नाम पर असल में विनाश हो रहा है। प्रकृति के साथ रहने और उसके साथ सामंजस्य बैठाने की बजाय प्रकृति के साथ छेड़-छाड़ की प्रवृत्ति ने आज हालात ऐसे बना दिए हैं पहाड़ों में रहने वालों का जीवन हर क्षण असुरक्षित हो गया है।

यहीं कहानी तटीय इलाकों की है। आज जब केरल में भारी तबाही मची है और बारिश, बाढ़ से दो दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई है तो सबको माधव गाडगिल रिपोर्ट की याद आ रही है। पारिस्थितिकी के जाने माने विद्वान माधव गाडगिल की अध्यक्षता में वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल का गठन 2010 में तब की केंद्र सरकार ने किया था। उस समय के वन व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश की पहल पर यह आयोग बना था। माधव गाडगिल ने अगस्त 2011 में अपनी रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट आने के 10 साल बाद भी इसकी किसी सिफारिश पर अमल नहीं हुआ है, जबकि उसके बाद से कम से कम तीन बार विध्वंसक बाढ़ आ चुकी है। केरल में 2018, 2020 और अब 2021 में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है।

गाडगिल आयोग की रिपोर्ट में वेस्टर्न घाट्स के 64 फीसदी हिस्से को 'इकोलॉजिकली सेंसिटिव' यानी पारिस्थितिकी के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश की गई थी। उन्होंने अपनी सिफारिशों में कहा था कि केरल के 12 जिलों के 123 गांवों में फैले करीब 13 हजार वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को पारिस्थितिकी के लिहाज से संवेदनशील घोषित किया जाए। इसमें से ज्यादातर गांव इडुक्की जिले में स्थित हैं, जहां इस बार की बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। गाडगिल आयोग ने खनन गतिविधियों और पेड़ों की कटाई पर सख्ती से रोक लगाने की सिफारिश भी की थी। लेकिन किसी भी सरकार ने इस रिपोर्ट को लागू करने में जरूरत नहीं समझी। उल्टे यह कहा गया कि अगर इस रिपोर्ट को लागू किया गया तो विकास की गतिविधियां पूरी तरह से ठप्प



खतरनाक संकेत

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल यानी इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) ने जलवायु परिवर्तन पर अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसे आईपीसीसी वर्किंग ग्रुप। रिपोर्ट ऑन द फिजिकल साइंस बेसिस नाम दिया गया है।

आइए जानते हैं, 1400 से अधिक वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर तैयार इस रिपोर्ट की दस प्रमुख बातें-

1. अगले 20 बरस में वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर जाएगा। पिछला दशक बीते 1.25 लाख वर्षों के मुकाबले काफी गर्म था, जो 1850 से लेकर 1900 के बीच के मुकाबले 2011 से 2020 के दौरान 1.09 डिग्री तापमान अधिक दर्ज किया गया।
2. यदि वर्तमान की तरह ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 21वीं सदी के मध्य में ही वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस सीमा को पार कर जाएगा

3. तापमान में प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भारी से भारी बारिश की घटनाओं की तीव्रता को 7 फीसदी बढ़ा देगी
4. कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता (कॉन्सन्ट्रेशन) 20 लाख वर्षों में सबसे अधिक है
5. समुद्री जलस्तर में वृद्धि 3,000 वर्षों में सबसे तेज है
6. आर्कटिक समुद्री बर्फ 1,000 वर्षों में सबसे कम है
7. कुछ बदलावों को हम और भी पलट सकते हैं, कम से कम आने वाले हजारों वर्षों तक
8. अगर हम अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित कर भी दें, तब भी अगले 1,000 वर्षों तक बर्फ का पिघलना जारी रहेगा
9. महासागरों का गर्म होना जारी रहेगा, यह 1970 के दशक से 2 से 8 गुना बढ़ गया है
10. समुद्र के स्तर में वृद्धि सैकड़ों वर्षों तक जारी रहेगी

हो जाएंगी। विकास पता नहीं कितना हुआ है लेकिन विकास की गतिविधियां विनाश को साफ तौर पर न्योता देती दिख रही हैं।

चाहे उत्तराखंड हो या केरल यह लगभग हर पर्वतीय और तटीय क्षेत्र की कहानी है, जहां विकास बनाम प्रकृति व पारिस्थितिकी की रक्षा की बहस चल रही है। एक तरफ राजनेता, अधिकारी और कारोबारी हैं, जिनका लगभग हर साल आ रही प्राकृतिक आपदा और लोगों की मौतों के बारे में मानना है कि यह विकास की अनिवार्य कीमत है, जो लोगों को चुकानी ही होगी। उनका मानना है कि देश की इतनी बड़ी आबादी के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना, जोखिम उठाए बगैर संभव नहीं है। इस लिहाज से कह सकते हैं कि यह जान बूझकर जोखिम लेने की सोच है। दूसरी ओर पर्यावरणविद् या आंदोलनजीवी हैं, जो मानते हैं कि विकास के नाम पर इस तरह से विनाश की इजाजत नहीं दी जा सकती है। इन दोनों के बीच की बहस सनातन है। जिस तरह से पहाड़ में दशकों पहले चिपको आंदोलन शुरू हुआ था उसी तरह मैदान में दशकों पहले नर्मदा आंदोलन शुरू हुआ था। इस किस्म के आंदोलन, बहस, विकास और विनाश सब साथ साथ चलते रहे।

इस बहस में एक बड़ा सवाल यह है कि आमतौर पर इस किस्म के विकास की कीमत कौन चुकाता है? जाहिर है सबसे गरीब या जंगल में रहने वाले आदिवासी और वंचित लोग इसकी कीमत चुकाते हैं। विकास के लिए या तो

उद्योगपति उनका घर उजाड़ता है या प्रकृति उजाड़ती है। हर हाल में नुकसान उनको उठाना होता है। लेकिन उनके हित की बात करने वाली ताकतें इतनी मजबूत नहीं हैं कि कारपोरेट, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी के गठबंधन से मुकाबला कर सकें। इसलिए विकास के नाम पर घने जंगल काटने, आकाश की ऊंचाई तक पहाड़ तोड़ने और पाताल तक जमीन खोदने का काम जोर-शोर से पूरे देश में चल रहा है। इसे विकास का नाम दिया गया है। जब कहीं भारी बारिश होती है, भूस्खलन होता है, ग्लेशियर टूटते हैं, बाढ़ आती है तो थोड़े समय के लिए प्रकृति को बचाने का शोर मचता है और मारे गए लोगों के

परिजनों को मुआवजा देकर सब कुछ पुराने ढर्रे पर चलने लगता है। जाहिर है जल, जंगल, पहाड़ की रक्षा किसी का सरोकार नहीं है, लेकिन प्राकृतिक संपदा के दोहन पर सबकी नजर है।

उत्तराखंड और केरल की बारिश के लिए जलवायु परिवर्तन कितना दोषी?

उत्तराखंड और केरल में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के कारण 80 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं

पहले सितंबर और फिर उसके बाद अक्टूबर में देश में भारी बारिश हुई है। खासकर



दो राज्यों, उत्तराखंड और केरल में बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन के चलते सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और यहां 80 से ज्यादा लोगों की जानें गईं।

इस बारिश का सबसे आश्चर्यजनक पहलू यह है कि यह ऐसे समय में हुई, जब दक्षिण-पश्चिमी मानसून लौटने की तैयारी में है, जबकि उत्तर-पूर्वी मानसून शुरू हो पाया है।

इन्हीं दो मानसूनों की वजह से देश में बारिश होती है। कहर ढाने वाली यह बारिश इन मानसूनों की बजाय भारतीय महाद्वीप में दूसरे कई मौसमी प्रणालियों के आपसी टकराव की वजह से हुई है।

इसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण वजह मानी जा रही है—वह है वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन, जिसने स्थानीय मौसमों के साथ मिलकर तबाही मचाई। विनाशकारी बरसात ने यह भी दिखा दिया कि चाहे शहरी हो या ग्रामीण पर्यावरण, दोनों मिलकर भी इस स्थिति में नहीं है कि इस तरह की भारी बारिश के साथ सामंजस्य बिठा सकें।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आंकड़ों के अनुसार, 1 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, 22 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छह में ज्यादा (एक्सेस) और 16 में बहुत ज्यादा (लार्ज एक्सेस) बारिश हुई है। ज्यादा बारिश तब होती है जब किसी क्षेत्र में सामान्य से 20 प्रतिशत से 59 प्रतिशत ज्यादा बारिश होती है। बहुत ज्यादा बारिश तब होती है जब किसी क्षेत्र में सामान्य



से 60 प्रतिशत ज्यादा बारिश होती है।

उत्तर-पूर्व भारत को छोड़कर, जो एक लंबे शुष्क दौर से गुजर रहा है, बाकी पूरे देश के 59 प्रतिशत जिलों में 21 अक्टूबर तक ज्यादा या बहुत ज्यादा बारिश हुई है। 21 अक्टूबर के दिन देश में कुल अतिरिक्त बारिश 41 प्रतिशत थी। यह आंकड़ा 7 अक्टूबर को 23 प्रतिशत और 18 अक्टूबर को 25 प्रतिशत था। 19 अक्टूबर को कुल बारिश 36 प्रतिशत तक बढ़ गई थी।

उत्तराखंड में बारिश के अवलोकन से पता चलता है कि किस तरह इसने राज्य में सर्वकालिक बारिश के रिकॉर्ड तोड़ डाले, जिसकी परिणति बाढ़ के रूप में हुई। एक अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच पूरे राज्य में

इस अवधि के लिए सामान्य से 6 गुना बारिश हुई। 18 अक्टूबर को राज्य में सामान्य से 14 गुना बारिश हुई। राज्य के जिलों में चंपावत में सबसे अधिक 115.6 मिमी बारिश हुई, जो उस दिन की सामान्य बारिश का 21 गुना थी।

उसके बाद 19 अक्टूबर को बारिश और बाढ़ कई गुना बढ़ गई। उस दिन राज्य में आमतौर पर होने वाली बारिश से सौ गुने से भी ज्यादा बारिश हुई। आमतौर पर यहां 1.1 मिमी बारिश होती है लेकिन उस दिन 122.4 मिमी बारिश हुई। यहां के 13 जिलों में तो बारिश का पैमाना 125 मिमी तक पहुंच गया। सबसे ज्यादा मौते और नुकसान का सामना करने वाले नैनीताल जिले में तो रिकार्ड लगभग 280 मिमी

ग्लासगो जाएंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महीने के अंत तक ब्रिटेन जाने की तैयारी भी हो रही है। मोदी के 31 अक्टूबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में ग्लासगो में होने वाले जलवायु परिवर्तन कांफ्रेंस (काप-26) में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचेंगे।

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि पीएम ग्लासगो जा रहे हैं। भारत दुनिया के उन गिने-चुने देशों में शुमार है, जो जलवायु परिवर्तन

की चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार अपनी ओर से अधिक प्रयास कर रहा है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, दुनिया में कई प्रदूषक देशों के मुकाबले हमारा राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (एनडीसी) ज्यादा प्रगतिशील है। भारत 2030 तक हरित ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर 450 गीगावॉट करने की ओर बढ़ रहा है। देश में 100 गीगावॉट से ज्यादा नवीनीकृत ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है।

वहीं, मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि हफ्तेभर में पीएम की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक के दौरान काप-26 को लेकर भारत का रुख तय हो जाएगा।



UN CLIMATE
CHANGE
CONFERENCE
UK 2021

IN PARTNERSHIP WITH ITALY

जाते मानसून का कहर

लौटते मानसून की भारी बारिश ने केरल में तबाही मचा दी है। बारिश और भूस्वलन से 26 लोगों की मौत हो चुकी है। घर नदी में समा गये, पुल और सड़कें पानी में बह गये।

लौटते मानसून की भारी बारिश ने केरल में तबाही मचा दी है। बारिश और भूस्वलन से 26 लोगों की मौत हो चुकी है। घर नदी में समा गये, पुल और सड़कें पानी में बह गये। कुदरत का क्रोध चारों तरफ नजर आ रहा है। कई लोगों का कुठ पता ही नहीं चल रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की टीम दिन-रात काम कर रही है। केरल में 2018 और 2019 की बाढ़ की तरह इस वर्ष भी तबाही मचने की आशंका है। मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों में रेड और सात जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। उत्तराखंड में भी बारिश, तूफान के रेड अलर्ट को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग सक्रिय हो गया है। चारधाम की यात्रा रोक दी गई है। इस वर्ष हिमाचल हो या उत्तराखंड भूस्वलन की घटनाएं कुठ ज्यादा ही हो रही हैं। मानसून अपने अंतिम पड़ाव पर है और जाते-जाते यह काफी दर्द देकर जाएगा। एक समय था जब मानसून की फुहार पड़ते ही हृदय उल्लास से भर जाता था। मानसून की वर्षा कई-कई दिन तक

रुकने का नाम नहीं लेती थी लेकिन भयंकर हदसे नहीं होते थे, अब मौसम का मिजाज ही बदल गया है। आज कुठ ही समय में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन ठप्प हो जाता है। वर्षा का पैटर्न ही बदल गया है। अब कुठ ही समय में बारिश सबको आफत में डाल देती है। हर साल बाढ़ आती है, करोड़ों रुपए की सम्पत्ति के नुकसान के साथ-साथ लोगों की जान भी चली जाती है। देश के कोने-कोने से यात्री धर्म लाभ के लिए चारधाम की यात्रा पर आते हैं लेकिन आजकल बरसात के समय उनके प्राण संकट में आ जाते हैं। शासन-प्रशासन जितने साधन उनके पास होते हैं उनके अनुसार सहायता करने का प्रयास करता है। सरकारें हर साल जान-माल की क्षति तो सहन कर लेती हैं लेकिन प्राकृतिक के प्रकोप से बचने के लिए उपायों पर ध्यान नहीं देती। हमारे देश में नहीं दुनियाभर में ग्लोबल वार्मिंग के चलते मौसम के

पैटर्न में बदलाव देखने का मिल रहा है। भारत में भी ग्लोबल वार्मिंग के चलते तापमान बढ़ रहा है और इसके चलते कहीं बहुत ज्यादा बारिश होती है तो कहीं सूखे के हालात पैदा हो जाते हैं। बीती शताब्दी के मुकाबले धरती का तापमान एक डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है। ग्रीन हाउस गैसों के बहुत ज्यादा उत्सर्जन से खासकर कार्बन डाइऑक्साइड से धरती का तापमान बढ़ रहा है। वहीं समुद्र का तापमान 06-07 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। हिन्द महासागर में तो यह बढ़ोतरी और भी ज्यादा हुई है। संपादकीय भारत-पाक महासंघ का विचारघाटी में टारगेट किलिंगकांग्रेस - चुनौतियों का अम्बारड्रस, रैकेट, आर्चन और क्षमा' दुर्गा पूजा' और 'शेख हसीना' क्या से क्या



हुआ, गांधी तेरा देश !इसकी वजह से हवा में नमी बढ़ गई है जिससे असामान्य बारिश देखने को मिल रही है क्योंकि समुद्र की सतह का तापमान बढ़ रहा है, जिसके कारण समुद्र में चक्रवाती तूफानों की संख्या भी बढ़ रही है। जो बारिश पहले कई महीनों में होती थी, अब उतनी ही बारिश एक महीने में ही हो जाती है। पहले मानसून के एक महीने में औसतन 15-20 दिन बारिश वाले होते थे। अब एक माह में बारिश वाले दिनों की संख्या घट कर दस दिन रह गई है। इन दस दिनों में भी बारिश में काफी असंतुलन होता है। भारी वर्षा दिवस में एक ही दिन में हो रही 6.5 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो जाती है। 7 अगस्त की शाम दिल्ली में ही कुठ देर की मूसलाधार बारिश ने राजधानी और आसपास के शहरों में हालात को अस्त-व्यस्त करके रख दिया था। ऐसा नहीं है की जलवायु परिवर्तन अचानक हो गया है। पिछले कई वर्षों से लगातार वैज्ञानिक

और पर्यावरण विशेषज्ञ इस बात के लिए आगाह करते आ रहे हैं कि मौसम तेजी से बदल रहा है और यह बदलाव मानवीय गतिविधियों के चलते हो रहा है। इसलिए बेहतर है कि इन गतिविधियों को रोका जाये जिससे कि अप्रत्याशित ढंग से धरती का गर्म होना रुके। तमाम चेतावनियों और भयावह दुष्परिणामों के रह-रह कर पुष्ट होने के बावजूद कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। पर्यावरण की परवाह बातों, शब्दों, किताबों में और भाषणों में तो दिखती है, व्यवहार में कहीं नहीं दिखती। नेपोलियन ने कहा था-युद्ध में तब हारना बहुत कष्टदायक होता है जब हमें यह पता है कि हम क्यों हार रहे हैं फिर भी हार को न रोका जा सके। ऐसा ही कुठ पर्यावरण को लेकर हो रहा है। इस बिगड़ते पर्यावरण को लेकर हम सब अंजान नहीं हैं, जानते हुए भी हम इसे रोक नहीं पा रहे हैं। जबकि तय यही है कि पर्यावरण महज नैतिकता का सवाल नहीं है। जिंदा रहने का सवाल है। आजादी के बाद से ही देश का विकास पूर्ण रूप से नियोजित नहीं हुआ। नदी-तालाब की जगह सड़कें, इमारतें, बना दी गईं। आबादी के बोझ तले शहर, महानगर दबते गये। अब तो बारिश के पानी की निकासी के लिए भी रास्ता नहीं मिल पाता। फिर जलभराव आफत की वजह बन जाता है। बाढ़ आती है तो फसलें

खराब होती हैं, जान एवं माल की हानि होती है। क्या हम हर साल शोकांतिका से नहीं बच सकते? जिम्मेदारी मानव की भी है। इसलिए पर्यावरण के मिजाज को समझो और इसे बेहतर बनाने के लिए हम जो कुठ कर सके उपाय करें।

ऐसे में यह सवाल फिर से उठने लगे हैं कि क्या इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है? विशेषज्ञों ने इस घटना को समझते हुए जवाब दिया है। बादल फटने से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के प्रभावित होने के सिलसिले में विशेषज्ञों का कहना है कि इस आपदा का पूर्वानुमान करना मुश्किल है क्योंकि यह मुख्य रूप से स्थानीय स्तर पर होने वाली घटना है और पर्वतीय क्षेत्रों में हुआ करती है।

कैसे कहते हैं बादल फटना?

विशेषज्ञों ने बताया कि किसी स्थान पर एक घंटे में यदि 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो इसे बादल का फटना कहा जाता है। अचानक इतनी अधिक मात्रा में वर्षा होने से न सिर्फ जनहानि होती है बल्कि संपत्ति को भी नुकसान होता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि बादल फटने की घटना बहुत छोटे क्षेत्र में होती है और यह हिमालयी क्षेत्रों या पश्चिमी घाट के पर्वतीय इलाकों में हुआ करती है।

उन्होंने कहा कि जब मॉनसून की गर्म हवाएं ठंडी हवाओं के संपर्क में आती हैं तब बहुत बड़े आकार के बादलों का निर्माण होता है। ऐसा स्थलाकृति या पर्वतीय कारकों के चलते भी होता है। स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष (मौसम विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन) महेश पलवत ने कहा कि इस तरह के बादल को घने काले बादल कहा जाता है और यह 13-14 किमी की ऊंचाई पर हो सकते हैं।

यदि वे किसी क्षेत्र के ऊपर फंस जाते हैं या उन्हें छितराने के लिए कोई वायु गति उपलब्ध नहीं होती है तो वे एक खास इलाके में बरस जाते हैं। इस महीने, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं हुईं। ये सभी पर्वतीय इलाके हैं।

क्या भारी बारिश का अलर्ट दे सकते हैं

महापात्रा ने कहा, 'बादल फटने का पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता। लेकिन हम बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के मामले में हमने एक रेड अलर्ट जारी किया था।' पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में सचिव एम राजीव ने कहा कि बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं।

उन्होंने कहा कि इसका पूर्वानुमान करना मुश्किल है लेकिन डोपप्लर रेडार उसका पूर्वानुमान करने में बहुत मददगार है। हालांकि, हर जगह रेडार नहीं हो सकता, खासतौर पर हिमालयी क्षेत्र में।

जलवायु संकट

जलवायु परिवर्तन पर आशंकाएं बिल्कुल वास्तविक हैं, खतरा करीब है और भविष्य विनाशकारी। जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल, आईपीसीसी की रिपोर्ट उन्हीं बातों की पुष्टि करती है जिन्हें हम पहले से जानते हैं और अपने आसपास की दुनिया में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए तापमान तेजी से बढ़ने की वजह से जंगलों में आग लगना और नमी का खोना, भयंकर बारिश के चलते प्रलयकारी बाढ़ और समुद्र व सतह के बीच बदलते तापमान के कारण आने वाले तीव्र चक्रवात।

जिस भविष्य की आशंका थी, वह आ चुका है और हमें इससे बहुत जयादा चिंतित होना चाहिए। बल्कि इस रिपोर्ट से डरकर हमें वास्तविक और सार्थक कार्रवाई करनी चाहिए।

रिपोर्ट के निहितार्थ बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहला, यह साफ है कि दुनिया 2040 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की ओर तेजी से बढ़ रही है। यानी कि अपने को सुरक्षित मानकर चल रही दुनिया के लिए दो दशक बाद सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। यह ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि 1880 के बाद अब तक हमने तापमान में 1.09 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी है, यह औद्योगिक क्रांति का दौर था। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि विज्ञान की मौजूदा चेतावनी कितनी खतरनाक है। अब यह कहने में संकोच नहीं है कि जलवायु में ये बदलाव मानवीय गतिविधियों के चलते आए हैं। अब हम निश्चित रूप से जानते हैं कि इसमें किसकी कितनी भूमिका है, चाहे वह कनाडा में तापमान बढ़ने का मामला हो, यूनाइटेड किंगडम में आग लगने की घटना हो या फिर जर्मनी में बाढ़। अब किसी अगर-मगर की बात ही नहीं है।

ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन 45-50 फीसद कम करके साल 2030 तक साल 2010 के नीचे के स्तर लाने और साल 2050 तक शून्य उत्सर्जन करने की जरूरत है। यानी कि हमें किसी किंतु-परंतु के बजाय तुरंत कदम उठाने होंगे। 2030 तक पेट्रोल की जगह ई-वाहन या कोयला की जगह प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल जैसी चीजों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्राकृतिक गैस भी एक जीवाश्म ईंधन ही है। हमें कहीं अधिक कठोर कदम उठाने होंगे। अगर हम 1870 से 2019 के बीच उत्सर्जन को देखें तो इसमें अमेरिका और यूरोपीय



संघ का योगदान 27 फीसद और ब्रिटेन, जापान और चीन का योगदान 60 फीसदी मिलता है। आने वाले दशक में चीन अपने कार्बन डाइऑक्साइड के मौजूदा 10 गीगाटन उत्सर्जन को बढ़ाकर 12 गीगाटन तक पहुंचा सकता है। चीन जहां, सालाना 10 गीगाटन और अमेरिका 5 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, वहीं भारत 2.6 गीगाटन का उत्सर्जन करता है।

हम केवल यह कह सकते हैं कि हम उतना भर कर रहे हैं, जिससे काम चल सके। ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन इतनी गंभीर चुनौती बन चुका है और विज्ञान हमें इससे निपटने के लिए स्पष्ट संदेश दे रहा है, हमारे प्रयास नाकाफी हैं। दरअसल जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक नेतृत्व की जरूरत है और वैकसीन उपलब्ध कराने के दिशा में किए जा रहे प्रयासों को देखकर हम कह सकते हैं कि मानव-इतिहास में या कम से कम अपने जीवन काल में हम वैश्विक नेतृत्व के सबसे बड़े संकट से गुजर रहे हैं।

जलवायु परिवर्तन भी कोरोना की तरह ही एक वैश्विक समस्या है और पूरी दुनिया को इससे निपटना है। हम अकेले इससे नहीं निपट सकते और न ही हर व्यक्ति को बेहतर वातावरण में रहने का अधिकार दिला सकते हैं। हालांकि जिस तरह से हम कोरोना वायरस और इसके वैरिएंट्स की लड़ाई में पिछड़े रहे हैं, वैसे ही जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने में भी। जबकि आज न केवल गरीब इससे प्रभावित हो रहा है, बल्कि अमीरों पर भी इसका असर पड़ रहा है। इसलिए हमें इस दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। हमें साथ में और तेजी से काम करना होगा। विज्ञान ने चेतावनी दे दी है। अब हमें ठोस कार्रवाई की जरूरत है।

- सुनीता नारायण

बारिश हुई, जो औसतन होने वाली 1.1 मिमी बारिश से लगभग 250 गुना ज्यादा थी।

केरल में बाढ़ की शुरुआत 15 अक्टूबर को हुई, हालांकि राज्य में इस महीने की शुरुआत से ही बारिश हो रही है। 7 अक्टूबर तक केरल में 55 प्रतिशत अधिक बारिश हुई थी। 18 अक्टूबर तक यह आंकड़ा बढ़कर 142 प्रतिशत हो गया था। 21 अक्टूबर तक यह आंकड़ा घटकर 128 प्रतिशत पर आ गया, लेकिन तब तक राज्य में मानसून के बाद होने वाली 90 प्रतिशत बारिश हो चुकी थी।

यह बारिश मुख्यतः उत्तर पूर्व मानसून के चलते होनी है, जो 26 अक्टूबर से ही शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों में और बारिश की भविष्यवाणी के कारण केरल अभी भी बाढ़ और भूस्खलन के लिए हाई अलर्ट पर है। यहां राज्य सरकार द्वारा पहली बार कई भूस्खलन संभावित क्षेत्रों को खाली कराया गया है।

देश के अलग-अलग हिस्सों में असामान्य समय पर हुई ये बारिश देश और उसके पड़ोसी देशों में अनश्चित मौसमी प्रणालियों का नतीजा है।

16 अक्टूबर को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा था कि दक्षिण-पूर्व अरब सागर और उससे सटे केरल तट पर एक कम दबाव का क्षेत्र (लो प्रेशर एरिया) है। इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश पर एक कम दबाव का क्षेत्र भी है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ेगा और अफगानिस्तान पर एक पश्चिमी विक्षोभ बनाएगा।

उसने पूर्वानुमान लगाया था कि अरब सागर पर कम दबाव का क्षेत्र केरल और दक्षिणी प्रायद्वीप में बारिश लेकर आएगा। केरल में आई ताजा बाढ़ और भूस्खलन इसी वजह से हुआ।

मौसम विज्ञान विभाग ने यह भी अनुमान लगाया था कि तटीय आंध्र प्रदेश पर एक कम दबाव का क्षेत्र और अफगानिस्तान पर पश्चिमी विक्षोभ एक दूसरे से टकराएंगे तो उत्तर और उत्तर-पश्चिमी भारत में बारिश होगी। इस परस्पर टकराव से ही उत्तराखंड में तेज बारिश और बाढ़ आई।

इसी तरह की मौसम प्रणालियों के टकरावों के चलते यह राज्य पहले भी तबाही का शिकार बना है। 2013 में उत्तराखंड में बादल फटना और अचानक बाढ़ आना, ऐसे ही



टकरावों की वजह से हुआ था, जिसमें 5000 से अधिक लोग मारे गए और हजारों करोड़ के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा था। जिस तरह से दुनिया गर्म हो रही है, भविष्य में इस तरह की घटनाएं और बढ़ने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता।

स्थानीय स्तर पर तापमान का बढ़ना भी राज्य में तबाही की एक वजह हो सकता है। उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार 50 वर्षीय महिपाल नेगी ने डाउन टू अर्थ को बताया - 'ताजा बाढ़ से एक सप्ताह पहले मैंने नई टिहरी में तापमान में बढ़ोतरी महसूस की और इस बारे में अल्मोड़ा और नैनीताल में अपने दोस्तों से बात की थी। दोस्तों ने बताया कि उन्होंने भी अपने-अपने जिलों में ऐसा ही महसूस किया है। उस सप्ताह तापमान 32-33 डिग्री सेल्सियस था, जो आमतौर पर यहां मई-जून में होता है। हालांकि रात का तापमान सामान्य ही था, जो 15 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है।'

नेगी कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में अक्टूबर महीने में इस तरह का बढ़ा तापमान और उसमें उतार-चढ़ाव पहले कभी नहीं देखा। ऐसी गर्मी का अनुभव करने वाला उत्तराखंड अकेला राज्य नहीं था। इसी दौरान उत्तर-पूर्व भारत ने अक्टूबर के सबसे गर्म महीनों में से एक देखा है। 16 अक्टूबर तक के दिनों में कई उत्तर-पूर्व भारतीय शहरों में तापमान सामान्य से 4-5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। 16 अक्टूबर को ईटानगर में तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस था।

इसके अलावा, इसमें वैश्विक जलवायु कारकों की भी एक भूमिका थी। मैरीलैंड विश्वविद्यालय में जलवायु वैज्ञानिक रघु मुतुर्गुडडे

के मुताबिक, 'यह चीजों का मारक संयोजन है। सितंबर के दौरान पश्चिमी यूरोप से यूरेशिया में एक बहुत ही ठंडी तापमानी विसंगति फैल गई, जो नम पश्चिमी विक्षोभ को स्पंदित कर रही थी, क्योंकि भूमध्य सागर बहुत गर्म था।'

इसके अलावा गर्म आर्कटिक और समुद्री बर्फ के रिकॉर्ड नुकसान ने सितंबर के चरम को जन्म दिया, जिसने ग्रीष्मकालीन मानसून परिसंचरण (दक्षिण पश्चिम मानसून) को बनाए रखा, लेकिन परिसंचरण के कमजोर होने और पूर्वी लहरों की शुरुआत ने नमी को बंगाल की खाड़ी से भी स्पंदित करने का मौका दिया।'

उनके मुताबिक, 'पूर्वी लहरें, उत्तर-पूर्वी मानसून की शुरुआत से जुड़ी हैं। ऐसी ही एक पूर्वी लहर के अगले कुछ दिनों में केरल में बारिश लाने की उम्मीद है, जिसके चलते मौसम विभाग ने राज्य के लिए अलर्ट भी जारी किया है। दक्षिण-पश्चिम मानसून की कमजोर वापसी और उत्तर-पूर्व मानसून की कमजोर और देर से शुरुआत के कारण कम दबाव वाले क्षेत्रों में बहुत अधिक नमी होती है और बहुत अधिक वर्षा होती है।'

वह आगे कहते हैं, 'लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि भूमि-उपयोग में परिवर्तन (लैंड यूज चेंज) और पश्चिमी घाट (केरल के मामले में पश्चिमी और उत्तराखंड के मामले में हिमालय) हमेशा भारी बारिश को अचानक बाढ़ और भूस्खलन में बदलने में सक्षम हैं। प्रकृति हमें बारिश देती है और हम बाढ़ पैदा करते हैं।'

Understanding Global Warming in the Correct Perspective

Surya Prakash Kapoor¹, Nishchay Kapoor^{2,*}, Scientific Advisor, Maulik Bharat

¹ Department of Physics, Punjab University, India

² Indo-Swiss Training Centre, CSIO, India

*Corresponding Author: nishchaykapoor22@gmail.com, nishchaykapoor221088@gmail.com

Copyright©2020 by authors, all rights reserved. Authors agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 International License

Abstract Presently, meteorologists are of the opinion that all weather is created by the sun alone. Warmth for the planets is provided primarily by the sun's energy. At an average distance from the Sun of nearly 150 million Kms the Earth intercepts only a very small fraction of the Sun's total energy output. However, it is this radiant energy (or radiation) that drives the atmosphere into the pattern of everyday wind and weather and allows the earth to maintain an average surface temperature of about 15° Centigrade [1]. During last 150 years of industrial revolution this average surface temperature of the Earth has risen to 15.8° Celsius. A careful study and an in-depth analysis of the above statement has revealed that the contribution of the geothermal energy element spewed out by the active volcanoes both on the dry land and on the seabed (I.e., mid-ocean ridge about 74,000 Kms long) has not been taken into account while attributing the entire credit to the solar incoming radiation alone. In view of this lapse, the problem of global warming deserves a reexamination. It is a common knowledge that heat radiations of 1100° Centigrade temperature are being pumped into the atmosphere from the caldera of every active volcano of

dry land and 1200° Centigrade Magma surges up through fissures and floods rapidly across the sea floor. The volcanoes at the mid-ocean ridge alone account for the 75% Magma output on the Earth. It has been estimated that the sea floor rifts and the hydrothermal springs along the Mid-Ocean Ridge have been around for at least 2 to 3.5 Billion years. Obviously, the surface temperature of the Earth is jointly due to Geothermal Energy and Incoming Solar Radiation.

Keywords Ring of Fire, Indo-Pacific Warm Water Pool Geothermal Energy

Introduction

The oceans of the world cover 2/3rd of the Earth's surface area. The upper layer of the sea (Thermocline) popularly known as Sunlight Zone is mainly influenced by the solar radiation. Since the sun commutes between Tropics of Cancer and Capricorn, thereby crossing the Equator twice a year; the intensity of solar heat is highest in equatorial region when this solar heat is overlapped by western portion of the Ring of Fire(Fig. 1-3), gives rise to the Indo-Pacific Warm Water

Pool(Fig. 4) the most important unique weather feature of the world [2].

The broad, shallow body of warm (>29° C) water found in the western tropical Pacific Ocean plays an important role in the coupled ocean-atmosphere dynamics and thermodynamics associated with the El Nino-southern oscillation phenomenon. Its area is more than 30x10⁶sq Km. In addition, those waters maintain such temperatures down to approximately 200 m in most regions, therefore the term "Warm Pool" has been coined [3]. This pool holds warmest sea waters in the world. It is considered as the "Heat Engine" of the globe. Since this area of warm water pushes western Pacific water into Indian Ocean it is also often referred to as the Indo-Pacific warm water pool. This region hosts the Indonesian through flow the network of the currents through which surface and thermocline waters are transported from the western equatorial Pacific Ocean into Indian Ocean[4]. The pacific warm pool is characterized by a mean sea surface temperature of 29° C (exceeding 28° C, the minimum surface water temperature that supports deep convection), weak trade winds,

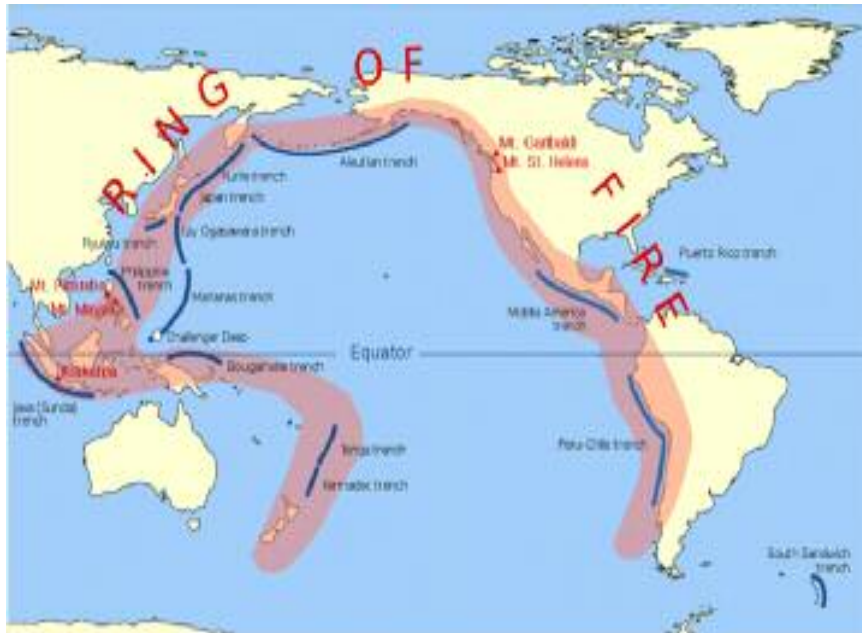


Fig. 1. The Pacific Ring of Fire

and the resultant deep convections with thunderstorm tops exceeding 15 Km. It has been found that over a period of roughly two decades, the warm pool's average annual temperature and dimensions increase and then decrease like a slowly pulsating beacon. Because these waters are hot enough to drive heat and moisture high into the atmosphere (by convection) the warm pool has a large effect on the climate of surrounding lands. It has been called the heat engine of the world and plays a key role in climate and monsoon variability for many nations throughout Asia & Africa, and also influences the remote regions and large-scale climate models variability. Furthermore, the size and intensity of the warm pool fluctuates with the El-Nino southern oscillation (ENSO). During El Nino events the pool expands horizontally but shrinks in vertical depth. The opposite occurs during La-Nina. Overall, in the recent years, the pool has increased in both horizontal coverage and ver-

tical depth[5].

Warm Water Pool being the joint venture of Solar & Geothermal Energy frequently generates the most powerful tropical cyclones of the world. The sea surface temperature

of this Warm Water Pool remains higher than 28° Celsius throughout the year. It may be recalled that the threshold sea surface temperature for genesis of Tropical Cyclone is 26.5° Celsius. For example, Average Annual Sea Surface Temperature(AASST) of Pacific Ocean is 29° Celsius, Atlantic Ocean 27° Celsius, Bay of Bengal 26° Celsius and Arabian Sea 25°Celsius, respectively. Coming to the frequency of the formation of Tropical Cyclones; Pacific Ocean spawns 65%, Atlantic Ocean 20%, Bay of Bengal 10% and Arabian Sea 5% only. Moreover, the diameter and maximum sustained surface wind speed also varies proportionately. For example, the diameter of Tropical Cyclone generated by this Warm Water Pool is double that of Tropical Cyclone generated in Arabian Sea. The maximum sustained surface wind speed in this variety of Tropical Cyclone is 450 Kms/hr in comparison to 150Kms/hr of that of Arabian



Fig. 2. Location of earth's major volcanoes

Sea. Had the sun been the alone source of energy, AASST would have been uniform in the Equatorial / Tropical zones of all oceans. Evidently, the ring of fire incorporating therein the major chunk of active volcanoes of the world, accounts for the highest AASST value of Pacific, the largest ocean of the world. In Atlantic Ocean there are few active volcanoes thereby proportionately reducing the AASST to 27° Celsius. In the Bay of Bengal there is only one active Barren Island Volcano, further reducing AASST to 26°Celsius. Since there's no active volcano in the Arabian Sea the AASST is the least 25°Celsius.

The Magma spewed out by mid ocean ridge heats up the water at the bottom of the ocean. The cold water at the ocean bed percolates into the ridge and comes in contact with 1200° Celsius Magma. As a result, hydrothermal vents are developed, and long-term circulation (convection currents) are set up in the oceans of the world. Accordingly, the top layer of ocean water is jointly heated by Solar and Geothermal Energy, whereas the bottom is solely heated by Geothermal Energy.

Due to the activities in the mid ocean ridge, 10 cubic Km of new crust is created every year. Accordingly, huge amount of Geothermal Energy is transferred to the cold sea water of the seabed. This amount of heat drastically changes the temperature profile of the seawater. Since, the phenomenon of sea spreading is faster (20 cm/year) in the East Pacific Rise of the Pacific Ocean as compared to that of Mid-Atlantic Ridge (1 cm/year) of Atlantic Ocean, therefore, much more heat is transferred to the Pacific Ocean Waters than that of Atlantic Ocean. Black Smokers

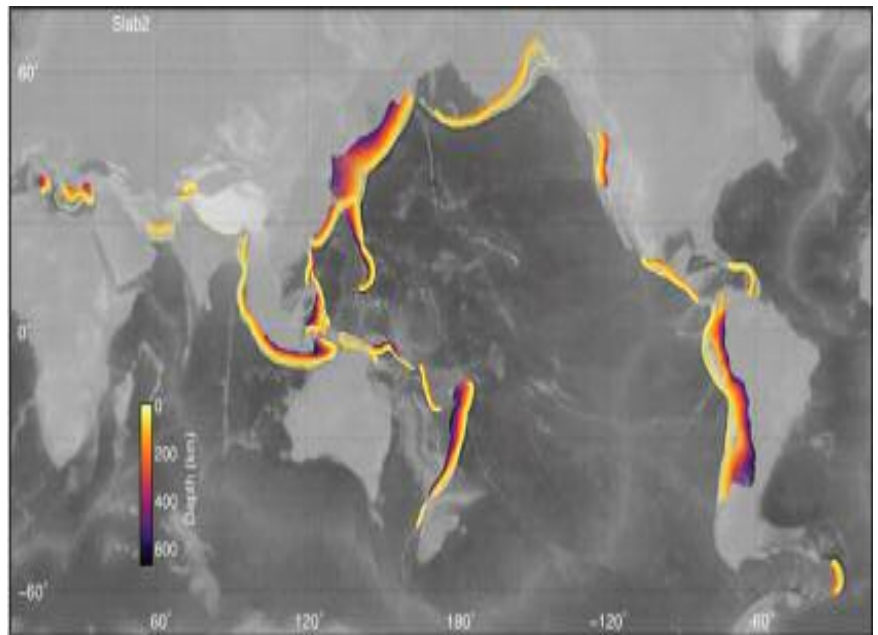


Fig. 3. Global map of subduction zones, with subducted slabs contoured by depth

(Hydrothermal Vents), the natural chimneys on the seabed, form along mid-ocean ridges where the tectonic plates are moving apart. The Black smokers begin when the seawater seeps through cracks in the sea floor. The water is heated by volcanic magma and it dissolves minerals from the rock. Once, the water is superheated, it spews from the vents in scalding, mineral-rich black plumes. Water jetting from Black Smokers can reach 662° Celsius. Each drop of seawater in the world circulates through a Black Smoker every 10 million years[6,7].

Discussion & Conclusion

The climate is the average of the weather prevalent in an area over a period of time. Weather conditions include temperature, rainfall, geothermal energy element, sunshine, wind, humidity and cloudiness. The

interaction of atmosphere and the ocean water is complex. In contrast to land, the ocean heats up and cools down more slowly. Since the overall effect of the oceans is to act as a heat reservoir, any land mass near large water body is protected from great swings of temperature. The role of smaller players like pollution contributed by consumption of fossil fuels, sunspot activity and orbital variation in the game of Climate Change have so far been over emphasized by the entire World Community of Meteorologists. Whereas the role of major player i.e., Geothermal Energy has been totally overlooked and the entire credit has been wrongly attributed to the Sunshine. Since the meteorologists failed to take cognizance of contribution of geothermal energy element in the formation of Indo-Pacific warm water pool, therefore, their understanding of its origin remained obscured. Likewise, there are many

other serious implications of this lapse on their part. For example, wind energy which is again a joint enterprise of solar and geothermal energy is being incorrectly termed as indirect solar energy (alone).

Water molecules of the oceans & air molecules of global atmosphere remain inert till solar or geothermal radiations agitate them; which implies that by favorably managing either or both of these sources of heat energy the atmosphere - ocean interactions and so on the global climate pattern will remain under human control.

The prevalent renewable energy sources viz. windmills, solar photovoltaic panels, geothermal power plants and gadgets for harnessing atmospheric electricity are quite efficient tools to realize this dream. Needless to say, all of these so-called global cooling machines, presently working worldwide have already reduced the global surface temperature to a fair extent. For experiment sake if these meritorious machines are switched off only for a period of six months, the global surface temperature will again shoot up noticeably. Going a step further, if geother-

mal power plants are installed on active volcanoes of Indonesia, The Philippines and Papua New Guinea, which are encompassing the Indo-Pacific warm water pool; the alarming rate of its growth can be certainly checked because the warmth of this pool is jointly sponsored by geothermal energy (of neighbouring active volcanoes) and the solar energy of the Equatorial / Tropical region. As an extreme measure if geothermal power plants are installed on all active volcanoes of dry land mass of the entire earth, the global surface temperature will miraculously dip below 15° Celsius. With the aid of coupled general circulation models an attempt can be made to simulate atmospheric and oceanic conditions to anticipate the post plant installation scenario. Instead of launching an impractical campaign for non-consumption of fossil fuels and also giving hot pursuit to weather / climate prediction programs like TOGA (tropical ocean and global atmosphere) and other components of world climate research programs (WCRP) the resources should be more justifiably utilized for the erad-



Figure 5. Hydrothermal Vents - Black Smokers

ication of problem of the global warming in mission mode manner.

All images: Courtesy Google Images Simultaneously, preference should also be given to the task of harnessing Atmospheric Electricity under the banner of International Commission on Atmospheric Electricity (I.C.A.E). A concerted attempt, made in this regard, will surely yield cherished results [8].

REFERENCES

1. C. Donald Ahrens, "The Earth & Its Atmosphere", *Meteorology Today: An Introduction to Weather, Climate & the Environment (Fifth Edition)*, West Publishing Company, USA, 1994, Pages No. 2, 306.
2. Tarbuck & Lutgens, Chapter 4: "Volcanic & Plutonic Activity", *Earth: An Introduction to Physical Geology (Sixth Edition)*, Prentice Hall, New Jersey, 1999, Pages No. 112 (Fig. 4.30).
3. BK Linsley, Y Rosenthal, DW Oppo, "Holocene Evolution of the Indonesian Throughflow and the Western Pacific Warm Pool", *Nature Geoscience* 3(8), 578-583, 2010, (nature.com).
4. SP Anderson, RA Weller & RB Lukas, "Surface Buoyancy Forcing and the Mixed Layer of Western Pacific Warm Pool: Observations and 1D Model Results", *Journal of Climate* 9(12), 3056-3085 (1996), (journals.ametsoc.org).
5. Patrick De Deckker, "The Indo-Pacific Warm Pool: Critical to World Oceanography and World Climate", *Geoscience Letters* 3, Article Number: 20 (2016), (*Official Journal of the Asia Oceania Geosciences Society (AOGS)*).
6. Western Pacific Warm Pool - SKYbrary Aviation Safety, (https://www.skybrary.aero/index.php/Western_Pacific_Warm_Pool)
7. John Farndon, "Diverging Plates" "Black Smokers", *Visual Factfinder: Earth & Space (First Edition)*, Bardfield Press, 2004, Pages No. 226-227, 386-387.
8. International Commission on Atmospheric Electricity, (<http://www.icae-iamas.org>)

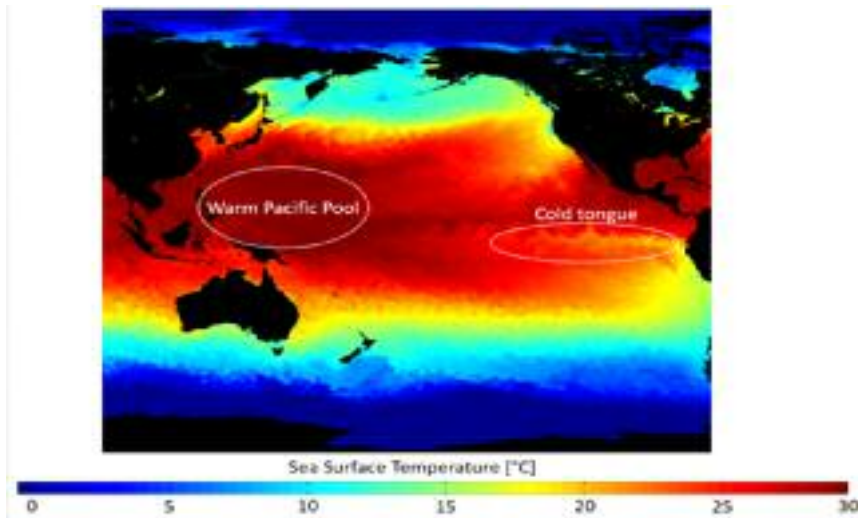


Fig. 4. Heat distribution map

सामाजिक निकृष्टता का राजनीति में श्रेष्ठता बन जाना

● रामस्वरूप रावतसरे

हरिया घर से बाहर निकला ही था कि एक लड़का लम्बा सा कुर्ता और पायजामा पहने हुए आ रहा था। उसने दाढ़ी भी बढ़ा रखी थी। पास आकर बोला काका राम राम। हरिया ने उसे उसकी आवाज से पहचाना कि यह तो नुकड़ वाले खेमा का लड़का है जो आवारा, निकम्मा, बदचलन की उपाधियों से विभूषित सत्या है। इसने कैसे अपना रंग रूप बदल लिया कहीं कोई बड़ा काण्ड करने की साजिश में तो नहीं है।

खैर हरिया ने भी उसे “राम राम” कहा और घर में घुसने लगा, कि सत्या बोला “काका आपके क्या हाल चाल है। काम धन्धा कैसा है।” हरिया सोचने लगा कि जो खुद कोई काम नहीं करता निकम्मा हो, घर वालों के लिए बोझ हो, वह आज कैसे इतना पूछ रहा है। फिर भी हरिया ने उससे कहा कि “बस जैसे तेरे चला रहे है।” हरिया ने उत्सुकता वस उससे पूछा कि आजकल तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि उसने एक एनजीओ जोड़ने कर लिया है। हरिया ने पूछा कि “तुम उसमें क्या करते हो?” वह बोला “काका उसमें मेरा काम है व्यवस्था देखना, भीड़ को जुटाना, नियंत्रित करना।”

हरिया विस्मित सा होते हुए बोला “व्यवस्था देखते हो! किस प्रकार की? तुम तो पढे लिखे भी नहीं हो और ..” हरिया आगे कुछ बोलता, वह मुस्कराते हुए बोला “मैं आवारा, निकम्मा कैसे व्यवस्था देखता हूँ। काका आजकल जिस प्रकार राजनीति ने किचड़ स्नान करना शुरू कर दिया है। वहाँ पढे लिखों की कहां आवश्यकता है। उसमें वहीं ठहर सकता है, सफल हो सकता है, जो गटर में उतरने का साहस रखे। काका राजनीति में जब तक जनता नहीं समझे प्रपंच तथा आडम्बर रचने वालों की बहुत पूछ है।

सभी पार्टियों में ऐसे लोगों की संख्या अधिक मिलेगी। वे सफल राजनेता भी कहलाते हैं। किचड़ उछालने तथा किचड़ में लोटने का साहस ही राजनीति में पहली सीढ़ी मानी जाने लगी है। सभ्य एवं संस्कारी लोग तुम्हारी तरह फटेहाल दड़बों में ही नजर आते हैं। उन्हें कोई नहीं पूछता।”

“आज मुझे देखों मेरे सम्पर्क में सत्तापक्ष विपक्ष तथा प्रशासन के लोग हैं। क्योंकि मैं हुड़दंग करने कराने में सबसे आगे रहता हूँ। हुड़दंग में पढाई की नहीं हिम्मत की आवश्यकता रहती है। गरीब गुरबों को डराकर, लालच देकर, इककठे करके रखना ही जुलूस एवं किसी प्रकार के सरकार विरोधी आंदोलन के लिए व्यवस्था कहलाता



है। किसी को भीड़ से डर लगता है, किसी को भीड़ सुकून देती है। तथाकथित नेताओं को और कभी कभी प्रशासन को मीडिया में हेडलाईन बनने के लिए भीड़ की आवश्यकता होती है। इन दोनों के लिए व्यवस्था बनाए रखना ही हमारा काम है।”

वह आगे बोला “काका इस समय कोरोना की महामारी फैल रही है। इसमें किसी भी प्रकार की भीड़ का होना प्रशासन के लिए बहुत बड़ा सर दर्द है। ऐसे में हम

ही काम आते हैं। किसी नेता या पार्टी को अपनी ताकत दिखानी है। उसमें हम ही संख्या बल की व्यवस्था देखते हैं। वे तो बस सुविधा शुल्क की व्यवस्था करते हैं। काका अब मैं वह आवारा सत्या नहीं रहा। अब कोआरडिनेटर सत्यनारायण हो गया हूँ।” हरिया के दिमाग में “ताउते तुफान” जोर मार रहा था। सत्या ने आगे कहा “काका मेरे लायक कोई काम हो तो याद करना।” यह कहते हुए वह चला गया।

हरिया वहीं दरवाजे पर ही बैठ गया। वह विचारने लगा सुबह दस बजे सोकर उठने वाले मंचों से भोर की वेला पर भाषण देते हैं। रात को दारू पीकर बीबी को पीटने वाले स्त्री अधिकारों पर बेबाक लिखते हैं, बोलते हैं। व्यवस्था के विरोध में बोलना, सत्ता धारी पार्टी को जी भरकर गाली देना। राष्ट्र विरोधियों का गुण गान करना। राष्ट्र हित की बात करने वालों को देश एवं मानवता का विरोधी बताना ही आजकल बुद्धिजीवी होने का सबूत बन कर रह गया है। जब तक सत्ता हासिल नहीं हो जाती संविधान की दुहाई दी जाती है और जब सत्ता मिल जाती है तो सारे काम स्वयं के सुख सुविधा के अनुसार होने लगते हैं। प्रशासन भी उन्हीं की बनाई लाईन पर कदमताल करता है। संविधान जनता को दिखाने (भरमाने) भर के लिए रह जाता है। सत्या की तरह भीड़ जुटाने तथा हटाने की व्यवस्था देखने वाले जब राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से सत्ता हथिया लेते हैं तो क्या होता है? इसकी अधिक व्याख्या की जरूरत नहीं है। आज उन्हें ना चाहते हुए भी जनता द्वारा भोगा जा रहा है। सामाजिक निकृष्टता का राजनीति में श्रेष्ठता बन जाना किसी भी प्रकार से शुभ संकेत नहीं है।

हरिया को लगा उसे कोई पुकार रहा है। उसने माथे का पसीना पूँछा और खुसक हुए हल्क को तर करने का असफल प्रयास करता हुआ घर के अन्दर चला गया। ■

मील का पत्थर 1 अरब टीका नहीं बल्कि सभी पात्र लोगों का पूरा टीकाकरण है

● बाँबी रमाकांत

अ सली मील का पत्थर 1 अरब टीका खुराक देना नहीं है बल्कि 12 साल से ऊपर सभी पात्र जनता को निश्चित समय-अवधि के भीतर पूरी खुराक टीका देना है। कोविड टीके के संदर्भ में, किसी भी देश का यही लक्ष्य होना चाहिए। जब तक दुनिया की पूरी आबादी का टीकाकरण नहीं हो जाता, तब तक कोविड पर हर्ड इम्यूनटी (सामुदायिक प्रतिरोधकता के जरिए) रोक लगाना मुश्किल है।

अनेक अमीर देशों ने अपनी अधिकांश पात्र जनता का पूरा टीकाकरण कर लिया है और कुछ तो तीसरी बूस्टर खुराक भी देने लगे हैं (हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन बूस्टर खुराक की फिलहाल सलाह नहीं दे रहा है)। अमरीका, कनाडा, यूरोप के अनेक अमीर देश, सिंगापुर, ने अपनी 50-80% जनता का पूरा टीकाकरण महीनों पहले ही कर लिया है। सिंगापुर दुनिया का पहला देश है जिसने जुलाई तक ही अपनी आबादी के 80% को पूरा टीका दे दिया था। चीन ने अपनी जनता को 223 करोड़ खुराक टीका दे दिया है। असल लक्ष्य 1 अरब या 2 अरब नहीं है बल्कि अपनी आबादी के 70% से अधिक का, एक निश्चित समय-अवधि में पूरा टीकाकरण करना है।

भारत के 1 अरब टीका खुराक देने के मील के पत्थर को सराहना चाहिए क्योंकि हमारी स्वास्थ्य प्रणाली अमीर देशों जैसी सशक्त नहीं है, जन स्वास्थ्य में निवेश दुनिया के अधिकांश देशों की तुलना में जीडीपी के भाग का अत्यंत कम है। पर यह भी संज्ञान में लेना चाहिए कि 9-10 महीने में हमने सिर्फ 1 अरब खुराक दी हैं जबकि अब तक सभी पात्र लोगों को पूरी खुराक मिल जानी चाहिए - देश में लगभग 111 करोड़ लोग पात्र हैं, इसलिए 222 करोड़ खुराक लगनी हैं, जिसमें से 100 करोड़ (1 अरब) लग चुकी हैं।



लोकप्रिय संक्रामक रोग विशेषज्ञ और ऑर्गनायज़्ड मेडिसिन ऐकडेमिक गिल्ड के महासचिव डॉ ईश्वर गिलाडा ने भारत सरकार की 100 करोड़ टीके लगाने की उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है - महामारी से पहले ही अनेक दशकों से, भारत दुनिया की 'फार्मैसी' कहा जाने वाला देश रहा है क्योंकि भारत में निर्मित सस्ती जेनेरिक दवाएं दुनिया के अनेक देशों में उपयोग की जाती हैं। महामारी से पूर्व भारत वैक्सीन निर्मित और दुनिया भर में निर्यात करने में भी सबसे आगे रहा है - सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया महामारी से पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता कहा जाता है।

पर भारत में जो दवा या वैक्सीन निर्मित और निर्यात होती है उनमें से अधिकांश की मौलिक शोध तो अमीर देशों द्वारा की गयी होती है। यह क्षमता भारत में विकसित होनी चाहिए कि मौलिक शोध की दिशा में भी प्रगति हो। फिलहाल यही हकीकत है। कोविड में भी भारत में हर 10 में से 9 वैक्सीन जो लगी हैं उसका मौलिक शोध विदेश में हुआ है।

डॉ ईश्वर गिलाडा ने बताया कि भारत में कोविड टीकाकरण 16 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। 278 दिन के बाद 21 अक्टूबर 2021 को भारत ने 1 अरब खुराक का लक्ष्य पूरा किया। भारत में सरकारी नीति के अनुसार, 12 साल से ऊपर हर इंसान का टीकाकरण होना चाहिए (पूरी खुराक) - 1 अरब 11 करोड़ लोग इसके पात्र हैं। 2 अरब 22 करोड़ खुराक का लक्ष्य पूरा करना है और अभी 9 महीने से अधिक समय अवधि में 1 अरब हुआ है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि आगामी 70 दिन में (2021 के अंत तक) हम लोग यह लक्ष्य पूरा कर लेंगे - जो यकीनन बहुत सराहनीय होगा - यदि ऐसा हुआ तो सभी पात्र लोगों को पूरी खुराक वैक्सीन लग जाएगी, और लगभग निर्धारित समय-अवधि में (11-12 महीनों में) लग जाएगी जो हर्ड इम्यूनटी (सामुदायिक प्रतिरोधक क्षमता) के लिए भी श्रेयस्कर रहेगा।

ऑर्गनायज़्ड मेडिसिन ऐकडेमिक गिल्ड की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ सुनीला गर्ग और महासचिव डॉ ईश्वर गिलाडा ने कहा कि 1 अरब खुराक देने के लक्ष्य को पूरा करने के बाद अब

दवा प्रतिरोधकता - टीबी, एचआईवी दवायें कारगर न रहें तो क्या होगा?

लगभग 2 साल पहले जब चीन के वुहान से पहला कोरोना वाइरस रिपोर्ट हुआ था, तो दुनिया में अमीर देश तक अत्यंत चिंतित हुए क्योंकि इस रोग की कोई कारगर दवा नहीं थी। महामारी के दौरान हम सबने देखा कि यह चिन्ता वाजिब थी क्योंकि हृदय विदारक त्रासदी वैश्विक स्तर पर हुई है। महामारी ने हमें एक सीख दी है कि जो दवाएं हमारे पास उपलब्ध हैं, उनको हम ज़म्मेदारी से इस्तेमाल करें क्योंकि दवा प्रतिरोधकता उत्पन्न हो गयी तो यह दवाएं कारगर नहीं रहेंगी और रोग के इलाज के लिए विकल्प कम (और अत्यंत महंगे) होते जाएंगे, और रोग लाइलाज हो जाए यह तक मुमकिन है।

दवा प्रतिरोधकता को रोगानुरोध प्रतिरोधकता (एंटी-मायक्रोबीयल रेजिस्टिन्स) भी कहते हैं।

भारत में जब प्रथम एचआईवी कেস की पुष्टि हुई थी तो डॉ ईश्वर गिलाड प्रथम पक्ति के चिकित्सकों में रहे हैं जिन्होंने एड्स-से जूझ रहे लोगों की चिकित्सकीय मुमकिन देखभाल शुरू की, एड्स सम्बंधित शोषण और भेदभाव के खिलाफ सक्रिय रहे और आज भी कोविड महामारी में पूरी कार्यसाधकता के साथ जुटे हुए हैं। डॉ ईश्वर गिलाड जो अंतर्राष्ट्रीय एड्स सुसाइटी (आईएएस) की अध्यक्षीय समिति में अकेले भारतीय निर्वाचित सदस्य हैं और एड्स सुसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ने कहा कि रोगानुरोध प्रतिरोधकता के कारण टीबी एवं एचआईवी से बचाव और चिकित्सकीय इलाज भी जटिल होता जाता है। टीबी बैक्टीरिया और एड्स वाइरस में ऐसा बदलाव आ जाता है जिसके कारण प्रभावकारी दवाएं उस पर कारगर नहीं रहतीं। इसीलिए रोगानुरोध प्रतिरोधकता के कारणवश, संक्रमण नियंत्रण असफल होने लगता है, इलाज अन्त महंगी दवाओं से करने का प्रयास किया जाता है जो लम्बा और जटिल हो जाता है, रोग गम्भीर होता जाता है, और मृत्यु तक का खतरा बढ़ जाता है।

अंतरराष्ट्रीय रोगानुरोध प्रतिरोधकता जागरूकता सप्ताह - 18-24 नवम्बर 2021

हर साल की तरह विश्व स्वास्थ्य संगठन इस साल 18-24 नवम्बर तक अंतरराष्ट्रीय रोगानुरोध प्रतिरोधकता जागरूकता सप्ताह का आयोजन कर रहा है जिससे कि लोग चेतें कि रोगानुरोध प्रतिरोधकता खतरनाक ढंग से बढ़ती पर है जिसके कारण दवा प्रतिरोधकता कीटानुषु दवाएं कारगर नहीं रहें हैं, और इलाज विकल्प और उपचार अत्यंत महंगा और जटिल होता जा रहा है।

इसी लिए डॉ ईश्वर गिलाड और भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉ सुदर्शन मंडल ने एक उच्च स्तरीय सलाहकार बैठक की अध्यक्षता की।

डॉ ईश्वर गिलाड ने कहा कि यदि मौजूदा टीबी और एचआईवी दवाओं के प्रति रोगानुरोध प्रतिरोधकता उत्पन्न होती चली जाएगी तो यह दवाएं कारगर नहीं रहेंगी फिर हम कैसे टीबी और एड्स उन्मूलन का सपना साकार करेंगे? इसीलिए जो दवाएं हमारे पास हैं वह वैज्ञानिक उपलब्धियां रहें हैं उनको हमें बड़ी सूझ-बूझ और ज़म्मेदारी के साथ सही उपयोग करना है जिससे कि रोगानुरोध प्रतिरोधकता उत्पन्न होने का खतरा न मंडराए।

कोविड महामारी के कारण लगी तालाबंदी और स्वास्थ्य सेवा पर पड़े अतिरिक्त बोझ के तले सभी स्वास्थ्य सेवाएं कुप्रभावित हो गयी थीं। एक ओर जहां कोविड के लिए स्वास्थ्य सेवा मिलना दूर हो रहा था तो दूसरी



ओर गैर-कोविड अन्त रोग का जांच-इलाज भी अत्याधिक प्रभावित रहा। टीबी और एचआईवी स्वास्थ्य सेवाएं भी अत्याधिक प्रभावित रहें।

हाल ही में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, कोविड महामारी का असर जो हमारी स्वास्थ्य प्रणाली पर पड़ा है, उसके कारणवश आगामी 5 साल में भारत में 20% अधिक टीबी मृत्यु और 10% अधिक एचआईवी मृत्यु हो सकती हैं।

डॉ ईश्वर गिलाड की अपील है कि अभी वर्तमान में कोविड दर नीचे की ओर जा रहा है और हमें अन्त रोगों के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को बिना विलम्ब मजबूत करना होगा। टीबी और एचआईवी स्वास्थ्य सेवा जितना लाभ पहुंचाती है उसे रोगानुरोध प्रतिरोधकता पंचकर कर देता है। रोगानुरोध प्रतिरोधकता पर अंकुश लगाना एक बड़ी चुनौती है और जन स्वास्थ्य के लिए उच्चतम प्राथमिकता होनी चाहिए।

मुंबई के डीपीएस शताब्दी म्यूनिसिपल अस्पताल के प्रमुख और भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के प्रशिक्षक और वरिष्ठ फेफड़े रोग विशेषज्ञ डॉ विकास एस ओसवाल ने इस माह ऑक्टोबर में एक महत्वपूर्ण शोध देश में आरम्भ किया है जो सरकार को भावी नीति निर्माण के लिए आधार देगा कि दवा प्रतिरोधक टीबी के इलाज के लिए नवीनतम दवाएं हमारे परिप्रेक्ष्य में अनुकूल हैं या नहीं। इन दवाओं को बीपीएएल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें 3 दवाएं शामिल हैं जो इस प्रकार हैं - बेडाकुइलीन, प्रीटोमेनिड और लिनेजोलिड।

विषाक्त दवा की डोज कम करें, कहना है डॉ अमीत द्रविड का

रूबी हाल क्लिनिक अस्पताल के वरिष्ठ एचआईवी और संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉ अमीत द्रविड ने कहा कि विश्व टीबी रिपोर्ट के नवीनतम आंकड़े देखें तो ज्ञात होगा कि 2019 में 4.45 लाख लोग टीबी के कारण भारत में मृत हुए जिनमें 9500 ऐसे लोग थे जो एचआईवी के साथ सह-संक्रमित थे। 2019 में 71000 ऐसे एचआईवी पॉजिटिव लोग थे जिनको टीबी रोग हुआ जिनमें से 44517 को जीवनरक्षक एंटीरेट्रोविरल दवाएं प्राप्त भी हो रही हैं। भारत में 124000 लोगों को 2019 में दवा प्रतिरोधक टीबी थी पर सिर्फ 56569 लोगों को मुनासिब दवा मिल पायी। डॉ अमीत द्रविड ने कहा कि दवा प्रतिरोधक टीबी के इलाज में उपयोग होने वाली एक दवा से विषाक्तता हो सकती है (लिनेजोलिड)। इसलिए वैज्ञानिक शोध के मद्देनजर हम लोगों को विषाक्त दवा (लिनेजोलिड) की डोस (खुराक की मात्रा) 1200 मिलीग्राम से 600 मिलीग्राम कम कर देनी चाहिए।

डॉ ईश्वर गिलाड का कहना है कि जब टीबी से बचाव मुमकिन है, पक्की जांच और पक्का इलाज मुमकिन है और सरकारी स्वास्थ्य सेवा में निशुल्क है तो क्यों लाखों लोग हर साल देश में टीबी से मृत होते हैं? टीबी आज भी एचआईवी के साथ जीवित लोगों के लिए सबसे सामान्य और घातक अवसरवादी संक्रमण है। यदि हम एचआईवी पॉजिटिव लोगों को टीबी से बचा पाएंगे तो टीबी और एड्स दोनों के उन्मूलन की ओर बढ़ने में सहायक रहेगा और मानव पीढ़ा भी घटेगी।

नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, दुनिया में एक साल में 1 करोड़ लोगों को टीबी रोग हुआ और 14 लाख लोग मृत, एवं एक साल में 15 लाख लोग नए एचआईवी से संक्रमित हुए और 680,000 लोग एड्स सम्बंधित रोगों से मृत।

बच्चों पर बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण हो

कोरोना काल के पूर्णबंदी के दौरान बाल विवाह, यौन शोषण, अपराध और ऑनलाइन दुर्व्यवहार के मामलों में चिंताजनक बढ़ोतरी दर्ज हुई। नए आंकड़ों के अनुसार पिछले साल रोज करीब साढ़े तीन सौ बच्चों के साथ आपराधिक घटनाएं घटीं। हालांकि अध्ययनकर्ताओं और राष्ट्रीय अपराध रेकार्ड ब्यूरो ने इसके पीछे बड़ी वजह कोरोना काल में हुई बंदी और कामकाज के ठप पड़ जाने, परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाने को माना है। बच्चों समाज में ही नहीं, अपने घरों में भी असुरक्षित है। बच्चों पर हो रहे अपराध एक सभ्य समाज पर बदनुमा दाग है। जबकि एक सभ्य समाज की पहचान इस बात से भी होती है कि उसमें बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होता है, वे खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। इस दृष्टि से हम सदा से पिछड़े नजर आते रहे हैं। कहते हैं कि समाज में शिक्षा के प्रसार से हिंसा और अपराध जैसी घटनाएं स्वतः कम होने लगती हैं। भारत में शिक्षा की दर तो बढ़ रही है, मगर हिंसा और अपराध के मामले भी उसी अनुपात में बढ़े हुए दर्ज होते हैं, यह शिक्षा की विसंगति का ही परिणाम है। सबसे चिंता की बात है कि भारत में बच्चों के साथ हिंसक व्यवहार, यौन अत्याचार एवं उनके अधिकारों के हनन पर अंकुश नहीं लग पा रहा, जो चिन्ताजनक होने के साथ शासन-व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।

हाल ही में स्कूल ऑफ बिजनेस में सेंटर फॉर इन्वैशन एटरप्रेन्योरशिप की मदद से एक सर्वे ऑनलाइन शिक्षा की स्थिति का आकलन करने के लिये किया गया था। इस सर्वे में समभागी बने लोगों में से 93 फीसदी लोगों ने यही माना है कि ऑनलाइन शिक्षा से बच्चों के सीखने और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ा है, घरों में कैद होकर भी वे ऑनलाइन अपराधों के शिकार हुए, उनमें मानसिक विकृतियां पनपी। इससे बच्चों पर नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ा, जिससे उनकी सुप्त शक्तियों का जागरण एवं जागृत शक्तियों का संरक्षण एवं संवर्धन अवरुद्ध हुआ है। बच्चों के समग्र विकास की संभावनाओं का प्रकटीकरण रूका है। लाखों छात्रों के लिए स्कूलों का बंद होना उनकी शिक्षा में अस्थाई व्यवधान बना है जिसके दूरगामी प्रभाव का आकलन धीरे-धीरे सामने आने लगा है। बच्चों का शिक्षा से मोहभंग हो गया। बच्चों अपराध एवं यौन शोषण के शिकार हुए हैं। ये स्थितियां गंभीर

एवं घातक होने के साथ चुनौतीपूर्ण बनी है। सत्य को ढका जाता है या नंगा किया जाता है पर स्वीकारा नहीं जाता। और जो सत्य के दीपक को पीछे रखते हैं वे मार्ग में अपनी ही छाया डालते हैं। बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के संबंध में ऐसा ही देखने को मिला है।

भले ही ताजा आंकड़ों में पहले की तुलना में आपराधिक मामलों में कुछ कमी दर्ज हुई है, मगर वह संतोषजनक नहीं है। कई मामलों में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ी हैं। मनोचिकित्सक अरुणा रूटा के अनुसार, 'बच्चों के साथ यौन शोषण करने वाले लोग सेक्शुअल डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। उन्हें बच्चों के यौन शोषण से मद्धा मिलता है और अपनी इन हरकतों का सबूत मिटाने के लिए वे बच्चों की हत्या तक कर देते हैं।' बच्चों को टारगेट करने वाले लोगों को पीडोफाइल कहा जाता है। इनका रुझान शुरू से बच्चों की तरफ होता है। वे वयस्कों के बजाय बच्चों को देखकर उत्तेजित होते हैं। ऐसे ही बीमार मानसिकता के लोगों ने पूर्णबंदी के दौरान बच्चों पर विकृत मानसिकता के हमले जहां-जैसे मौके मिले किये। जब कल-कारखाने बंद रहने और उसके बाद भी बहुत सारे रोजगार सुचारुरूप से बहुत दिनों तक नहीं चल पाने की स्थिति में बच्चों के साथ काम की जगहों पर दुर्व्यवहार की घटनाएं नहीं होने पाईं, इसलिए आंकड़े पहले की तुलना में कुछ घटे हुए दर्ज हुए। बंदी की वजह से बच्चों को घरों में बंद रहने पर मजबूर होना पड़ा था, ऐसे में उनके माता-पिता का अनुशासन और हिंसक व्यवहार कुछ अधिक देखा गया। यह खुलासा बंदी के दौरान हुए अन्य अध्ययनों से हो चुका है। ऐसे में बाल अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्थाओं और सरकारी महकमों के लिए यह चुनौती बनी हुई है कि इस पर कैसे काबू पाया जाए। यों बाल अपराध, बाल अधिकारों के हनन, बेवजह प्रताड़ना, बाल मजदूरी, यौन शोषण आदि के खिलाफ कड़े कानून हैं, मगर उनका कितना पालन हो पा रहा है, इसका अंदाजा ताजा आंकड़ों से लगाया जा सकता है। बच्चों के खिलाफ आपराधिक घटनाओं के मामले में मध्यप्रदेश अग्रणी है, फिर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार हैं।

पीडोफाइल खास योजना के तहत बच्चों पर अपराधों को अंजाम देते हैं। वे अक्सर बच्चों के आस-पास रहने कोशिश करते हैं। वे

ज्यादातर स्कूलों या ऐसी जगहों को चुनते हैं, जहां बच्चों का आना-जाना ज्यादा हो। ज्यादातर मामलों में बच्चों को शिकार बनाने वाले उनके करीबी ही होते हैं। ये स्कूल बस का ड्राइवर, कंडक्टर, शिक्षक या स्कूल का कोई कर्मचारी हो सकते हैं। दूसरी तरह के लोग घर के भी हो सकते हैं चाहे वे चाचा, मामा, पड़ोसी भी हो सकता है। दूसरी तरह के ये लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसे लोग आसानी से शक के दायरे में नहीं आते। कई बार बच्चों के शिकायत करने पर भी अभिभावक बच्चों का यकीन नहीं करते। भारतीय समाज में बच्चों के प्रति यौन व्यवहार एक आम चलन की तरह देखा जाता है। बच्चों के यौन शोषण पर काबू पाना तो दिन पर दिन कठिन होता जा रहा है। इसलिए हर बार की तरह महज आंकड़ों पर चिंता जाहिर करने के बजाय ऐसे अपराधों की जड़ों पर प्रहार करने के उपायों पर विचार करने की जरूरत है।

बहुत सारे गरीब परिवारों के बच्चे कानूनी प्रतिबंध के बावजूद कालीन, पटाखे बनाने वाले कारखानों, चाय की दुकानों, ढाबों और घरेलू नौकर के रूप में काम करते पाए जाते हैं। वहां उनके मालिक न तो उनकी बुनियादी और अनिवार्य सुविधाओं का ध्यान रखते हैं और न खाने-पीने का। ऊपर से उनके साथ मार-पिट्टाई भी करते हैं। बच्चों अपने अभिभावकों की पिटाई के भी शिकार होते हैं। बहुत सारे लोगों की धारणा है कि मारने-पीटने से बच्चे अनुशासित होते हैं, जबकि अनेक मौकों पर, अनेक अध्ययनों से उजागर है कि मार-पीट का बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उनमें अपराध बोध पनपता है।

बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराध, खासतौर पर यौन अपराध के ज्यादातर मामले सामने नहीं आ पाते, क्योंकि बच्चे समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। अगर वे समझते भी हैं तो डंट के डर से अभिभावकों से इस बारे में बात नहीं करते हैं। महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय के अध्ययन में भी यही बात सामने आई है। बच्चों पर बढ़ रहे अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिये व्यापक प्रयत्नों की अपेक्षा है। बच्चों से खुलकर बात करें। उनकी बात सुनें और समझें। अगर बच्चा कुछ ऐसा बताता है तो उसे गंभीरता से लें। इस समस्या को हल करने की कोशिश करें। पुलिस में बेझिझक शिकायत करें। बच्चों को 'गुड टच-बैड टच' के बारे में बताएं- बच्चों को बताएं कि किस तरह

GRIM RECORD

8% HIKE IN CRIMES AGAINST CHILDREN

► In 2017, 3,955 cases had victims under 18 years of age. The state recorded a rise of 8% compared to 3,637 recorded in 2016

► Kidnapping & abduction biggest crime against children; as per 2017 report, 21% children yet to be traced

► Ahmedabad recorded 25% jump in crimes against children up from 481 in 2016 to 600 in 2017. In Surat, 526 crimes against minors were recorded



121% HIKE IN CRIMES AGAINST SENIOR CITIZENS

► In 2017, 1,099 persons above the age of 60 were victims of crimes compared to 496 in 2016 and 195 in 2015 – 6th highest in India

► Ahmedabad recorded 534 crimes against senior citizens, a 48% jump from 362 in 2016



NEGLIGENT DRIVING KILLED 22 DAILY

► 22 persons died on Gujarat roads daily due to negligence in 2017 – eighth highest in India. Of these, 4 deaths were attributed to 'hit-and-run' cases – 11th highest in India

► A total 21,114 rash driving cases registered on state roads – 3 cases every hour. This is 6th highest in India. Of these, 5,711 cases reported grievous injuries while 5,132 were minor injuries

MISSING CHILDREN/MINORS

	Boys	Girls	Total
Untraced from previous years	257	503	760
Reported missing in 2017	387	1,025	1,412
Total	644	1,528	2,172
Traced in 2017	476	1,177	1,653
% of recovered children	73.9%	77%	76.1%



CRIME AGAINST CHILDREN/MINORS

Kidnapping	1,746
POCSO cases	1,704
Exposure/abandonment	122
Murder	87
JJ Act cases	50
Foeticide	18
Child marriage	6
Cyber crime	5
Child labour	3
Rape	2

PROFILE OF THE ACCUSED IN THE POCSO CASES

Boyfriend/
online friend | 571
Friend/neighbour/
relative | 537
Family member | 93
Not known | 32
Total | 1,233



NO. OF VICTIMS

Theft/ snatching	270
Forgery/ cheating	147
Criminal intimidation	135
Injury	112
Grievous hurt	45
Murder	44
Robbery	44



SENIOR CITIZENS

	2015	2016	2017
Ahmedabad	17	362	534
Surat	0	0	131
Gujarat	195	496	1,099



CRIME BY DELINQUENTS

Theft	461
Assault	284
Burglary	183
Rioting	107
Rash driving	105
Robbery	79
Murder	67
Death by negligence	29
Rape	2

किसी का उनको छूना गलत है। बच्चों के आस-पास काम करने वाले लोगों की पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए। जब कोई अपराध करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। अपराधियों को जल्द सजा समाज में सख्त संदेश देती है कि ऐसा अपराध करने

वाले बच नहीं सकते। बाल रौन अपराधियों को सजा देने के लिए खास कानून है- पॉक्सो यानि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। इस कानून का मकसद बच्चों के साथ रौन अपराध करने वालों को जल्द से जल्द सजा दिलाना है, इस कानून का सही परिप्रेक्ष्य में तत्परता से पालन होना चाहिए।

बच्चों के खिलाफ अपराध के ज्यादा मामले बाल सुरक्षा अधिनियम 2012 आने के बाद सामने आए हैं। पहले अपराधों को दर्ज नहीं कराया जाता था लेकिन अब लोगों में जागरूकता आने के कारण बच्चों के खिलाफ अपराध के दर्ज मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है।

ललित गर्ग

चावल के फोर्टीफिकेशन से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के धंधे का फोर्टीफिकेशन

इस तरह के अनाज आगे जाकर कैसर का कारण बनेंगे

प्रकृति के साथ खिलवाड़ अब हमारे देश में एक नया षड्यंत्र कंपनियों करवा रही हैं, जिसमें गरीबों को मिलने वाले चावल को फोर्टिफाइड करने की घोषणा कर रहे हैं

राशन की दुकान पर मिलने वाला चावल हो, मिड-डे मील में बालकों को मिलने वाला चावल हो, वर्ष 2024 तक हर योजना के माध्यम से मिलने वाला चावल फोर्टिफाइड कर दिया जाएगा। महिलाओं और बच्चों के कुपोषण की समस्या के निदान हेतु चावल को फोर्टिफाइड करना एक समाधान के रूप में प्रचारित किया जा रहा है।

लेकिन क्या वाकई भारत सरकार गरीबों के कुपोषण को लेकर चिंतित है? या बहुराष्ट्रीय कंपनियों की एजेंट बनकर दोनों मोटे धंधे में साजिधार बन गए हैं।

फोर्टीफिकेशन क्या है?

'फोर्टीफिकेशन एक अंग्रेजी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है दुर्गबन्दी या किलेबन्दी' किंतु अनाज के लिए इस शब्द का प्रयोग पोषक तत्वों से अनाज को 'पुष्ट' करना है।

अनाज का फोर्टीफिकेशन कैसे किया जाता है??

प्राकृतिक रूप से कोई भी अनाज अपने गुण-धर्म अनुसार मिट्टी-सूर्यप्रकाश एवं जल से स्वयं ही पुष्टिकर्ता होता है, जैसे जामुन का फल लौह तत्व से भरपूर है, किंतु केलें में उसकी मात्रा भिन्न है, आंवले में विटामिन सी के साथ कैल्शियम-आयरन भी है।

किंतु जब कृत्रिम रूप से उसपर कोई परत चढ़ा दी जाती है तो उसे अंग्रेजी के शब्द फोर्टिफाइड से अलंकृत कर दिया जाता है।

चावल को फोर्टिफाइड करने के लिए टूटे हुए चावलों का पाउडर बनाया जाता है फिर उसमें आयरन-कैल्शियम और कृत्रिम विटामिन्स का पाउडर मिला दिया जाता है, इस सबका आटा बनाने के बाद तेज गर्म चावलों पर मशीनों द्वारा इस लेप को चिपका दिया जाता है। और कृत्रिम रूप से कथित पौष्टिक चावलों का निर्माण होता है।

क्या ये चावल वास्तव में पौष्टिक हैं?

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली(एम्स) के पेट रोग एवं मानव पोषण के वरिष्ठ डॉक्टरों ने बताया की दुनिया के किसी कोने में ऐसे चावल या अनाज खाने से किसी भी प्रकार के कुपोषण में आजतक कोई कमी नहीं आयी है।

कृत्रिम रूप से पौष्टिक किये गए चावल पोषण तो करते ही नहीं हैं बल्कि उल्टा शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि कृत्रिम परत चढ़े चावल अपने पूर्ण रूप से पकते ही नहीं हैं।

किस-किस खाद्य पदार्थ को फोर्टिफाइड किया जा रहा है?

देश में अनाज को फोर्टिफाइड करने से पहले सबसे पहले समुद्री 'नमक' को आयोडीन से फोर्टिफाइड किया गया। बिना आयोडीन युक्त नमक को देश में कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया और उसे दिमाग के लिए बेहद जरूरी बताया गया। जबकि उससे कई गुणा पौष्टिक सेंधा नमक और सांभर झील का नमक देशवासियों के भोजन से दूर करके उन्हें कुपोषित किया गया, जिस देश के हर भोजन दाल-सब्जी अनाजों में भरपूर आयोडीन था उन्हें जबरन कृत्रिम आयोडीन वाला घातक कुपोषित नमक खाने पर मजबूर किया गया।

इसके अलावा दूध को भी कृत्रिम 'विटामिन डी' से फोर्टिफाइड किया जा रहा है लेकिन देश की सबसे बड़ी दूध सहकारिता कंपनी अमूल ने अपने दूध को कृत्रिम फोर्टीफिकेशन करने से रो कहे हुए मना कर दिया कि हम अपने ग्राहकों की सेहत से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं।

भारत सरकार अब बड़े पैमाने पर खाद्य तेलों को कृत्रिम रूप से फोर्टिफाइड करने जा रही है।

इतनी चीजों का फोर्टीफिकेशन क्यों?

अगर मान लिया जाय कि देशवासियों में आयरन की कमी है तो केवल चावल का फोर्टीफिकेशन से काम क्यों नहीं चल

सकता? गेहूँ, दालें, खाद्य तेल, दूध इतनी चीजों को फोर्टिफाय करने की क्या आवश्यकता है जबकि आजतक कोई वैज्ञानिक प्रमाण फोर्टीफिकेशन को सही नहीं मानता बल्कि कृत्रिम पदार्थ डालने से सेहत पर घातक दुष्परिणाम ही मिले हैं।

पांच बहुराष्ट्रीय कंपनियों का धंधा

दुनिया में केवल पांच बहुराष्ट्रीय कंपनियों (जर्मनी की बी ए एस एफ , स्विट्जरलैंड की लोनजा, फ्रांस की अइसओ, नेदरलैंड की रॉयल डी सी एम और ए डी एम) ही कृत्रिम पोषक तत्वों की निर्माता और आपूर्तिकर्ता हैं और किसी भी देश की सरकारों के माध्यम से लॉबी बनाकर, सत्तारूढ़ पार्टियों को लालच देकर जबरन कानूनी रूप से खाद्य वस्तुओं को फोर्टिफाय कराने के लाखों करोड़ों के धंधे में लगी हुई हैं।

कुपोषण का भारतीय समाधान

अगर भारत सरकार वास्तव में देशवासियों के कुपोषण को लेकर चिंतित है तो सरकारी राशन दुकानों के माध्यम से हर गरीब के घर में स्वदेशी सस्ता और बेहद पौष्टिक गुड़ पहुंचा सकती थी, भारतीय गुड़ आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस एवं अनेक आवश्यक विटामिन्स का सस्ता भंडार है।

देश में करोड़ों टन गन्ने से केमिकल युक्त चीनी के स्थान पर पौष्टिक गुड़ बने और सरकार अपनी सस्ते गहले की दुकानों के माध्यम से अनाजों के साथ-साथ गुड़ खरीदकर भी पहुंचा सकती है। इससे लाखों कोल्हू गांव-गांव खुल जाएंगे, करोड़ों लोगों को अपने गांव में स्वरोजगार भी मिलेगा।

ना सिर्फ देश का गुड़ देशवासियों का कुपोषण दूर करता बल्कि दुनिया में अनेक देशों के लोगों की कुपोषण की तकलीफ दूर करने का स्वदेशी,सस्ता और स्वास्थ्यवर्धक समाधान बनता।

लेकिन दुर्भाग्य से भारत सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के धंधे को चमकाने और सत्तारूढ़ पार्टी ने उन्हीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के फायदे के बदले मोटा कमीशन खाने वाले रास्ते को चुना है

ज्योतिर्मय गौमृत सेवा संस्थान
(गों सेवा एवं कैसर पीड़ितों को समर्पित संस्थान)



भारत अगले लक्ष्य - 1 अरब 22 करोड़ और टीके की खुराक लगाने की ओर अग्रसर है जिससे कि सभी 12 साल से ऊपर लोगों का पूरा टीकाकरण हो सके। इसके लिए यह भी जरूरी है कि जिन 6 वैक्सीन को भारत सरकार ने अनुमति दी है वह सभी पूरी क्षमता के साथ निर्मित हो रही हों और टीकाकरण कार्यक्रम में लग रही हों। पर हकीकत यह है कि सरकार ने जिन 6 वैक्सीन को अनुमति दी है, उनमें से लग सिर्फ 3 रही हैं। जो 3 वैक्सीन लग रही हैं उनमें से सिर्फ 1 ही लगभग 90% लोगों को लगी है (कोविशील्ड - आक्सफर्ड एस्ट्रा-जेनेका)। कोवैक्सिन जिसे भारत बाइओटेक ने भारत सरकार के साथ बनाया है वह कुल खुराक का सिर्फ 10-11% है और रूस की वैक्सीन स्पुतनिक तो बहुत ही कम लगी है (1% से भी कम)। 3 ऐसी वैक्सीन हैं जो सरकार द्वारा महीनों से पारित हैं पर लगनी शुरू भी नहीं हुई हैं। मोडेरेना (इस अमरीकी वैक्सीन की भारत में मार्केटिंग सिपला कम्पनी करेगी), जॉनसन एंड जॉनसन (इस अमरीकी टीके को बाइओलोजिकल-ई भारत में निर्मित करेगी) और जाई-कोवडी (जाईडस कैडिला और भारत सरकार द्वारा बनायी हुई दुनिया की पहली प्लाजमिड डीएनए वैक्सीन) भारत में पारित हैं पर लगनी शुरू तक नहीं हुई हैं।

भारत सरकार द्वारा जिन 6 वैक्सीन को अनुमति मिली है उन सब को बिना विलम्ब पूरी क्षमता के साथ निर्मित करके जल्दी से जल्दी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अन्य वैक्सीन जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पारित हैं उनपर भारत सरकार विचार करे कि उन्हें जल्दी से जल्दी अनुमति मिले और वह भी देश में उपलब्ध हों। जब वैक्सीन पूरी क्षमता के साथ निर्मित हो सकेंगी और बिना विलम्ब लग सकेंगी तब ही निर्यात के लिए और भारत सरकार के मैत्री कार्यक्रम के लिए टीके अधिक उपलब्ध रहेंगे।

डॉ ईश्वर गिलाडा और डॉ सुनीला गर्ग ने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर दवाएं और टीके निर्यात करता आया है। यदि कोरोना को हराना है तो दुनिया की कम-से-कम 70% आबादी का पूरा टीकाकरण एक निश्चित समय अवधि में हो जाना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य है कि दुनिया के हर देश की कम-से-कम 70% आबादी का पूरा टीका जून 2022 तक मिल

जाए। यदि भारत की टीका कम्पनियां अपनी पूरी क्षमता से वैक्सीन निर्मित नहीं कर पाएंगी तो कैसे यह लक्ष्य पूरे होंगे? इसीलिए यह जरूरी है कि टीकाकरण में विलम्ब न हो, टीकाकरण गति अनेक गुना बढ़ें, वैक्सीन निर्माण में अत्याधिक बढ़ोतरी हो, अन्य वैक्सीन जो पारित हैं पर लगनी नहीं शुरू हुई हैं वह सब भरसक रूप से कार्यक्रम में नीतिगत लग रही हों, निर्यात आदि के लिए स्टॉक रहे और सभी देश अपनी आबादी का टीकाकरण समय से कर सकें।

यदि इन 1 अरब खुराक के आंकड़े ध्यान से देखें तो पाएंगे कि टीकाकरण सामान रूप से नहीं हुआ है - कुछ प्रदेश में जो आबादी में पूरा टीकाकरण करवाए लोगों का औसत दर है वह राष्ट्रीय दर से कहीं ज्यादा है तो अनेक प्रदेश में राष्ट्रीय दर से बहुत कम। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल में अत्याधिक टीकाकरण जो राष्ट्रीय औसत पूरे-टीके-दर से कहीं ज्यादा है तो उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में राष्ट्रीय औसत का आधा या कम। 278 दिन के टीकाकरण में 2-3 दिन मात्र ऐसे हैं जब भारत ने अपने रोजाना टीका लक्ष्य पूरा किया (1 करोड़ टीका रोज का लक्ष्य) बाकी दिन बहुत कम टीकाकरण हुआ।

वर्तमान रोजाना 53 लाख टीका दर है, पर दर होना चाहिए 1.74 करोड़

टीकाकरण दर बढ़ोतरी पर तो है पर रोजाना लक्ष्य (1 करोड़ टीका रोज) से बहुत कम ही रहा है। मई 2021 में रोजाना 19.69 लाख टीके लगे, जून 2021 में रोजाना 39.89 लाख टीके लगे, जुलाई में 43.41 लाख टीके लगे, अगस्त में 59.29 लाख टीके लगे, सितम्बर 2021 में 78.69 लाख टीके लगे पर अक्टूबर 2021 में औसत रोजाना टीका दर गिर कर 53.21 लाख हो गया।

अब भारत में यदि 70 दिन में 1 अरब 22 करोड़ टीके लगाने हैं तो अत्याधिक सक्रियता के साथ एकजुट होना होगा। समय बलवान है। वैक्सीन निश्चित समय अवधि में सभी पात्र लोगों को लगनी है यह जन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जरूरी है। यदि 70 दिन में 1 अरब 22 करोड़ टीका लगाने हैं तो रोजाना 1 करोड़ 74 लाख टीके का औसत दर आना चाहिए जो मौजूदा 53 लाख के दर से 3 गुना से अधिक है।

बूस्टर डोज डॉ सुनीला गर्ग और डॉ ईश्वर गिलाडा ने कहा कि जिन लोगों ने शुरू में टीका

लगवा लिया था उनमें से अधिकांश वही लोग थे जिन्हें कोरोना का खतरा अत्याधिक था जैसे कि वरिष्ठ नागरिक, पहली पंक्ति के कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कर्मी आदि। यह मुमकिन है कि जो वैक्सीन से लाभ उन्हें मिल रहा था, वह संभवतः 6 माह या अधिक अवधि में कुछ कम हुआ हो - यदि ऐसा है तो क्या उन्हें तीसरी खुराक या बूस्टर डोज मिलनी चाहिए? एक ओर जो लोग वर्तमान में टीके के सुरक्षा कवच से बाहर है या वर्चित हैं, उन्हें टीके की सुरक्षा देना जरूरी है तो दूसरी ओर यह भी देखना जरूरी है जो लोग पहले टीका करवा चुके हैं वह सब पूरी तरह से सुरक्षित बने रहें। बूस्टर डोज देनी है या नहीं इस पर वैज्ञानिक रूप से राय स्पष्ट हो, और नीति और कार्यक्रम बिना विलम्ब तय हो क्योंकि अनेक अमीर देश ऐसे हैं जहां तेजी से बूस्टर डोज लगनी शुरू हो चुकी है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बूस्टर डोज के लिए फिलहाल मनाही की हुई है।

भारत सरकार ने मई 2021 में आदेश दिया था कि कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों खुराक के बीच समय अवधि 12-16 हफ्ते रहेगी। डॉ ईश्वर गिलाडा जैसे विशेषज्ञों का मानना है कि यह अवधि कम होनी चाहिए - यही जन स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी रहेगा। भारत सरकार ने 25% वैक्सीन निजी वर्ग के लिए आरक्षित कर रखी हैं परंतु निजी वर्ग इनका बहुत ही कम उपयोग कर पाया है।

कोविड टीकाकरण 2 पारी में सुबह से मध्यरात्रि तो होना ही चाहिए जिससे कि लोग अपनी सुविधानुसार लगवा सकें और देहाड़ी का नुकसान आदि न हो। अवकाश के दिन टीकाकरण बंद हो जाता है जब कि अनेक लोगों को अवकाश के दिन करवाना शायद सुविधाजनक रहे। सरकार ने वृद्ध और सीमित शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए घर पर टीकाकरण का वादा तो किया था पर वह असलियत में कितना हो पा रहा है वह मूल्यांकन का विषय है।

ड्रग कंट्रोलर जनरल ओफ इंडिया ने कोविड टीके को इमर्जन्सी उपयोग के लिए लाइसेंस तो दे दिया था अब लगभग 1 साल हो गया है - इसलिए उसको फ़ाइनल शोध नतीजे देख के सामान्य लाइसेंस देना चाहिए। ■

दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन

● बाँबी रमाकांत

ती

स साल के निरंतर शोध के बाद आखिरकार, दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन, 'आटीएस,एस', को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों में उपयोग के लिए संस्तुति दे दी। इस मलेरिया वैक्सीन टीके से बच्चे सबसे घातक कस्मि की मलेरिया से बचेंगे जो मलेरिया कीटाणु, 'प्लैज़मोडीयम फ़ेलकीपेरम', के कारण रोग ग्रस्त होते हैं। यह मलेरिया टीका अत्यंत लाभकारी तो है परंतु मलेरिया नियंत्रण और उन्मूलन के लिए कदापि पर्याप्त नहीं है।

कीटनाशक से युक्त मच्छरदानी, साफ़-सफ़ाई और मच्छर निवारक छिड़काव, सभी के लिए मलेरिया रोग की बिना विलम्ब जांच और सही इलाज आदि, ऐसे जरूरी प्रभावकारी कदम हैं जो इस मलेरिया टीके के साथ सभी जगह लागू होने चाहिए।

पर असलियत बहुत गम्भीर है क्योंकि मलेरिया अनेक लोगों को रोग ग्रस्त कर रहा है और कमजोर स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के चलते अनेक लोगों के लिए प्राणघातक रोग बना हुआ है। मलेरिया रोकथाम के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं जरूरतमंद लोगों तक समय से नहीं पहुंच रही हैं इसीलिए वैश्विक स्तर पर, मलेरिया से एक साल में 22.90 करोड़ लोग रोग ग्रस्त हुए और 4.09 लाख मृत। मलेरिया से मृत होने वालों में से दो-तिहाई बच्चे थे। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ही मलेरिया से सम्बंधित प्राण-घातक रोग होने का खतरा सर्वाधिक होता है।

जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं यदि हर जरूरतमंद इंसान तक नहीं पहुंचेंगी तो विश्व में सभी सरकारों का वादा कि 2030 तक मलेरिया उन्मूलन हो जाएगा, कैसे पूरा होगा ?

उत्तर प्रदेश में इस साल बारिश में फिर से, जल भराव के साथ-साथ डेंगू, मलेरिया और बुखार का प्रकोप जनता ने झेला जबकि इन रोगों से बचाव और रोकथाम, समय से जांच-इलाज सब मुमकिन है। यदि यह पहली मलेरिया वैक्सीन सभी आवश्यक मलेरिया नियंत्रण

सेवाओं के साथ, जरूरतमंद लोगों - विशेषकर बच्चों तक, नहीं पहुंचीं (चाहे वह बच्ची अमीर हो या गरीब, अमीर देश में हो या गरीब देश में) तो कैसे होगा 2030 तक मलेरिया उन्मूलन? सिर्फ 110 महीने रह गए हैं और मलेरिया आज भी भारत में एक जन स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है जबकि पड़ोसी देश जैसे कि, श्री लंका, मॉल्डोव, आदि ने, मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य हासिल कर लिया है।

दुनिया की सबसे पहली मलेरिया वैक्सीन के बारे में जाने

संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च स्वास्थ्य एजेन्सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, इस मलेरिया वैक्सीन (आटीएस,एस) को अक्टूबर 2021 में मोहर लगा के सभी देशों को वैश्विक मलेरिया उन्मूलन के लिए एक और प्रभावकारी माध्यम दिया है।

यह मलेरिया वैक्सीन दुनिया के उन देशों या क्षेत्रों में अधिक कारगर रहेगी जहां यह रोग, मलेरिया कीटाणु 'प्लैज़मोडीयम फ़ेलकीपेरम' के कारण होता है। इस कीटाणु के कारण सबसे जानलेवा मलेरिया होने का खतरा रहता है, और यही कीटाणु अधिकांश अफ्रीकी मलेरिया के लिए भी जिम्मेदार है। भारत में अधिकांश मलेरिया इस कीटाणु से तो नहीं होती परंतु अनेक प्रदेशों में यह जानलेवा मलेरिया वाले कीटाणु का प्रकोप है।

इस मलेरिया वैक्सीन का शोध शुरू हुए 30 साल से भी अधिक समय हो चुका है। इसके शोध के दौरान, जिन बच्चों को वैक्सीन लगी थी उनमें से बहुत ही कम बच्चों पर अत्यंत गम्भीर दुष्प्रभाव पड़ने की आशंका थी - पर यह स्थापित नहीं था कि यह दुष्प्रभाव वैक्सीन के कारण हुए या किसी अन्य कारण से। यह भी एक कारण था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2015 में वैक्सीन शोधकर्ताओं से एक पाइलट शोध करने को कहा जो 2019 में 3 अफ्रीकी देशों में शुरू हुआ - अप्रैल 2019 में यह मलावी में शुरू हुआ, मई 2019 में घाना में और सितम्बर 2019 में कीन्या में शुरू हुआ। इस शोध में 8 लाख से

अधिक बच्चों को यह वैक्सीन लगी - पहली 3 खुराक 5-9 महीने की उम्र में लगी और 4वीं खुराक 2 साल की उम्र में लगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, चौथी खुराक लगे या नहीं इसका प्रमाण अभी पुख्ता नहीं है इसीलिए शोध जारी है कि 4वीं खुराक का लाभ है या नहीं। 2019 से हुए पाइलट शोध में जिसमें 8 लाख से अधिक बच्चों का टीकाकरण हुआ, यह सिद्ध हुआ कि इस टीके के कोई गम्भीर दुष्प्रभाव नहीं हैं। बल्कि इस टीके से मलेरिया से बच्चों का बचाव हुआ है।

30+ साल से हो रहे मलेरिया टीके शोध के मुख्य नतीजे

जिन बच्चों को टीका नहीं लगा उनकी तुलना में टीकाकरण करवाए हुए बच्चों में मलेरिया से बचाव होता है

- हर 10 मलेरिया ग्रस्त होने वाले बच्चों में से 4 को टीके के कारण मलेरिया नहीं हुआ
- हर 10 मलेरिया से मृत होने वाले बच्चों में से 3 की जान टीके के कारण बची
- हर 10 गम्भीर मलेरिया 'अनीमिया' झेलने वाले बच्चों में से 6 का बचाव टीके ने किया। यह इस लिए भी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि मलेरिया से मृत होने वाले बच्चों में से अधिकांश मलेरिया 'अनीमिया' के कारण मृत होते हैं

इसके अलावा भी इस मलेरिया वैक्सीन के अनेक लाभ मिले। मलेरिया अनीमिया के कारण ही अधिकांश बच्चे अस्पताल में भर्ती होते हैं और रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ती है। चूंकि वैक्सीन के कारण मलेरिया अनीमिया का दर घटी इसीलिए मलेरिया के कारण अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में गिरावट आयी और रक्त चढ़ाने की जरूरत भी कम हुई।

पर यह बात समझना जरूरी है कि यह टीका अकेले पर्याप्त नहीं है बल्कि बाकी सभी



वायु प्रदूषण और हार्ट अटैक

हिमोजी, अलबेली, ललमुजिया, चित्रगीत जैसे अभिव्यक्ति के अलग-अलग और मन के साथ जुड़ जाने वाले माध्यमों किरदारों को गढ़ने वाली मिरांडा हाउस हिंदी विभाग के अपराजिता शर्मा इस शरीर को छोड़कर अनंत यात्रा पर चली गईं। उनको विनम्र श्रद्धांजलि। इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक से हुई इनकी मृत्यु ने कुछ दिन पहले हुई टीवी कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला के असमय मृत्यु की याद दिला दिया। सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु को लेकर कूपर हॉस्पिटल का बयान यह आया कि इनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई।

बहुत सारे लोग फेसबुक पर अभी लिख रहे हैं की हार्ट के सही ढंग से फंक्शन नहीं करने का कारण शरीर में विटामिन डी एवं कैल्शियम की कमी हो सकती है।

बात केवल अपराजिता शर्मा या सिद्धार्थ शुक्ला की नहीं है। हम यह देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से विशेषकर सन 2000 के बाद से 40 साल या उससे कम उम्र के लोगों में भी हार्ट अटैक की घटनाएं या कार्डियोवैस्कुलर बीमारी बढ़ने की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं।

इसके क्या कारण हैं? इनकी भी एक चर्चा होनी आवश्यक है। पहले यह कहा जाता था हार्ट अटैक आने का कारण धूम्रपान है, लेकिन अभी हम बहुत से ऐसे लोगों को देख रहे

हैं जो लोग धूम्रपान भी नहीं करते, शारीरिक रूप से तंदुरुस्त दिखाई देते हैं जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करते रहते हैं, अचानक से ऐसे लोगों में हार्ट अटैक की घटनाएं देखी जा रही हैं और उनमें से अधिकांश लोगों को बचाया नहीं जा सका। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि ऐसी घटनाओं में लोग कैल्शियम व विटामिन डी की कमी की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि यह एक कारण हो। लेकिन एक विशेष कारण पर कहीं चर्चा नहीं हो रही है, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, भारत के महानगरों में हार्ट डिजीज के संख्या बढ़ने का। और वह कारण है कणीय वायु प्रदूषण, मुख्य रूप से सूक्ष्म कणीय वायु प्रदूषण।

सामान्य तौर पर कणीय वायु प्रदूषण को हम दो प्रकार में विभाजित करते हैं - पीएम 2.5 वाले और सबसे छोटे कण और पीएम 10 वाले एवं उससे से छोटे कण।

यहां पीएम 2.5 का अर्थ है ऐसे पार्टिकुलेट मैटर जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर है।

इसमें स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सबसे हानिकारक हैं पीएम 2.5 से छोटे और विशेषकर पीएम 1 से भी छोटे कण।

जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में प्रकृति ने बहुत से रक्षा व्यवस्थाओं का निर्माण किया है जो हमें विभिन्न प्रकार के

प्रदूषण को से बचाती हैं जैसे नाक के अंदर मौजूद बाल जो बड़े कणों को रोकने में सक्षम होते हैं इसके अतिरिक्त नाक के अंदर मौजूद म्यूकस भी कुछ खास तरह के कणों और प्रदूषकों को रोक सकते हैं, लेकिन यह दोनों बड़े साइज के कणीय प्रदूषकों को रोकने में सक्षम होते हैं।

पीएम 2.5 से छोटे का आसानी से हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं और वहां से हमारे ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाते हैं और एक बार ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के बाद शरीर से उनके बाहर निकलने की संभावना नगण्य हो जाती है।

धीरे धीरे जब हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र में इस तरह के सूक्ष्म कण इकट्ठा होने लगते हैं तो कुछ समय के बाद वह हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र के माध्यम से हमारे हृदय को प्रभावित करने लगते हैं और उसकी परिणति हार्ट अटैक के रूप में होती है। आज के समय में वायु प्रदूषण विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए जिम्मेदार है और उसमें भी हार्ट एवं लॉन्ग से संबंधित बीमारियों की संख्या बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम भविष्य में इस तरह की दुखद घटनाओं को रोकना चाहते हैं तो उसके लिए वायु प्रदूषण को लेकर और सीरियस होने की आवश्यकता है।

- धीपड़ा द्विवेदी

प्रभावकारी मलेरिया नियंत्रण और रोकधाम के जो तरीके हैं उनके साथ समोचित ढंग से बिना-विलम्ब लागू होना चाहिए।

अफ्रीका में हुए पाइलट शोध के अनुसार, जिन 8 लाख बच्चों तक वैक्सीन पहुंची उनमें से दो-तिहाई बच्चे, कीटनाशक युक्त मच्छरदानी के भीतर नहीं सो रहे थे। यह महत्व की बात है कि मलेरिया टीका उन बच्चों तक पहुंचा जिन तक कीटनाशक युक्त मच्छरदानी नहीं पहुंच पा रही थी। यह सवाल भी उठता है कि जरूरतमंद बच्चों तक मलेरिया नियंत्रण के पुराने प्रभावकारी तरीके क्यों नहीं पहुंच पा रहे थे?

इन अफ्रीकी देशों में हुए शोध में यह भी देखा गया कि मलेरिया टीका लगने से कहीं अन्य मलेरिया नियंत्रण और रोकधाम के तरीकों के उपयोग में कमी तो नहीं आती और यह सिद्ध हुआ कि टीके के बाद भी, जो लोग मच्छरदानी का उपयोग कर रहे थे वह करते रहे और अन्य

मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम भी सुचारु रूप से चलते रहे।

दुनिया के लिए जीएसके के साथ मिलकर भारत की बाइओटेक कम्पनी बनाएगी यह टीका

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया टीके को जारी करते हुए कहा कि दुनिया के सभी बाइओ-टेक उद्योग से अनुरोध किया गया था कि वह जीएसके (जिस कम्पनी का यह टीका है) के साथ मिल कर इसको निर्मित और वितरण के लिए अर्जी दें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक और अन्य विशेषज्ञों ने कहा कि विश्व में सिर्फ भारत की बाइओ-टेक कम्पनी ही चयनित हुई है जो जीएसके के साथ इस टीके को बनाएगी और दुनिया में वितरित करेगी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह भी कहा कि प्रारम्भिक प्रयास हो रहे हैं कि इस नए मलेरिया

वैक्सीन को खरीदने के लिए धनराशि एकत्रित हो पर यह सवाल महत्वपूर्ण है कि जब वैज्ञानिक उपलब्धि प्राप्त होती है तो जरूरतमंद तक पहुंचने में अनावश्यक विलम्ब होता है। हर पांच में से चार कोविड वैक्सीन टीके अमीर देशों में लगे हैं - इस गैर बराबरी को नजरंदाज नहीं कर सकते।

मलेरिया वैक्सीन को जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाने के लिए, बिना विलम्ब, आवश्यक सभी कदम उठाने चाहिए। पैसे के अभाव हो या हर देश की अपनी अंदरूनी प्रक्रिया जिसके तहत नयी वैक्सीन को संस्तुति आदि मिलती है - यह कहीं अनावश्यक विलम्ब न करे। यदि मलेरिया उन्मूलन का सपना साकार करना है तो हर प्रभावकारी मलेरिया नियंत्रण, रोकधाम, जांच-इलाज सेवाएं आदि सभी जरूरतमंद तक बिना विलम्ब दुनिया भर में पहुंचे वरना न सिर्फ मलेरिया उन्मूलन में हम असफल होंगे बल्कि अन्य सतत विकास लक्ष्यों पर भी पिछड़ेंगे। ■



आर.के.
सिन्हा

भारत की आईटी कंपनियों की कामयाबी के पीछे का सच

माफ करें, पर यह सच है कि अब भारत में सकारात्मक खबरों को लेकर कोई बहुत चर्चा ही नहीं होती। वैसी खबरें कभी कभी सामने आती हैं और फिर गायब हो जाती है। अब नेगटिव समाचारों पर अतिरिक्त रूप से फोकस देने का सिलसिला चालू हो गया है और सच कहें तो बढ़ता ही चला जा रहा है। इसका एक उदाहरण लें। देश की चार सबसे प्रमुख आई टी कंपनियां – टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), इंफोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में एक लाख से अधिक पेशेवर युवक-युवतियों की भर्तियां कीं। यह पिछले वित्त साल के पहले छह महीनों से 13 गुना अधिक है। ये भर्तियां ठोस संकेत हैं कि भारत का आईटी सेक्टर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। टीसीएस में फिलहाल सवा पांच लाख पेशेवर हैं। बाकी जिन आईटी कंपनियों का हमने जिक्र किया है, उनमें भी कुल मिलाकर तो लाखों पेशेवर काम कर रहे हैं। गौर करें कि इन कंपनियों में भर्तियां ही नहीं हो रही हैं। इनमें काम करने वाले पेशेवर बेहतर विकल्प मिलने पर अन्य कंपनियों का दामन थाम भी रहे हैं। इंफोसिस को पिछली तिमाही में उसके 20 फीसद स्टाफ ने छोड़ दिया। अगर कोई इंफोसिस जैसी प्रतिष्ठित कंपनी को छोड़ रहा है तो समझ लें कि उन्हें उससे बहुत बेहतर अवसर मिल रहे हैं। वरना कोई इंफोसिस सरीखी श्रेष्ठ कंपनी को छोड़ने से पहले दस बार तो सोचेगा ही। यह तो सिर्फ एक उदाहरण था यह बताने के लिए किस तरह से देश के आईटी सेक्टर की कंपनियां तरक्की के सारे कीर्तिमान तोड़ती ही चली जा रही है। जो कंपनी अपने स्टाफ में नए युवक-युवतियों को रख रही है। इसका मतलब यह है कि उनका मुनाफा भी तेजी से बढ़ रहा है। टीसीएस को चालू साल की दूसरी तिमाही में 9,624 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। इसी साल की पहली तिमाही में कंपनी को 9008 करोड़ रुपये का फायदा हुआ था। इंफोसिस को चालू साल की पहली तिमाही में लगभग साढ़े पांच हजार करोड़ रुपए का लाभ हुआ। विप्रो और एचसीएल के भी शानदार नतीजे आए। लेकिन इतनी शानदार खबर को लेकर देश में कोई खास बात

नहीं हुई। आजकल बात तो सिर्फ यह होती है कि कहां और कैसी हिंसा हुई या देश को क्षति पहुंची।

बहरहाल, कहने वाले तो यही कहते हैं कि टाटा समूह ने हाल ही में एयर इंडिया को 18 हजार करोड़ रुपए में अपनी फ्लैगशिप कंपनी टीसीएस के लगातार हो रहे भारी-भरकम मुनाफे के चलते ही खरीदा। टीसीएस के दो तिमाही के नतीजों के दम पर टाटा समूह एयर इंडिया को आसानी से खरीद सकता था।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), इंफोसिस, विप्रो और एचसीएल की अभूतपूर्व उपलब्धि के आलोक में क्या आपने कभी सोचा कि कौन सी कंपनियां मुनाफा कमाने में अब्बल रहती हैं? किनकी साख बाजार में सबसे अधिक होती है? इन सवालियों के जवाब खोजने मुश्किल नहीं है। ये सब इसलिए आगे बढ़ रही है क्योंकि इन्हें नेतृत्व बेहतरीन मिला हुआ है। अब टीसीएस को ही लें। इसके मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश गोपीनाथ

के टीसीएस में शिखर पद को संभालने से पहले ही टीसीएस विश्व स्तरीय कंपनी बन चुकी थी। इसका श्रेय टाटा समूह के मौजूदा चेयरमैन एन.चंद्रशेखर को ही देना होगा। वे टीसीएस के 2009 में सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए थे। उन्होंने टीसीएस से ही अपने पेशेवर करियर का आगाज किया था। उन्हें टीसीएस स्वस्थ हालत में मिली थी। चंद्रशेखर ने



टीसीएस में रहते हुए टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा और टीसीएस के फाउंडर चेयरमैन फकीरचंद कोहली से लीडरशिप के गुणों को सीखा था। अगर आज भारत को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया सबसे खास शक्तियों में से एक मानती है और भारत का आईटी सेक्टर 190 अरब डॉलर तक पहुंच गया है तो इसका क्रेडिट फकीरचंद कोहली जी को ही देना होगा। उन्होंने ही वस्तुतः देश के आईटी सेक्टर की नींव रखी थी। कोहली और रतन टाटा के साथ काम करके चंद्रशेखर ने प्रौद्योगिकी जगत में नवोन्मेष और उत्कृष्टता की संस्कृति को संस्थागत

स्वरूप देना सीखा।

तमिलनाडू के तंजावुर के रहने वाले शिव नाडार की अगर बात करें तो उन्होंने एचसीएल टेक्नोलॉजीज को अपने लंबे नेतृत्व के दौरान इसे महान सॉफ्टवेयर कंपनी के रूप में खड़ा किया। कहते हैं कि वे अपने सीईओज और मैनेजरों को हमेशा कुछ हटकर करने के लिए प्रेरित करते रहते थे। नाडार अपने अफसरों के सदैव साथ खड़े रहते हैं। वे उनका असफलता में भी कभी उनका साथ नहीं छोड़ते थे। इसलिए उनके मैनेजर भी बेहतरीन नतीजे लाकर देते। शिव नाडार ने एचसीएल टेक्नोलॉजीज की स्थापना की थी। अब करीब आधा दर्जन देशों में, 100 से ज्यादा कार्यालय, करीब एक लाख पेशेवर इंजीनियर उनके साथ जुड़े हैं। और नोएडा में तो शिव नाडार के दफ्तरों की भरमार है। नाडार में जेआरडी टाटा का अक्स देखा जा सकता है। दोनों की शिक्षा और राष्ट्र निर्माण के प्रति सोच लगभग एक सी है।

अगर बात इंफोसिस लिमिटेड की करें तो इसका भले ही मौजूदा सीईओ सलिल पारेख हैं, पर इसकी बुनियाद चट्टान जैसी मजबूत है। इसकी नींव डाली थी एन.नारायणमूर्ति जैसे युगांतकारी उद्यमी ने। उन्हें इस बाबत सहयोग मिला नंदन नीलकेणी जैसे साथियों का। नंदन नीलकेणी आजकल भी इंफोसिस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। नारायणमूर्ति अपने जीवन के हर पल को सार्थक बनाने में जुटे ही रहते हैं। बेशक मानव जीवन क्षण भंगुर हो, फिर भी उसे इंसान को अपने सतकर्मों से ही सार्थक बनाने का अवसर ईश्वर प्रदान करते हैं। अंधकार का साम्राज्य चाहे कितना भी बड़ा हो पर एक कोने में पड़ा हुआ छोटा सा दीपक अपने जीवन के अंत समय तक अंधेरे से मुकाबला तो करता ही रहता है। अब देखिए कि फूलों का जीवन कितना छोटा सा होता है पर वो अपने सुगंध देने के धर्म का निर्वाह तो करते ही रहते हैं। नारायणमूर्ति ने अपने जीवन को फूलों और दीपक जैसा जाने-अनजाने में बना ही लिया है। वे सदैव पहले से भी बेहतर कर्म करते ही रहना चाहते हैं। उनका जीवन भी बेदाग रहा है। वे अपनी कंपनी को नई दिशा देते हुए कल्याणकारी योजनाओं के लिए मोटी राशि समाज कल्याण के कार्यों के लिये दान में देते रहे हैं। इसीलिए तो वे और उनकी इंफोसिस लगातार सफलता ही अर्जित कर रही है।

इन सबकी ही तरह ही विप्रो लिमिटेड के चेयरमेन अजीम प्रेमजी भी हैं। उनमें एक कमाल का गुण है। वे चुन-चुनकर एक से बढ़कर एक मैनेजरों को अपने साथ जोड़ लेते थे। अजीम प्रेमजी सिर्फ मेरिट पर विप्रो में पेशेवरों को अहम पद देते हैं। उनके कुशल निर्देशन के फलस्वरूप विप्रो को देश की चोटी की आईटी कंपनी का दर्जा प्राप्त है।

तो लब्बोलुआब यह है कि भारत की आई टी कंपनियों के आगे बढ़ने से जहां नौजवानों को रोजगार के भारी अवसर मिल रहे हैं, वहीं देश को भारी आयकर और विदेशी मुद्रा भी मिल रहा है। लेकिन वे ही कंपनियां आज के दिन अभूतपूर्व सफलता हासिल कर रही हैं, जिन्हें सशक्त नेतृत्व मिला हुआ है।

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं)

कोयला और बढ़ता उर्जा संकट



● अवधेश प्रताप सिंह

कोल इंडिया ने पिछले 4 दिनों में 1.57 मिलियन टन से 1.94 मिलियन टन प्रति दिन उत्पादन बढ़ाया है और इसे और बढ़ाया जाएगा। अगले सप्ताह तक इसके 2 मिलियन टन प्रति दिन तक पहुंचने की उम्मीद है।

कुछ बिजली संयंत्रों में स्टॉक की कमी, जो imported coals कोयले पर निर्भर थे उन्होंने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमतों के तीन गुना होने के कारण आयात को कम कर दिया था और केंद्र से अधिक आपूर्ति पर जोर देना शुरू कर दिया था। इससे कोयले के आयात में 12 फीसदी की गिरावट आई है।

कोल इंडिया के पास एक सीमा से अधिक कोयले का भंडार नहीं हो सकता था क्योंकि हमेशा आग लगने का खतरा रहता है। इसलिए राज्यों को कोल इंडिया से अपना कोटा उठाकर स्थानीय स्तर पर स्टॉक करना चाहिए था। रिमाइंडर के बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ। जब मांग और खपत बढ़ रही थी तो राज्य प्रतिक्रिया देने में विफल रहे।

राज्यों को कोल इंडिया को लगभग 21000 करोड़ के बकाया का भुगतान करना है। महाराष्ट्र को 2600 करोड़, तमिलनाडु को 1100 करोड़, बंगाल को 2000 करोड़, दिल्ली को 278 करोड़, पंजाब को 1200 करोड़ एमपी को 1000 करोड़ राजस्थान को 600 करोड़ और कर्नाटक को 23 करोड़ रुपये कोल इंडिया को देने हैं।

बिजली बिल हर महीने कड़ाई से वसूल करते हैं, कोयले का पैसा देते नहीं हैं, तो ये पैसा जाता कहा है ?

कोई बड़ा घोटाला तो नहीं है ?

कोयला क्राइसिस की हाइप बना कर जनता को जानबूझ कर भड़काया जा रहा है जबकि मुझे इसमें आर्टिफिशियल क्राइसिस क्रिएट करने की साजिश नजर आ रही है ताकि चुनावी माहौल में राजनीतिक फायदा ले सके।

वाशिंगटन, प्रेट्र। कोविड से हुए नुकसान के बाद भारत के हालात तेजी से सुधर रहे हैं। आने वाले दिनों में भारत के लिए खुशखबरी है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने का अनुमान जताया है। आईएमएफ द्वारा मंगलवार को जारी ताजा अनुमानों के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्ष 2021 में 9.5 प्रतिशत और 2022 में 8.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जबकि 2022 में अमेरिका में यह दर 5.2 फीसद और चीन की 5.6 फीसद



विनीत
नारायण

टाटा के हुए 'महाराजा'

● विनीत नारायण

डूबते हुए एयर इंडिया के 'महाराजा' का हाथ टाटा समूह ने 68 सालों बाद फिर से थाम लिया है। एवीएशन विशेषज्ञों की मानें तो टाटा के मालिक बनते ही 'महाराजा' को बचाने और दोबारा ऊंची उड़ान भरने के काबिल बनाने के लिए कई ऐसे फैसले लेने होंगे जिससे एयर इंडिया एक बार फिर से भारत की एवीएशन का महाराजा बन जाए। टाटा ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कई डूबती हुई कम्पनियों को खरीदा है। इनमें से कई कम्पनियों को फायदे का सौदा भी बना दिया है। अब देखना यह है कि अफसरशाही में कैद एयर इंडिया को उसकी खोई हुई गरिमा कैसे वापिस मिलती है।

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो अब तक एअर इंडिया के विमानों पर किराए या लीज के तौर पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा था। इसके साथ ही इन पुराने हवाई जहाजों का कई वर्षों से सही रख रखाव भी नहीं हुआ है। यात्रियों के हित में टाटा को केबिन अपग्रेडेशन, इंजन अपग्रेडेशन समेत कई महत्वपूर्ण बदलाव लाने होंगे। विशेषज्ञों के अनुसार टाटा समूह को एअर इंडिया मौजूदा विमानों को अपग्रेड करने के लिए कम से कम 2 से 5 मिलियन डॉलर की मोटी रकम खर्च करनी पड़ सकती है। गौरतलब है कि जब नरेश गोयल की जेट एयरवेज को खरीदने के लिए टाटा के बोर्ड में चर्चा हुई तो कहा गया था कि डूबती हुई एयरलाइन को खरीदने से अच्छा होता है कि ऐसी एयरलाइन के बंद होने पर रिक्त स्थानों पर नए विमानों से भरा जाए।

जिस तरह अफसरशाही ने सरकारी एयरलाइन में अनुभवहीन लोगों को अहम पदों पर तैनात किया था उससे भी एयर इंडिया को नुकसान हुआ। किसी भी एयरलाइन को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रोफेशनल टीम की जरूरत होती है। भाई-भतीजेवाद या सिफारिशी भर्तियों की एयरलाइन जैसे संवेदनशील सेक्टर में कोई जगह नहीं होती। टाटा जैसे समूह से आप केवल प्रोफेशनल कार्य की ही कल्पना कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर टाटा समूह द्वारा भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट जारी करने में जो योगदान दिखाई दे रहा है वो एक अतुलनीय

योगदान है। जिन दिनों पासपोर्ट सेवा लाल फीताशाही में कैद थी तब लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ता था। वही काम अब कुछ ही दिनों में हो जाता है। आजकल के सोशल मीडिया और आईटी युग में हर ग्राहक जागरूक हो चुका है। यदि वो निराश होता है तो कम्पनी की साख को कुछ ही मिनटों में अर्श से फर्श पर पहुंचा सकता है। इसलिए ग्राहक संतुष्टि की प्रतिस्पर्धा के दबाव के चलते हर कम्पनी को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना पड़ता है।

विश्वभर में पिछले दो सालों में कोरोना की सबसे ज्यादा मार पर्यटन क्षेत्र को पड़ी है। एवीएशन सेक्टर इसका एक अहम हिस्सा है। एक अनुमान के तहत इन दो सालों में इस महामारी के चलते एवीएशन सेक्टर को 200 बिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है। माना जा रहा है कि अगर

सब कुछ सही रहता है और कोविड की तीसरी लहर नहीं आती है तो 2023 से एवीएशन सेक्टर की गाड़ी फिर से पटरी पर आ जाएगी।

एयर इंडिया का निजीकरण कर टाटा को दिए जाने के फैसले को ज्यादातर लोगों द्वारा एक अच्छा



कदम ही माना गया है। टाटा को इसे एक सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन बनाने के लिए कुछ बुनियादी बदलाव लाने होंगे। जैसा कि सभी जानते हैं टाटा समूह के पास पहले से ही दो एयरलाइन हैं 'विस्तारा' और 'एयर एशिया' और अब एयर इंडिया और 'एयर इंडिया एक्सप्रेस'। टाटा को इन चारों एयरलाइन के पाइलट और स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए अपनी ही एक अकैडमी बना देनी चाहिए। जिसमें ट्रेनिंग अंतरराष्ट्रीय मानक के आधार पर हो। इससे पैसा भी बचेगा और ट्रेनिंग के मानक भी उच्च कोटि के होंगे।

चार-चार एयरलाइन के स्वामी बनने के बाद टाटा समूह की सीधी टक्कर मध्यपूर्व की 'कतर एयरलाइन' से होना तय है। मध्यपूर्व जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर होने के चलते, इस समय कतर एयर के पास एवीएशन सेक्टर के व्यापार का सबसे अधिक हिस्सा है। कोविड काल में सिंगापुर एयर के 60 प्रतिशत विमान ग्राउंड हो चुके हैं। सिंगापुर एयरलाइन में टाटा समूह की साझेदारी होने के कारण, टाटा को सिंगापुर

एयर के विमानों को अपने साथ जोड़ कर एयर इंडिया को दुनिया के हर कोने में पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। इससे कर्ज में डूबी एयर इंडिया के आय के नए स्रोत भी खुलेंगे।

टाटा को अपनी चारों विमानन कम्पनियों को अलग ही रखना चाहिए। जिस तरह टाटा समूह के अलग-अलग प्रकार के होटल हैं जैसे 'ताज' 'विवांता' व 'जिंजर' आदि उसी तरह बजट एयरलाइन और मुख्यधारा की हवाई सेवा को भी अलग-अलग रखना बेहतर होगा। अलग कम्पनी होने से टाटा समूह की ही दोनों कम्पनियों को बेहतर परफॉर्म करना होगा और आपस की प्रतिस्पर्धा से ग्राहक का फायदा होना निश्चित है। इनमें दो कम्पनी 'एयर एशिया' और 'एयर इंडिया एक्सप्रेस' सस्ती यानी 'बजट एयरलाइन' रहें जो मौजूदा बजट एयरलाइन व आने वाले समय में राकेश झुनझुनवाला की 'आकासा' को सीधी टक्कर देंगी। मौजूदा 'विस्तारा' को भी मध्यवर्गीय एयरलाइन के साथ प्रतिस्पर्धा में रहते हुए पड़ोसी देशों में अपने पंख फैलाने होंगे। एयर इंडिया में नए विमान जोड़ कर इसे एवीएशन की दुनिया का महाराजा बनने की ओर कदम तेजी से दौड़ाने होंगे।

बीते कई वर्षों से नुकसान उठा रही एयर इंडिया की देरी और खराब सेवा को लेकर नकारात्मक छवि बनी है। इस चुनौती को भी टाटा को गम्भीरता से लेना होगा और सेवाओं की बेहतरी की दिशा में कुछ सक्रिय कदम उठाने होंगे। यह इतना आसान नहीं होगा, परंतु टाटा समूह में विषम परिस्थितियों में टिके रहने और लम्बी अवधि तक खेलने की क्षमता किसी से छुपी नहीं है। टाटा को इस चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए एवीएशन सेक्टर के अनुभवी लोगों की टीम बनानी होगी और यह सिद्ध करना होगा कि एयर इंडिया को वापस लेकर टाटा ने कोई गलती नहीं की। ■

तक ही हो सकती है। खास बात यह है कि भारत और स्पेन को छोड़कर किसी भी अन्य देश किसी भी अन्य देश में यह वृद्धि दर 6 फीसदी से ऊपर नहीं जाने का अनुमान जताया गया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि भारत अपने लोगों का कोविड टीकाकरण करने के मामले में अच्छा कर रहा है। यह निश्चित रूप से उसकी अर्थव्यवस्था के लिए मददगार साबित होगा।

ज्ञात हो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 7.3 प्रतिशत की गिरावट आई थी। आईएमएफ के ताजा विश्व आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूईओ) में भारत के वृद्धि अनुमानों को इस साल जुलाई में जारी पिछले अनुमान पर स्थिर रखा गया है, हालांकि यह अप्रैल के अनुमानों के मुकाबले 1.6 प्रतिशत कम है।

ईएमएफ और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक से पहले जारी ताजा डब्ल्यूईओ के अनुसार 2021 में पूरी दुनिया की वृद्धि दर 5.9 प्रतिशत और

2022 में 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं अमेरिका की अर्थव्यवस्था के इस साल छह फीसदी और अगले साल 5.2 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान है। इन पूर्वानुमानों के अनुसार, चीन की अर्थव्यवस्था 2021 में आठ प्रतिशत और 2022 में 5.6 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है।

आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा कि उनके जुलाई के पूर्वानुमान की तुलना में 2021 के लिए वैश्विक वृद्धि अनुमान को मामूली रूप से संशोधित कर 5.9 प्रतिशत कर दिया गया है। 2022 के लिए यह 4.9 प्रतिशत पर यथावत है। हमारे पास भारत के लिए इस वर्ष के लिए विकास पूर्वानुमान में कोई बदलाव नहीं है। मेरा मतलब है कि भारत एक बहुत ही कठिन दूसरी लहर से बाहर आया और जुलाई के महीने में बड़ी गिरावट आई, लेकिन अपने विकास दर अनुमानों में कोई बदलाव नहीं है। ■

उर्जा संकट और इंटरनेशनल सोलर अलायन्स

● अवधेश प्रताप सिंह

आजकल हिंदुस्तान की इंडस्ट्री, रॉ मटीरियल के दामों को लेकर बहुत परेशान है। हर एक दो दिनों के अंतर से दामों में भारी उछाल आ रहा है। पिछले दो महीनों में कच्चे मालों में लगभग 100% से भी ज्यादा का उछाल आ चुका है।

लोग बाग इसका कारण समझने में असमर्थ हैं। कोई मोदी को गाली देता है, कोई केजरीवाल को और कोई कांग्रेस को। पर इसका मूल कारण भारत में न होकर चीन से शुरू हुआ है।

मतलब

मतलब यह कि चीन में लगभग दुनिया भर की खस का 45% से भी ज्यादा माल बनता है। अगर चीन में माल बनना कम या बन्द हो जाये तो पूरी दुनिया में हाहाकार मचना तय है।

अतः मूल्यवृद्धि के सिलसिलेवार निम्न कारण जिम्मेवार हैं-

1. 2018-19 में चीन ने एक मास्टर प्लान

बनाया। इसके तहत वो पूरी दुनिया में एक वाय*रस फैला कर लोगों को बुरी तरह से प्रताड़ित करना चाहता था। यानी उस वाय*रस के द्वारा चीन दुनिया की बाकी की 55% प्रोडक्शन को भी बन्द करवाने के बाद अपना माल मनचाहे दामों पर बेच कर पूरी दुनिया को अपना आर्थिक गुलाम बनाना चाहता था। उसका यह प्लान कामयाब हो भी जाता पर दुर्भाग्यवश उस वायरस पर काम कर रहे चीनी वैज्ञानिकों के हाथों उस वायरस की शीशे की नली हाथ से छूट कर टूट गयी और उस वायरस का पहला अटैक उस वायरस को बनाने वाले वैज्ञानिक पर ही हो गया और उसने चीन के वुहान में भारी तबाही मचानी शुरू कर दी। चीन की जो मन्शा पूरे विश्व की प्रोडक्शन लाइन को तबाह करने की थी उससे पहले ही चीन की अपनी प्रोडक्शन लाइन प्रभावित हो गयी। जिसके चलते विश्व में मालों की कमी होने लगी और दामों का बढ़ना शुरू हुआ।



2. 2019-20 में चीन से निकले उस वायरस ने पूरे विश्व में तबाही मचानी शुरू की और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था और प्रोडक्शन, लोकडॉन के चलते ठप्प हो गयी। क्योंकि यह दौर लोकडॉन का था इसलिए खपत में भी भारी कमी आई थी अतः वस्तुओं के दाम बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुए। लेकिन प्रोडक्शन में भारी कमी आने के चलते वस्तुओं की कमी आने लगी।

3. फिर आया 2020-21. इस वर्ष दो बातें हुईं। एक तो बीमारी का प्रकोप कुछ कम हुआ और दूसरा लोगों ने भी धीरे धीरे इस बीमारी के साथ जीना सीख लिया। पूरे विश्व की ठप्प पड़ी अर्थव्यवस्था ने एकदम रफ्तार पकड़ी पर यहां पूरे विश्व की फैक्ट्री चीन में बहुत बड़ी त्रासदी हो गयी। अत्यधिक वर्षा और चीन के सबसे बड़े डैम के टूटने से चीन में भारी बाढ़ का प्रकोप आया। उसने चीन की इंडस्ट्री में हो रही प्रोडक्शन को भी भारी नुकसान पहुंचाया। उधर चीन ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। ऑस्ट्रेलिया से कोयला आदि खरीदते खरीदते आस्ट्रेलिया के साथ चीन ने व्यापार बन्द कर दिया। अब चीन अपनी कोयले की डिमांड के लिए पूर्णतया अपनी खुद की कोल माइंस पर निर्भर था। पर होनी ने एक बार फिर चीन के साथ दूसरा क्रूर मजाक किया। चीन की कोयले की खदानों में पानी भर गया और वो खदाने बन्द हो गईं जिससे चीन में बिलजी का उत्पादन बड़ी मात्रा में प्रभावित हुआ और एक बार फिर चीनी फैक्ट्रियां बिजली की शॉर्टेज के चलते प्रोडक्शन नहीं कर पाईं। पर विश्व को तो माल चाहिए था। चीन से आने वाले माल के न आने से

पूरे विश्व में हाहाकार मचना शुरू हो गया। जहां से जो माल मिला उसको मुंह मांगे दामों पर खरीदा जाने लगा और दाम रोज रोज बढ़ने लगे।

4. पर मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई। जैसे ही विश्व भर की अर्थव्यवस्था और प्रोडक्शन लाइन पर आने वाली थी कि चीन में पिछले हफ्ते एक बार फिर से भारी वर्षा होने के कारण चीन की कोयले की खदानों में पानी भर गया और जानकार सूत्रों का मानना है कि इसबार फिर चीन को 6 महीने और लग जाएंगे कोयले की खदानों को फिर से पूरी तरह चालू करने में। मतलब साफ है कि अगले 6 महीने अभी और चीन से माल बहुत थोड़ी मात्रा में आएंगे। ये जो माल कम बनेंगे उस माल की आपूर्ति बाकी के सभी देश मिलकर भी पूरी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में जिसे जो माल चाहिए होगा वो ज्यादा दाम दे कर खरीद लेगा।

यानि विश्व में मंदी का दौर तो जारी रहेगा पर दामों में भी बेतहाशा वृद्धि जारी रहेगी। बहुत से अतिवादी हिन्दू अक्सर मुझसे पूछते थे कि भारत इस्त्राइल का साथ न देकर मुस्लिम देश जैसे UAE, सऊदी, कुवैत, ईरान, इराक का साथ क्यों देता है। इससे मुझे बहुत चौड़े होते हैं।

उनको पेट्रोल के कारण ब्रिटेन में फैली अराजकता से मेरे प्रश्न का उत्तर तो मिल ही चुका होगा। पर फिर भी हमारा देश विश्व भर में चीन के बाद पेट्रोल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अब पेट्रोल कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि एक आध साल में हम अपनी फैक्ट्रियों में बनाने लगे। इसके लिए हम जिन देशों पर निर्भर थे उनमें से ज्यादातर पेट्रोल उत्पादक देश मुस्लिम देश ही थे। अब इस्त्राइल की तरह अगर

हमारी जनता भी 1 करोड़ से कम होती तो हम भी इन देशों से दुष्मनी लेकर किसी और तेल उत्पादक देश से दोस्ती कर लेते। दूसरा दो वर्षों पहले तक इन सभी मुस्लिम देशों का एकमात्र आण्विक शक्ति से सम्पन्न और OIC का सरपरस्त देश था पाकिस्तान जो भारत का परम शत्रु था।

ऐसे में कांग्रेस तो क्या मोदी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि इन मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों से दुश्मनी लेकर इस्त्राइल से दोस्ती पाली जाए। क्योंकि ये देश कभी भी भारत का परमानेंट वो हाल कर सकते थे जो आज कुछ समय के लिए ब्रिटेन का हो गया है। इसीलिये हमारा देश पिछलग्गू बनकर इन देशों से माल भी खरीदता था और इन्हें अपना बाप भी मानता था।

फिर आया मोदी राज। आते ही मोदी ने अपना इंड्रजाल फैलाया और 130 से ज्यादा देश मोदी के इस जाल में अपने आप आ गए। इंटरनेशनल सोलर अलायन्स का गठन हुआ। अगला कदम इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर उठाया। तीसरा डीजल की जगह इथेनॉल का प्रयोग चौथा कोयले से इथेनॉल का उत्पादन आदि शुरू किया। अब तक मिडिल ईस्ट को समझ आ गया था कि अगर अपनी तड़ी कायम रखेंगे तो जल्द कहीं के भी न रहेंगे। फिर भी मोदी को ब्लैकमेल करने की पूरी कोशिश की गई। एकदम से क्रेड ऑयल के रेट बढ़ाये। पर मोदी ने भी धीरे धीरे अपना प्रभाव छोड़ना चालू किया। गैर मुस्लिम देशों से भी पेट्रोल खरीदने के लिए अपने सम्बन्ध कायम करने शुरू किये। रूस, अमेरिका, वेनेजुएला, मेक्ससिको आदि से बड़ी मात्रा में आयल खरीदा गया और सऊदी आदि को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया।

आज ये देश भारत की धुन पर नाचने लगे हैं। पाकिस्तान देख कर हैरान है कि तालिबान जैसे मुद्दे पर आपस में धुर विरोधी ईरान, इस्त्राइल और सऊदी अरब भारत को साथ दे रहे हैं। यह देखकर पाकिस्तान अपने बाल नोच रहा है।

तो दोस्तों चिंतित होना छोड़ दो। यह मोदी है। जब शेख अब्दुल्ला को कश्मीरी पंडित बना दिया, राहुल को वैष्णोदेवी और मानसरोवर की सैर करवा कर उनहु धारण कर दिया तो ये दो दो कौड़ी के लोगों से डरने की जरूरत नहीं। बस अपनी एकता कायम रखो और मोदी के पीछे चट्टान की तरह खड़े हो जाओ। ये सब अपने आप राष्ट्रवाद बन जाएंगे। ■

चीन का नया सीमा कानून चिंता का विषय



भा

रत ने कहा कि भूमि सीमा कानून (लैंड बाउंड्री लॉ) लाने के चीन के ताजा एकतरफा फैसले का सीमा प्रबंधन पर मौजूदा द्विपक्षीय व्यवस्थाओं पर असर पड़ सकता है। विदेश मंत्रालय (एमईए) के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हमें यह जानकारी है कि चीन ने 23 अक्टूबर को नया भूमि सीमा कानून पारित किया है। इस कानून में अन्य बातों के अलावा यह कहा गया है कि भूमि सीमा मामलों पर चीन दूसरे देशों के साथ किए या संयुक्त रूप से स्वीकार किए समझौतों का पालन करेगा। इसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में जिलों के पुनर्गठन के प्रावधान भी हैं।

उन्होंने आगे कहा कि भारत और चीन ने सीमा संबंधी प्रश्नों का अभी तक समाधान नहीं निकाला है और दोनों पक्षों ने समानता पर

आधारित विचार विमर्श के आधार पर निष्पक्ष, व्यावहारिक और एक दूसरे को स्वीकार्य समाधान निकालने पर सहमति व्यक्त की है।

उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अमन और शांति बनाए रखने के लिए कई द्विपक्षीय समझौते, प्रोटोकॉल और व्यवस्थाएं कर चुके हैं।

चीन के नए भूमि सीमा नियम को भारतीय विदेश मंत्रालय ने एकतरफा फैसला करार देते हुए कहा कि एक ऐसा कानून लाने का चीन का एकतरफा निर्णय, जो सीमा प्रबंधन के साथ-साथ सीमा से संबंधित मुद्दों पर हमारी मौजूदा द्विपक्षीय व्यवस्थाओं पर प्रभाव डाल सकता है, हमारे लिए चिंता का विषय है।

मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के एकतरफा कदम का उन व्यवस्थाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जिन पर दोनों पक्ष पहले ही सहमत हो

चुके हैं, फिर चाहे वह सीमा से संबंधित मामलों पर हो या भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर शांति बनाए रखने के लिए हो।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि चीन इस कानून के बहाने ऐसे कदम उठाने से बचेगा, जो भारत और चीन के बीच सीमा क्षेत्रों में स्थिति को एकतरफा रूप से बदल सकते हैं और तनाव पैदा कर सकते हैं।

उन्होंने कहा, इसके अलावा, इस नए कानून का पारित होना हमारे विचार में 1963 के तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को कोई वैधता प्रदान नहीं करता है, जिसे भारत सरकार ने हमेशा से ही एक अवैध और अमान्य समझौता करार दिया है।

भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया

बैलेस्टिक व क्रूज रेंज की मिसाइलों के लगातार परीक्षण के बाद बुधवार को देश की सबसे ताकतवर मिसाइल कही जाने वाली अग्नि-5 का सफल परीक्षण किया गया। यह मिसाइल पांच हजार किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य भेदने में सक्षम है। मिसाइल के परीक्षण के साथ ही दुनिया के कई देश इसके लक्ष्य की जद में आ गए हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने पहली बार ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से रात में इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अग्नि-5 का यह आठवां सफल परीक्षण है। इसके साथ ही भारत इस तरह की मिसाइल विकसित करने वाला दुनिया का पांचवां देश बन गया है। अभी सिर्फ अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन के पास ही ऐसी मिसाइलें थीं।



क्या पार्टियों में अब आंतरिक लोकतंत्र बढ़ेगा ?

● डॉ. वेदप्रताप वैदिक



द साल के अंतराल के बाद कांग्रेस कार्यसमिति की वास्तविक बैठक हुई, जिसमें पार्टी के विभिन्न पदों के लिए आंतरिक चुनावों की घोषणा हुई है। ये चुनाव अगले साल अगस्त-सितंबर में होंगे।

इन चुनावों में पार्टी-अध्यक्ष का चुनाव भी शामिल है। अच्छा हुआ कि इस बैठक में नए पार्टी-अध्यक्ष की घोषणा नहीं हुई। यदि हो जाती तो किस में दम था कि वह उसका विरोध करता? लेकिन सबसे अच्छा यह हुआ कि अब पार्टी अध्यक्ष चाहे अगले साल ही नियुक्त होगा लेकिन उसकी नियुक्ति ऊपर से नहीं होगी। वह नीचे से

होगी। चुने हुए पार्टी अधिकारी उसे चुनेंगे।

पार्टी-अध्यक्ष के लिए पहले भी चुनाव की औपचारिकताएं पूरी की जाती रही हैं लेकिन पिछले 15-20 साल में क्या वाकई कोई कांग्रेस अध्यक्ष उस तरह से नियुक्त हुआ है, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन आदि लोकतांत्रिक देशों में शुद्ध चुनाव के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? इस प्रक्रिया की

कैप्टन अमरिंदर सिंह का नई पार्टी बनाने का ऐलान

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ में नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मैं एक पार्टी बना रहा हूं। अब सवाल ये है कि पार्टी का नाम क्या है, ये मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये मैं खुद नहीं जानता। जब चुनाव आयोग पार्टी के नाम और चिन्ह को मंजूर करता है, मैं आपको बता दूंगा।' कैप्टन ने पिछले हफ्ते कहा था कि वह जल्द ही अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे और अगर तीन कृषि कानूनों को लेकर किसानों के हित में कुछ समाधान निकलता है तो वह भारतीय जनता पार्टी के साथ 2022 के चुनाव में सीटों के समझौते के लिए भी तैयार होंगे।

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'हां, मैं एक नई पार्टी बनाऊंगा। चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद चुनाव चिन्ह के साथ नाम की घोषणा की जाएगी। मेरे वकील इस पर काम कर रहे हैं।' उन्होंने कहा कि जहां तक नवजोत सिंह सिद्धू की बात है, वो जहां से भी लड़ेंगे, हम उस सीट से लड़ेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आगे बताया, 'पंजाब में हम सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, फिर चाहे लड़ाई गठबंधन में हो या अपने दम पर।

जो कुछ हासिल किया है उसके कागजात दिखाए

चंडीगढ़ में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, इन 4.5 सालों

के दौरान जब मैं वहां था, हमने जो हासिल किया है उसके सभी कागजात यहां दिए गए हैं। उन्होंने कागज दिखाते हुए कहा, 'यह हमारा घोषणापत्र है जब मैंने पदभार संभाला था। हमने जो हासिल किया है उसका यह हमारा घोषणापत्र है।' उन्होंने कहा कि मैं 9.5 साल तक पंजाब का गृहमंत्री रहा। कोई जो 1



महीने से गृहमंत्री रहा है, ऐसा लगता है कि वह मुझे से ज्यादा जानता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, 'कोई भी परेशान पंजाब नहीं चाहता। हमें समझना चाहिए कि हम पंजाब में बहुत मुश्किल दौर से गुजरे हैं।

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ में कहा कि वे सुरक्षा उपायों को लेकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरी बेसिक ट्रेनिंग एक सैनिक की है। मैं 10 साल तक सेवा में रहा हूं इसलिए मुझे मूल बातें पता हैं। केंद्र के तीन कृषि

कानूनों को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कल हम लगभग 25-30 लोगों को अपने साथ ले जा रहे हैं और हम इस मुद्दे पर गृहमंत्री से मिलेंगे

सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इस कदम को बताया बड़ी गलती

पिछले महीने कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले अमरिंदर सिंह ने कहा था कि वह समान विचारधारा वाले दलों जैसे कि अकाली से अलग हुए समूहों के साथ गठबंधन पर भी विचार कर रहे हैं। दो बार मुख्यमंत्री रहे सिंह ने कहा था कि जब तक वह 'अपने लोगों और अपने राज्य' का भविष्य सुरक्षित नहीं कर लेते, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। वहीं दूसरी ओर पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि अगर अमरिंदर सिंह ने एक नया राजनीतिक दल बनाया तो यह उनकी 'बड़ी गलती' होगी। सुखजिंदर

सिंह रंधावा ने कहा कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो यह उनके दामन पर दाग होगा। कांग्रेस ने उन्हें सम्मान दिया और वह पार्टी में कई पदों पर रहे। अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के साथ सत्ता संघर्ष के बीच पिछले महीने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। सिंह ने हाल में कहा था कि वह जल्द ही अपना राजनीतिक दल बनाएंगे।

कमी कांग्रेस में ही नहीं, देश की लगभग सभी पार्टियों में देखी जाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद उस पद को भरने के लिए कौनसा चुनाव हुआ है? कोई नहीं। राहुल की माता और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दुबारा मोर्चा संभाल लिया याने कांग्रेस-अध्यक्ष घूम-फिरकर फिर उसी परिवार से आ गया।

लेकिन उसका फायदा क्या हुआ ? कांग्रेस 2019 का लोकसभा का चुनाव दुबारा हार गई। इतना ही नहीं, हरयाणा और असम में उसकी सरकारें गिर गईं, प. बंगाल ने उसे कूड़ेदान के हवाले कर दिया, मध्यप्रदेश में चलते-चलते वह लड़खड़ाकर गिर पड़ी। पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस-पार्टी के आंतरिक दंगल की खबरें गरमाती रहती हैं। संसद में वह सबसे बड़ा विरोधी दल है लेकिन उसकी आवाज सुनाई ही नहीं पड़ती है। भाजपा सरकार निरंकुश हाथी की तरह मस्ताना चाल में चली जा रही है।

यदि राहुल गांधी का 2019 में इस्तीफा नहीं होता तो वे 2022 तक कांग्रेस अध्यक्ष बने रहते। पिछले 5 साल से कांग्रेस कार्यकारी याने कामचलाऊ अध्यक्ष से काम चला रही है। कांग्रेस से कोई पूछे कि आपका काम कौन चला रहा है तो उसके पास कोई दो-टूक जवाब नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि वह चाहे तो एक तीन-टूक जवाब दे सकती है याने कांग्रेस-पार्टी का संचालन तीन लोग कर रहे हैं- मां, बेटा और बेटे। याने सोनिया, राहुल और प्रियंका ! इस रहस्य को समझना हो तो आप पंजाब की उठापटक पर गौर कीजिए और पूछिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलौत से और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से। कांग्रेस में इस समय सत्ता के तीन-तीन केंद्र काम कर रहे हैं।

कार्यसमिति की ताजा बैठक में सोनिया गांधी को अपने भक्तों के उक्त 'भ्रम' को मजबूर होकर दूर करना पड़ा। उन्होंने कहा कि वे पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं और वे अपना काम डटकर कर रही हैं। मोदी सरकार के गलत कामों का वे डटकर विरोध कर रही हैं। उन्होंने तीनों किसान-विरोधी 'काले कानूनों' पर जमकर मोर्चा लिया है। उन्होंने लखीमपुर-खीरी हत्याकांड, सरकारी संपत्तियों के विक्रय, जम्मू-कश्मीर में हुई अल्पसंख्यकों की हत्या और विदेश नीति के मामलों में भी सरकारी अकर्मण्यता पर तीखे



सवाल उठाए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि अगले कुछ ही महिनो में होनेवाले विधानसभा चुनावों के लिए भी हमने जमकर तैयारी शुरू कर दी है। उन्हें विश्वास है कि कांग्रेस को काफी सफलता मिलेगी।

लेकिन कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ताओं से अगर आप पूछें कि इन आगामी चुनावों में कांग्रेस की सफलता के बारे में आपका ख्याल क्या है? तो वे चुप रहना ही ज्यादा पसंद करेंगे। कार्यसमिति की इस बैठक से उन्हें बहुत आशा थी लेकिन हुआ क्या? वही ढाक के तीन पात! जिन 23 नेताओं ने पार्टी-सुधार के लिए सोनियाजी को खुला पत्र लिखा था और यह भी कहा था कि वे 'जी-हुजूर' नहीं हैं, उनकी बोलती भी बंद रही। सभी कांग्रेसी मुख्यमंत्री राहुल से अध्यक्ष बनने की मांग करते रहे। यदि राहुल की तैयारी होती तो सोनियाजी अपनी कुर्सी तुरंत खाली कर देतीं। सारा देश त्यागमूर्ति के रूप में उनका आदर करता है। वे चाहतीं तो 2014 में ही प्रधानमंत्री बन सकती थीं लेकिन डॉ. मनमोहन सिंह को वह पद उन्होंने सौंप दिया। वैसा ही संकोच अब राहुल को भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सारे बुजुर्ग कांग्रेसियों की मित्रता के बावजूद वे कांग्रेस का अध्यक्ष पद लेने के लिए राहुल की हां नहीं करवा पाए।

लेकिन यहां सवाल यह भी है कि यदि सोनिया गांधी पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं तो राहुल गांधी का नाम इस समय क्यों उछला गया? सोनियाजी ने उन 23 नेताओं को आड़े हाथों

लिया, जिन्होंने पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग की थी। उन्होंने कहा कि पार्टी के आंतरिक मामलों को धोबीघाट पर ले जाकर पछाड़ने की जरूरत नहीं है। वे सभी वरिष्ठ नेता फिर से राहुल गांधी की बीन बजाने लगे। किसी ने भी हिम्मत नहीं की कि वह कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव की पद्धति को मूल रूप से बदलने की वकालत करता। यदि कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता सीधे चुनाव के द्वारा अपना अध्यक्ष चुनें तो कांग्रेस फिर से एक जानदार पार्टी बन सकती है। इतना ही नहीं, इसका असर दूसरी सभी पार्टियों पर भी पड़ेगा। इस समय देश की सभी पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह बन गई हैं। उनमें आंतरिक लोकतंत्र शून्य होता जा रहा है। वे सब इंदिरा गांधी के ढर्रे पर ढलती जा रही हैं। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए गहन चिंता का विषय है। इस समय कांग्रेस ही ऐसी एकमात्र विरोधी पार्टी है, जो सचमुच अखिल भारतीय है। उसकी गिरी-पड़ी हालत हो गई है, इसके बावजूद देश का शायद ही कोई जिला होगा, जहां आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। लेकिन यह भी सत्य है कि कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और कुछ नामी-गिरामी नेता भी अन्य विरोधी पार्टियों में शामिल होते जा रहे हैं। यही राजनीतिक प्रक्रिया देश में जारी रही तो अगले पांच-सात साल में चीन और रूस की तरह भारत में भी एक नेता, एक नारा और एक पार्टी का राज हो जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कहे जानेवाले भारत को इस विभीषिका से बचाने की पूरा प्रयत्न करना होगा। ■

सावरकर रूपी उजालों पर कालिख पोतने की कोशिशें

● ललित गर्ग

दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय महुरकर और चिरायु पंडित द्वारा लिखित पुस्तक 'वीर सावरकर; दी मैन हू कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन' के विमोचन समारोह में प्रकट हुये विचारों को लेकर न केवल विवाद छिड़ा हुआ है बल्कि सावरकर रूपी उजाले पर कालिख पोतने की कोशिश बुद्धि के दिवालियापन को दर्शाती है। इस प्रकार की स्वार्थप्रेरित, राष्ट्र तोड़क, उद्देश्यहीन, उच्छृंखल, विध्वंससात्मक विरोध से किसी का भी हित सधता हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। इस तरह का विरोध कोई नई बात नहीं है, न ही उससे उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिनकी ऐसी आलोचना की जाती है। यह तो समय, शक्ति, अर्थ एवं सोच का अपव्यय है। विभिन्न राजनैतिक दलों, कांग्रेस एवं वामपंथी दल ऐसा कोई अवसर नहीं छोड़ते जब वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं उससे जुड़े शीर्ष राष्ट्रनायकों की छवि को तार-तार न करते हो। यह तो सर्वविदित है कि वीर दामोदर सावरकर को बदनाम करने की लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन इन विरोधों के बावजूद वे और उनका व्यक्तित्व अधिक निखार पाता रहा है।

विनायक दामोदर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रखर सेनानी, महान देशभक्त, ओजस्वी वक्ता, दूरदर्शी राजनेता, इतिहासकार, एक बहुत निराले साहित्यकार-कवि और प्रखर राष्ट्रवादी थे। उन पर लिखी गयी यह पुस्तक एवं इसका विमोचन करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान के बाद कि आजादी के बाद वीर सावरकर को बदनाम करने की मुहिम चली थी, पर विवाद गहराया हुआ है। न केवल मोहन भागवत बल्कि रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के यह कहने पर कि सावरकर ने महात्मा गांधी के कहने पर दया याचिका दायर की थी, राजनीतिक



विवाद खड़ा हो गया है। ऑल इंडिया मजलिस ए इतेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि सावरकर के बारे में ऐतिहासिक तथ्य है कि उन्होंने अपनी रिहाई के लिए माफीनामा लिखा था। जबकि सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने कहा है कि यह माफीनामा नहीं था बल्कि जेल में बंद सभी क्रांतिकारियों की रिहाई के लिए यह एक दया याचिका थी।

संघ एवं सावरकर के विरोध की आंधी चलते हुए पचहतर वर्ष हो गये हैं, ऐसे लोग, राजनीतिक दल एवं राष्ट्र-विरोधी ताकते निरन्तर यह विरोध कर रहे हैं। इस दृष्टि से संघ एवं उसके नायकों का विरोध कोई नई बात नहीं है। कभी-कभी तो ऐसा प्रतीत होने लगता है कि विरोध इनकी नियति है। आश्चर्य की बात है कि विरोध की तीव्रता एवं दीर्घता के बावजूद संघ के अस्तित्व पर कोई आंच नहीं आ सकी है। सावरकर की गणना दुनिया के चर्चित राष्ट्रनायकों में आती है। जो बहुचर्चित होता है, उसका विरोध भी उतना ही तीक्ष्ण और तेजधार होता है। पर विरोध का भी कोई उद्देश्य एवं स्तर होता है। निरुद्देश्य एवं स्तरहीन विरोध, विरोधी खेमे, निराशा एवं हताशा राजनीतिक दलों एवं नेताओं की स्वार्थपूर्ण मनोवृत्ति, ईर्ष्या, विध्वंस एवं मानसिक दिवालियापन की नीति का स्वयंभू प्रमाण बन जाता है। ये राष्ट्र-विरोधी ताकते हैं, जो सशक्त भारत के निर्माण में तरह-तरह की

बाधाएं डालती है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने तभी कहा है कि आज संघ और सावरकर पर बहुत टीका टिप्पणी हो रही है। इनका असल मकसद दूसरा है। इसके बाद नंबर लगेगा स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और योगी अरविंद का। क्योंकि भारत की जो राष्ट्रीयता है उसका प्रथम उद्घोष इन तीनों ने किया है।

सावरकर का जीवन-दर्शन एवं राष्ट्र-निर्माण में योगदान अविस्मरणीय है, आधार-स्तंभ एवं प्रकाश-किरण है। उनकी प्रेरणाएं एवं शिक्षाएं इसलिये प्रकाश-स्तंभ हैं कि उनमें नये भारत को निर्मित करने की क्षमता है। उन्होंने एक भारत और मजबूत भारत की कल्पना की जिसे साकार करने का संकल्प हर भारतीय के मन में है। हम आजाद हो गये, लेकिन हमारी मानसिकता अभी भी गुलामी की मानसिकता को ओढ़े हैं। इन्हीं राजनीतिक स्वार्थों एवं गुलामी मानसिकता से जुड़े लोगों ने ही वीर सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया है। बार-बार यह कहा गया कि सावरकर ने ब्रिटिश सरकार के सामने कई बार माफीनामा लिखा। लेकिन रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार सच्चाई यह है कि दया याचिका उन्होंने खुद को रिहा करने के लिए नहीं दाखिल की थी। एक सामान्य कैदी अपने लिए दया याचिका दायर कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें माफीनामा दायर करने के लिए कहा था। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने दया याचिका दायर की। महात्मा गांधी ने सावरकरजी को रिहा

करने की अपील भी की थी, उन्होंने कहा था कि जिस तरह से आजादी हासिल करने के लिए हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चला रहे हैं, वैसे ही सावरकर भी आंदोलन चलाएंगे। सावरकरजी की तरफ से माफीनामा लिखने की बात बेबुनियाद और गलत है।'

सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने स्पष्ट किया है कि यह माफीनामा नहीं था बल्कि जेल में बंद यह सभी क्रांतिकारियों के लिए एक दया-याचिका थी। दूसरी बात इसे महात्मा गांधी के कहने पर लिखा गया था। गांधीजी सावरकर को अपना छोटा भाई मानते थे। रंजीत सावरकर ने कहा, 'मुझे यह नहीं पता कि गांधीजी क्या व्यक्तिगत रूप से ऐसा करने के लिए सावरकरजी से कहा था, लेकिन गांधीजी की ओर से 25 जनवरी, 1920 को सावरकर को लिखा गया पत्र मेरे पास है। राजनाथजी जरूर

इस पत्र अथवा किसी अन्य पत्र के बारे में जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, उसका जिक्र कर रहे होंगे। मार्च 1920 में यंग इंडिया में गांधीजी का एक लेख छपा था। इस लेख में गांधीजी ने राजनीतिक क्रांतिकारियों की रिहाई वाले सावरकर की अर्जियों का समर्थन किया था। गांधीजी ने सावरकर को भी अर्जी दायर करने की सलाह दी थी।' इन साक्ष्यों एवं तथ्यों के बावजूद इस विषय को विवादास्पद बनाकर राजनीतिक दल अपने स्वार्थों की रोटियां सेक रहे हैं, जो राष्ट्र-विरोधी कृत्य है। जबकि सावरकरजी के जीवन का उद्देश्य है- निज संस्कृति को बल देना, उज्वल आचरण, सात्विक वृत्ति एवं स्व-पहचान। भारतीय जनता के बड़े भाग में राष्ट्रीयता एवं स्व-संस्कृति की कमी को दूर करना ही सावरकरजी के जन्म एवं जीवन का ध्येय था। वे विश्वभर के क्रांतिकारियों

में अद्वितीय थे। उनका नाम ही भारतीय क्रांतिकारियों के लिए उनका संदेश था। उनकी पुस्तकें क्रांतिकारियों के लिए गीता के समान थीं।

वीर सावरकर जैसे बहुत कम क्रांतिकारी एवं देशभक्त होते हैं जिनके तन में जितनी ज्वाला हो उतना ही उफान मन में भी हो। उनकी कलम में चिंगारी थी, उसके कार्यों में भी क्रांति की अग्नि धधकती थी। वीर सावरकर ऐसे महान सपूत थे जिनकी कविताएं एवं विचार भी क्रांति मचाते थे और वह स्वयं भी महान् क्रांतिकारी थे। उनमें तेज भी था, तप भी था और त्याग भी था। राष्ट्रीय एकता और समरसता उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। रत्नागिरी आंदोलन के समय उन्होंने जातिगत भेदभाव मिटाने का जो कार्य किया वह अनुकरणीय था। वहां उन्होंने दलितों को मंदिरों में प्रवेश के लिए सराहनीय अभियान

सावरकर के बारे में नई बातें

- केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहुरकर की एक नई किताब आई है... Veer Savarkar: The Man Who Could Have Prevented Partition

हिंदी में इस किताब के शीर्षक का अर्थ हुआ वीर सावरकर... वो आदमी जो भारत के संविधान भारत के बंटवारे को रोक सकता था।

- इस किताब की कीमत कुल 445 रुपए है लेकिन हमने इस किताब को खरीदा और खरीदकर पढ़ा और आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठी की हैं।

- भारत में कम्युनिस्टों के पितामह माने जाने वाले एम एन राय ने सावरकर की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि सावरकर बरगद के पेड़ हैं और हम सब उनकी शाखाएं हैं।

- इसी किताब में लिखा है कि साल 1938 में लाहौर में हिंदू महासभा का एक सम्मेलन हुआ और इसी सम्मेलन में एक पत्रकार ने वीर

सावरकर से एक सवाल पूछा... वो सवाल ये था कि आप (सावरकर) और जिन्ना देश को तोड़ना चाहते हैं तो इस पर वीर सावरकर ने जवाब दिया था कि मुझमें और जिन्ना में बहुत बड़ा फर्क है... जिन्ना चाहते हैं कि मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिले लेकिन मैं चाहता हूँ कि हिंदू हो या फिर मुस्लिम... सबको समान अधिकार मिले।

- साल 1937 में जब वीर सावरकर नजरबंद से बाहर निकले तो सुभाष चंद्र बोस ने सावरकर से कहा कि आप कांग्रेस में शामिल हो जाइए तब सावरकर ने जवाब दिया कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के पथ पर इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब मैं कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ।

- साल 1939 में एक शिवा संगठन ने लखनऊ में ये घोषणा की थी कि जो भी गाय की हत्या कर देगा उसको हिंदू मुस्लिम एकता का विरोधी माना जाएगा। तब वीर सावरकर ने चिट्ठी लिखकर उस संगठन की तारीफ की थी।

- पहले सिंध और मुंबई प्रांत एक ही थे अलग नहीं थे। सिंध बॉम्बे स्टेट का ही हिस्सा था रानी कराची और मुंबई एक ही सूबे कि हिस्से हुआ करते थे लेकिन 1936 में मुसलमानों के दबाव में जब सिंध एक अलग प्रांत बनाया गया और उसमें

मुस्लिम पॉपुलेशन को प्रभावशाली बनाने की साजिश रची गई तभी 1936 में ही सावरकर ने ये भांप लिया था कि ये हिस्सा देश से तोड़ने की साजिश चल रही है।

- साल 1941 में जब असम में मुसलमान बसने लगे तब सावरकर ने कहा था कि इससे असम के कल्चर को नुकसान पहुंचेगा और इससे खतरा पैदा होगा तब जवाहर लाल नेहरू ने मुस्लिम तुष्टीकरण करते हुए कहा कि जहां पर खाली जगह खाली होगी वहां कोई ना कोई तो आएगा ही। तब सावरकर ने पंडित नेहरू को फटकार लगाते हुए कहा था कि नेहरू का पर्यावरण का ज्ञान बहुत निम्न है कि जहां खालीपन होता है वहां जहरीली गैस भी आ सकती है।

- आजादी के बाद 75 सालों तक सावरकर को साइडलाइन किया गया लेकिन अब उनके अत्यंत लोकप्रिय होने का समय आ चुका है। जैसे जब गौतम बुद्ध का निर्वाण हुआ तो गौतम बुद्ध को कोई नहीं जानता था। 250 सालों तक बुद्ध को कोई नहीं जानता था। लेकिन जब अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तब बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैलने लगा और आज बौद्ध धर्म दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। ठीक इसी तरह आज नहीं कल हिंदुस्तान का हर हिंदू सावरकर के हिंदुत्व के विचारों पर आगे बढ़ेगा ऐसा हमारा विचार है।





सावरकर : गुमनाम तथ्य

आइए जानते हैं एक ऐसे महान क्रांतिकारी के बारे में जिनका नाम इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया। जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा इतनी यातनाएं झेलीं कि वीर सावरकर के बारे में कल्पना करके ही कार्यों में सिहरन पैदा हो जायेगी।

जिनका नाम लेने मात्र से आज भी हमारे देश के राजनेता भयभीत होते हैं क्योंकि उन्होंने मां भारती की निस्वार्थ सेवा की थी।

वो थे हमारे परम वीर सावरकर

1. वीर सावरकर पहले क्रांतिकारी देशभक्त थे जिन्होंने 1901 में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया की मृत्यु पर नासिक में शोकसभा का विरोध किया और कहा कि वो हमारे शत्रु देश की रानी थी, हम शोक व्यक्त करें ? क्या किसी भारतीय महापुरुष के निधन पर ब्रिटेन में शोक सभा हुई ?
2. वीर सावरकर पहले देशभक्त थे जिन्होंने एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह का उत्सव मनाने वालों को टर्मबकेंशर में बड़े बड़े पोस्टर लगाकर कहा था कि गुलामी का उत्सव मत मनाओ!
3. विदेशी वस्त्रों की पहली होली पूना में 7 अक्टूबर 1905 को वीर सावरकर ने जलाई थी!
4. वीर सावरकर पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने विदेशी वस्त्रों का दहन किया, तब बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी में उनको शिवाजी के समान बताकर उनकी प्रशंसा की थी जबकि इस घटना की दक्षिण अफ्रीका के अपने पत्र 'इन्डियन ओपीनियन' में गांधी ने निंदा की थी।
5. वीर सावरकर द्वारा विदेशी वस्त्र दहन की इस प्रथम घटना के 16 वर्ष बाद गांधी उनके मार्ग पर चले और 11 जुलाई 1921 को मुंबई के परेल में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया।
6. सावरकर पहले भारतीय थे जिनको 1905 में विदेशी वस्त्र दहन के कारण पुणे के फर्म्युसन कॉलेज से निकाल दिया गया और दस रुपये जुर्माना किया जिनके विरोध में हड़ताल हुई स्वयं तिलक जी ने 'केसरी' पत्र में सावरकर के पक्ष में सम्पादकीय लिखा।
7. वीर सावरकर ऐसे पहले बैरिस्टर थे जिन्होंने 1909 में ब्रिटेन में ग्रेज-इन परीक्षा पास करने के बाद ब्रिटेन के राजा के प्रति वफादार होने की शपथ नहीं ली। इस कारण उन्हें बैरिस्टर होने की उपाधि का पत्र कभी नहीं दिया गया।
8. वीर सावरकर पहले ऐसे लेखक थे जिन्होंने अंग्रेजों द्वारा गदर कहे जाने वाले संघर्ष को '1857 का स्वातंत्र्य समर' नामक ग्रन्थ लिखकर सिद्ध कर दिया।
10. '1857 का स्वातंत्र्य समर' विदेशों में छपा गया और भारत में भगत सिंह ने इसे छपवाया था जिसकी एक एक प्रति तीन-तीन सौ रुपये में बिकी थी। भारतीय क्रांतिकारियों के लिए यह पवित्र गीता थी ज पुलिस छापों में देशभक्तों के घरों में यही पुस्तक मिलती थी।

11. वीर सावरकर पहले कान्तिकारी थे जो समुद्री जहाज में बंदी बनाकर ब्रिटेन से भारत लाते समय आठ जुलाई 1910 को समुद्र में कूद पड़े थे और तैरकर फ्रांस पहुंच गए थे।
12. सावरकर पहले कान्तिकारी थे जिनका मुकद्दमा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में चला, मगर ब्रिटेन और फ्रांस की मिलीभगत के कारण उनको न्याय नहीं मिला और बंदी बनाकर भारत लाया गया।
13. वीर सावरकर विश्व के पहले क्रांतिकारी और भारत के पहले राष्ट्रभक्त थे जिन्हें अंग्रेजी सरकार ने दो आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
14. वीर सावरकर पहले ऐसे देशभक्त थे जो दो जन्म कारावास की सजा सुनते ही हंसकर बोले - 'चलो, ईसाई सत्ता ने हिन्दू धर्म के पुनर्जन्म सिद्धांत को मान लिया'।
15. वीर सावरकर पहले राजनैतिक बंदी थे जिन्होंने काला पानी की सजा के समय 10 साल से भी अधिक समय तक आजादी के लिए कोल्हू चलाकर 30 पौंड तेल प्रतिदिन निकाला।
16. वीर सावरकर काला पानी में पहले ऐसे कैदी थे जिन्होंने काल कोठी की दीवारों पर कंकर कोयले से कवितायें लिखीं और 6000 पंक्तियां याद रखीं।
17. वीर सावरकर पहले देशभक्त लेखक थे, जिनकी लिखी हुई पुस्तकों पर आजादी के बाद कई वर्षों तक प्रतिबन्ध लगा रहा।
18. वीर सावरकर पहले विद्वान लेखक थे जिन्होंने हिन्दू को परिभाषित करते हुए लिखा कि

'आसिन्धु सिन्धुपर्वन्ता यस्य भारत भूमिका,
पितृभू-पुण्यभूश्चैव स वै हिन्दुरितीरस्मृतः।

अर्थात् समुद्र से हिमालय तक भारत भूमि जिसकी पितृभूमि है, जिसके पूर्वज यहीं पैदा हुए हैं व यही पुण्य भूमि है, जिसके तीर्थ भारत भूमि में ही हैं, वही हिन्दू है।

19. वीर सावरकर प्रथम राष्ट्रभक्त थे जिन्हें अंग्रेजी सत्ता ने 30 वर्षों तक जेलों में रखा तथा आजादी के बाद 1948 में नेहरू सरकार ने गांधी वध की आड़ में लाल किले में बंद रखा पर न्यायालय द्वारा आरोप झूठे पाए जाने के बाद ससम्मान रिहा कर दिया। नेहरू उनके राष्ट्रवादी विचारों से डरता था।
20. वीर सावरकर पहले क्रांतिकारी थे जब उनका 26 फरवरी 1966 को उनका स्वर्गारोहण हुआ तब भारतीय संसद में कुछ सांसदों ने शोक प्रस्ताव रखा तो वह कहकर रोक दिया गया कि वे संसद सदस्य नहीं थे जबकि चर्चिल की मौत पर शोक मनाया गया था।
21. वीर सावरकर पहले क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त स्वातंत्र्य वीर थे जिनके मरणोपरांत 26 फरवरी 2003 को उसी संसद में मूर्ति लगी जिसमें कभी उनके निधन पर शोक प्रस्ताव भी रोका गया था।
22. वीर सावरकर ऐसे पहले राष्ट्रवादी विचारक थे जिनके चित्र को संसद भवन में लगाने से रोकने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी उर्फ एंटोनिया माइनी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा लेकिन राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम ने सुझाव पत्र नकार दिया और वीर सावरकर के चित्र अनावरण राष्ट्रपति ने अपने कर-कमलों से किया।
23. वीर सावरकर पहले ऐसे राष्ट्रभक्त हुए जिनके शिलालेख को अंडमान द्वीप की सेल्युलर जेल के कीर्ति स्तम्भ से क्ल सरकार के मंत्री मणिशंकर अय्यर ने हटवा दिया था और उसकी जगह गांधी का शिलालेख लगवा दिया था।
24. वीर सावरकर ने दस साल स्वतंत्रता के लिए काला पानी में कोल्हू चलाया था जबकि गांधी ने काला पानी की उस जेल में कभी दस मिनट चरखा नहीं चलाया।
25. वीर सावरकर मां भारती के पहले सपूत थे जिन्हें जीते जी और मरने के बाद भी आगे बढ़ने से रोका गया ज पर आश्चर्य की बात यह है कि इन सभी विरोधों के घोर अंधेरे को चीरकर आज वीर सावरकर सूर्य के समान सभी में लोकप्रिय और युवाओं के आदर्श बन रहे हैं।

चलाया। महात्मा गांधी ने तब खुले मंच से सावरकर की इस मुहिम की प्रशंसा की थी, भले ही आजादी के माध्यमों के बारे में गांधीजी और सावरकर का नजरिया अलग-अलग था। सावरकर हिन्दू राष्ट्र एवं हिन्दू संस्कृति की बात करते थे, यही उनके विरोध का बड़ा कारण बना है।

भारत को सशक्त हिन्दू राष्ट्र के रूप में उभरते हुए देखना अनेक राष्ट्र-विरोधी लोगों का मुख्य एजेंडा रहा है। ऐसे ही निन्दक एवं आलोचक लोगों को सब कुछ गलत ही गलत दिखाई देता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कहीं भी आहत भी हो जाती है तो भूकम्प-सा आ जाता है। मजे की बात तो यह है कि इन तथाकथित राजनीतिक दलों एवं उनके नेताओं को संघ की एक भी विशेषता दिखाई नहीं देती। जबकि संघ में राष्ट्र-निर्माण के लिये कितने रचनात्मक एवं सृजनात्मक काम हो रहे हैं। निन्दा का वातुल संघ को विचलित नहीं कर पाता एवं प्रशंसा की थपकियां उसे प्रमत्त नहीं बना सकती- ऐसा है अनूठा एवं विलक्षण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं उसका समूचा संगठनात्मक ढांचा। संघ के नेतृत्व ने निन्दा और प्रशंसा-दोनों को सहना सीखा है, इसलिये संघ एवं उनके नायक महान् हैं। संघ पर कीचड़ उछालने की जो हरकतें हो रही हैं, उससे संघ का वर्चस्व धूमिल होने वाला नहीं है। क्योंकि इसकी नीति विशुद्ध राष्ट्र-निर्माण की है और सैद्धान्तिक आधार पवित्रता-पुष्ट है। विरोध करने वाले व्यक्ति स्वयं भी इस बात को महसूस करते हैं। फिर भी आम-जनता को गुमराह करने के लिये और उनका मनोबल कमजोर करने के लिये जो भी राजनीतिक दल एवं नेता उजालों पर कालिख पोत रहे हैं, इससे उन्हीं के हाथ काले होने की संभावना है। ऐसे लोगों को सद्बुद्धि आये, वे

अपना समय एवं श्रम किसी राष्ट्र-निर्माण के रचनात्मक काम में लगायें तो राष्ट्र की सच्ची सेवा हो सकती है।



सावरकर पर हमला क्यों ?

स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर पर एक पुस्तक का विमोचन करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत और रक्षा मंत्री राजनाथसिंह ने सावरकर पर किए जानेवाले आक्षेपों का कड़ा प्रतिवाद किया है। उन्होंने सावरकर को बेजोड़ राष्ट्रभक्त और विलक्षण स्वातंत्र्य-सेनानी बताया है लेकिन कई वामपंथी और कांग्रेसी मानते हैं कि सावरकर माफी मांगकर अंडमान-निकोबार की जेल से छूटे थे, उन्होंने हिंदुत्व की संकीर्ण सांप्रदायिकता फैलाई थी और उन्होंने ही गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को आशीर्वाद दिया था। गांधी-हत्याकांड में सावरकर को भी फंसा लिया गया था लेकिन उन्हें ससम्मान बरी करते हुए जस्टिस खोसला ने कहा था कि इतने बड़े आदमी को फिजूल ही इतना सताया गया। स्वयं गांधीजी सावरकर से लंदन के 'इंडिया हाउस' में 1909 में मिले और 1927 में वे उनसे मिलने रत्नागिरी में उनके घर भी गए। दोनों में अहिंसा और उस समय की मुस्लिम सांप्रदायिकता को लेकर गहरा मतभेद था। सावरकर अखंड भारत के कट्टर समर्थक थे लेकिन जिन्ना के नेतृत्व में खड़े दो राष्ट्रों की सच्चाई को वे खुलकर बताते थे। वे मुसलमानों के नहीं, मुस्लिम लीगियों के विरोधी थे। हिंदू महासभा के अपने अध्यक्षीय भाषणों में उन्होंने सदा हिंदुओं और मुसलमानों के समान अधिकार

की बात कही। उनके विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ '1857 का स्वातंत्र्य-समर' में उन्होंने बहादुरशाह जफर, अवध की बेगमों तथा कई मुस्लिम फौजी अफसरों की बहादुरी का मार्मिक वर्णन किया है। जब वे लंदन में पढ़ते थे तो आसफअली, सय्यद रजा हैदर, सिकंदर हयात खां, मदाम भिकायजी कामा वगैरह उनके अभिन्न मित्र होते थे। उन्होंने खिलाफत आंदोलन का विरोध जरूर किया। गांधीजी उसके समर्थक थे लेकिन वही आंदोलन भारत-विभाजन की नींव बना। यह ठीक है कि सावरकर का हिंदुत्व ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का आधार बना लेकिन सावरकर का हिंदुत्व संकीर्ण और पोंगापंथी नहीं था। सावरकर की विचारधारा पर आर्यसमाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद और उनके भक्त श्यामजी कृष्ण वर्मा का गहरा प्रभाव था। वे इतने निर्भीक और तर्कशील थे कि उन्होंने वेदों की अपौरुषेयता, गौरक्षा, फलित ज्योतिष, व्रत-उपवास, ब्राह्मणी कर्मकांड, जन्मना वर्ण-व्यवस्था, जातिवाद, अस्पृश्यता आदि को भी अमान्य किया है। वे ऐसे मुक्त विचारक और बुद्धिजीवी थे कि उनके सामने विवेकानंद, गांधी और आंबेडकर भी कहीं-कहीं फीके पड़ जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी उनके सभी विचारों से सहमत नहीं हो सकता। सावरकर के विचारों पर यदि मुह्ला-मौलवी छुरा ताने रहते थे तो पंडित-पुरोहित उन पर गदा प्रहार किया करते थे। जहां तक सावरकर द्वारा ब्रिटिश सरकार से माफी मांगने की बात है, इस मुद्दे पर मैंने कई वर्षों पहले 'राष्ट्रीय संग्रहालय' के गोपनीय दस्तावेज खंगाले थे और अंग्रेजी में लेख भी लिखे थे। उन दस्तावेजों से पता चलता है कि सावरकर और उनके चार साथियों ने ब्रिटिश वायसराय को अपनी रिहाई के लिए जो पत्र भेजा था, उस पर गवर्नर जनरल के विशेष अफसर रेजिनाल्ड क्रेडोक ने लिखा था कि सावरकर झूठा अफसोस जाहिर कर रहा है। वह जेल से छूटकर यूरोप के आतंकवादियों से जाकर हाथ मिलाएगा और सरकार को उलटाने की कोशिश करेगा। सावरकर की इस सच्चाई को छिपाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कई बार की गई। अंडमान-निकोबार जेल से उनकी नामपट्टी भी हटाई गई लेकिन मैं तो उस कोठरी को देखकर रोमांचित हो उठा, जिसमें सावरकर ने बरसों काटे थे और जिसकी दीवारों पर गोद कर सावरकर ने कविताएं लिखी थीं। ■



ड्रग्स के मकड़ जाल में फंसता बॉलीवुड

महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने इसे ड्रग मामले में की गई सामान्य कानूनी कार्रवाई से आगे ले जाकर खुद और एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के बीच का मामला बना दिया है। नतीजा यह हुआ है कि महाराष्ट्र की राजनीति अब राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के दिनों से भी नीचे चली गई है।

एनसीबी ने आर्यन खान को ड्रग मामले में गिरफ्तार किया तो परंपरागत और सोशल मीडिया पर युद्ध सा छिड़ गया। आर्यन खान के

समर्थन और एनसीबी के विरोध में कई लोग उठ खड़े हुए। तर्क, कुतर्क और बालसुलभ बातों से मीडिया स्पेस भर गया। गिरफ्तारी के पीछे के कारणों को लेकर लगाए गए कुछ कयास और जारी किए गए कुछ बयानों को पढ़कर लगा जैसे उनका उद्देश्य ही एनसीबी की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाना और आम लोगों में भ्रम पैदा करना था। हाल के वर्षों में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के खिलाफ माहौल बना कर भ्रम पैदा करना लिबरल इकोसिस्टम के टूलकिट का ऐसा हिस्सा है जिसे बार-बार आजमाया जाता रहा है।

यह बताया गया कि केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी दरअसल आर्यन खान को नहीं बल्कि उनके बहाने शाहरुख खान के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ऐसे बयान के पीछे के कारण तो इसे जारी करने वाले बयानबाजों को ही पता होंगे पर सबकुछ धड़ल्ले से कहा गया। जैसे शाहरुख खान की वर्तमान केंद्र सरकार से कोई दुश्मनी है और सरकार इसी कारण से शाहरुख खान को परेशान कर रही है। यह तब जब शाहरुख खान की केंद्र सरकार से



ही नहीं, भाजपा के साथ भी कभी किसी तरह का सार्वजनिक विवाद नहीं रहा। फिर भी कुछ टीवी न्यूज चैनल, उनके संपादक और संवाददाताओं ने अपनी चिर परिचित नीति के तहत एनसीबी की कार्रवाई का खुलकर विरोध और आर्यन खान का समर्थन किया।

आगे चलकर कहा गया कि शाहरुख खान को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वे मुसलमान हैं। इस तरह के तर्क हमेशा से अजीब लगते रहे हैं पर समय-समय पर यह दोहरा कर इसे सच बनाने का प्रयास जारी है। कुछ तो अपने कुतर्क मार्ग पर चलकर वहां पहुंच गए जहां से यह कहते सुने गए कि; चूंकि शाहरुख खान सदी के सबसे लोकप्रिय भारतीय हैं इसलिए उनके बेटे के साथ ऐसा व्यवहार न तो कानून सम्मत है और न ही संविधान सम्मत।

भारत का कानून या सरकार शाहरुख खान की लोकप्रियता के आधार पर आचरण करें, यह कहना वैसा ही है जैसे यह कहा जाए कि अमिताभ बच्चन के कर्ज बैंकों द्वारा केवल इसलिए माफ कर देने चाहिए थे क्योंकि उन्हें सदी का महानायक माना जाता रहा है।

ऐसा लगता है जैसे मीडिया में आर्यन और शाहरुख खान के समर्थन में दिए गए बयान और कुतर्क वगैरह का असर होता दिखाई न दिया तो राजनीतिक हस्तक्षेप का सहारा लिया गया। अब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने इसे ड्रग मामले में की गई सामान्य कानूनी कार्रवाई से आगे ले जाकर खुद और एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के बीच का मामला बना दिया है। नतीजा यह हुआ है कि महाराष्ट्र की राजनीति अब राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के दिनों से भी नीचे चली गई है। नवाब मलिक को वानखेड़े से चाहे जो समस्या हो पर आर्यन खान मामले में उनका व्यक्तिगत हस्तक्षेप किसी भी तरह से संवैधानिक नहीं है।

वानखेड़े के विरुद्ध वे रोज कोई न कोई ऐसा बयान जारी करते हैं जो लगते तो व्यक्तिगत हमले हैं पर उनका उद्देश्य एनसीबी के साथ-साथ केंद्र सरकार के अन्य विभागों की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठाना जान पड़ता है। ऐसा महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार के मंत्री और सत्ताधारी दलों के अन्य नेता पहले भी कर चुके हैं। आज नवाब मलिक जो कर रहे हैं वो केंद्र

सरकार के विरुद्ध खड़े होने के अनिल देशमुख के अजेंडे का ही विस्तार है। पूर्व गृहमंत्री देशमुख अपने दिनों में लगभग रोज केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कोई न कोई जांच का आदेश देते ही रहते थे। यह बात और है कि बाद में उनका और उनके पुलिस अफसरों का क्या बना वह सबके सामने है।

पिछले कुछ वर्षों से केंद्रीय जांच एजेंसियों के विरुद्ध कुछ राज्य सरकारों ने जिस तरह की राजनीति की है वह कई स्तरों पर संघीय ढांचे को क्षति पहुंचाने वाली रही है। चंद्रबाबू नायडू और ममता बनर्जी का अपने राज्य में सीबीआई को न घुसने देने की घोषणा इसी राजनीति का हिस्सा थी। अपने मंत्रियों की गिरफ्तारी पर ममता बनर्जी द्वारा सीबीआई का घेराव इसी वर्ष किया गया। नवाब मलिक आज जो कर रहे हैं वह इसी राजनीति का नवीनतम संस्करण है। उन्हें वानखेड़े से जो भी समस्या है, उसका खुलासा जब होगा तब होगा पर फिलहाल उनके आचरण ने एनसीबी की एक विशुद्ध कानूनी कार्रवाई को राजनीतिक लड़ाई बना दिया है। यह बात वर्तमान विपक्ष द्वारा केंद्र सरकार के विरुद्ध शुरू की गई राजनीतिक प्रवृत्ति को पुख्ता ही नहीं करेगी बल्कि अन्य राज्य सरकारों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगी।

मलिक एक मंत्री की हैसियत से यह सब कर रहे हैं पर आश्चर्य यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के ऐसे आचरण पर प्रतिक्रिया नहीं देते। मुख्यमंत्री ठाकरे की यही चुप्पी अनिल देशमुख की अति सक्रियता के समय भी थी। ठाकरे तो चुप हैं ही पर शरद पवार की चुप्पी और महत्वपूर्ण है। वर्तमान भारतीय राजनीति के सबसे वरिष्ठ नेता पिछले लगभग दो वर्षों से चुप होकर अपने दल के नेताओं को निकृष्ट राजनीतिक आचरण करते हुए

आर्यन खान के केस में कब-कब क्या हुआ, देखें पूरी टाइम लाइन

सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आजकल ड्रग केस में फंसने के बाद चर्चा में हैं। वरुज पर छुट्टी बिताने गए आर्यन ड्रग के मामले में कई लोगों सहित गिरफ्तार हो गए थे। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई टल चुकी है।

2 अक्टूबर: एनसीबी (नार्कॉटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) ने मुंबई से गोवा जा रही वरुज पर रेड डाली, जिसमें 13 ग्राम कोकीन, 21 ग्राम चरण और एमडीएमए के 22 गोली मिली। इस मामले में आर्यन खान सहित कई लोगों को हिरासत में लिया गया।

3 अक्टूबर: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेट, मॉडल मुनमुन धमेचा की गिरफ्तारी की गई और तीनों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तीनों को एनसीबी की रिमांड पर सौंप दिया।

4 अक्टूबर: आर्यन खान एवं अन्य लोगों के फिर से अदालत में पेश किया गया। एनसीबी ने आर्यन खान के फोन से मिली डिटेल्स के आधार पर अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी से आर्यन खान के संबंध बताए। अदालत ने आर्यन खान की कस्टडी 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी।

7 अक्टूबर: इस दिन एनसीबी ने फिर से आर्यन खान को रिमांड पर देने की मांग की लेकिन अदालत ने मना कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आर्यन की ओर से जमानत याचिका दाखल की गई।

8 अक्टूबर: अदालत ने आर्यन खान,



अरबाज मर्चेट, मुनमुन धमेचा की जमानत का याचिका रद्द कर दी।

9 अक्टूबर: आर्यन खान की ओर से दोबारा जमानत याचिका दाखल की गई। कहा कि उन्हें गलत तरीके से दोषी करार किया गया है। उनके पास से कोई ड्रग नहीं मिला, जिस बात को एनसीबी ने भी अपनी रिपोर्ट में माना है।

11 अक्टूबर: आर्यन खान के वकील ने जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की। कोर्ट ने इस मामले में 13 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा।

13 अक्टूबर: स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई एक दिन के लिए टाल दी।

एनसीबी ने 14 अक्टूबर को विशेष एनडीपीएस अदालत में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए दावा किया कि वह मादक पदार्थों के निरामित उपभोक्ता हैं। आर्यन खान को वरुज शिप पर कथित तौर पर मादक पदार्थ जब्त करने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है।



लगातार देख रहे हैं पर हस्तक्षेप नहीं करते। उनका ऐसा राजनीतिक आचरण महाराष्ट्र की वर्तमान राजनीति पर उनकी लगातार ढीली होती पकड़ का नतीजा है या फिर केंद्र सरकार से अलग-अलग स्तर पर टकराव का, यह देखना दिलचस्प रहेगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

पिछले बार के बड़े नेता स्वर्गीय प्रमोद

यह कैसी मस्ती की अंधेरी काली दुनिया!



कराये जाते हैं। देर रात तक चलने वाली इन पार्टियों में महफिलें जमती हैं, महानगरों में हर वीकेंड पर फार्म हाउस एवं आलीशान बिल्डिंगों, होटलों, वरुज में ये महफिलें सजती हैं। इन महफिलों में आने वाले लोगों को पूरी रात डांस, म्यूजिक, ड्रग्स और सैक्स का काकटेल मिलता है। इन रेव पार्टी में भारी मात्रा में विदेशी ब्रांड की शराब

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा मुंबई से गोवा जा रहे वरुज में नशाखोरी कर रहे अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन समेत अन्य लोगों की गिरफ्तारी न केवल शर्मनाक है बल्कि देश की जड़ों को खोखला करने वाली है। देश में नशीले पदार्थों का कारोबार और सेवन जिस गति से बढ़ता चला जा रहा है, वह चिन्ताजनक है। यह पहली बार नहीं, जब नशे का सेवन कर रहे नामचीन अथवा धनी लोगों को गिरफ्तार किया गया हो। रेव पार्टियां, नशे का बढ़ता प्रचलन एक त्रासदी है, विडम्बना है। ऐसे बहुत से गिरोह सक्रिय हैं जो युवावर्ग को नशे की दलदल में ढकेल रहे हैं। बढ़ती रेव पार्टियां उन्मुक्त होने एवं नशे की अंधी सुरंगों में उतरने का एक माध्यम है, जो समाज एवं राष्ट्र के लिये खतरनाक साबित होती जा रही है। क्या ऐसी पार्टियां बिना स्थानीय पुलिस की मिलीभगत के हो सकती हैं? यह सब कुछ पुलिस और ड्रग्स एवं नशे का धंधा करने वालों की सांठागांठ से ही होता है। इसमें सरकार की नीतियों पर भी प्रश्न खड़े होते हैं।

रेव पार्टियों का बढ़ता प्रचलन इसलिये खतरनाक है कि इनमें गांजा, चरस, अफीम, कोकीन और न जाने किन-किन ड्रग्स का इस्तेमाल होता ही है, एमडीएमए नाम के एक ड्रग का भी उपयोग होता है जो सेक्स को लेकर उत्तेजना पैदा करता है। इतनी भीषण उत्तेजना कि घंटों तक और कई लोगों के साथ सेक्स में लगे रहने की शक्ति पैदा हो जाती है। जरा सोचिए कि जिन लड़कियों के साथ यह सब होता होगा वो भी तो किसी घर की बेटा ही होंगी! मस्ती के चक्कर में मासूम बालिकाएं किस तरह खुद को

वरुज पंजों में सौंप देती हैं? इसके लिए क्या वो अकेली दोषी हैं? आश्चर्य नहीं कि नशाखोरी से कलकित बालीवुड फिर से विवादों में है। शाहरुख खान कोई आम भारतीय नहीं हैं। हिंदी सिनेमा के करोड़ों प्रशंसकों में उनकी पहचान है। जिन शाहरुख को उनके चाहने वाले अपना प्रेरणास्रोत मानते हैं, उनके पुत्र का इतने संगीन अपराध से जुड़ा होना क्या प्रेरणा दे रहा है? शाहरुख खान जैसे धनाढ्य माता-पिता और परिवार इसके लिए ज्यादा दोषी है। हमारा बच्चा क्या कर रहा है, इसकी जानकारी रखना परिवार का दायित्व है।

दुनिया की चकाचैंध से आकर्षित मध्यम वर्ग की बच्चियों को शिकार बनाया जाता है तो दौलतमंद लोगों की संतानों केवल मौज-मस्ती के चक्कर में फंस जाती हैं। गलत तरीकों से कमाई दौलत का इसी तरह औलादों को बिगाड़ रही हैं। एक वो माता-पिता होते हैं जो मजदूरी करके, घरों में बर्तन मांजकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उम्र से ही कोई अब्दुल कलाम निकल आता है। दूसरे वो मां-बाप हैं जो बच्चे को हर रोज हजारों रूपए जेब खर्च देते समय यह नहीं पूछते कि इतने पैसे क्यों चाहिए? देर रात तक लौटे तो नहीं पूछते कि कहां थे? नतीजा आपके सामने हैं। बच्चों को फांसने के लिए तो हर मोड़ पर ड्रग्स के सौदागर ग्लैमर लिए खड़े हैं। रेव पार्टियों में इसीलिए तो हलीवुड और बॉलीवुड के सितारों या उनकी औलादों को शामिल किया जाता है।

रेव पार्टियों की नई पनप रही संस्कृति अनेक विकृतियों का सबब बन रही है, जिसमें युवापीढ़ी को नये-नये नशे के साधन उपलब्ध

के साथ ब्रिक्स कोकिंग टैबलेट परोसी जाती है। रात भर उन्मुक्तता, अश्लीलता एवं सैक्स से भरपूर मनोरंजन तरह-तरह के नशे के साथ परोसा जाता है। नशे एवं पागलपन की हद तक चूर हो जाने के बाद छात्र-छात्राएँ अपनी चमचमाती गाड़ियों में घर लौट जाते हैं। इन महफिलों की सूचना भी खास-खास लोगों को सोशल मीडिया पर दी जाती है। समाज में नशीले पदार्थों एवं सैक्स के एजेंट सक्रिय हैं जो युवा पीढ़ी को ऐसी पार्टियों के लिये आकर्षित करते हैं। रेव पार्टियों में पकड़े जाने वाले लोगों में स्कूल जाने वाले छात्र-छात्राओं से लेकर बड़े बिजनेसमैन, सिने स्टार, राजनीतिज्ञों और अफसरों के बच्चे तक शामिल हैं। ऐसी पार्टियों में ऊंची पहुंच वाले और पैसे वाले ही जा सकते हैं। आर्योजक न केवल एक ही रात में लाखों कमाते हैं बल्कि जो लड़के-लड़कियां अपने ज्यादा दोस्तों को लाते हैं, उन्हें भी मोटी कमीशन दी जाती है। यह मुम्बई-दिल्ली जैसे महानगरों की रातों को रंगीन बनाने का जरिया बनता जा रहा है। लेकिन ये रंगीनियां कितने अंधेरे एवं खतरों का कारण बन रही है, इस चिन्तन करना जरूरी है।

मुम्बई, गोवा, पुणे, खंडाला, पुष्कर, मनाली से चली रेव पार्टियों ने दिल्ली और आसपास के शहरों में भी जगह बना ली है। ड्रग्स का धंधा करने वालों के लिये यह पार्टियां फायदे का धंधा बन गई हैं। जो देश के युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, अब तो लड़कियों ने भी सारी सीमाएं तोड़ दी है। नशीले पदार्थों, शराब, बीयर से लेकर तेज मादक पदार्थों, औषधियों तक की सहज उपलब्धता से इन रेव पार्टियों के प्रति युवा

एवं किशोर वर्ग का आकर्षक बढ़ता जा रहा है। इस दीवानगी को ओढ़ने के लिए प्रचार माध्यमों ने भी भटकाया है। सरकार भी विवेक से काम नहीं ले रही है। शराबबन्दी का नारा देती है, नशे की बुराइयों से लोगों को आगाह भी करती है और शराब, तम्बाकू का उत्पादन भी बढ़ा रही है। राजस्व प्राप्ति के लिए जनता की जिन्दगी से खेलना क्या किसी लोककल्याणकारी सरकार का काम होना चाहिए? यह कैसी समाज-व्यवस्था है जिसमें लाइसेंस लेकर आप चाहे जो करों? इनके पीछे कौन-कौन लोग हैं, जो देश के युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, ड्रग्स एवं नशीले पदार्थों के सेवन से जवानी खत्म हो रही है। बावजूद इसके उन पर हथ डालने की हिम्मत किसी में नहीं होती। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) अब सक्रिय हुआ है, तो उसे अपराध पर काबू पाने में कोई बाधा राजनीतिक पहुंच या बड़ी हस्ति होने की न खड़ी हो, इस पर शीघ्र नेतृत्व को ध्यान देना चाहिए।

विश्व की गम्भीर समस्याओं में प्रमुख है नशीले पदार्थों का उत्पादन, तस्करी और सेवन की निरंतर हो रही वृद्धि। नई पीढ़ी इस जाल में बुरी तरह कैद हो चुकी है। आज हर तीसरा व्यक्ति किसी न किसी नशे का आदी हो चुका है। गुजरात प्रांत में कुल शराबबन्दी है, क्योंकि वह महात्मा गांधी का गृह प्रदेश है। क्या पूरा देश गांधी का नहीं है? वे तो राष्ट्र के पिता थे, जनता के बापू थे। नशे की संस्कृति युवा पीढ़ी को गुमराह कर रही है। अगर यही प्रवृत्ति रही तो सरकार, सेना और समाज के ऊंचे पदों के लिए शरीर और दिमाग से स्वस्थ व्यक्ति नहीं मिलेंगे। एक नशेड़ी पीढ़ी का देश कैसे अपना पूर्व गौरव प्राप्त कर सकेगा?

बढ़ती नशा प्रवृत्ति के चलते महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। भावी पीढ़ी को बचाना है तो राजनीतिक दलों और समाज को मिलकर नशे के विरुद्ध अभियान चलाना होगा और पुलिस को भी युवाओं को मौत की ओर धकेलने वाली अपने भीतर की काली भेड़ों की पहचान करनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो युवा वर्ग नशे की दलदल में इतना फंस जायेगा जहां से उसे निकालना मुश्किल होगा। किसी भी महानगर का रात की बांहों में झूमना जीवन की शैली हो सकता है लेकिन नशे में झूमना एक कैंसर है। नशे की आदत कांच की तरह नहीं टूटती, इसे लोहे की तरह गलाना पड़ता है। पक्षी भी एक विशेष मौसम में अपने घोंसले बदल लेते हैं। पर मनुष्य अपनी वृत्तियां नहीं बदलता। वह अपनी वृत्तियां तब बदलने को मजबूर होता है जब दुर्घटना, दुर्दिन या दुर्भाग्य का सामना होता है। आखिर हम क्यों दुर्घटना, दुर्दिन या दुर्भाग्य का इंतजार कर रहे हैं? हजारों-लाखों लोग अपने लाभ के लिए नशे के व्यापार में लगे हुए हैं और राष्ट्र के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चमड़े के फीते के लिए भैंस मारने जैसा अपराध कर रहे हैं।

य ललित गर्ग

महाजन जी के बेटे राहुल महाजन भी थी उन्होंने धाराओं में गिरफ्तार हुए थे जिन धाराओं में आर्यन खान NCB द्वारा गिरफ्तार हुआ।

यानी एनडीपीएस एक्ट के 25 26 और 27 के तहत राहुल महाजन भी 06 महीने के लिए जेल गए थे।

लेकिन तब आपको पता भी नहीं होगा कि किस अधिकारी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। उस अधिकारी के बाप का क्या धर्म था। उस अधिकारी की पत्नी का क्या धर्म था, या उस अधिकारी की बहन कहां कहां घूम रही थी। उस वक्त किसी भी नेता ने NCB अधिकारी पर कोई इल्जाम या दबाव नहीं डाला।

संजय दत्त भी ड्रग्स मामले में 07 महीने जेल में थे। भारत के किसी भी पत्रकार को नहीं पता होगा कि कौन से अधिकारी ने संजय दत्त को गिरफ्तार किया था और उसके बाप का क्या धर्म था और उस अधिकारी का जन्म प्रमाण पत्र क्या था।

अरमान कोहली पिछले 08 महीनों से NCB की कस्टडी में जेल में बंद है, लेकिन कोई शोर शराबा नहीं, कोई आरोप नहीं, किसी NCB अधिकारी को जान से मारने की धमकी तक नहीं। ना किसी NCB अधिकारी के परिवार को टॉर्चर किया गया।

लेकिन जब आर्यन खान गिरफ्तार हुआ, तब पूरी महाराष्ट्र सरकार और खासकर नवाब मलिक अपने धर्म के उस असली कैरेक्टर पर आ गया है, यानी सीधे समीर वानखेड़े के परिवार के महिलाओं पर वार। देशभक्त अधिकारी समीर वानखेड़े के परिवारवालों को जान से मारने की धमकी मिल रही है।

आर्यन खान को उनके धर्म के वजह से NCB ने उसे फसाया, ऐसा आरोप नवाब मलिक कर रहा है। जब NCB ने संजय दत्त, राहुल महाजन, अरमान कोहली, और कई अन्य लोगों को भी तो ड्रग्स मामले में पकड़ा तब किसी ने ये आरोप नहीं लगाया कि उनके धर्म के वजहसे NCB ने उन्हें पकड़ा।

यह जब कमजोर हो जाते हैं, तब यह

देशभक्त अधिकारियों के घर के महिलाओं पर वार करते हैं।

NCB का दावा- डार्कनेट के जरिए किया गया था ड्रग्स का पेमेंट

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने शनिवार को बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े मामले में ड्रग्स के लेन-देन में डार्कनेट के इस्तेमाल का संकेत दिया है। समचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, एजेंसी ने आर्यन खान के इस नई खोज से जुड़े होने के बारे में कुछ नहीं कहा है।

क्या है डार्क नेट?

डार्क नेट गुप्त इंटरनेट पोर्टल है जिसे केवल विशिष्ट सॉफ्टवेयर, कॉन्फ़ीगुरेशन आदि के साथ ही एक्सेस किया जा सकता है। यह पहली बार नहीं है जब एनसीबी ने क्लोज की छापेमारी के तुरंत बाद डार्कनेट और बिटकॉइन का जिक्र किया है। हालांकि, अब एजेंसी ने दावा किया है कि किस तरह से डार्कनेट का इस्तेमाल किया गया है।

समाचार एजेंसी पीटीआई ने एनसीबी के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि एजेंसी ने आरोपी के पास से हाइड्रोपोनिक वीड जब्त किया है, जिसकी संख्या अब 20 है। इसे डार्कनेट के जरिए खरीदा गया था। एनसीबी ने छापेमारी के दौरान कथित तौर पर कुछ आरोपियों से एमडीएमए पाया था। अधिकारी ने कहा कि यह ड्रग्स ज्यादातर यूरोप और अमेरिका से मंगवाई जाती है। एजेंसी अब इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी ने इसे कहां से हासिल किया।

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स के साथ नहीं पकड़ा गया था, हालांकि एनसीबी उन पर एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप लगा रही है। तीन अक्टूबर को आर्यन सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किए जाने के बाद, एजेंसी ने कई छापे मारे। एक महीने में 12 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अचित कुमार भी शामिल है, जिसने हाल

समीर वानखेड़े पर रिश्त मांगने का आरोप

समीर वानखेड़े पर रिश्त मांगने का आरोप बचकाना लग सकता है लेकिन इस बचकाने टाइप के फिल्मी स्क्रिप्ट से आगे बहुत कुछ होने वाला है। आपलोग जल्द ही देखेंगे कि महाराष्ट्र की सरकार किस तरह से समीर वानखेड़े जैसे ईमानदार अधिकारी को हथकड़ी डाल कर जेल में ले जाते हैं। अर्नब गोस्वामी के ऊपर ऐसा ही एक FIR का केस निकाला गया था। आत्महत्या के लिए उकसाने वाला। हिरेन मनसुख भी याद ही होगा ? कंगना के ऊपर BMC का नोटिस लेकर कितनी बड़ी कार्रवाई हो गयी ? महाराष्ट्र और केंद्र की सरकार में वर्चस्व की लड़ाई उसी समय शुरू हो गयी थी जब सुशांत का केस आया था। उस वक़्त तो महाराष्ट्र की सरकार ही भारी पड़ी थी।

जांच करने आयी पुलिस से लेकर न्यूज दिखाने वाले रिपोर्टर तक को उठाकर लॉकअप में डाल दिया था। इसके बाद केंद्र ED के छापे मारकर संतुष्ट होता रहा। इस जीत से इधर हैसला मिला तो अम्बानी के घर तक सरकारी गुंडों को भेज दिया गया।

मौके की ताक में बैठे केंद्र सरकार ने इसे लपक लिया। फिर तो ऐसी रगड़ाई चालू किया कि अबतक सारे बाप-बाप कर रहे हैं। गृहमंत्री से लेकर

कमिश्नर तक का पता साफ हो चुका है। अभी भी सबको ना जाने कहां कहां भागना पड़ा रहा है।

इस हमले से ही महाराष्ट्र सरकार का हैसला पस्त हुआ वरना समीर वानखेड़े को कब का उठा लिया गया होता। लेकिन अब मरता क्या ना करता। बहुत बड़ा दवाब है। आर्यन को बचाने का।

हम लोग जिसे सिर्फ एक फिल्म स्टार का बच्चा समझ रहे हैं वो पहचान छोटी है। इसके पीछे दुनिया भर की ताकतें लगी हैं। हर तरह की।

अब रिश्त में झूठे आरोप पर पुलिस को स्वतः संज्ञान लेने का आदेश मिल गया है यानी वही होगा जो मैं सोच रहा हूँ। समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी तो ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम वानखेड़े जी का और अन्य ऐसे लोगों का पुरजोर समर्थन करें जो किसी भी क्षेत्र में सनातन या समाज में उचित न्याय के लिए वास्तविक प्रयास कर रहे हैं क्योंकि यदि अब हमने ऐसे समय में इनका साथ छोड़ दिया तो कभी कोई हमारे लिए बोलने अथवा खड़ा होने की हिम्मत शायद ही करेगा।

- अवधेश प्रताप सिंह

इन जिहादियों के खिलाफ चुप्पी खतरनाक होगी

बॉलीवुड, मीडिया और राजनीति के कुछ अड्डों से NCB के मुखिया समीर वानखेड़े के विरुद्ध जिहाद शुरू किया गया है। अचानक ऐसा क्यों हुआ है ?

दअरसल शाह्रुख खान के नशेड़ी कपूत की गिरफ्तारी के साथ ही कराची में बैठा आतंकी दाऊद और रावलपिंडी में बैठे ISI के सरगना बुरी तरह तिलमिलाए हुए हैं। वो समझ गए हैं कि NCB की कार्रवाई बॉलीवुड में उनके उन गुणों के गिरेबान तक पहुंच रही है, जिन गुणों के द्वारा वो बॉलीवुड को अपनी उंगलियों पर पिछले 3-4 दशकों से नचाते रहे हैं। NCB अब बॉलीवुड में उनके माफिया राज को बुरी तरह ध्वस्त करती जा रही है। यही कारण है कि उन्होंने भारतीय मीडिया, बॉलीवुड और राजनीति में जमे हुए अपने गुणों को NCB और उसके मुखिया के खिलाफ पूरी ताकत से सक्रिय कर दिया है। जरा याद करिए निकट अतीत के इन घटनाक्रमों को।

पिछले वर्ष जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के जो बिलबोर्ड अमेरिका के हॉलीवुड में लगे थे उनको कुछ ही घंटों में उतरवा दिया गया था। उन बिलबोर्ड को हटवाने में अजीज-उल-हसन अशाई उर्फ टोनी अशाई का नाम सामने आया था जो भारतीय मूल का कश्मीरी है और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूह जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का सदस्य रह चुका है।

अमेरिका में वो पाकिस्तान की उस खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट है जो पिछले 30 सालों से हिन्दूस्तान में आतंकी जिहाद चलवा रही है। भारतीय और अमेरिकी जांच एजेंसियों के दस्तावेजों में उसकी यह पहचान दर्ज है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि शाह्रुख खान और उसकी बीबी गौरी खान का बिजनेस पार्टनर भी यही टोनी अशाई है। (तथ्य की पुष्टि के लिए देखें कमेंट)।

आप समझ सकते हैं कि शाह्रुख खान जब जब अमेरिका गया तब तब उसके कपड़े उतरवा कर उसकी तलाश क्यों ली गयी ? उसने इस पर हल्का भी खूब मचाया। लेकिन अमेरिकी प्रशासन पर कोई असर नहीं पड़ा। किसी ने, खासकर सेवयुलरों और लुटियन मीडिया ने उससे कभी यह नहीं पूछा कि लता मंगेशकर अमिताभ बच्चन, धर्मेन्द्र सरीखे दिग्गजों से लेकर अक्षयकुमार और सनी देओल, सोनू निगम तक, दर्जनों भारतीय फिल्मस्टार एक नहीं अनेक बार अमेरिका गए हैं, लेकिन उनके कपड़े उतरवा कर उनकी तलाशी कभी क्यों नहीं ली गयी ? ISI का यही एजेंट जो शाह्रुख का जिगरी दोस्त और बिजनेस पार्टनर भी है, NCB की कार्रवाई से तिलमिलाया हुआ है। NCB को रोकने के लिए ISI सक्रिय हो गयी है। यही कारण है कि मीडिया,

बॉलीवुड और राजनीति का एक विशेष वर्ग NCB के खिलाफ जहर उगलने में जुट गया है। इससे पहले अफजल गुरु, याकूब मेमन, बटला हाऊस के आतंकीयों को बचाने के लिए भी दाऊद और ISI ने भारतीय मीडिया, बॉलीवुड और राजनीति में बैठे अपने गुणों का इस्तेमाल भारतीय सेना और भारतीय अदालतों पर दबाव बनाने के लिए किस तरह किया था ? उस शर्मनाक खतरनाक सच को पूरा देश देख चुका है। उस सच से भलीभांति परिचित है।

जनवरी में NCB ने ब्रिटिश नागरिकता वाले भारतीय मूल के करन संजानानी के मुंबई स्थित अड्डे पर छापा मार कर बहुत हाई मालिती का 2 विक्टल विदेशी गांजा बरामद किया था। यह गांजा अमेरिका से तस्करी कर के लाया गया था। करन संजानानी के उस नशे के अड्डे से मिले ठोस सबूतों के बाद शुरू हुई NCB की जांच में नवाब मलिक का दामाद समीर खान भी ठोस सबूतों के साथ NCB के हथके चढ़ गया था। NCB ने 11 जनवरी को उसे गिरफ्तार कर के जेल भेज दिया था। उसके खिलाफ NCB के सबूत इतने पुख्ता थे कि साढ़े 8 महीने तक कोर्ट ने उसे जमानत नहीं दी थी। 27 सितंबर को कोर्ट ने उसे जमानत इस शर्त के साथ दी है कि वो अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराए तथा कोर्ट की अनुमति के बिना मुंबई के बाहर नहीं जा सकता। साढ़े 8 महीने जेल में बंद रहने के बाद इन शर्तों के साथ कोर्ट द्वारा नवाब मलिक के दामाद समीर खान को दी गयी जमानत बताती है कि वो कितना मासूम और निर्दोष है ? समीर वानखेड़े द्वारा उसके खिलाफ की गई कार्रवाई कितनी सही या गलत है ? यही कारण है कि जब नवाब मलिक का दामाद गिरफ्तार हुआ था तब नवाब मलिक साढ़े 8 महीने तक चुप्पी तो साधे रहा था लेकिन समीर वानखेड़े के खिलाफ बुरी तरह तिलमिलाया हुआ था। लेकिन अब वो अपनी खीझ उतार रहा है। अपनी इस करतूत से वो NCB और समीर वानखेड़े के खिलाफ ISI और दाऊद इब्राहीम की मुहिम को भरपूर ताकत भी दे रहा है।

यह निर्णायक क्षण है। NCB और समीर वानखेड़े के खिलाफ नवाब मलिक और ISI तथा दाऊद इब्राहीम के जिहाद के खिलाफ चुप्पी तोड़िए। सोशलमीडिया पर उपरोक्त सच्चाई अधिकतम लोगों को जमकर बताइए। क्योंकि इन जिहादियों के खिलाफ हमारी आपकी चुप्पी बहुत खतरनाक होगी।

- सतीश चंद्र मिश्रा

मैं अधीर इसीलिए नहीं होता

खुद को किंग कहने वाला आज लटका हुआ मुंह लेकर आर्थर रोड जेल के दरवाजे पहुंचा तो यह पोस्ट लिख रहा हूँ।

ठीक एक वर्ष पहले की बात है। पिछले वर्ष इसी अक्टूबर माह में सुशांत की रहस्यमय मौत/हत्या। कंगना रनौत के रिवलाफ अहंकारी सत्ता का आततायी प्रदर्शन। उसी अहंकारी सत्ता द्वारा अरनब गोस्वामी के रिवलाफ नीचता और नंगई की सारी हदें पार कर जाने की घटनाओं से देश उबल रहा था। देश के आक्रोश की उस आग में महाराष्ट्र सरकार की नाक के नीचे, उसकी आंखों के सामने, उसके घेरे में पालघर में हुई निर्दोष साधुओं की निर्मम हत्या घी डाल रही थी। उस समय बड़ी संख्या में सोशलमीडिया में यह सवाल पूछे जा रहे थे कि केन्द्र सरकार क्या कर रही है? प्रधानमंत्री, गृहमंत्री चुप क्यों हैं?

उक्त प्रकरणों से संबंधित मेरी हर पोस्ट पर भी आक्रोश में डूबे ऐसे सवाल की अधिकता रहती थी? मैं यही कहता था कि धैर्य रविए। आज उन सवालों का उत्तर मेरे पास है। उन्हें क्रमवार यहां लिख रहा हूँ।

सबसे पहला तथ्य यह कि उपरोक्त चारों प्रकरणों के मुख्य खलनायक थे पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे, कमिश्नर परमबीर सिंह, गृहमंत्री अनिल देशमुख। इन तीनों ने ही उपरोक्त सभी षड्यंत्रों का धरातल पर क्रियान्वयन किया था, जिसके परिणामस्वरूप देश उबल उठा था। वाजे आज जेल में है, शतप्रतिशत सम्भवना यही है कि उसकी शेष जिंदगी भी अब जेल में ही गुजरेगी। परमबीर सिंह जेल जाने से बचने के लिए फरार हो चुका है। फिलहाल कहीं छुपा हुआ है और एक भगोड़े फरार अपराधी की जिंदगी जी रहा है। मुंबई पुलिस कमिश्नर सररीखे प्रतिष्ठा पूर्ण पद पर रहे व्यक्ति के लिए यह स्थिति चुहू भर पानी में डूब मरने से भी बदतर है। अनिल देशमुख भी फरारी की स्थिति में है। उसका और उसके सुपुत्र का जेल जाना भी निश्चित है। उसकी अवैध सम्पत्तियों को जांच एजेंसियां लगातार जब्त करती जा रही हैं। बाप बेटे की जिस जोड़ी के इशारों पर यह तीनों कठपुतली की तरह नाच रहे थे। उस जोड़ी के शर्मनाक हथ्र की कितनी कसी हुई पटकथा लिखी जा रही है। यह सच भी पूरा देश देखेगा। धूमधाम से ढोल नगाड़े के साथ देखेगा। बस थोड़ा धैर्य और रविए।

अब बात, सुशांत की राजपूत की। सच यह भी है कि सुशांत की रहस्यमय मौत हत्या रही हो या आत्महत्या। लेकिन उसका दोषी अपराधी कोई एक नहीं बल्कि बॉलीवुड का वही गैंग है जिसे NCB पिछले एक वर्ष से तिगनी का नाच नचा रही है।

किसी आम आदमी की अपेक्षा, अपने पत्रकार जीवन के कारण मैंने कई ऐसे प्रकरण देखे हैं जहां पुलिस या जांच एजेंसी को यह स्पष्ट समझ में आ रहा होता है कि हत्यारा कौन है? लेकिन उसे ठोस स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते। यही कारण है कि सुशांत की रहस्यमय मौत/हत्या की जांच



में छद्म अभी किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। जांच के दौरान मिले बहुत मजबूत साक्ष्यों के साथ बॉलीवुड के नशे के गोरखधंधे की डोर छद्म ने ही NCB के हथ में सौंपी थी। NCB के अधिकारियों की विशेष टीम भी दिल्ली से भेजी गयी। उसके बाद से NCB बॉलीवुड की नाक में लगातार दम किए हुए है। बॉलीवुड अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। जिस खान तिकड़ी के पेशाब से बॉलीवुड में चिराग जला करते थे। उस तिकड़ी का किंग खुद को कहने वाला आज किस हाल में है। खुद को सुपरस्टार किंग खान कहने वाला आर्थर रोड जेल में बंद अपने कपूत को बाहर नहीं निकालने के लिए तिलमिला रहा है। लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहा है। क्योंकि अब किसी का वह कांग्रेसी साम्राज्य नहीं है, जिसकी युवानी किंग खान के साथ पिक्चर देखने जाती थी। अखबारों में पहले पन्ने पर वह फोटो छपती थी। नशे का गोरखधंधा तो तब भी, बहुत पहले से बॉलीवुड की नसों में दौड़ रहा था। लेकिन गिरफ्तारी तो छोड़िए कभी पूछताछ तक नहीं होती थी इन सरगनाओं से।

इर का माहौल है... इर का माहौल है... चिल्लाने वाला कांग्रेसी टूलकिट का मास्टरमाइंड, तिकड़ी का दूसरा सरगना, बौना खान आज वास्तव में सहमा हुआ है, वास्तव में डरा हुआ है। जनता के प्रचंड क्रोध का बुलडोजर उसके धंधे पर जिस तरह चल रहा है, उसे देखकर बौना खान हिल चुका है। उसे अपनी तबाही सामने दिखायी दे रही है। यही कारण है कि अब असली इर से सामना होने के बावजूद बौना खान इर का माहौल है... इर का माहौल है... नहीं चिल्ला रहा है। मेरी बीबी देश छोड़कर भाग जाएगी, यह प्लान देश को नहीं बता रहा है।

तीसरे सरगना, नशेड़ी बौड़म खान के नशे के धंधे की जहरीली जड़ों पर NCB तेजाब डाल चुकी है। जनाने जौहर समेत लंबी सूची है बॉलीवुड के उन लोगों की जिनके प्राण NCB की कार्रवाई से कंठ तक आकर अटक चुके हैं। इसका कारण भी समझ लीजिए। भूसे के ढेर में सुई ढूँढने की तरह सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय हत्या/आत्महत्या का ठोस सुराग साक्ष्य ढूँढ रही CBI को यह उम्मीद है कि NCB की कार्रवाई के दौरान वह सुराग, वह साक्ष्य उसके हथ लग सकता है जिसकी उसे तलाश है, क्योंकि सुशांत की मौत की कहानी में ड्रग्स का एंगिल बहुत महत्वपूर्ण है।

इसलिए मैं साल भर पहले भी अधीर नहीं था। आज भी नहीं हूँ। क्योंकि उन लोगों पर मुझे विश्वास है, जिनकी यह जिम्मेदारी है कि पापियों को दंड मिले, मुझे विश्वास है कबीर के इस दोहे पर...

धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुठ होय।

माली सींचे सौ गड़ा, ऋतु आए फल होए॥

- सतीश चंद्र मिश्रा

ही में अदालत से कहा था कि उसे 'पेडलर' कहकर उसका भविष्य खराब किया जा रहा है। वकील ने अदालत को बताया कि वह महामारी

के कारण लंदन और भारत में एक विश्वविद्यालय में पढ़ता है। उसकी जमानत याचिका का एनसीबी ने भी विरोध किया है।

एजेंसी ने कहा कि उन्हें एक पेडलर नहीं कह रही है, बल्कि उनके खिलाफ इसके कुछ सबूत हैं।

किसान आंदोलन : क्या करें आमजन

● बी.एल. गौ

आज की राजनीति ने देश के हर नागरिक को चिंता की नदी में धकेल दिया है। प्रायः देखा गया है कि पूरे का पूरा मौहल्ला एक गुण्डे से डरता है और मौहल्ले के लोग उससे बच-बच कर चलते हैं, उसकी हर नाजायज बात मजबूरी में मानते हैं।

ठीक उसी तरह एक नेता के क्षेत्र के लोग अधिकतर नेता की बात मानते हैं, चाहे वह गलत ही क्यों न हो। इस सबका कारण है एक गुट, एक झुण्ड, एक विशेष भीड़ जो हर वक्त उसके साथ बनी रहती है और आप सभी जानते हैं कि भीड़ क्या क्या कर सकती है- रास्ते जाम कर किसी बीमार व्यक्ति को एम्बुलेंस में ही दम तोड़ने को मजबूर कर सकती है, किसी गर्भवती महिला का प्रसव एम्बुलेंस के फर्श पर ही करा सकती है। जाम में फंसी वाहनों की भीड़ भी ऐसे में असहाय हो जाती है, किसी की मदद करने में। और यह सब बातें अब आम आदमी की आये दिन की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। आदमी अब सोचने



लगा है कि उसकी दाद-फरियाद भी बेमानी है। उच्चतम न्यायालय कभी-कभी स्वयं संज्ञान लेकर कोई आदेश पारित कर भी दे तो उसे लागू कौन कराये। सो काल्ड किसानों के विषय में उच्चतम न्यायालय ने एक टिप्पणी की थी कि जब ये तीन कृषि कानूनों का मामला न्यायालय

में विचाराधीन है तो इस आंदोलन का औचित्य क्या है ? तो यह प्रश्न बस प्रश्न ही रहा। इसका कहीं पर भी कोई उत्तर नहीं है।

आज अपने देश के सबसे बड़े किसान नेता (लोग ऐसा कहते हैं) श्री महेन्द्र सिंह टिकैत ने फिर घोषणा कर दी है कि 18 अक्टूबर को हम रेल रोकेंगे।

अब देश या प्रदेश की सरकार उनका कुछ बिगाड़ सकती है तो बिगाड़ ले। उस प्रदेश या केन्द्र की सरकार इस मामले में बेचारी है। क्योंकि यदि उसने कोई कार्यवाही की तो एक और खीरी काण्ड हो जाएगा और साथ ही उसका वोट बैंक भी खिसक जाएगा।

टिकैत साहब की भीड़ में कुछ लोग 'भिण्डरावाले' की छपी हुई टी-शर्ट पहने और खालिस्तानी झण्डे में डण्डा लिए घुस जाएंगे और फिर कोई चाहे न चाहे, वे दो-चार हत्यायें तो कर ही जाएंगे। जिसे टिकैत साहब का मोर्चा कहेगा कि ये उनके लोग नहीं थे, ये तो असामाजिक तत्व थे। जिन्हें रोकने की जिम्मेवारी सरकार की थी, हम इसमें कहाँ जिम्मेवार हैं ? अरे भई जो 26 जनवरी को लालकिले पर हुआ था, वे भी हमारे किसान



गाजीपुर बॉर्डर की सर्विस रोड से बड़ा तंबू हटाया

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद हरकत में किसान, दिल्ली पुलिस से कहा- वह भी बैरीकेडिंग हटाए

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि किसान आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन रास्ता बाधित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने खुद ही गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाली सर्विस लेन पर रखे एक बड़े तंबू को हटा दिया है। भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अब दिल्ली पुलिस से भी अपील करते हुए कहा है कि वह अपनी 16 लेटर बैरीकेडिंग हटाएं, ताकि किसान दिल्ली जा सकें। हालांकि किसानों का कहना है कि वह तंबू हटाकर यह दिखाना चाहते हैं कि रास्ता उन्होंने नहीं रोक रखा। बता दें कि किसानों के धरने के चलते यह सर्विस लेन 26 नवंबर 2020 से बंद चल रही है। एक तरफ यूपी की सीमा में किसानों के टेंट लगे हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली की सीमा में पुलिस ने बैरीकेडिंग लगाई हुई है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि सड़कें साफ होनी चाहिए। आपको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन सड़क को जाम नहीं कर सकते। अब कुछ समाधान निकालना होगा। हालांकि किसान संगठनों की तरफ से वकील ने कहा कि हमने सड़क बंद नहीं की। सड़क पुलिस ने बंद की है, हम दिल्ली जाना चाहते थे। पुलिस यह महसूस करा रही है कि किसान सड़क जाम कर रहे हैं। हमें रामलीला मैदान में आने दें। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।

बाड़ तंबू हटाया, पुलिस भी अब बैरीकेडिंग हटाए

नहीं थे। हम तो केवल भीड़ जुटाते हैं, शेष हमारा काम तो ये असामाजिक तत्व ही करते हैं।

अब 18 तारीख को जगह-जगह रेल रोकी जाएंगी, जनता अपनी रक्षा स्वयं करे। अपनी रिजर्व कराई गई टिकट को कैंसिल कराए, किसी अपने की अंतिम फिया में भाग लेने जाना अगर जरूरी है तो बस या ट्रक आदि में बैठकर चली जाए। हम तो अपना अहिंसक आंदोलन करके ही रहेंगे। हम तो गांधी जी के अनुयायी हैं, हमें हिंसा से क्या मतलब। अब इसमें कोई संसार छोड़कर चला जाए तो चला जाए। जब तक सरकार तीन कृषि कानूनों को

सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का कुछ घंटे बाद ही यूपी-दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर असर दिखाई देना शुरू हो गया है। भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत के निर्देश पर किसानों ने नेशनल हाईवे-24 के नीचे वाली सर्विस लेन को खोलना शुरू कर दिया है। इसके लिए वह सड़क पर रखे बड़े तंबू को हटा रहे हैं। इस स्थान पर पूर्व में मीडिया सेंटर बना था और वहीं पर लंगर लग रहा था। यह लेन गाजीपुर मुर्गा मंडी की तरफ जाती है। किसानों ने सबसे पहले आंदोलन के दौरान इसी लेन को रोका और सड़क पर ही टेंट-तंबू गाढ़ लिए थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 16 लेटर बैरीकेडिंग लगाई थी, ताकि किसान आगे न बढ़ सकें।

राकेश टिकैत बोले- हमें संसद जाना है

इस बीच भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हमें दिल्ली जाना है। हमने कोई रास्ता नहीं रोक रखा है। रास्ते पुलिस ने रोके हैं। पुलिस अपनी बैरीकेडिंग हटाए। हमें संसद जाना है, जिसने कानून बनाए हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि सड़क चलने के लिए है, रोकने के लिए नहीं। हम यह दिखाना चाहते हैं कि रास्ता पुलिस ने रोका है, किसानों ने नहीं। इसलिए पुलिस अपनी बैरीकेडिंग हटाए और हमें दिल्ली जाने दे।



समाप्त नहीं करती तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे।

और फिर हमें चिंता किस बात की है। आदमी को जीवित रहने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है- रोटी, कपड़ा, और मकान। ये तीनों चीजें हमें हमारे दिल्ली की सीमाओं पर लगे मोर्चों को निशुल्क मिल रही हैं। भला हो उन 14 विपक्षी पार्टियों का जो हमारे इस आन्दोलन को सफल बनाने में मददगार हैं।

हम सरकार से तीन कानूनों पर वार्ता करने

को तैयार हैं लेकिन सरकार पहले तीनों कानूनों को निरस्त कर दे। फिर जो बचेगा हम उस पर वार्ता कर लेंगे। यह मत है किसान नेताओं का। सरकार से बात कर यह बताने को कोई तैयार नहीं है कि इन तीनों कानूनों में जो-जो गलत है, काला-काला है उसे हटा दे। अब उनका कहना है- हमें तो जो करना है करेंगे और सरकार को जो करना है करे।

जब भी कोई हारता है, वह अपनी से ही हारता है।



चीन और पाकिस्तान

हालात बिगाड़ने की जिद्द

● अमित त्यागी

चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव के बीच भारत की स्थिति जटिल हो गयी है। जैसे जैसे चीन अडियल होकर आक्रामक बन रहा है वैसे वैसे अमेरिका अपने क्षेत्रीय साथियों को साधकर कड़े प्रत्युत्तर की तैयारी में जुट गया है।

अमेरिका और चीन के बीच ताइवान एक प्रमुख तनातनी का केंद्र बनकर उभर रहा है। ताइवान के संदर्भ में अमेरिका एक लंबे समय से संतुलन साधने की कवायद करता आ रहा था किन्तु अब वह कवायद असफल होती दिखने लगी है। हिन्द प्रशांत क्षेत्र इस समय शक्ति संतुलन संक्रमण का प्रमुख केंद्र बन गया है। यह संक्रमण वर्तमान में इतना तेज है कि इससे

सामंजस्य बैठाने में क्षेत्रीय ताकतों को भी समस्या आ रही है। वर्तमान में ऐसा कोई संस्थागत ढांचा मौजूद नहीं है जो मध्यस्थता के माध्यम से टकराव दूर कर सके। सभी परिणाम नकारात्मक साबित हो रहे हैं। अन्तराष्ट्रीय स्तर पर ताइवान को बहुत ज्यादा तवज्जो मिल रही है। पिछले दो तीन दशक में ताइवान को इतना महत्व कभी नहीं दिया गया है। एक तरफ

जबसे अफ़ग़ानिस्तान से अमेरिका की वापसी हुयी है तबसे भारत की स्थिति अन्तराष्ट्रिय कूटनीति में बैकफूट वाली हो गयी है। अमेरिका के पीछे चलकर भारत चीन के साथ आमने सामने की लड़ाई ले रहा था। अमेरिका के भारत के साथ आने की वजह थी कि वह चीन के सबसे बड़े उत्पादक देश की छवि के सामने भारत की सबसे बड़े वैकल्पिक उत्पादक की छवि को खड़ा करना चाहता था। भारत और चीन दोनों ही जनसंख्या और संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध देश माने जाते हैं। एक तरफ अमेरिका भारत के माध्यम से चीन को नियंत्रित कर रहा था तो दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान की सहायता से भारत को नियंत्रित रख रहा था। इसके बाद जब कोरोना काल आया तो अचानक से शक्ति संतुलन गड़बड़ा गया। पूरे विश्व में एक नया समीकरण बन गया। अमेरिका में ट्रम्प की हार के बाद बाइडेन राष्ट्रपति बने जो भारत से ज्यादा चीन के करीबी दिखे। इसके बाद जब अफ़ग़ानिस्तान से अमेरिका की वापसी हुयी तो चीन के खिलाफ मुस्तैदी से खड़े भारत की हालत पतली हो गयी। इस बीच भारत में बेरोजगारी, महंगाई, किसान आंदोलन, ऊर्जा संकट जैसे विषय तेज़ी से उभरने लगे जिससे भारत की स्थिति पहले से कमजोर हुयी। आंतरिक गतिरोध ज्यादा उभरने लगे। चीन के खिलाफ भारत की आत्मकता पर लगाम लग गयी। अमेरिका का पिछलग्गू बनना भारत को कमजोर कर गया। अब इन कमजोरियों के बीच चीन और पाकिस्तान भारत को प्रत्युत्तर देने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। अब चाहें वह सीमा पर विवाद का विषय हो या सीमा पर घुसपैठ का। चाहें, भारत के अंदर विरोध का तंत्र खड़ा करने का विषय हो या आंतरिक आंदोलन को वैश्विक परिदृश्य पर उठाने का, हर तरफ से भारत के लिए चुनौतियाँ बढ़ रही हैं। अनियंत्रित होती महंगाई और बेरोजगारी के कारण जनता में आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। विपक्षी दलों को यह मुद्दे रास आ रहे हैं और वह प्रमुखता से इन मुद्दों को उठा रहे हैं। चूँकि, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव हैं इसलिए हर छोटा बड़ा विषय कब चुनावी मुद्दा बन जाएगा, यह कहा नहीं जा सकता है। मौसम के कारण भी जनता की परेशानियाँ बढ़ रही हैं। असमय बरसात ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी नुकसान किया है। इसके द्वारा भी महंगाई बढ़ेगी। तेल और गैस की कीमतें पहले से आसमान छू रही हैं। चूँकि, वैश्विक स्तर पर चीन ने अपनी नयी नीतियों के अंतर्गत अपना उत्पादन कम करने का लक्ष्य रखा है इसलिए इसका असर वैश्विक महंगाई पर पड़ेगा। वर्तमान में चीन के उत्पादों पर ज्यादातर देशों की मांग टिकी हुयी है। चूँकि, चीन द्वारा आपूर्ति सीमित होगी इसलिए इसका सीधा असर उनकी कीमतों पर पड़ेगा। भारत के संदर्भ में देखें तो बुखार की दवाई पैरासिटामॉल के लिए भी हम चीन पर निर्भर हैं। ऐसे में भविष्य में जो देश अपनी जरूरतों के लिए चीन पर कम निर्भर रहेंगे उनके लिए अपने देशों के आंतरिक गतिरोधों को भी संभालना आसान होगा। चीन स्वयं भी अपने आंतरिक गतिरोधों में उलझा है। उसके अंदर के हालत भी अच्छे नहीं हैं। चीन ने बीआरआई के अंतर्गत आने वाली ढांचगत परियोजनाओं को रोक दिया है। उसकी रियल एस्टेट कंपनी एवरलैंड पर वित्तीय संकट है। चीन में ऊर्जा संकट के कारण वहां की औद्योगिक इकाइयों के सामने चुनौतियाँ हैं। पर इन सबके बीच चीन और पाकिस्तान अब लगातार भारत को सीमा पर और आंतरिक गतिरोधों के आधार राजनीतिक स्तर पर घेरने में कामयाब होते दिख रहे हैं।

ताइवान के पक्ष में सकारात्मक माहौल बन रहा है वहीं चीन की साख लगातार घट रही है। इस कारण चीन ताइवान के संदर्भ में आक्रामक होकर सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी कर सकता है। इन सबके बीच बाइडेन और जिनफिंग ने परस्पर सहयोग से ताइवान समझौते पर सहमति जताई है। इसका निहितार्थ साफ है कि अमेरिका वन चाइना नीति का समर्थक हो रहा है। वह ताइवान के बजाय चीन को महत्व और मान्यता दे रहा है। यह ट्रम्प के जाने के बाद का बड़ा बदलाव है। ट्रम्प के राष्ट्रपति काल में उनकी और चीन की टकराहट आमने सामने से होती रही थी। पर बाइडेन के आने के बाद चीन और अमेरिका के बीच अब उस तरह की तल्लिखयाँ नहीं दिखती हैं। अफ़ग़ानिस्तान के विषय पर भी अमेरिका और चीन के आपसी हित कहीं नहीं टकराए, बस यही से भारत के लिए खतरे की घंटी की शुरुआत होती है।

भारत की आक्रामक विदेश नीति अचानक



बस इतना समझिये कि इनको समस्या सिर्फ भाजपा सरकारों से हैं

जानकर या अंजाने में यह तो नहीं कहा जा सकता है किन्तु बॉलीवुड चीन के खेमे में खेल ही जाता है। कितनी क्रांतिकारी बात है यह लोग देश में परिवर्तन लाने के लिए आर्यन खान के साथ हैं। इस मासूम के बाप शाहरुख खान के साथ हैं। बस इतनी सी बात है। आप लोग जाने क्यों यह छोटी सी बात समझ नहीं पा रहे। जैसे भी हो देश में परिवर्तन बहुत जरूरी है। परिवर्तन मतलब सत्ता परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन मतलब महाराष्ट्र में नहीं, राजस्थान, पंजाब, बंगाल, छत्तीसगढ़ में नहीं। सत्ता परिवर्तन मतलब केंद्र में। उत्तर प्रदेश में। आदि-इत्यादि में। जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब अगर किसी अखबार या पत्रकार से नाराज होते थे तब एफ आई आर वगैरह के झमेले में नहीं पड़ते थे। सीधे हल्ला बोल देते थे। शह-दर-शह। अखबार के दफ्तर, पत्रकार यहां तक कि हॉकरों तक पर। बिचारे गरीब हॉकर सुबह-सुबह अखबार बांटने निकलते थे और पिट-पिटा कर घर पहुंचते थे। अखबार फेंक कर सपाईं गुंडों से जान बचाते थे। जब तक अगला सरेंडर न कर दे तब तक यह हल्ला बोल चालू रहता था। बाद के दिनों में अखबार मालिक पूरी तरह शरणागत हो गए। अखबार मालिकों, चैनल मालिकों से उन की गहरी दोस्ती हो गई। कभी-कभी कोई नवधा पत्रकार अप्रिय सवाल पूछ लेता गलती से तो वह डपट कर पूछते किस अखबार से हो, किस चैनल से हो ? दूसरे ही दिन उस की नौकरी चली जाती थी। मायावती ने तो बिना किसी पूछताछ या डॉट डॉट के ही इसी तरह कई पत्रकारों की नौकरी खाई। एक अयोधित आतंक था मायावती और मुलायम का तब और आज भी वह बदस्तूर जारी है। इसी लिए इन के रिवलाफ न कभी कोई खबर चलती है, न छपती है। मीडिया मालिकों को लगता है कि जाने कब इन लोगों की सत्ता में वापसी हो जाए तो मुश्किलें बढ़ जाएं। सो स्वामीश ! उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना भी कमोवेश हल्ला बोल वाली कारंशैली के हामीदार हैं। पर एक तो अर्णब गोस्वामी को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है दूसरे, केंद्र सरकार से ठाकरे सरकार के रिश्ते बेहद खराब हैं। तो यह लगाम लगी हुई है। हल्ला बोल की जगह चोर-सिपाही की तरह एफआईआर, एफआईआर खेल रही है। तो यह एफआईआर नहीं है, यह उद्धव ठाकरे का हल्ला बोल है।

गजब यह कि कल शाहरुख खान के कसीदे लिखने वाले कुछ पेड न्यूज वर्कर लुक हुए तो आज समीर वानखेड़े को बकअप करने वाले भी बहुतायत में उतर आए। समीर की बहन की मुंबई एयरपोर्ट की फोटो बता कर नवाब मलिक ने खुद को नंगा कर लिया। जया बच्चन की थाली में छेद करने वाले राज्यसभा के भाषण की भी तफ़्तीश बस हुआ



ही चाहती है। शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान पूरी महाभारत करवा कर ही मानेगा। और जो सब कुछ इसी स्पीड और इसी धार से चलता रहा तो बहुत मुमकिन है कि आर्यन खान की दीपावली भी जेल में मने। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक सहित कुछ लोग ऐसे ही बयानबाजी में हमलावर रहे तो समीर वानखेड़े पर प्राणघातक हमला भी हो सकता है। बीते बरस जैसे सुशांत सिंह राजपूत प्रसंग पर रिया चक्रवर्ती के पक्ष में सेक्यूलर चैंपियंस खुल कर बैटिंग कर रहे थे, कुछ-कुछ उसी तर्ज पर आर्यन खान प्रसंग में भी यही सेक्यूलर चैंपियंस आर्यन के लिए बैटिंग करते हुए समीर वानखेड़े पर हमलावर हैं। दिलचस्प यह कि रिया चक्रवर्ती मंडली के रिवलाफ चार्जशीट भी फ़ाइल होने के लिए फड़फड़ा रही है। क्या पता इग्न रैकेट के यह दोनों मामले क्लब हो जाएं। दाऊद गैंग भी नाकायमयाब हो गया दीखता है। लड़ाई आर-पार की होने जा रही है। आर्यन अब बस एक मोहरा है। निशाने पर कुछ और लोग हैं और उन का बिखरता रैकेट है। नवाब मलिक की फड़फड़ाहट को इस दीवार पर लिखी इबारत के रूप में भी पढ़ने की जरूरत है। मामला बिलकुल कौरव, पांडव के युद्ध में तब्दील है। युद्ध के शंख का उद्घोष बस होना ही चाहता है। कृष्ण बन कर कौन उपस्थित होता है, यह देखना शेष है। समीर की मां मुस्लिम हैं, इस पेंच से बेखबर लोगों का सेक्यूलर कार्ड भीग कर लुगदी हो गया है। कुल जमा यह कि समर अभी शेष है।

- दयानन्द पांडे

से बैकफुट पर चली गयी दिखती है। अब चीन ने भारत की सीमाओं पर अपनी सेना बढ़ा दी है और भारतीय सीमा में घुसने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अरुणाचल प्रदेश पर फिर से दावा शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को उकसाकर पाकिस्तानी क्षेत्र से भी भारत पर दवाब बढ़वा दिया है। जम्मू कश्मीर सीमा पर पाकिस्तानी गोलाबारी बहुत



तेजी से हो रही है। भारत के कई सैनिक शहीद हो चुके हैं। ऐसे में भारत के लिए पाकिस्तान और चीन दोनों से युद्ध के हालात बन गए हैं। अब तक भारत चीन को उकसा रहा था किन्तु अब चीन भारत को उकसा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी ललकार रहा है। जम्मू कश्मीर में भी हालात थोड़े बेकाबू होते दिख रहे हैं। 370 के बाद जम्मू कश्मीर क्षेत्र में एक

नयी ऊर्जा का आगाज हुआ था किन्तु अब वहां काफी समय से शांत दिख रहे असामाजिक तत्व उभरने लगे हैं। हजारों लोगों का पलायन भी हुआ है। भारत के आंतरिक गतिरोधों के इस दौर में चीन और पाकिस्तान ऐसा कोई मौका नहीं चूकना चाहते हैं जिसमें वह भारत को कमजोर

कर सकें। या भारत में कोई ऐसी सरकार बनवा सकें जो उनके अनुकूल हो। भारत ने अपनी आक्रामक विदेश नीति के कारण अब स्वयं को ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है जहां अब पीओके में कोई छोटा युद्ध आवश्यक दिखने लगा है। पीओके इसलिए लगता है क्योंकि चीन

से युद्ध की स्थिति में हम नहीं है। जब तक हमारे ऊपर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प का हाथ था तब तक चीन से शक्ति संतुलन साधने में हम अमेरिका का मोहरा थे। ट्रम्प के जाने के बाद अब हम चीन से सीधे सामना करने की स्थिति में भी नहीं है।

मोदी बनाम इमरान, इमरान ने बेचे करोड़ों के उपहार

पड़ोसी इस्लामी जम्हूरियाये पाकिस्तान के वजीरे आजम खान मोहम्मद इमरान खान पठान के विषय में कराची दैनिक (जिन्ना द्वारा स्थापित) 'दि डान' की खबरों के अनुसार विदेश की यात्रा पर इमरान को करोड़ों रुपयों के उपहार मिलते हैं। उन्होंने उसे दुबई में बेचकर अकूत धन कमाया। सरकारी नियम है कि राष्ट्रनायकों को मिले उपहारों को सरकारी खजाने में जमा करना पड़ता है। इमरान ने इस कानून की सरेआम अवहेलना की और निजी मुनाफे में जोड़ लिया। पाकिस्तान प्रतिपक्ष की नेता मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के अनुसार खाड़ी राष्ट्र के एक अरब शाहजादे ने इमरान को एक कीमती घड़ी पेश की थी, जिसे उन्होंने दूसरे अमीर अरब को बेचकर दस लाख डॉलर (70 लाख रुपये) कमा लिये। नियम यह है कि केवल दस हजार से कम का उपहार साध ले जा सकते हैं। इमरान के विशेष सचिव शाहबाज गिल ने बताया कि राष्ट्रीय सूचना आयोग के आदेशानुसार यदि प्रधानमंत्री के मिले उपहारों की कीमत सार्वजनिक कर दी जाये तो राष्ट्र के गौरव को धक्का लगेगा। अब जानने की कोशिश करें कि भारतीय प्रधानमंत्रियों को भेंट में मिली वस्तुओं का क्या होता रहा है ?

नरेन्द्र दामोदरदास मोदी ने निहायत सावधानी बरती है। अभी कुछ दिन पहले मोदी ने अपने समस्त उपहारों का ईआक्शन (आनलाइन नीलामी) कर दिया था। जितनी राशि मिली सब गंगा सफाई अभियान फण्ड (नमामि गंगे) में दे दिया। पास कुछ भी नहीं रखा। इमरान खान और नरेन्द्र मोदी की समता तो हो ही नहीं सकती। इसी संदर्भ में कुछ पुराने उदाहरणों का विवरण जान लें। वह दौर था साठ और सत्तर के दशकों का। कम्युनिस्ट सोवियत रूस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रनायकों में प्रतिस्पर्धा थी कि किसका वर्चस्व नयी दिल्ली पर जमे। रूसी गुप्तचर संस्था केजीबी तब इन्दिरा काबीना के मंत्रियों को सूचना का स्रोत बनाने में जुटी थी। यह आरोप भी लगा था एक मंत्री पर कि वह सीआईए का इन्फार्मर है। उधर भारत की दोनों कम्युनिस्ट पार्टियां सरकारी सूचना लीक करने के एवज में केवल चन्द वोडका बोतलों पर ही संतुष्ट हो जाती थी। उस वक्त राष्ट्राध्यक्षों को बेशकीमती उपहार देने का जबरदस्त चलन था। तब की एक दुखद घटना है। जवाहर लाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। इन्दिरा गांधी उन दिनों मास्को की यात्रा पर गयीं। रूसी प्रधानमंत्री तथा सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के प्रधान सचिव निकिता ख्रुश्चेव ने इन्दिरा गांधी को एक मूल्यवान मिक कोट भेंट किया। मिक एक प्रकार का ऊदबिलाव होता है। इसके महीन रोयें से बुना कोट था यह। यह अत्यधिक



आकर्षक होता है। इसे केवल अत्यंत धनाढ्य कुलीन जन ही पहन सकते हैं। कभी रानी महारानी उपयोग किया करती थीं। इन्दिरा गांधी इसको लेकर दिल्ली लौटीं, मगर तोशखाना में जमा नहीं किया। मामला लगातार लोकसभा में उठा। तूफान खड़ा करने वाले थे कन्नौज के सोशलिस्ट सदस्य डा. राममनोहर लोहिया। मुद्दा कई बार उठा। सदन में हंगामा होता रहा। अंततः कुछ वरिष्ठ कांग्रेसियों ने लोहिया को मनाया कि काफी हानि इन्दिरा गांधी की प्रतिष्ठा को हो चुकी है। अतः विवाद का अंत हो। लोहिया का नेहरू परिवार से पुराना नाता था। वे मौन हो गये। फिर परिवेश महिला से था, लोहिया स्वाभावतः नारी के पक्षधर रहे।

लेकिन बुनियादी सवाल फिर भी बना रहा कि लाखों रुपयों का कीमती कोट को निजी संपत्ति कैसे बना दिया गया ? तोशखाना में क्यों नहीं जमा किया गया ? हालांकि यह गम्भीर आर्थिक अपराध है। इमरान खान फंस गये। मोदी ने उपहार की विक्रय राशि सरकार या जन फंड में (नमामि गंगे) जमा कर दी। किन्तु तोशखाना की भांति सरकारी धनराशि का अपव्यय तो अब बेहिकक हो रहा है। एक बार जवाहरलाल नेहरू ने राजीव गांधी और संजय गांधी को लंदन में उच्च शिक्षा हेतु भेजना चाहा था। दोनों ने सरकारी ऋण हेतु आवेदन किया। तब वित्त मंत्री ने अपनी आपत्ति फाइल में दर्ज करा दी कि दोनों किशोर इतने स्तर तक भारत में शिक्षित नहीं है कि उन्हें उच्च शिक्षा हेतु राजकीय मदद देकर विलायत भेजा जाये। इन्हीं वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री को सचेत किया था कि ब्रिटिश

प्रकाशकों द्वारा प्रदत्त परिश्रमिक पर आयकर न जमा करना एक गंभीर आर्थिक अपराध है। सजा हो सकती है। नेहरू को भुगतान करना पड़ा। मोरारजी देसाई के हटने के बाद ऐसी कठिनाई किसी राजनेता को नहीं हुयी। यहाँ स्मरण हो आता है मौर्यकाल के मगध का। एक निजी व्यक्ति अपने मित्र अर्थशास्त्री कौटिल्य से पाटलिपुत्र के उपनगर में मिलने आया। तब सम्राट चन्द्रगुप्त के ऐश्वर्य सम्पन्न साम्राज्य के महामात्य एक लालटेन की रोशनी में कुछ लिख रहे थे। फिर उसे बुझाया, दूसरी जलाया और मित्र से बात करने लगे। चकित सुहृद ने इस हरकत का कारण पूछा ? चाणक्य बोले, अब रोशनी मेरे निजी उपयोग की है तो राजकीय लालटेन नहीं जल सकती है। इसी कौटिल्य ने कहा था कि 'राजपुरुष कब सरकारी धन खा ले और मछली कब पानी पी ले, इसे जानना असंभव है।' मोदी के पास में भी इसको भांपने का कोई उपाय अथवा ग्रंथ नहीं है।

-के विक्रम राव

भारत की असली ताकत!

जिस बात को लेकर मैं पिछले दो वर्षों से डर रहा था वो बात अब खुलकर अमेरिकन थिंक टैंक ने कह दी है।

मेरा मानना था कि अमेरिका की मंशा चीन को नेस्तनाबूद करने के लिए भारत को इस्तेमाल करने की थी। अमेरिका प्यार जता कर भारत को उकसा रहा था ताकि भारत जोश में आकर चीन पर हमला कर दे। इससे अमेरिका को कई फायदे थे।

1. चीन जिस हिसाब से तरछी कर रहा था, यह बात पक्की थी कि 2030 के आते आते चीन अमेरिका पर अपना प्रभुत्व कायम करने में कामयाब हो जाता। इसे न्यूट्रलाइस करने के लिए उसे पाकिस्तान जैसे किसी बेवकूफ की जरूरत थी जो वो भारत में देख रहा था।

2. भारत को उकसा कर अमेरिका चीन के साथ भारत का युद्ध करवाना चाहता था ताकि चीन तो चीन विश्व की उभरती हुई दूसरी ताकत भारत भी चीन के साथ बर्बाद हो जाये और अमेरिका के पुराने कंटेंट के साथ साथ आने वाला कांटा भी निकल जाए।

3. इस लड़ाई के शुरू होने के बाद मदद के तौर पर भारत को अमेरिका भर कर अपने हथियार बहुत महंगे दामों पर बेचने के लिए भी बेताब था।



4. भारतीय अर्थव्यवस्था से बर्बाद होने के बाद एक बार फिर से ब्रेन ड्रेन चालू हो जाता और भारतीय वैज्ञानिक जो मोदी के स्टार्टअप के चलते भारत में रुकने लगे हैं फिर से अमेरिका के लिए काम करने लगते।

अब आज को ही लो। भारत के मुंबई के IIT ने एक ऐसी SUV (Triton सोलर) ने बनाई है जो इलेक्ट्रिक पर चलेगी और एक बार के चार्ज में 1200 किलोमीटर तय करेगी।

इससे टेस्ला की बाट तो

लगेगी ही जो 700 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज पर ही इतरा रही है।

एक दूसरे स्टार्टअप ने नई टेक्निक खोजी है जो मात्र 7 से 15 मिनट में कार पूरी चार्ज कर देगी।

इन सभी बातों से अमेरिकन थिंक टैंक ने अमेरिकन नेतृत्व को वार्निंग जारी की है कि भारत को मदद दे कर चीन को तबाह करते करते कहीं चीन से भी ज्यादा भारत को ताकतवर देश न बना दे।

अतः मोदी को देश हित में सावधान रहने की जरूरत है।

- चंद्र मोहन अग्रवाल

इसी वजह से जब अभी 10 अक्टूबर 2021 के दिन भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच कोर कमांडर स्तर की बात हुयी तो इस बार चीन के तेवर काफी अलग थे। चीन के अडिगल और अक्खड़ रवैये के कारण लद्दाख के चूसुल मोल्डो इलाके में चली इस बैठक का नौ घंटे में भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। इस बैठक के बाद दोनों पक्षों की तरफ से इस तरह के गरम बयान आए जिससे स्पष्ट हो गया कि इस बार की सर्दियां गरम हो सकती हैं। भारत जब जब लद्दाख क्षेत्र में आक्रामक होता है तो चीन पूर्वोत्तर में सरगर्मियां तेज कर देता है। कुछ दिन पहले अभी 16 सितंबर को दुशाम्बे में दोनों देश के विदेश मंत्रियों की बैठक में दोनों पक्षों में सहमति बनी थी कि दोनों देश बातचीत से सीमा तनाव कम करेंगे। चीन का रवैया अब बिलकुल बदल गया है। उसने उत्तराखंड के बाराहोती में घुसपैठ की। अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिक 5 किमी अंदर घुस आए थे। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की अरुणाचल यात्रा का चीन ने

विरोध किया। जबकि गलवान घाटी की घटना के बाद दोनों देशों में तनाव कम करने के लिए जब फरवरी 2021 में वार्ता हो चुकी थी उसमे इस बात पर सहमति बनी थी कि भारत कैलाश मानसरोवर वाले पेंगांग सो इलाके से अपने सैनिक वापस हटा लेगा और चीन लद्दाख के देप्सांग और हाट स्पिंग इलाके से अपनी सेना को वापस बुला लेगा। अब ऐसा लगता है कि चीन भारत को उकसा रहा है कि भारत कैलाश मानसरोवर की चोटियों को कब्जाने जैसा कोई कदम उठाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान से भारत की सीमा पर गोलीबारी चल रही है। भारत के अंदर के हालात सरकार के हाथ से बाहर जा रहे हैं। बढ़ती महंगाई और तेल की कीमतों के कारण जनता का ध्यान इन विषयों की तरफ न गया है न जाने वाला है। यह सरकार के सामने एक नयी तरह की चुनौती है जिसमे चीन आंतरिक गतिरोध को बढ़ावा देकर भारत में अपने मन माफिक सरकार बनवाना चाहता है। पाकिस्तान के द्वारा सीमा पर गोलीबारी और

चीन से वार्ता का बेनतीजा रहना यहां से समझ आता है।

आंतरिक संकटों से धिरता चीन -

चीन आंतरिक तौर पर कई संकटों से जूझ रहा है। चीन के अंदर वित्तीय भ्रष्टाचार भी इस समय चरम पर है। चीन की आर्थिक स्थिति डांवाडोल होने का प्रभाव सम्पूर्ण विश्व पर पड़ता है क्योंकि चीन एक बड़ा निर्यातक देश है। ज्यादातर देशों में स्वनिर्मित होने वाली वस्तुओं का कच्चा माल भी चीन से आता है। जैसे भारत में बुखार की दवाई पैरासेटामॉल के लिए भी हम चीन पर आश्रित हैं। वैश्विक परिदृश्य का ताना बाना कुछ ऐसा बन गया है कि देशों में आपसी सामंजस्य बिगड़ने पर आर्थिक सामंजस्य बिगड़ जाता है। चीन वर्तमान में तीन गंभीर संकटों से जूझ रहा है। पहला, विश्व के तमाम देशों में चीन द्वारा चलायी जा रही ढांचागत परियोजनाएं निरस्त की जा रहीं हैं। दूसरा, चीन की रीयल एस्टेट कंपनी एवर ग्रैंड पर वित्तीय संकट दिख रहा है। तीसरा,



चीन को खरी-खरी सुनाने का समय

अधिकार जताने का उसे न तो कोई नैतिक अधिकार है और न कानूनी।

अब तर्कसंगत यही है कि भारत तिब्बत पर चीन के अधिकार को अमान्य ठहराते हुए सीमा का फिर से मूल नामकरण करके उसे 'भारत-चीन सीमा' के बजाय 'भारत-तिब्बत सीमा' कर दे। चीन को बता दिया जाए कि यदि इस सीमा पर कोई विवाद है तो उसे तिब्बत के मूल शासक दलाई लामा और तिब्बती जनता के साथ बातचीत में हल किया जाएगा, चीन के साथ नहीं। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी ताइवान की राष्ट्रपति जैसा साहस दिखाना चाहिए, जिन्होंने चीन की धमकियों के जवाब में इन्के की चोट पर कहा कि ताइवान एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है, जिसमें चीनी हस्तक्षेप सहन नहीं किया जाएगा। यदि मोदी सरकार भारत-तिब्बत सीमा के सवाल पर ऐसा कदम उठाती है, तो तय है कि चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग अपना संतुलन खो बैठेंगे।

यह ध्यान रहे कि गलवन टकराव में अपने 40 से अधिक जवानों के मरने और गलवन से लेकर दौलतबेग-ओल्डी तक कब्जा करने की चीनी योजना के ठप होने के बाद चीनी राष्ट्रपति की छवि को बहुत आघात पहुंचा है। शी चिनफिंग का इरादा पश्चिमी लद्दाख पर कब्जा करके चीन के कराकोरम हाईवे को भारतीय दबाव से हमेशा के लिए मुक्त करा लेना था। इसकी आड़ में वह चीन का नया हीरो बनने और 2022 में चीन का आजन्म राष्ट्रपति बने रहने की जुगत लगाए हुए थे।

गलवन प्रकरण के बाद 2020 की सर्दियों में लद्दाख में चीनी सेना की तैनाती के अनुभव के बाद शी और उनके जनरलों को यह समझ आ चुका है कि शून्य से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान में भारतीय सैनिकों का मुकाबला करना पाना चीनियों के बूते से बाहर है। सिराचिन में बरसों से सक्रिय भारतीय सेना के पास वहां की कठिन परिस्थितियों में कौशल दिखाने वाले सैनिकों की संख्या हजारों में है। पिछली सर्दियों में कितने चीनी सैनिक और अफसर बिना लड़े सर्दी के कारण मारे गए, इस सवाल पर चीन चुप्पी साधे हुए है। शायद इसीलिए चीन ने अपने कब्जाए हुए तिब्बत के युवाओं को सेना में भर्ती करने का नया अभियान शुरू किया है।

इसके अलावा चीनी सेना ने पिछले कुछ महीनों में अपना पूरा जोर थल सेना के बजाय लद्दाख के आसपास वाले तिब्बती और शिनजियांग क्षेत्रों में नए हवाई ठिकानों और मिसाइलों आदि पर लगा दिया है। इस इलाके में एक साल के भीतर तीन बार अपने जनरलों को बदलकर भी शी ने अपनी बदहवासी का ही परिचय दिया है। अगर शी के कोर कमांडर भारतीय सेना के साथ किसी सहमति या शांतिपूर्ण हल निकालने के बजाय धमकियों और आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो भारत को समझ लेना चाहिए कि चीन के इरादे नेक नहीं हैं। अगर लद्दाख में आने वाली सर्दियां युद्ध की गरमी लाती हैं तो भारत को इसके लिए तैयार रहना होगा। इसमें किसी भी किस्म की लापरवाही के लिए कोई गुंजाइश नहीं।

विजय क्रांति

(लेखक तिब्बत एवं चीन मामलों के विशेषज्ञ और सेंटर फॉर हिमालयन एशिया स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन हैं)

भारत और चीन के रिश्तों पर नजर रखने वाले कुछ अति आशावादियों को उम्मीद थी कि 10 अक्टूबर को भारतीय और चीनी सेना के कोर कमांडरों की 13वीं बैठक में शांति का कोई रास्ता निकलेगा और 17 महीने से लद्दाख में चल रहे सैनिक तनाव में कुछ कमी आएगी, लेकिन चीनी पक्ष के अक्सर रवैये ने इन सब उम्मीदों की तेरहवीं कर डाली। लद्दाख के चुसुल-मोल्डो इलाके के उस पार नौ घंटे चली इस बैठक में किसी भी तरह की सहमति नहीं बन पाई। उल्टे दोनों पक्षों की ओर से दिए गए बयानों ने स्पष्ट कर दिया कि आने वाली सर्दियों में सीमा किसी भी हद तक गरम हो सकती है। ताजा वार्ता से कुछ लोगों की आशा अकारण भी नहीं थी। इससे पहले 16 सितंबर को दुशाबे में विदेश मंत्रियों की बैठक में दोनों पक्षों के बीच यह सहमति बन चुकी थी कि सीमा पर चल रहे तनाव को कम किया जाएगा, लेकिन अब चीन के रवैये से यही लगता है कि वह तभी झुकेगा, जब कैलास चोटियों को कब्जाने जैसा कोई कदम उठाया जाएगा।

गत वर्ष गलवन की घटना के बाद दोनों देशों के बीच सैनिक तनाव कम करने के लिए इस साल फरवरी में भारत-चीन वार्ताओं में जो सहमति बनी थी, उसके तहत भारत ने फेंगगोंग-सो इलाके में कैलास चोटियों से अपने सैनिक और हथियार इस उम्मीद से हटा लिए थे कि चीन भी लद्दाख के देपसांग और हाट-स्पिंग्स में घुस आई अपनी सेना को टकराव से पहले वाली जगहों पर वापस ले जाएगा। ये चोटियां ऐसी थीं जिन पर भारतीय सेना के जांबाज तिब्बती सैनिकों वाली स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने कब्जा करके पूरे इलाके का सैनिक संतुलन भारत के पक्ष में कर दिया था।

हाल की वार्ता से ठीक पहले चीनी सेना ने उत्तराखंड के बाराहेती में जिस तरह घुसपैठ की और अरुणाचल सीमा पर 30 अगस्त को लगभग दो सौ चीनी सैनिक पांच किमी तक घुस आए, उससे यह साफ हो चुका था कि सीमा पर तनाव घटाने में चीन की कोई रुचि नहीं है। शांति की बची-खुची उम्मीद को चीन के उस बयान ने भी खत्म कर दिया, जिसमें उसने अरुणाचल पर अपना दावा दोहराते हुए भारतीय उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू की वहां की यात्रा का विरोध किया। इससे पहले एपीजे अब्दुल कलाम, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री की अरुणाचल यात्राओं के समय भी चीन हायतौबा मचाता रहा है। ऐसे हर मौके पर चीन सरकार की दलील यह रहती है कि अरुणाचल दक्षिणी तिब्बत है और चूक तिब्बत चीन का हिस्सा है, इसलिए अरुणाचल पर भी उसका हक है। दुर्भाग्य से किसी भी भारत सरकार ने आज तक चीन को यह जवाब नहीं दिया कि तिब्बत पर गैर-कानूनी और औपनिवेशिक कब्जे को आधार बनाकर किसी तीसरे देश की भूमि पर

चीन के बिजली उत्पादन में लगातार कमी आ रही हैं। यह तीनों संकट देखने में सामान्य दिख रहे हैं किन्तु इनके प्रभाव बहुत व्यापक हैं।

इसको समझने के लिए चीन के पिछले 30 साल के आर्थिक इतिहास को समझना होगा। पिछले तीन दशक में चीन का निर्यात काफी बढ़ा

है। चीन द्वारा आर्थिक सहायता देकर अन्य देशों में ट्रेड यूनियन खड़ी की गई जिसकी वजह से अन्य देशों में चीन उत्पादन कम करवाने में

तालिबानी चक्रव्यूह में फंसती शेख हसीना

शेख हसीना ने अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान के आत्माघाती नक्शेकदम पर चलना शुरू कर दिया था। शेख मुजुबुर रहमान ने इसी तरह भारत को आंख दिखाना शुरू कर दिया था और भारत की सेना की उपस्थिति को अपनी संप्रभुता में हस्तक्षेप मानना शुरू कर दिया था। खासकर भारतीय गुप्तचर एजेंसी 'रा' की सक्रियता शेख मुजीबुर रहमान को अच्छी नहीं लगती थी। जबकि भारतीय गुप्तचर एजेंसी 'रा' को यह मालूम था कि पाकिस्तान अपनी नापाक चालें चल रहा और पाकिस्तान परस्त ताकतों साजिशों में लगी हुई हैं। भारत ने जब यह देखा कि शेख मुजीबुर रहमान खुद जब अपने ऊपर मंडरा रहे खतरों को लेकर उदासीन हैं और खुशफहमी से भरे हुए हैं तब उनकी पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आंतरिक ताकतों के खिलाफ सक्रियता का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। 'रा' ने अपनी सक्रियता लगभग समाप्त कर दी थी। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि शेख मुजीबुर रहमान मारे गये और उनके परिवार का सफाया कर दिया गया। उनके परिवार में सिर्फ शेख हसीना ही बची थी जो बांग्लादेश से बाहर थी। अगर शेख मुजीबुर रहमान भारत को आंख दिखाने की कोशिश नहीं करते, भारत के अहसान को बोझ नहीं समझते, भारत को बांग्लादेश के मामलों में सक्रिय रहने से अलग नहीं करते तो फिर उनकी सरकार का तत्वापलट होता नहीं और न ही उनकी हत्या होती, उनका परिवार भी सुरक्षित होता।

दुर्भाग्य से शेख हसीना अपने पिता मुजुबुर रहमान का इतिहास दोहरा रही हैं। शेख हसीना का आंख दिखाना भारत के लोगों को कहीं से भी अच्छा नहीं लगा, अब तक उन्हें भारत का अच्छा मित्र माना जाता था, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने वाला शख्स माना जाता था, उन्हें धर्मनिरपेक्षता के प्रति समर्पित माना जाता था, उन्हें पाकिस्तान के दुश्मक न फंसने वाली शरिक्सयत माना जाता था। लेकिन उन्होंने भारत को आंख दिखाने की अपनी विशेषताएं खुद ही ध्वस्त कर दी, भारतीय लोगों के विश्वास पर खुद बुलडोजर चला दिया। भारत के लोगों को ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी। भारत सरकार ने शेख हसीना के इस आंख दिखाने वाली गुस्ताखी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं जाहिर की है, प्रतिक्रिया न जाहिर कर भारत सरकार ने अच्छा ही किया है। पर भारत सरकार ने उनकी गुस्ताखी को जरूर

संज्ञान में लिया है। खासकर सोशल मीडिया में शेख हसीना की आंख दिखाने वाली गुस्ताखी को खूब संज्ञान में लिया गया, सोशल मीडिया में इसके खिलाफ खूब प्रतिक्रिया हुई, शेख हसीना को नसीहतें भी दी गयीं और सावधान भी किया गया। अगर भारत और बांग्लादेश के संबंध बिगड़ते हैं तो फिर इसका नुकसान किसको होगा? इसका सर्वाधिक नुकसान भारत को नहीं बल्कि बांग्लादेश को ही होगा और खासकर शेख हसीना को ही होगा। शेख हसीना यह सोच रही है कि भारत को आंख दिखाने पर वह बहुत बड़ी जीत हासिल की है या फिर भारत को कड़ा संदेश दे दिया है तो यह उनकी बहुत बड़ी भूल होगी। बांग्लादेश में स्थितियां तेजी के साथ विकट हो रही हैं। सांप्रदायिक शक्तियों का तालिबानीकरण हो रहा है। तालिबानीकरण खुद शेख हसीना के शासन के लिए ठीक नहीं है। तालिबानी शक्तियों का लक्ष्य शेख हसीना को हटाना और बांग्लादेश को अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरह तालिबानी देश घोषित कराना है?

बांग्लादेश में हिन्दू मंदिरों और पूजा पंडालों में जो श्रृंखला बद्ध हमले हुए हैं वे पूर्व नियोजित रहे हैं। बांग्लादेश का मीडिया भी यह मानता है कि हमले पूर्व नियोजित थे, साजिशान थे। पूजा पंडाल में साजिशकर्ताओं ने स्वयं कुरान की प्रति रखवायी थी और अफवाह फैला कर हिंसा की थी। बांग्लादेश के हिन्दू पहले से ही डरे हुए हैं। डरे हुए हिन्दू बांग्लादेश को छोड़कर बाहर जाने के अवसर तलाशते रहते हैं। इसलिए बांग्लादेश के हिन्दुओं के अंदर इतनी शक्ति है नहीं कि वे कुरान का अपमान करें। कुरान के अपमान का दुष्परिणाम हिन्दुओं को पहले से मालूम है। जहां भी कुरान का अपमान हुआ है वहां मुस्लिम समुदाय हिंसा मचाती है, कत्लेआम करती है। इसलिए हिन्दू यह गुस्ताखी कर ही नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हिन्दू समुदाय कुरान ही क्यों बल्कि सभी धर्मग्रंथों में विश्वास रखती है। हिन्दू समुदाय का किसी भी धर्म ग्रंथ का अपमान करने या फिर उसकी खिल्ली उड़ाने का स्वभाव और मानसिकताएं नहीं होती है। हिन्दू मंदिरों और

पूजा पंडालों पर सिर्फ हमले ही नहीं हुए हैं बल्कि वीभत्स ढंग से हिंसा भी हुई है। दो लोगों की हत्याएं भी हुई हैं, दर्जनों लोगों को घायल कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि छोटी-छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हुए हैं। हिन्दुओं के घरों को सरेआम जलाया गया है।

पाकिस्तान और उसकी बदनाम गुप्तचर एजेंसी आईएसआई सहित अन्य मुस्लिम आतंकवादी संगठनों की उपस्थिति, सक्रियता और हस्तक्षेप भी स्पष्ट है। बांग्लादेश का तालिबानीकरण तेजी के साथ हो रहा है। बांग्लादेश को एक तालिबानी देश में तब्दील करने की मजहबी प्रक्रिया बहुत तेज चल रही है। अफगानिस्तान का तालिबानीकरण करने के बाद तालिबानी शक्तियों के हौसले बढ़े हैं। तालिबानी शक्तियां गैर मुसलमानों का निशाना बनाना शुरू कर दिया था। अफगानिस्तान से भी हिन्दुओं और सिखों का सफाया हो रहा है। कश्मीर में जो मुस्लिम आतंकवाद की आंच लगभग बुझ गयी थी उस मुस्लिम आतंकवाद की आंच को फिर से लहसारी जा रही है। कश्मीर में हिन्दुओं की हत्या योजनाबद्ध ढंग से हो रही है। लगभग एक दर्जन हिन्दुओं की हत्या अभी तक हो गयी है। जिस तरह से अफगानिस्तान, भारत के कश्मीर में हिन्दुओं की हत्याएं हो रही हैं, हिन्दुओं को भगाने की साजिशें हो रही हैं उसी प्रकार से बांग्लादेश में हिन्दुओं की हत्याएं हो रही हैं और हिन्दुओं को भगाने की साजिशें जारी हैं। बांग्लादेश के हिन्दुओं को सरेआम मुसलमान बनने या फिर जान गंवाने की धमकी दी जा रही है।

जब कोई इतनी बड़ी घटना साजिशान होती है, पूर्व प्रायोजित होती है तो उसकी गूँज दूर तक जाती है। यही कारण है कि बांग्लादेश के अंदर



हिन्दुओं की हत्याओं और उत्पीड़न की घटनाओं की गूँज भारत तक पहुंची है। अगर भारत के लोगों ने हिन्दुओं की हत्याओं के खिलाफ अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं तो फिर यह कौन सा गुनाह है। एकाएक घटी घटनाओं पर कोई सरकार अपनी नाकामी से इनकार कर सकती है। ये घटनाएं तो साजिशन थी, पूर्व प्रयोजित थी। साजिशन और पूर्व प्रयोजित घटनाओं को न रोकना सरकार की ही विफलता मानी जाती है। इस कसौटी पर शेख हसीना की विफलता क्यों नहीं मानी जानी चाहिए। एक अच्छी सरकार इस तरह की पूर्व प्रयोजित और साजिशन घटनाओं को रोकती है। अब यहां यह प्रश्न उठता है कि पूर्व प्रयोजित घटनाओं को शेख हसीना की सरकार क्यों नहीं रोक पायी? क्या उनकी अपनी गुप्तचर एजेंसी ऐसी पूर्व घटनाओं की जानकारी नहीं दी थी? यह कोई इस दशहरे पर ही ऐसी घटना नहीं घटी है। हर हिन्दू त्यौहारों पर इस तरह की घटना घटती है और हिंसक इस्लामिक तत्व अपनी हिंसा का शिकार हिन्दुओं को बनाते हैं।

पूर्व पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में हिन्दुओं के बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। हिन्दुओं ने कितना बड़ा बलिदान दिया था, यह भी स्पष्ट है। हिन्दुओं ने इसकी बहुत ही वीभत्स कीकत चुकायी थी। दस लाख से अधिक हिन्दू महिलाओं के साथ पाकिस्तान के सैनिक और पुलिस ने बलात्कार किये थे। हजारों हिन्दुओं को मौत का घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान की सेना और पुलिस इसलिए हिन्दुओं को निशाना बनाती थी कि हिन्दू बांग्लादेश के निर्माण के अभियान में आगे थे। अगर हिन्दुओं का समर्थन नहीं होता और हिन्दुओं का बलिदान नहीं होता तो फिर बांग्लादेश का निर्माण भी संभव नहीं था। भारत की सेना ने बांग्लादेशी बनाने में कितनी बड़ी वीरता दिखायी थी, यह भी मालूम है। भारत की सेना की वीरता का ही प्रमाण था कि पाकिस्तान की सेना को समर्पण करना पड़ा था। कोई एक दो हजार नहीं बल्कि 90 हजार पाकिस्तान सैनिक भारत के कब्जे में थे।

शेख हसीना को अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की आत्मघाती कदम पर चलने का दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। हिंसक इस्लामिक तत्व से शेख हसीना को ही अधिक खतरा है। इस्लामिक हिंसक तत्व तख्ता पलट कर सकते हैं। सेना और पुलिस का भी तेजी के साथ इस्लामिक करण हुआ है। इसलिए शेख हसीना को हमेशा भारत का साथ और सहयोग चाहिए। शेख हसीना को 1972 के धर्मनिरपेक्ष संविधान की ओर लौटना होगा। 1972 का धर्मनिरपेक्ष संविधान ही बांग्लादेश का तालिबान करने से रोक सकता है।

विष्णुगुप्त

आयुध निर्माणी बोर्ड की सात नई रक्षा कंपनियां

संचालन स्वायत्तता, दक्षता बढ़ाने और नई विकास क्षमता और नवाचार लाने के लिए, सरकार ने देश की रक्षा तैयारियों में आत्मनिर्भरता में सुधार के उपाय के रूप में ओएफबी को सरकारी विभाग से सात शत प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट कंपनियों में बदलने का निर्णय लिया था।

सात नई रक्षा कंपनियां हैं-

- म्यूनीशन्स इंडिया लिमिटेड (एमआईएल);
- आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (अवनी);
- एडवांस्ड वेपंस एंड इम्पैक्ट इंडिया लिमिटेड (एडब्ल्यूई इंडिया);
- टूरुप कम्फर्ट्स लिमिटेड (टीसीएल) (टूरुप कम्फर्ट आइटम);
- टंज्र इंडिया लिमिटेड (वाईआईएल);
- इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल) और
- ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (जीआईएल)।

इन कंपनियों ने 01 अक्टूबर, 2021 से कारोबार शुरू कर दिया है।

65,000 करोड़ रुपये से अधिक की ऑर्डर बुकिंग इन कंपनियों को मिली है।

पिछले पांच वर्षों में हमारा रक्षा निर्यात 325 प्रतिशत बढ़ा है। रक्षा मंत्रालय ने 2024 तक एयरोस्पेस और रक्षा उपकरणों और सेवाओं में 1.75 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 35,000 करोड़ रुपये का निर्यात भी शामिल है।

इन 41 उत्पादन इकाइयों के पास 79,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है और सबसे बढ़कर, इसकी विरासत 220 वर्षों से अधिक की है।



कामयाब रहा। भारत में देखें तो उत्पादन का प्रमुख केंद्र कोलकाता में ट्रेड यूनिन के वर्चस्व ने हावड़ा में बड़ी बड़ी कंपनियों को बंद करा दिया। चूंकि, मांग और पूर्ति के सिद्धान्त में मांग तो कम नहीं हुयी इसलिए पूर्ति के लिए पहले हम आत्मनिर्भर थे, अब चीन पर निर्भर हो गए। चीन ने ऐसा भारत में ही नहीं किया बल्कि वैश्विक बाजार के ज्यादातर देशों में ऐसा किया। पिछले दो दशक में इस तरह चीन के पास काफी धन उपलब्ध हो गया। इस धन को चीन ने दूसरे देशों में बुनियादी संरचना खड़ा करने के क्रम में कर्ज देने में प्रयोग किया। चूंकि चीन में घरेलू बचत दर भी ऊंची थी इसलिए चीन के पास धन आवश्यकता से अधिक था। ढांचागत निवेश के द्वारा चीन अन्य देशों में अपनी पैट बढ़ाता चला जा रहा था। चीन ने इस परियोजना को बीआरआई प्रोजेक्ट (बेल्ट एंड रोड इनिशियटिव) नाम दिया। 2019 में विश्व बैंक ने इस परियोजना का अध्ययन किया और पाया कि इस प्रोजेक्ट के द्वारा अन्य देशों को भी लाभ हो सकते हैं। इसके बाद जब इन प्रोजेक्ट्स की जांच हुयी तो पता चला कि इनमें तो व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार चल रहा है। धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट्स से जुड़े देश अपने अपने हाथ पीछे खींचने लगे। ऐसे प्रोजेक्ट्स कई देशों में चल रहे हैं। चीन से यूरोप तक एक रेल लाइन बिछाई जा रही है। यह कजाखिस्तान और पोलैंड से होकर जाती है। म्यांमार में एक बन्दरगाह का निर्माण चल रहा है। पाकिस्तान से होकर एक कॉरीडोर बन रहा है। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में भी इसी तरह के मूलभूत ढांचे को मजबूत करने वाले प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। चीन के इन प्रोजेक्ट्स में भ्रष्टाचार के चलते इनमें कई डूबने की तरफ बढ़ रहे हैं। कई देशों की सरकारें इनसे पीछे हटने लगी हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने बीआरआई को उपनिवेशवाद का नया प्रारूप बताया है। म्यांमार ने क्यौकप्यू बन्दरगाह परियोजना को निरस्त

गैर घातक हथियार

गलवान घाटी में संघर्ष के दौरान चीनी सैनिकों ने तार वाली लाठी, टेसर वगैरह का इस्तेमाल किया था। इसके बाद भारतीय सेना ने उत्तर प्रदेश की एक कंपनी को गैर घातक हथियार बनाने को कहा था। नोएडा के स्टार्टअप फर्म एपेस्ट्रॉन प्राइवेट लिमिटेड ने यह जानकारी देते हुए ऐसे हथियार तैयार कर लेने की बात कही है। पारंपरिक भारतीय अस्त्रों से प्रेरित इन हथियारों का इस्तेमाल न केवल दुश्मन देश की सेना के खिलाफ संघर्ष में किया जा सकता है, बल्कि हिंसा, उपद्रव जैसी स्थिति पर काबू पाने में भी ये कारगर साबित हो सकते हैं।

एपेस्ट्रॉन के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी मोहित कुमार ने, हल्लू को बताया, 'जब चीनी ने हमारे सैनिकों के खिलाफ गलवान संघर्ष में तार की छड़ें और टेसर का इस्तेमाल किया था तब हमें भारतीय सुरक्षा बलों के लिए गैर-घातक उपकरण विकसित करने के लिए कहा गया था।' कुमार ने कहा, 'हमने भारतीय सुरक्षा बलों के लिए अपने पारंपरिक हथियारों से प्रेरित ऐसे ही टेसर और गैर-घातक उपकरण विकसित किए हैं।'

वज्र नाम से मेटल रोड टेजर

विभिन्न हथियारों का प्रदर्शन करते हुए कुमार ने कहा कि वज्र नाम से स्पाइक्स के साथ एक मेटल रोड टेसर विकसित किया गया है। इसका इस्तेमाल दुश्मन सैनिकों पर आक्रामक रूप से हमला करने के लिए हाथ से मुकाबला करने के साथ-साथ उनके बुलेट फ्रफ वाहनों को पंचर करने के लिए भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वज्र में स्पाइक्स भी होते हैं जो करंट को डिस्चार्ज करते हैं और दुश्मन के सैनिक को आमने-सामने की लड़ाई के दौरान अप्रभावी बना



सकते हैं।

त्रिशूल का प्रदर्शन

कुमार ने त्रिशूल का भी प्रदर्शन किया। इसका उपयोग वाहनों को रोकने के साथ-साथ रिस्ट्रिक्टेड एरिया में युसपैठ को रोकने के लिए किया जा सकता है।

सैपर पंच

सुरक्षा बलों को 'सैपर पंच' नामक एक और टेसिंग उपकरण प्रदान किया गया है, जिसे सर्दियों के सुरक्षा दस्ताने की तरह पहना जा सकता है। इसका इस्तेमाल हमलावर दुश्मन सैनिकों को झटका देने के लिए किया जा सकता है। यह वाटरप्रूफ या शून्य से 30 डिग्री कम तापमान में भी काम कर सकता है। ये करीब 8 घंटे तक बिजली से चार्ज रह सकता है।

दंड

दंड यानी बिजली से चलने वाला डंडा। ये 8 घंटे तक बिजली से चार्ज रह सकता है। ये वाटरप्रूफ भी है। इस बिजली वाले डंडे की मार जिस पर पड़ेगी वो फिर मुड़कर नहीं आएगा।

भद्र

भद्र एक खास तरह की ढाल है, जो जवान को पत्थर के हमले से बचाती है। इसमें बहने वाला करंट दुश्मन को जोर का झटका धीरे से देता है।

कुमार ने कहा कि इनमें से कोई भी हथियार मौत या किसी भी गंभीर चोट का कारण नहीं बन सकता है, लेकिन दुश्मन सैनिकों को शारीरिक संघर्ष के दौरान अस्थायी रूप से अप्रभावी बना सकता है। उन्होंने कहा कि ये हथियार किसी भी आम नागरिक को नहीं बेचे जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि पिछले साल लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने लोहे की रॉड पर लिपटे कंटील तारों और टेजर्स के जरिए भारतीय सेना के जवानों पर हमला कर दिया था। जिसके बाद हुई झड़प में भारत के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे जबकि चीन के करीब 40 सैनिक मारे गए थे।



कर दिया है। मालदीव में चीन समर्थित प्रोग्रेसिव पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि देशों ने भी इन प्रोजेक्ट्स के स्वरूप को बदलने का आग्रह किया है।

आत्मनिर्भर देश स्वयं को बचा लेंगे चीनी संकट से

यह कुछ ऐसी बातें हैं जो चीन की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रही हैं। चूंकि, चीन विश्व बाजार में एक बड़ा उत्पादक देश है इसलिए जो जो देश आत्मनिर्भर होंगे वह चीन की घटती अर्थव्यवस्था में खुद को बचा ले जाएंगे। जिन देशों की चीन पर निर्भरता ज्यादा रहेगी वह स्वयं को संभाल पाने की स्थिति में भी नहीं होंगे। अब अगर चीन के अंदर के दूसरे संकट की बात करें तो वह एवरग्रैंड कंपनी का है। यह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का मौलिक विचार रहा है। इसमें उनका मानना है कि प्रदूषण, असमानता और वित्तीय अस्थिरता को दूर करना अब ज्यादा आवश्यक हो गया है। इस क्रम में ऋण के मानक काफी कड़े किए गए हैं। इसके लिए तीन मानक बनाए गए हैं। ऋण के सामने कंपनी की संपत्ति, अल्पकालिक कर्ज की तुलना में नकदी, कुल ऋण की तुलना में पूंजी। अगर एक भी मापदंड कमजोर पड़ता है तो उसे ऋण नहीं दिया जाता है। एवरग्रैंड ने समय रहते अपनी परियोजनाओं को पूर्ण तो किया था किन्तु कोरोना संकटकाल में उसके फ्लैटों की बिक्री कम हो गयी। इससे निपटने के लिए चीन सरकार को अपनी ही सरकारी इकाइयों को आदेश देना पड़ा कि वह इस परियोजना की इकाइयों को खरीद लें। सरकार द्वारा परियोजना को अपने हाथों में लेना दिखाता है कि संकट कितना बड़ा है। यह कुछ उस तरह का संकट है जब 2008 में अमेरिका ने जनरल मोटर्स को वित्तीय सहायता देकर बचाया था।

चीन के अंदर तीसरा बड़ा संकट बिजली का है। उसका प्रभाव व्यापक होने जा रहा है। यह वैश्विक महंगाई का आधार भी बनने जा रहा है। शी जिनपिंग ने प्रदूषण, असमानता और

जिहाद की प्रकृति!

कश्मीर में गैर मुलसिमो का सफाया किया जाना ही जिहाद की प्रकृति है, जिससे हम वर्तमान में जूझ रहे हैं।

हम भारतवासी जब तक इलसाम की वास्तविकताओं को नहीं समझ लेते, तब तक हम नहीं समझ सकेंगे कि भारत भूमि पर पाकिस्तान क्यों बना ?

यदि देशवासी वहाबियों की वास्तविकता से अनभिज्ञ रहे आर्यो वे देश के पुनः विभाजन को आमंत्रित करेंगे।

हिन्दुओं को कत्ल करके और उनकी संस्कृति को नष्ट करके, अरबी संस्कृति का विस्तार करना ही इनका उद्देश्य है।

यहां यह समझना जरूरी है -

जिहादी आंतकवाद व्यक्ति की जड़ों, उसके स्वतंत्र विचारों, महिलाओं के अधिकारों और बोलने की आजादी, गणराज्य की प्रकृति पर आघात करता है।

साऊदी अरब में यहूदी पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं, ईरान में अपने पैतृक स्थान पर कोई पारसी नहीं बचा है। इसी तरह मुल्तान व अफगानिस्तान में अब हिन्दू नहीं है, लाहौर में सिख नहीं है, जो कभी सिखों का शहर हुआ करता था।

कश्मीर में हिन्दुओं का लगभग सफाया हो चुका है, यहीं जिहाद की प्रकृति है, जिससे हम वर्तमान में जूझ रहे हैं।

क्या आपने सोचा कि वहाबी व वहाबी संगठन क्यों कांग्रेस का समर्थन या एक तरफा वोट करते रहे हैं?

वहाबी मुस्लिम राजनीतिक रूप से हिन्दू से कहीं अधिक परिपक्व व उनका उद्देश्य एकदम स्पष्ट है। उन्हें काफिरों की इस भारत भूमि पर अधिपत्य स्थापित करना है और जो भी राजनीतिक दल इस काम में उनकी सहायता करेगा, वे उसी को वोट देंगे।

उन्हें न लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, न इंप्लेशन, न HDI (ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स), न WPI (होलसेल प्राइस इंडेक्स), न CPI(कमोडिटी प्राइस इंडेक्स), न IIP (इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन) से कोई मतलब।

उन्हें न फिस्कल डेफिसिट, न करेंट अकाउंट डेफिसिट, न विदेशी मुद्रा भंडार, न देश के विद्युतीकरण, न फाइनेंशियल इंकलूजन, न जॉब ग्रोथ, न GDP (सकल घरेलू उत्पादन), न रक्षा क्षेत्र के नए सौदों, न सेना को मिल रहे नए हथियारों, उपकरणों, लड़ाकू व लाजिस्टिक विमानों, AWACS (एयरबोर्न अल्टी वार्निंग एन्ड कंट्रोल सिस्टम), न देश की रक्षाथर्व विकसित किये जा रहे BMD (बैलिस्टिक मिसाइल डिफेन्स) सिस्टम और न न्यूक्लियर क्षमता को धार देने हेतु विकसित किये जा रहे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कि MIRV (मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री-एंट्री वेहिकल) क्षमता से कोई मतलब।

न वैश्विक कूटनीति में भारत द्वारा प्राप्त सफलताओं और न भारत के MTCR, Australian group व Wassenar agreement जैसे समूहों का सदस्य बनने से कोई मतलब।

यदि मतलब है तो उन्हें फ्री राशन, सरकारी सुविधाएं, चार बीघियां रखने के आजादी, तीन तलाक, मदरसों, मस्जिदों व कब्रिस्तानों के फैलाव, काफिर लड़कियों का धर्म-परिवर्तन व लव जिहाद, अवैध बंगलादेशी व रोहिंग्या की घुसपैठ कर जनसंख्यिकीय असंतुलन के द्वारा इस्लाम का परचम लहाना।

दूसरी ओर, हिन्दू सेक्युलरिज्म का कम्बल ओढ़कर नींद की खुमारी में अभी तक यह समझ ही नहीं पाया है कि उसका अस्तित्व व भविष्य संकट में है, जो उसे यथार्थ से अवगत कराने का प्रयास करता है, वह कुत्सित-छोटी दकियानुसी सोच वाला सांप्रदायिक व संघी लगता है, जो देश के सौहार्द को बिगाड़ना चाहता है।

उच्च शिक्षित हिंदू अपनी असुरक्षा से बेखबर होकर अपने संकीर्ण उद्देश्यों को पाने में लगा है। एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी पत्नी, एक मंहो स्कूल में पढ़ती सन्तान, एक अच्छा घर, एक मंहंगी कार, ठीक वही स्थिति कश्मीर, असम, कैराना, कंदला, शामली व बंगाल के हिंदुओं की थी, उनकी परिणीति क्या हुई?, किसी से छिपा नहीं है।

वहाबियों ने जनसंख्या बल पर उनके घरों, सम्पत्ति व महिलाओं पर कब्जा कर लिया गया, कुछ मार दिये और बचे खुचे जान बचाकर घर, सम्पत्ति, रोजगार छोड़कर भाग गए और आज रिफ्यूजी बने बैठे हैं। हाल का उदाहरण कश्मीर।

हिन्दू न तो आक्रामक रहा, न संगठित।

अतः वह अपनी रक्षा हेतु सरकार व प्रशासन पर निर्भर है, और सरकार यदि मुस्लिमों के वोट बैंक के आधार पर बनी हो, तो वह किसी भी साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति में प्रथम यह देखती हैं कि कहीं किसी कार्यवाही से उसका एकमुश्त वोट बैंक का तो नहीं फिसल जायेगा। यदि ऐसा है, तो वह निष्क्रिय रहती है और वहाबी अपने दीन के कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम दे देते हैं।

उदाहरण कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस सरकार, रूपी की समाजवादी सरकार, असम की कांग्रेस सरकार, बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार, इन सभी जगह मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं का घोर उत्पीड़न हुआ/हो रहा है।

मुख्य सेक्युलर राजनेता व सेक्युलर राजनितिक दल अपने तत्कालीन लाभ हेतु मुस्लिम तुष्टिकरण कर वहाबियों के उद्देश्य प्राप्त में सहयोग करते हैं। एक बार जब मुस्लिम जनसंख्या हिंदुओं से अधिक हो जायेगी, तब इस उन्नत सेक्युलरिज्म की बात करने वाला कोई नहीं होगा। बांग्लादेश व पाकिस्तान का उदाहरण उठाकर देख लीजिए, हिंदुओं की क्या स्थिति है, 57 इस्लामिक देश हैं, हिंदुओं का केवल एक देश है, विपरीत परिस्थितियों में कहां जाओगे ?

कम से कम दिमाग का प्रयोग कर सरकारें तो ऐसी चुने, जो समय आने पर प्रशासन, पुलिस व सुरक्षा बल लगाकर उनकी जान माल की रक्षा कर सके।

- दिक्षा भारगव



पाकिस्तानी सेना तो हमेशा चाहती है कि युद्ध हो

पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने का अर्थ यह नहीं है कि हम भी उसकी तरह अपनी जनता के हितों को ताक पर रखकर जनता को युद्ध की तरफ झोंक दें। एक असफल राष्ट्र जब खुद डूब रहा होता है तब उसका प्रयास होता है कि अपने साथ एक दो औरों को भी डूबा दें। पाकिस्तान में सिंध, गिलगित और बलूचिस्तान में इतना आंतरिक असंतोष उभर चुका है कि अब उसकी अखंडता खंडित होने की कगार पर है। आक्रामकता और पराक्रम दो शब्द हैं। कमजोर सदा आक्रामक होता है और मजबूत पराक्रमी। आक्रामकता के द्वारा दूसरों को भयकांत किया जाता है। पराक्रम के द्वारा वर्चस्व स्थापित किया जाता है। सदियों से इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि आक्रामक जमींदोज हुये हैं और पराक्रमी ने विश्व पर अपनी विजय पताका फहराई है। अब यदि बात पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान के द्वारा अक्सर भारतीय सैन्य ठिकानो पर हमला आक्रामकता की निशानी है। यह सिर्फ और सिर्फ भारत को उकसाने वाली हकत होती हैं। पाकिस्तान की भारत के संदर्भ में विदेश नीति अब दुनिया के सामने खुल चुकी है। कश्मीर पर उसकी आक्रामकता ने पहले भारत के पराक्रम को जगा दिया इसके बाद भारत के द्वारा बलूचिस्तान के मुद्दे को उठाना पाकिस्तान की दुखती रग को दबा गया। इस तरह के पराक्रम की उम्मीद पाकिस्तान को भारत से नहीं थी। एक ओर 370 हटने के

क्रम में भारत के पक्ष को अन्तराष्ट्रिय मंचों पर स्वीकार किया गया वहीं पाकिस्तान उस संदर्भ में भी अकेला पड़ गया। पाकिस्तान की नीति रहती है कि भारत के जनमानस में मोदी सरकार के लिये गुस्सा भड़के। जनता सैन्य कार्यवाही का दवाब अपनी सरकार पर बनाये। और ऐसा होने की स्थिति में भारत को आक्रामक साबित किया जा सके।

वास्तव में पाकिस्तान की सब समस्याओं की जड़ वहाँ की अशिक्षा एवं रक्षा बजट है। वर्ल्ड डेवपमेंट रिपोर्ट-2013 के अनुसार पाकिस्तान का रक्षा बजट 36.5 प्रतिशत एवं शिक्षा बजट 3.5 प्रतिशत है। सरकार का स्वास्थ्य बजट सिर्फ 2.05 प्रतिशत है। अब जिस देश में इतनी बड़ी राशि सेना के लिये खर्च की जाती है वहाँ तरक्की की बात सोचना भी बेमानी हो जाता है। उस देश की सेना अगर सक्रिय नहीं होगी तो इस बजट को खर्च कहाँ करेगी। अगर बजट खर्च नहीं होगा तो अगले साल बजट में कटौती कर दी जाएगी। बस यही एक छोटी से बात पाकिस्तान की सेना को आक्रामक बनाये रखती है। पाकिस्तान की सेना कभी भारत से उलझती है तो कभी खुद अपने ही हुक्मरानों से। कभी खुद भारत से लड़ाई के प्रपंच रचती है तो कभी आतंकवादियों को भेजकर अपनी आक्रामकता दिखाती है। उसको समय समय पर चीन से सहयोग मिल जाता है और इस क्रम में अमेरिका, रूस, फ्रांस के हथियार बिक जाते हैं।

अब इस तरह के गुंडे बदमाशों के साथ उसकी ही औकात पर उतर कर बात करना मूर्खतापूर्ण बात होगी। पराक्रमी वही है जो समस्या की मूल जड़ पर चोट करे। एक कम दिमाग गुंडे का फायदा पूंजीपति उठाते हैं और उसकी बददिमागी के द्वारा सिर्फ उसे दारू-मुर्गा देकर अपने दुश्मनों को निपटाने में लगाते हैं, ठीक वैसा ही इस्तेमाल पाकिस्तान का होता है। भारत से आर्थिक एवं सामरिक मोर्चे पर प्रतिद्वंदी चीन, पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है। अमेरिका, रूस और चीन के पास होने के कारण पाकिस्तान के एयरबेस को इस्तेमाल करता है।

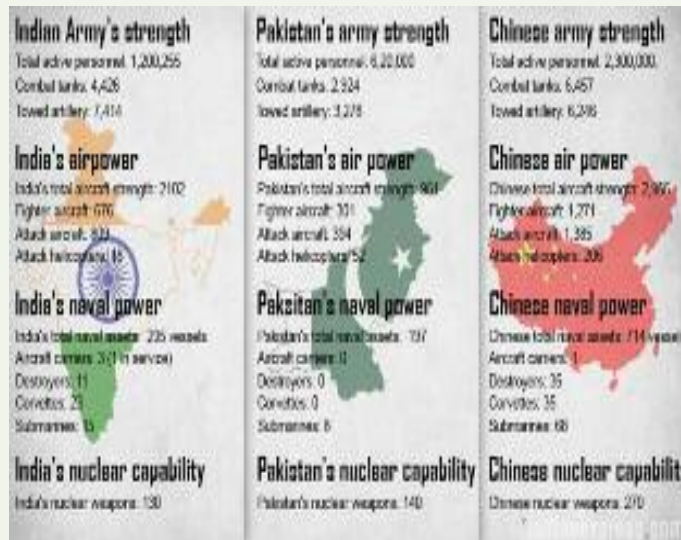
ओसामा को ढूँढने के बहाने सालों अमेरिका ने पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल किया। बीच बीच में दारू-मुर्गों के रूप में सौगातें पाकिस्तान को मिलती रहीं। चीन अपना एक कॉरीडोर पाकिस्तान में बना रहा है। वह भी अपना व्यापारिक हित पाकिस्तान के जरिये साध रहा है। पाकिस्तान की फौज और हुक्मरान इन देशों से मिले फायदे की बंदर बांट कर लेते हैं और जनता को अपनी गरीबी का रोना रोकर दिखाते रहते हैं। एक सोची समझी साजिश के तहत भारत उनके लिये कितना बड़ा खतरा है यह बात दुष्प्रचारित करते हैं। इसके साथ ही जनता में भारत का भय बैठाया जाता है ताकि जनता अपने उम्हाराओं और अधिकारों की शिकायत न करे। इसी क्रम में पाकिस्तानी सेना

उल-कपट से गाहे बगाहे हमले आदि करवाने की फिराक में लगी रहती है। जब भी किसी हमले में भारत के द्वारा आत्मरक्षा में जवाब दिया जाता है तब उसे वहाँ जनता में भारत के द्वारा पाकिस्तान पर किया गया हमला बताया जाता है। ऐसे में इस बद-दिमाग राष्ट्र के उकसावे में आकर उस पर आक्रामक कार्यवाही करके भारत उनके मंसूबों को सफल कर देगा। भारत को पाकिस्तान के साथ आक्रामक तो रहना चाहिए किन्तु संयम के साथ सिर्फ उतना ही निराश्रित ऑपरेशन करना चाहिए जितना आवश्यक है। न कम न ज्यादा।

वर्ल्ड डेवपमेंट रिपोर्ट-2013 के अनुसार विभिन्न देशों के सरकारी खर्च का वितरण

देश	रक्षा बजट	शिक्षा बजट	स्वास्थ्य बजट
बांग्लादेश	13.7%	14.8%	5.3%
श्रीलंका	16.8%	13.7%	6.2%
पाकिस्तान	36.5%	3.5%	2.05%
भारत	28.6%	19.3%	4.2%
कोस्टरिका	19.6%	23.4%	28.8%

- अमित त्यागी



भारत-चीन - सीमा विवाद और आपसी व्यापार साथ-साथ

अब कभी-कभी लगता है कि भारत-चीन ने यह तय कर लिया है इनका जटिल सीमा विवाद का कोई हल निकले या न निकले, पर ये अपने आपसी कारोबारी संबंधों को प्रभावित नहीं होने देंगे। अब जरा देखिए कि कुछ दिन पहले पूर्वी लद्दाख के निकट एलएसी पर तनाव खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच 13वें दौर की कोर कमांडर स्तर की सैन्य वार्ता हुई। बैठक में कोई प्रगति नहीं हुई। भारतीय पक्ष ने विवादित क्षेत्रों के मुद्दों को हल करने के लिए रचनात्मक सुझाव भी दिए। बातचीत आगे भी जारी रहेगी, ऐसा कहा गया।

अब इससे बिलकुल हटकर यह भी खबर आई कि भारत-चीन का इस साल के पहले नौ महीनों के दौरान ही आपसी व्यापार 90 अरब रुपए तक पहुंच गया। यह पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 49 फीसद बढ़ा है। यह जानकारी आधिकारिक रूप से भारत के विदेश सचिव श्री हर्षवर्धन श्रृंगला ने दी। तो बहुत साफ है कि भारत-चीन आपसी व्यापार बढ़ता रहेगा, भले ही सीमा विवाद का कोई स्थायी हल न निकले। यह तो साफ है कि चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने के नारों को कोई बहुत असर नहीं हुआ। राद करें कि लद्दाख सीमा पर चीन की ओर से हिंसक झड़प करने और अतिक्रमण के बाद अखिल भारतीय स्तर पर चीनी सामान के बहिष्कार की मांग ने जोर पकड़ा था।

कड़वी हकीकत यह है कि भारत चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों तथा मोबाइल फोन कंपोनेंट्स का बहुत बड़े स्तर पर आयात करता है। हमारी फार्मा कंपनियों की चीन पर निर्भरता तो खासी अधिक है। इस निर्भरता को हम कुछ महीनों में या नारेबाजी से खत्म नहीं कर सकते। जब तक हम खुद आत्म निर्भर नहीं हो जाते तब तक तो हमें चीन से विभिन्न उत्पादों का आयात करना ही होगा। एक बात साफ है कि कोरोना संक्रमण ने भारत के फार्मा सेक्टर को एक अनुपम अवसर दिया है कि वह अपने को आत्म निर्भर बना ले। भारत का फार्मा सेक्टर हर साल भले ही देश-विदेश में अपनी दवाएं बेचकर अरबों रुपए कमाता है, पर हमारी फार्मा कंपनियां अपनी जेनेरिक दवाओं को बनाने के लिए करीब 85 फीसदी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स (एपीआई) चीन से ही आयात करती हैं। एपीआई यानी दवाओं को बनाने के काम में आने वाला कच्चा माल। भारत में एपीआई का उत्पादन बेहद कम है और जो एपीआई भारत में बनाया जाता है उसके फ़ाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए भी कुछ चीजें चीन से मंगानी ही पड़ती हैं।

तो जान लें कि भारत की फार्मा कंपनियां एपीआई के उत्पादन के लिए भी चीन की तरफ ही देखती हैं। किसी भी फार्मा कंपनी की पहचान इस आधार पर की जाती है कि वह कितनी नई जीवनरक्षक दवाओं को इजाद कर रही हैं? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी फार्मा कंपनियों ने अपने को विश्व स्तरीय बनाने की कभी इच्छा ही नहीं दिखाई। उनका एकमात्र लक्ष्य पैसा कमाना ही रहा है। वे आमतौर पर नई औषधियां विकसित करने में तकलीफ नहीं खतीं। हां, इन कंपनियों ने कोरोना के टीके विकसित करके अपनी छवि को उजला किया। इस लिहाज से भारत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक, डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज, जाइडस कैडिला, बाँयोलाजिकल ई, जेन्नोवा बायोफार्मा और पैनेसिया बायोटेक जैसी कंपनियों का कृतज्ञ रहेगा। एपीआई विकसित करने के लिए ही भारत सरकार ने सत्तर के दशक में आईडीपीएल (इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड) की स्थापना की थी लेकिन, कुशासन और भ्रष्टाचार से ग्रस्त होकर इसकी ऋषिकेश, मुजफ्फरपुर आदि सारी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं।



देखिए भारत-चीन के बीच आपसी व्यापार तो कुलाचे भर रहा है, पर इससे भारत को फायदा नहीं हो रहा है। नुकसान इस लिहाज से होता है कि हम उससे जितना माल खरीदते हैं, उस तुलना में बेहद कम उसे बेचते हैं। हमारा चीन के साथ कुछ साल पहले तक व्यापार घाटा 29 अरब रुपए तक का हो गया था। विदेश सचिव श्री हर्षवर्धन श्रृंगला भी मानते हैं कि इस व्यापार घाटे को संतुलित करने की जरूरत है। भारत जिस भी चीज का निर्यात कर सकता है, उसको उसे अपने लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद जगह पर अच्छी से अच्छी कीमत लेकर ही बेचना चाहिए। भारत को अपनी जरूरत की चीजें भी ऐसे ही देशों से ही आयात करनी चाहिए, जहां वे कम से कम कीमत पर उपलब्ध हों। भारत को कतई बिजली के सजावटी सामानों से लेकर कपड़ों और मूर्तियों वगैरह का कभी भी चीन से आयात नहीं करना चाहिए। क्योंकि, यह सब तो हमारे कुटीर उद्योग बना सकते हैं दू अब दीपोत्सव आ रहा है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले तक दिवाली के मौके पर हमारे बाजार चीनी पटाखों से अट जाया करते थे। लेकिन भारत सरकार ने विदेशी पटाखों की बाजार में बिक्री को अवैध करार कर दिया है दू विदेशी पटाखों से मतलब चीनी पटाखों से ही है। इससे शिवाकाशी (तमिलनाडु) के परम्परागत पटाखा उद्योग में नई जान आ जायेगी।

भारत से चीन से वह बनी-बनाई चीजें, खासकर तरह-तरह की मशीनरी, टेलिकॉम उपकरण और बिजली के सामान और रिवलोन, इलेक्ट्रिकल मशीनरी व उपकरण, मैकेनिकल मशीनरी व उपकरण, प्रोजेक्ट गुड्स, आर्गेनिक केमिकल और लौह व इस्पात आदि प्रमुख चीजें मंगाता है। उधर, भारत मुख्य रूप से चीन को लौह अयस्क और कुछ अन्य खनिजों का निर्यात करता है।

तो बात ये है कि भारत- चीन व्यापार तो तबतक बढ़ता रहेगा जब तक हम अपने को आत्म निर्भर नहीं कर लेते। इसके साथ ही दोनों देश सीमा विवाद को हल करने की भी कोशिश करते रहेंगे। सबसे सुकून देने वाली बात यही है कि दोनों देश कम से कम आपस में बात तो कर रहे हैं। बात से बात निकलेगी और वह दूर तक जाएगी।

पर हमें एक बात का ध्यान तो रखना होगा कि भारत-चीन के बीच चल रही ताजा तानातनी के बीच हमें किसी भी हलत में यह सुनिश्चित करना है कि भारत में बसे चीनी मूल के नागरिकों के साथ किसी भी तरह की कोई नाइसाफी या अत्याचार न हो। वे भारत में लगभग सौ सालों से ज्यादा से बसे हुए हैं। भारत में हजारों चीनी नागरिक देश के सभी शहरों में सक्रिय हैं। ये डेंटिस्ट हैं, कारोबारी हैं और नौकरी भी करते हैं। इनमें से कुछ बेहद विख्यात हैं। उदाहरण के रूप में दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बिरादरी प्रो.तान चुंग के नाम से परिचित हैं। उन्होंने ही पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी और फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के चीनी विभाग स्थापित किए थे। वे कहते रहे हैं कि भारत-चीन को अपने सीमा विवाद को हल करने को लेकर बहुत विलंब नहीं करना चाहिए। बिना सीमा विवाद हल किए संबंधों में तनाव बना रहेगा। साल 2011 में पद्म विभूषण से सम्मानित डा. तान चुंग की राय रही है कि सीमा मसले को हल करने की दिशा में दोनों देशों को प्रो-एक्टिव रुख अपनाना होगा। प्रो. तान चुंग की पत्नी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थीं। उनके पिता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के निमंत्रण पर भारत में आकर बस गए थे। लगता तो यही है कि फिलहाल दोनों देश वार्ता और व्यापार साथ-साथ करते रहेंगे।

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं)



वित्तीय अस्थिरता दूर करने का जो संकल्प लिया है उसके क्रम में उन्होंने अपने यहां के थर्मल संयंत्र एवं अन्य बिजली उत्पादक संयंत्रों को प्रदूषण कम करने का आदेश दिया है। जो बिजली संयंत्र इन नियमों का पालन नहीं कर पा रहे थे उनमें से कई को बंद कर दिया गया है। चीन में इस कारण बिजली का उत्पादन काफी कम हो गया है। कम उत्पादन के कारण कई व्यावसायिक इकाइयों को बिजली देना बंद कर दिया गया है। 24 घंटे बिजली की उपलब्धता वाले शहरी क्षेत्र भी वर्तमान में बिजली कटने की समस्या से दो चार हैं। अब चूंकि व्यवसायिक क्षेत्र में बिजली कटौती की जा रही है इसलिए बहुत से कुटीर उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। घरेलू मांग की आपूर्ति तो शायद चीन पूरी कर लें पर इसका प्रभाव निर्यात पर अवश्य पड़ने जा रहा है। चूंकि, चीन पर बहुत से देशों की अर्थव्यवस्था भी निर्भर है इसलिए चीन का यह प्रभाव वैश्विक परिदृश्य में महंगाई के रूप में भी पड़ने जा रहा है।

चीन और भारत में किसे चुने अमेरिका

चीन अब भारत की तर्ज पर पवन और सौर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तरफ बढ़ने लगा है। चीन के अंदर के इन हालातों के बाद अगर चीन इस समस्या से उबर कर बाहर आता है तो यह चीन के लिए बड़ा संकेत होगा। इसे उसकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। उसका पर्यावरण स्वच्छ होगा और बिजली संकट भी दूर होगा और अगर चीन इन समस्याओं से बाहर नहीं आ पाता है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा दुष्प्रभाव होगा। यदि भारत के संदर्भ में देखें तो अमेरिका ने भारत का उपयोग चीन के उत्पादन को निर्यात करने के लिए समानान्तर रूप में किया है। अमेरिका चाहता है कि चीन विश्व का अग्रणी उत्पादक ज्यादा समय तक न रह सके। चीन को जनसंख्या और अन्य संसाधनों में टक्कर भारत ही दे सकता है इसलिए अमेरिका का भारत की तरफ झुकाव बढ़ा। जबसे बाइडन की सरकार बनी तब से भारत और अमेरिका के सम्बन्धों में अंतर आ गया है। अफगानिस्तान के विषय पर जिस तरह अमेरिका की किरकिरी हुयी है उसके बाद भारत का भी पक्ष कमजोर हुआ है। अमेरिका एक तरफ भारत को चीन के साथ युद्ध के लिए तैयार करता रहा दूसरी तरफ वह यह भी नहीं चाहता है कि चीन को निर्यात

करने के क्रम में भारत बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाये। बस यही बाहर का दृष्टिकोण है जिसमें भारत के लिए इधर कुआं और उधर खाई वाली स्थिति है।

भारत के आंतरिक गतिरोध को भुनाते चीन, पाकिस्तान

अफगानिस्तान में उठापटक का बहुत व्यापक वैश्विक प्रभाव पड़ा है। अमेरिका और चीन के आर्थिक युद्ध के बीच पाकिस्तान की स्थिति मजबूत हो गयी है। उसे अफगानिस्तान में भी अनुकूल माहौल मिल गया है तो चीन से भी मदद मिल रही है। भारत का सहयोगी अमेरिका भी अब भारत का अभिन्न सहयोगी नहीं है। इससे मोदी के कमजोर होने के कारण भारत के अंदर राजनीतिक दलों में वैचारिक खाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि सीमाओं की सुरक्षा के विषय भी राजनीतिक विषय बनने लगे हैं। इसको इस तरह समझा जा सकता है कि अभी केंद्र सरकार द्वारा पंजाब, बंगाल और असम में अन्तराष्ट्रिय सीमा के 50 किमी के दायरे में सीमा सुरक्षा बल के द्वारा तलाशी लेने, जब्ती करने और गिरफ्तारी का अधिकार देने का निर्णय लिया गया। असम की सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया तो पंजाब और बंगाल की सरकारों ने इसका विरोध किया। इन लोगों का तर्क है कि इससे संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचेगा। अब इन विरोध करने वालों को शायद यह पता नहीं है कि राजस्थान में 50 किमी दायरे वाला यह नियम पहले से लागू है। गुजरात में तो यह सीमा एक समय में 80 किमी तक थी किन्तु अब वहां भी इसे घटाकर 50 किमी कर दिया गया है। इन लोगों के तर्कों के अनुसार तो राजस्थान और गुजरात संघीय ढांचे को कमजोर कर रहे हैं। वास्तव में बंगाल और पंजाब की सरकारों द्वारा विरोध सिर्फ विरोध तक सीमित है, उसका कोई वैचारिक आधार नहीं है।

केंद्र और मोदी के विरोध में अक्सर विपक्ष ऐसे ऐसे तर्क गढ़ देता है जो जाने अंजाने चीन के समर्थन वाले नजर आने लगते हैं। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठ रहा है कि राज्य की राजनीति के आगे क्यों यह क्षेत्रीय दल राष्ट्र को पीछे कर रहे हैं। केंद्र सरकार के फैसले के विरोध करने वाले लोग इस तथ्य को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं कि सीमा सुरक्षा बालों

के अधिकारों में वृद्धि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के साथ आतंकी घुसपैट रोकने के लिए की जा रही है। यदि पंजाब की बात करें तो अभी कुछ समय पूर्व ही पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस दौरान उनकी मांग थी कि पंजाब से सटी सीमाओं को सील किया जाये क्योंकि तमाम चौकसी के बाद भी सीमा पार से गतिविधियां निर्यात नहीं हो पा रही है। पंजाब कांग्रेस के कई बड़े नेता लगातार यह बात कहते रहे हैं कि क्या पंजाब का प्रशासन इस बात से अंजान है कि राज्य में ड्रग्स की तस्करी किस कदर बढ़ती चली जा रही है। पंजाब में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी पुलिस के सहयोग के बिना संभव नहीं है जो राज्य सरकार के आधीन होती है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के पसंदीदा तालिबान के होने के कारण पंजाब बार्डर तस्करी के लिए और ज्यादा मुफिद हो गया है। अब संघीय ढांचे को नुकसान तस्करी से होता है या तस्करी रोकने वाले कानून से, इसको समझने के लिए किसी राकेट साइन्स का जानकार होने की आवश्यकता नहीं है। चीन और पाकिस्तान भारत के अंदर के इन्ही गतिरोधों को भुनाते रहे हैं। कभी इसका स्तर कम रहता है तो कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।

कुल मिलाकर अगर देखा जाये तो मोदी के लिए चुनौतियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। वह जैसे ही एक चुनौती से निपटते हैं दूसरी उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। राजनीतिक विरोध और वैचारिक विरोध से तो निपटा जा सकता है किन्तु मौसम की मार के आगे वह भी लाचार हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली में भारी बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि जनता का मनोबल टूट गया है। महंगाई की मार झेल रहे लोगों पर मौसम की यह मार बहुत भारी पड़ी है। मोदी और उनकी टीम को अब वाह्य और आंतरिक चुनौतियां से कड़े तेवर से निपटने का जनता इंतजार कर रही है।

कश्मीर में शाह की हुंकार

● ललित गर्ग

केन्द्रीय गृहमन्त्री श्री अमित शाह ने एक बार फिर जटिल एवं अशांत होते जम्मू-कश्मीर राज्य के हालातों के बीच तीन दिवसीय दौरा करके अशांति पैदा करने वालों को न केवल चेताया है, बल्कि वहां के हिन्दुओं एवं सिखों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन भी दिया है। उनकी यह कश्मीर यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वे स्वयं अनुच्छेद 370 को हटाने के रचनाकार एवं साहसिक निर्णय लेने वाले मुख्य स्तंभ हैं, उन्होंने ही 5 अगस्त, 2019 को संसद के दोनों सदन में घोषणा की थी कि भारतीय संविधान में कश्मीर पर लागू किये गये अनुच्छेद 370 को अन्तहीन समय तक लागू नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह 'अस्थायी' प्रावधान था। कश्मीर पहुँचकर उन्होंने हुंकार भरते हुए जहाँ शांति में खलल पैदा करने वालों को ललकारा है, वहीं विकास योजनाओं के साथ सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की है, निश्चित ही हाल की खौफनाक आतंकी घटनाओं और उसके बाद प्रवासी मजदूरों के पलायन के सिलसिले को देखते हुए उनकी इस यात्रा से अनेक सकारात्मक संदेश जाने वाले हैं। यह यात्रा एक नये अध्याय की शुरुआत भी है।

शाह की यह यात्रा लोकतांत्रिक मूल्यों को भी सशक्त बनाने का माध्यम है। यह सही समय पर सही दिशा में कश्मीर में शांति, विकास एवं सुरक्षा को नये आयाम देने का सराहनीय उपक्रम है। लोकतंत्र एक पवित्र प्रणाली है। पवित्रता ही इसकी ताकत है। इसे पवित्रता से चलाने के लिये आम कश्मीरियों का इसमें विश्वास, जागरूक एवं सक्रिय होना जरूरी है, इसी विश्वास को बल देना इस यात्रा का उद्देश्य है। आतंकवादी एवं अलगाववादी लोगों की अपवित्रता से यह कमजोर हो जाती है। ठीक इसी प्रकार अपराध के पैर कमजोर होते हैं। पर अच्छे आदमी की चुप्पी उसके पैर बन जाती है। आतंकवाद एवं अलगाववाद अंधेरे में दौड़ते हैं।



रोशनी में लड़खड़ाकर गिर जाते हैं। आम कश्मीरियों को रोशनी बनना होगा। और रोशनी आतंक एवं अराष्ट्रीयता से प्राप्त नहीं होती।

श्री शाह भारतीय राजनीति के ऐसे कद्दावर एवं साहसिक निर्णय लेने वाले, देश की एकता को मजबूती देने वाले नेता हैं, जिन्होंने अपनी रणनीति से हिंसक, आतंकवादी एवं अराष्ट्रीय शक्तियों को उनकी जमीन दिखाई है, बल्कि यह भी जताया है कि शांति एवं राष्ट्रीय एकता की बाधक शक्तियों से कैसे निपटा जाता है। सख्त एवं कठोर निर्णयों से इन शक्तियों को सुधरने का अवसर भी दिया है। शाह के प्रयासों का ही परिणाम है कि पिछले सात वर्षों एवं अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद कश्मीर में लगभग शांति बनी रही। अब पाकिस्तान कश्मीर को पुनः अशांत करने में जुटा है, ऐसे समय में शाह का कश्मीर दौरा करना और पाकिस्तान और उसकी आतंकवादी शक्तियों को यह संदेश देना है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, जम्मू-कश्मीर में हर भारतवासी पूरी तरह सुरक्षित रहेगा चाहे हिन्दु हो या सिख, बिहारी हो या पंजाबी अथवा बंगाली।

जम्मू-कश्मीर राज्य में पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों बेअसर होती रही है। अब उसने नयी रणनीति उन गैर कश्मीरियों को निशाना बनाने की बनाई जो इस राज्य के

विकास और इसकी अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे। कश्मीर में विकास की जो गंगा प्रवहमान हुई है, वह अनवरत गतिमान रहेगी। सच्चाई है कि पिछले दो साल में इस राज्य में नागरिकों के विकास की कई केन्द्रीय परियोजनाएं चालू की गई हैं और उनके अच्छे परिणाम भी आने शुरू हुए हैं। पर्यटन गतिविधियां तेज हो रही हैं और भारत के विभिन्न राज्यों से इस खूबसूरत राज्य की सैर करने लोग भारी तादाद में आने लगे हैं। कश्मीरी जिस गर्मजोशी के साथ अपने भारतीय नागरिकों का स्वागत करते हैं और उनकी मेजबानी करते हुए अपनी सहृदयता, आत्मीयता और ईमानदारी की छाप छोड़ते हैं उससे पूरे भारत में जम्मू-कश्मीर की छवि में चार चांद लग रहे हैं और दूसरे राज्यों के लोगों से कश्मीरियों की आत्मीयता एवं सौहार्द बढ़ रहा है। आम कश्मीरी जनता एक नया संतोष महसूस कर रही है। यह स्थिति कई दृष्टियों से अनूठी है, प्रेरक है।

आजादी के अमृत महोत्सव मनाते हुए सम्पूर्ण राष्ट्र कश्मीर के साथ अंतरंगता एवं एकात्मता महसूस करने लगा है, इन सुखद स्थितियों को खंडित करने की पाकिस्तान की नयी रणनीति को असफल बनाने में भारतीय सेना के जवान अनूठे उपक्रम करते हुए आतंकियों को चुन-चुन कर मारने का जो

अभियान पिछले दस दिनों से चला रही है उससे राष्ट्रविरोधी तत्वों के हौसले पस्त होने जाहिर हैं। शाह ने इसके लिये न केवल सेना के अधिकारियों एवं जवानों को अधिक सतर्कता एवं सावधानी से अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिये जागरूक किया बल्कि इसमें किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के लिये भी चेताया है। शाह ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा का काम न केवल समग्रता से किया है बल्कि सुरक्षा व्यवस्था को अधिक दुरस्त एवं चैकस बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने सुरक्षा की गंभीर समीक्षा करते हुए उन कारणों को पहचानकर उनका निवारण किये जाने की आवश्यकता व्यक्त की, जिनके कारण आतंकियों और उनके समर्थकों ने फिर से सिर उठाने का दुस्साहस किया। कश्मीर में जितनी जरूरत आतंकियों पर दबाव बनाने और उन्हें बचकर निकलने के अवसर न देने की है, उतनी ही उनके समर्थकों पर शिकंजा कसने की है। आतंकियों के समर्थक केवल वे ही नहीं हैं, जो उन्हें शरण, सहायता एवं संरक्षण देते हैं, बल्कि वे भी हैं जो उनके पक्ष में माहौल बनाते हैं, जिनमें राजनेता, नौकरशाह एवं सरकारी कर्मचारी भी हैं। जो घर का भेदी लंका ढाहवे वाली स्थिति वाले होते हैं, इन खतरनाक एवं राष्ट्र-विरोधी तत्वों से कैसे निपटा जाये, यही इस सुरक्षा समीक्षा का मुख्य हार्द है, गहनता एवं समग्रता है।

श्री शाह की यह तीन दिन की यात्रा न केवल कश्मीर के लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से आश्वस्त करने का सक्षम वातावरण निर्मित करेगी बल्कि कश्मीर में राष्ट्रीयता को भी मजबूत बनायेगी। इसके लिये शाह को सबसे पहले यही श्रेय जाता है कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर पर पूरी तरीके से संविधान लागू करके इसे भारत में समावेशी रूप में अन्तर्गतता प्रदान की। क्योंकि आम कश्मीरी प्रारम्भ से ही भारतीयता के रंग में रंगा रहा है और उसने पाकिस्तान की मजहबी संकीर्ण मानसिकता एवं स्थानीय स्वार्थी राजनेताओं को कभी तवज्जो नहीं दी। यह भी ऐतिहासिक सच है कि 1947 में जब भारत को बांट कर पाकिस्तान बनाया जा रहा था तो कश्मीर की आम जनता इसके खिलाफ थी। इसकी खास वजह यही थी कि कश्मीरी संस्कृति किसी भी जेहादी या कट्टरपंथी विचारधारा का विरोध करती रही है। यही कारण है कि श्री शाह

के 370 समाप्त करने के फैसले का राज्य की जनता ने विरोध नहीं किया। भले आतंकवादी एवं अलगाववादी मानसिकता से जुड़े तथाकथित राजनेताओं को यह निर्णय खटका।

श्री शाह ने अपनी इस यात्रा में कश्मीर की जनता के दिलों में शांति, अमन एवं विकास की राष्ट्रीय धारा को बलशाली बनाया है। अपनी यात्रा के पहले दिन ही उन्होंने जम्मू-कश्मीर पुलिस के शहीद इंस्पैक्टर परवेज अहमद डार के निवास पर जाकर विनम्रता एवं आत्मीयता से पीड़ित परिवार के लोगों से भेंट की और शहीद की पत्नी को सरकारी नौकरी दी। यह संकेत इस



बात का है कि राष्ट्र के अस्तित्व एवं अस्मिता की सुरक्षा पर जान लुटाने वाले हर कश्मीरी का ध्यान सरकार रखेगी। इसके साथ ही उन्होंने श्रीनगर से शारजाह की हवाई यात्रा खोलने का भी ऐलान किया जिससे पूरी दुनिया को लगे कि कश्मीर नये माहौल, राष्ट्र की मूल धारा में पूरी तरह ढल चुका है और इसके लोग सामान्य भारतीयों की तरह ही मुल्क द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं। कश्मीरियों में इस विश्वास एवं आशा के प्रस्फुटित एवं पल्लवित होते अंकुर बताते हैं कि पाकिस्तान कभी भी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि हर कश्मीरी भारत का अभिन्न अंग है, हिस्सा है, भारतीयता ही उसकी आत्मा है, संस्कृति है। शाह की यात्रा पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देने का एक प्रभावी उपक्रम है कि वह

हिन्दू-मुसलमान या मजहब को आगे लाकर कश्मीरियों के उस विश्वास को नहीं डिगा सकता जो उनका भारत में है।

पाकिस्तान की कंगाली का कारण है एंटीनेशन होना

भारत में लगातार आतंकवादी गतिविधियों को पोषित करते हुए कश्मीर को हथियाने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान की नेशन से ज्यादा एंटीनेशन की तस्वीर सशक्त दिखाई देती है। अपनी इन कुचेष्टाओं एवं षड्यंत्रों से वह कभी भी सफल राष्ट्र न बन पाया है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दिवालियेपन के कगार पर है और वैश्विक वित्तीय निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानि एफएटीएफ के द्वारा उसे ग्रे-लिस्ट में रखे जाने पर उसकी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होना तय है। पहले पाकिस्तान बार-बार तुर्की की मदद से ब्लैक लिस्टेड होने से बचता रहा था और अब तुर्की खुद एफएटीएफ के लपेटे में आ गया है। इसकी वजह से उसे आर्थिक मदद मिलना मुश्किल होगा, जबकि पाकिस्तान को अगले दो सालों में अरबों डालर के ऋण की सख्त जरूरत है। अगर ऋण नहीं मिला तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी, गरीबी बढ़ेगी, महंगाई आसमान छूने लगेगी, आम जनता को दाने-दाने के लिये तरशना होगा। प्रश्न है कि गरीबी एवं कर्ज के दलदल में फंसा पाकिस्तान कब तक आतंकवाद को पोषित एवं पल्लवित करते हुए खुद अशांति का जीवन जीता रहेगा एवं दूसरे राष्ट्रों की शांति को भंग करता रहेगा? क्यों नहीं वह विकास एवं अमन-चैन को अपना लक्ष्य बनाता? शांति, अहिंसा एवं अयुद्ध का नजरिया ही पाकिस्तान की दशा एवं दिशा को बदल सकता है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने वादा किया था कि वह पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकालवाएंगे लेकिन यह वादा खोखला ही साबित हो गया। क्योंकि उनकी नीति एवं नियत दोनों ही खोट से भरी हैं, उनकी कथनी और करनी में बड़ा फासला है। एफएटीएफ ने अपनी निगरानी सूची अर्थात् ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को बनाए रखने का फैसला किया। इस फैसले के बाद

पाकिस्तान पर यह दबाव बढ़ गया है कि वह आतंकी संगठनों को पालने-पोसने से बाज आए, लेकिन वह शायद ही ऐसा करे। इसके आसार इसलिए कम हैं, क्योंकि आतंकी संगठनों को संरक्षण देना उसकी नीति का अभिन्न अंग है। वह केवल अपने यहां सक्रिय आतंकी संगठनों को ही नहीं पाल रहा है, बल्कि तालिबान और खासकर उनके साझीदार हक़ानी नेटवर्क के आतंकी सरगनाओं को भी हर तरह का सहयोग-समर्थन दे रहा है। भारत विरोधी गतिविधियां, कश्मीर का राग, आतंकवाद को पोषित करना-पाकिस्तानी राजनीति का पिछले 75 वर्षों से अहम हिस्सा रही है, इन्हीं भारत विरोधी गतिविधियों के कारण ही पाकिस्तान की सरकारों का ध्यान विकास एवं शांति पर न होकर आतंकवाद पर बना हुआ है। इसी कारण पाकिस्तान दुर्दशा एवं दुर्दिनों का शिकार हो रहा है।

इमरान खान आर्थिक मदद और ऋण लेने के लिए कटोरा लेकर घूमते रहते हैं। अमेरिका द्वारा फंड रोकने के बाद पाकिस्तान की कंगाली किसी से छिपी नहीं हुई। अब पाकिस्तान चीन की गोद में बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। तुर्की भी उसका हमदर्द रहा है, लेकिन अब उसको भी पाकिस्तान की तरह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और यूरोपीय संघ से आर्थिक मदद मिलना मुश्किल हो जाएगा। इन स्थितियों के कारण पाकिस्तान में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। राष्ट्र-निर्माण में जिन ठोस एवं बुनियादी चीजों एवं चरित्र की जरूरत होती है, वे सब किसी-न-किसी रूप में वहां मृग-मरीचिका की तरह नदारद हैं।

पाकिस्तान भारत में ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राष्ट्रों में भारतीयों एवं हिन्दुओं पर हमले करने के षड्यंत्र करता रहा है। हाल में बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो भीषण हमले हुए, उनके पीछे भी पाकिस्तान का हाथ है। बांग्लादेश के गृहमंत्री ने



इन हमलों के लिए अपने यहां के उन कट्टरपंथी संगठनों को दोषी ठहराया है, जिनका संबंध पाकिस्तान से है। निःसंदेह बांग्लादेश पाकिस्तान की ओर संकेत कर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता, उसे हिंदुओं को चुन-चुनकर निशाना बनाने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करनी होगी। इस समय भारत को पाकिस्तान पर नए सिरे से अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ाने के लिए सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि एक तो उसकी कठपुतली माने जाने वाले अधिकांश आतंकी अफगानिस्तान में काबिज हो गए हैं और दूसरे यह बात सामने आई है कि भारत को इसके लिए बांग्लादेश पर दबाव बनाने के साथ यह भी समझना होगा कि पाकिस्तान उसके लिए और बड़ा सिरदर्द बन रहा है। वह यदि अफगानिस्तान और बांग्लादेश में भारतीय हितों के खिलाफ काम करने के साथ कश्मीर में आतंकवाद को नए सिरे से हवा दे रहा है तो इसका अर्थ है कि भारत को उसके विरुद्ध अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करना होगा।

विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट से पता चलता है कि पाकिस्तान दुनिया के उन दस देशों की सूची में शामिल हो गया है, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा विदेशी कर्ज है। इसी बीच विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने अब अपना लोन कार्यक्रम रद्द कर दिया है, जिससे अब पाकिस्तान के लिए कर्ज जुटाना भारी पड़ रहा है। इसी वजह से अब पाकिस्तान के लिए आईएमएफ से किसी भी तरह 6 अरब डालर का कर्ज जुटाना ही होगा। आईएमएफ पाकिस्तान पर कड़ी शर्तें लाद रहा है। इसी बीच आशंकाएं जताई जा रही हैं कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां पाकिस्तान की

रेटिंग और ज्यादा गिरा सकती है, जिससे उसके लिए इंटरनेशनल ब्रांड जारी करके पैसा जुटाना और ज्यादा महंगा हो सकता है। ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को करोड़ों की मदद का ऐलान पाकिस्तान के लोगों को नागवार गुजर रहा है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का घरोंदा खंडों में बंटा हुआ है। भारत विरोधी मुहिम के आवेश एवं नासमझी

में पाकिस्तान के शासक सीधी से ज्यादा उल्टी चाल चलने के आदी हो गये हैं। पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा आतंकी गतिविधियों को संचालित करने में खर्च होता है। इस तरह के शोध भी हुए हैं जिनमें यह कहा गया है कि विदेशों से लिये गये कर्ज या अनुदान का आधा से अधिक हिस्सा पाकिस्तान हथियारों की खरीददारी और भारत विरोधी गतिविधियों में खर्च करता है। आखिर क्या कारण है कि पाकिस्तान की राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया में भारत विरोधी तेवर ज्यादा उग्र हो जाते हैं?

पाकिस्तान तो 72 वर्षों के अंतराल में यह तक नहीं समझ पाया कि एक आदर्श शासन-व्यवस्था की क्या जरूरतें होंगी? वैध शासन किसे कहा जाये? तानाशाहों की बनावटी जम्हूरियत को या लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर शांतिर भेड़िये की तरह दुबक के बैठी सैनिक अफसरशाही को। सैनिक तानाशाही एवं निर्वाचित सरकारों के बीच गुणात्मक अंतर बहुत ही क्षीण रहा है। एक वैध राष्ट्र-व्यवस्था अपने यहां कैसे कायम करें और खुद को लोकतंत्र विरोधी ताकतों के चंगुल में जाने से कैसे बचाये, यह वर्तमान पाकिस्तान की बड़ी जरूरत है। पाकिस्तान प्रकृति सम्पन्न राष्ट्र है, उसके भीतर पर्याप्त खनिज सम्पदा है, तेल की संभावनाएं भी हैं, उन्नत खेती की वहां के कृषि क्षेत्र में व्यापक संभावनायें हैं, अगर इन चीजों को आगे बढ़ाया जाये तो न सिर्फ विदेशी कर्ज को चुकाने की सामर्थ्य पैदा होगी, बल्कि आर्थिक रूप से एक मजबूत राष्ट्र बनकर उभर सकता है, अन्यथा आतंकवाद को पोषित करने के चक्कर में वह बद से बदतर स्थिति में पहुंचता रहेगा, कहीं टूट कर बिखर न जाये। कश्मीर का सपना देखना तो उसे बन्द करना ही होगा, अब भारत अपने कश्मीर की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। ■



QUAD-2

UAE, US और इजरायल के विदेश मंत्रियों के साथ एस जयशंकर की अहम बैठक

भा रत, इजरायल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय फोरम स्थापित करने का फैसला किया है। ये फैसला एक वर्चुअल बैठक में लिया गया। जिसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान और इजरायल के विदेश मंत्री यायर लैपिड शामिल थे।

सभी नेताओं ने आने वाले महीनों में दुबई में एक्सपो 2020 के दौरान मंत्रियों की एक व्यक्तिगत बैठक आयोजित करने की इच्छा भी जताई है। इस बैठक के दौरान, चारों मंत्रियों ने परिवहन, प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा, अर्थशास्त्र और व्यापार को लेकर चर्चा की। बातचीत के अंत में यह फैसला लिया गया कि प्रत्येक मंत्री वर्किंग ग्रुप के लिए वरिष्ठ स्तर का एक विशेषज्ञ नियुक्त करेंगे। जो इन सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए विकल्प तैयार करेंगे। जयशंकर इन दिनों इजरायल की पांच दिवसीय यात्रा पर हैं।

ब्लिंकन की बात पर जताई सहमति

जयशंकर ने ट्वीट किया, 'इजरायल के विदेश मंत्री यायर लैपिड, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के साथ पहली बैठक अच्छी रही। आर्थिक विकास



और वैश्विक मुद्दों पर एक साथ मिलकर काम करने को लेकर चर्चा की। शीघ्र कदम उठाने पर सहमति बनी है।' जयशंकर ने एक संक्षिप्त टिप्पणी में कहा, 'आप तीनों हमारे सबसे करीबी साझेदारों में से हैं।' उन्होंने ब्लिंकन की इस बात से सहमति जताई कि इस तरह का एक मंच तीन अलग-अलग द्विपक्षीय कार्यक्रमों की तुलना में बहुत बेहतर काम कर सकता है।

पश्चिम एशिया पर भी हुई चर्चा

उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि यह बहुत स्पष्ट है कि अपने समय के बड़े मुद्दों पर हम सभी की एक समान सोच है और यह काफी मददगार होगा अगर हम काम करने के लिए कुछ व्यावहारिक चीजों पर सहमत हो सकें।' अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने एक बयान में बताया कि ब्लिंकन ने तीनों समकक्षों के साथ व्यापार, जलवायु

परिवर्तन से निपटने, ऊर्जा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के जरिए पश्चिम एशिया और एशिया में 'आर्थिक और राजनीतिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।'

तीनों देशों को रणनीतिक साझेदार बताया

उन्होंने कहा कि मंत्रियों ने प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में लोगों के आपसी संबंध बढ़ाने और कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रकोप के दौरान विश्व स्तर पर जन स्वास्थ्य का कैसे समर्थन किया जाए, इस पर चर्चा की। ब्लिंकन ने ट्वीट किया कि बैठक में 'क्षेत्र और विश्व स्तर पर चिंता के साझा मुद्दों और हमारे आर्थिक और राजनीतिक सहयोग के विस्तार के महत्व पर चर्चा की।' ब्लिंकन ने एक बयान में, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और भारत को अपने तीन बड़े 'रणनीतिक साझेदार' के रूप वर्णित किया गया है।

ऊर्जा और जलवायु पर भी हुई बात

ब्लिंकन ने कहा, 'नए तरीके से दोस्तों को साथ लाकर, हम इन साझेदारियों को और व्यापक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह बैठक इसी बारे में है। यहां वाशिंगटन में बैठकर, मैं कह सकता हूँ कि इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और भारत हमारे तीन बड़े रणनीतिक साझेदार हैं। ऊर्जा, जलवायु, व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा आदि इन सभी परस्पर-व्यापक हितों को देखते हुए। यह वास्तव में एक दिलचस्प एवं अच्छा विचार प्रतीत होता है कि इस नई साझेदारी और पूरक क्षमताओं का इस्तेमाल अन्य क्षेत्रों में किया जाए।'

लैपिड ने नेटवर्क बनाने पर दिया जोर

वहीं लैपिड ने कहा, 'जिन चीजों की हम तलाश कर रहे हैं, उनमें से एक है तालमेल और हम इस बैठक के बाद यही कायम करने की कोशिश करेंगे। यह तालमेल ही हमें आगे साथ में काम करने में मदद करेगा। इस मेज पर हमारे पास क्षमताओं, ज्ञान और अनुभवों का एक अनूठा मेल है, जिसका उपयोग एक नेटवर्क बनाने के लिए किया जा सकता है, जिसे हम सभी बनाना भी चाहते हैं।'

ब्लिंकन और लैपिड को कहा शुक्रिया

यूईई के अल नाहयान ने ब्लिंकन और लैपिड का सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का

एक मंच बनाने का विचार रखने के लिए शुक्रिया अदा किया। भारत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, 'जयशंकर एक पुराने मित्र हैं। साथ ही भारत और यूईई के बीच मजबूत और विविधतापूर्ण संबंध हैं।' इसके बाद, चारों विदेश मंत्रियों ने इस चतुष्पक्षीय सहकारी योजना को वास्तविक रूप देने के वास्ते रणनीति बनाने के लिए बंद कमरे में चर्चा की।

अमेरिका-कनाडा ने ताइवान

जलडमरूमध्य के जरिए भेजा युद्धपोत

चीनी सेना ने ताइवान जलडमरूमध्य (Taiwan Strait) के जरिए अमेरिका और कनाडा द्वारा अपने युद्धपोत भेजने के लिए उन्हें चेतावनी दी

तालिबान: भारत की सही पहल

पिछले ढाई महिने से हमारी विदेश नीति बगले झांक रही थी। मुझे खुशी है कि अब वह धीरे-धीरे पटरी पर आने लगी है। जब से तालिबान काबुल में काबिज हुए हैं, अफगानिस्तान के सारे पड़ोसी देश और तीनों महाशक्तियां निरंतर सक्रिय हैं। वे कुछ न कुछ कदम उठा रही हैं लेकिन भारत की नीति शुद्ध पिछलग्गूपन की रही है। हमारे विदेश मंत्री कहते रहे कि हमारी विदेश नीति है- बैठे रहो और देखते रहो की! मैं कहता रहा कि यह नीति है- लेटो रहो और देखते रहो की। चलो, कोई बात नहीं। देर आया, दुरुस्त आया! अब भारत सरकार ने नवंबर में अफगानिस्तान के सवाल पर एक बैठक करने की घोषणा की है। इसके लिए उसने पाकिस्तान, ईरान, उजबेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन और रूस के सुरक्षा सलाहकारों को आमंत्रित किया है। इस निमंत्रण पर मेरे दो सवाल हैं।

पहला, यह कि सिर्फ सुरक्षा सलाहकारों को क्यों बुलाया जा रहा है? उनके विदेश मंत्रियों को क्यों नहीं? हमारे सुरक्षा सलाहकार की हैसियत तो भारत के उप-प्रधानमंत्री- जैसी है लेकिन बाकी सभी देशों में उनका महत्व उतना ही है, जितना किसी अन्य

नौकरशाह का होता है। हमारे विदेश मंत्री भी मूलतः नौकरशाह ही हैं। नौकरशाह फैसले नहीं करते हैं। ये काम नेताओं का है। नौकरशाहों का काम फैसलों को लागू करना है। दूसरा सवाल यह है कि जब चीन और रूस को बुलाया जा रहा है तो अमेरिका को भारत ने क्यों नहीं बुलाया? इस समय अफगान-संकट के मूल में तो अमेरिका ही है। क्या अमेरिका को इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है कि भारत ही उसका प्रवक्ता बन गया है? अमेरिकी हितों की रक्षा का ठेका कहीं भारत ने तो ही नहीं ले लिया है? यदि

इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं है।

तालिबान के काबुल में सत्तारूढ़ होते ही मैंने लिखा था कि भारत को पाकिस्तान से बात करके कोई संयुक्त पहल करनी चाहिए। काबुल में यदि अस्थिरता और अराजकता बढ़ेगी तो उसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पाकिस्तान और भारत पर ही होगा। दोनों देशों का दर्द समान होगा तो ये दोनों देश मिलकर उसकी दवा भी समान क्यों न करें? इसीलिए मेरी बधाई! यदि तालिबान के सवाल पर दोनों देश सहयोग करें तो कश्मीर का हल तो अपने आप निकल आएगा। इस समय अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत खादान की है। भुवमरी का दौर वहां शुरू हो गया है। यूरोपीय देश गैर-तालिबान संस्थाओं के जरिए मदद पहुंचा रहे हैं लेकिन भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। इस वक्त यदि वह अफगान जनता की खुद मदद करे और इस काम में सभी देशों की अगुवाई करे तो तालिबान भी उसके शुक्रगुजार हो जाएंगे और अफगान जनता तो पहले से उसकी आभारी है ही। विभिन्न



ऐसा है तो यह कदम भारत के स्वतंत्र अस्तित्व और उसकी संप्रभुता को ठेस पहुंचा सकता है। पता नहीं, पाकिस्तान हमारा निमंत्रण स्वीकार करेगा या नहीं? यदि पाकिस्तान आता है तो

देशों के सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में भारत क्या-क्या मुद्दे उठाए और उनकी समग्र रणनीति क्या हो, इस पर अभी से हमारे विचारों में स्पष्टता होनी जरूरी है।

विदेश नीति: हमारी दो नई पहल



ढाई महिने से गिरती-लुढ़कती हमारी विदेश नीति अपने पावों पर खड़े होने की कोशिश कर रही है, यह बात मेरे लिए विशेष खुशी की है। मैं बराबर पहले दिन से ही लिख रहा था कि भारत सरकार को तालिबान से सीधे बात करनी चाहिए लेकिन नौकरशाहों के लिए कोई भी पहल करना इतना आसान नहीं होता, जितना कि किसी साहसी और अनुभवी नेता के लिए होता है। जो भी हो, इस समय दो सकारात्मक घटनाएँ हुई हैं। पहली, मास्को में तालिबान के साथ हमारी सीधी बातचीत और दूसरी, अमेरिका, इस्त्राएल, यूएई तथा भारत के नए नए चौगुटे की शुरुआत! जहाँ तक मास्को-बैठक का सवाल है, उसमें रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ-साफ कहा है कि तालिबान की सरकार और नीतियाँ सर्वसमावेशी होनी चाहिए। उनमें सारे कबीलों और लोगों को ही प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए, बल्कि विभिन्न राजनीतिक शक्तियों का भी उसमें समावेश होना चाहिए याने हमिद करजई और अब्दुल्ला-जैसे नेताओं को भी शासन में भागीदारी मिलनी चाहिए अर्थात् तालिबान सरकार में कुछ अनुभवी और जनता में लोकप्रिय तत्व भी होने चाहिए। इसके अलावा लावरोव ने इस बात पर भी जोर दिया कि अब अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों में आतंकवाद का निर्यात कतई नहीं होना चाहिए। इस बैठक में चीन, पाकिस्तान और ईरान समेत 10 देश शामिल हुए थे। रूस ने वही बात इस बैठक में कही, जो भारत कहता रहा है। भारत के

प्रतिनिधि जे.पी.सिंग ने, जिन्हें काबुल में कूटनीति का लंबा अनुभव है, मास्को आए तालिबान नेताओं से खुलकर बात भी की और अफगान जनता की मदद के लिए पहले की तरह 50 हजार टन अनाज और दवाइयाँ भेजने की भी घोषणा की। यदि अगले कुछ हफ्तों में तालिबान सरकार का बर्ताव ठीक-ठाक दिखे तो कोई आश्चर्य नहीं कि उसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिलनी शुरू हो जाए। लेकिन गृहमंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने कल-परसों ही तालिबानी स्वीर में कुछ नीम की पत्तियाँ डाल दी हैं। उन्होंने ऐसे 'शहीदों' का सम्मान किया है और उनके परिजन को कुछ धनराशि भेंट की है, जिन्होंने पिछली सरकार के फौजियों और नेताओं पर जानलेवा हमले किए थे। ऐसी उत्तेजक कार्रवाई से उन्हें फिलहाल बचना चाहिए था। यदि भारत सरकार अपना दूतावास काबुल में फिर से खोल दे तो हमारे राजनयिक तालिबान को उचित सलाह दे सकते हैं। भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर पश्चिम एशिया में जो चौगुटा बनाया है, वह अफगान-संकट के हल में तो मददगार होगा ही, इस्लामिक जगत से भी भारत के संबंध मजबूत बनाएगा लेकिन भारत को दो बातों का ध्यान जरूर रखना होगा। एक तो वह अमेरिका का चप्पू होने से बचना रहे और दूसरा, इस नए चौगुटे को ईरान के खिलाफ मोर्चाबंदी न करने दे।

डॉ. वेदप्रताप वैदिक
भारतीय विदेश परिषद के अध्यक्ष हैं

हफ्ते ताइवान जलडमरूमध्य में पहुंचे। ये इलाका ताइवान को मुख्य चीनी भूभाग से अलग करता है।

अमेरिका और कनाडा द्वारा ऐसा किए जाने से चीन भड़क उठा और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पूर्वी थिएटर कमांड ने एक तीखी प्रतिक्रिया दी। इसने कहा कि अमेरिका और कनाडा ने परेशानी को भड़काने के लिए मिलीभगत की है। इससे ताइवान जलडमरूमध्य की शांति और स्थिरता को गंभीर रूप से खतरा पैदा हुआ है। बयान में कहा गया कि चीनी सुरक्षा बल हमेशा उच्च स्तर की सतर्कता बनाए रखते हैं और सभी खतरों और उकसावे का दृढ़ता से मुकाबला करते हैं। इस क्षेत्र में लंबे समय से तनाव बना हुआ है।

चीनी सेना ने ताइवान के पास किया सैन्य अभ्यास

दूसरी ओर, पेंटागन ने जोर देकर कहा है कि ताइवान जलडमरूमध्य के जरिए डेवी और विन्निपेग का गुजरना एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत के लिए अमेरिका और हमारे सहयोगियों और भागीदारों की प्रतिबद्धता को पारदर्शिता करता है। बीजिंग 'वन चाइना पॉलिसी' के तहत ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और इसकी स्वायत्तता को मान्यता नहीं देता है। अमेरिका के साथ जारी जुबानी जंग के बीच चीनी सेना ने पिछले हफ्ते एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें इसके जवान तटों पर लैंडिंग कर रहे थे। ये सैन्य अभ्यास ताइवान के दूसरी ओर स्थित फुजियान प्रांत में किया गया।

चीन और ताइवान के बीच क्यों हैं विवाद?

हाल के दिनों में चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ताइवान का अपना संविधान, सेना और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार है, जबकि चीन इसे अपना हिस्सा मानता है। ताइवान एक गृहयुद्ध के दौरान मुख्य चीनी भूभाग से अलग हो गया। इसके बाद चीन पर 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण हो गया। चीन, इस द्वीप को एक अलग प्रांत के रूप में देखता रहा है जबकि ताइपे में अधिकारियों ने एक देश, दो प्रणालियों के लिए चीन के प्रस्ताव को लगातार खारिज कर चुका है।

है। बीजिंग ने दावा करते हुए कि इस तरह के स्टंट क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालते हैं। चीन का ये बयान तब आया है, जब वो खुद ही पास के प्रांत में समुद्र तट अभ्यास कर रहा है। अमेरिकी अर्लें बर्क-क्लास गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉययर यूएसएस 'डेवी' और कनाडाई युद्धपोत एचएमसीएस 'विन्निपेग' दोनों पिछले



पेगासस केस में केंद्र को झटका

SC ने गठित की जांच कमेटी

पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को झटका देते हुए कहा कि पेगासस केस की जांच होगी, कोर्ट ने जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन भी कर दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार पर निशाने साधते हुए निजता के उल्लंघन, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे का भी जिक्र किया है। आइए अब आपको बताते हैं पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें क्या थीं।

1. कोर्ट ने इस मामले में कहा कि केंद्र सरकार का कोई साफ स्टैंड नहीं था। निजता के उल्लंघन की जांच होनी चाहिए। फैसला सुनाते हुए CJI एनवी रमना ने कहा कि हमने लोगों को उनके मौलिक अधिकारों के हनन से बचाने से कभी परहेज नहीं किया।
2. याचिकाओं में इस बात पर चिंता जताई है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जा सकता है ? प्रेस की स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण है, जो लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है, पत्रकारों के सूत्रों की सुरक्षा भी जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कई रिपोर्ट थीं। मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
3. CJI एनवी रमना ने आगे कहा, तकनीक जीवन को उन्नत बनाने का सबसे बेहतरीन औजार है, हम भी ये मानते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सबसे ऊंचा है, उनमें संतुलन भी जरूरी है। तकनीक पर आपत्ति सबूतों के आधार पर होनी चाहिए। प्रेस की आजादी पर कोई असर नहीं होना चाहिए। उनको सूचना मिलने के स्रोत खुले होने चाहिए।
4. तकनीक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि निगरानी में यह लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता को प्रभावित करता है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। यह प्रेस की स्वतंत्रता और उनके द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में भी है, ऐसी तकनीक का प्रेस के अधिकार पर प्रभाव



5. पड़ सकता है।
6. केंद्र सरकार पर निशाने साधते हुए कहा, केंद्र को बार-बार मौके देने के बावजूद उन्होंने सीमित हलफनामा दिया जो स्पष्ट नहीं था। अगर उन्होंने स्पष्ट किया होता तो हम पर बोझ कम होता ।
7. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को उनकी निजता के अधिकार के उल्लंघन से बचाया जाना चाहिए। पेगासस जासूसी का आरोप प्रकृति में बड़े प्रभाव वाला है। अदालत को सच्चाई का पता लगाना चाहिए।
8. कोर्ट ने केंद्र को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को उठाकर सरकार को हर बार फ्री पास नहीं मिल सकता।
9. न्यायिक समीक्षा के खिलाफ कोई

10. सर्वव्यापी प्रतिबंध नहीं है। केंद्र को यहां अपने रुख को सही ठहराना चाहिए था। अदालत को मूकदर्शक बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी।
9. न्यूज पेपर पर आधारित रिपोर्ट के आधार पर दायर की गई याचिकाओं से पहले हम संतुष्ट नहीं थे, लेकिन फिर बहस आगे बढ़ी। सॉलिसिटर जनरल ने ऐसी याचिकाओं को तथ्यों से परे और गलत मानसिकता से प्रेरित बताया था।
10. CJI एनवी रमना ने कहा, केंद्र द्वारा कोई विशेष खंडन नहीं किया गया है। इस प्रकार हमारे पास याचिकाकर्ता की दलीलों को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और इस प्रकार हम एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करते हैं जिसका कार्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखा जाएगा। ■



चुनाव की दहलीज पर राजनीतिक दलों का धार्मिक पर्यटन एवं नायकों की मूर्ति पूजा

उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन की अनेक संभावनाएं हैं। मथुरा, काशी, अयोध्या, गोला गोकर्णनाथ, नैमिषारण्य, प्रयागराज संगम, चित्रकूट जैसे अनेकों स्थान हैं जो उत्तर प्रदेश को धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज एवं फैजाबाद का नाम अयोध्या करने का धार्मिक पर्यटन पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। किसी देश के निर्माण में उसके नायकों का बड़ा योगदान होता है। इतिहास के पन्नों में ऐसे बहुत से चरित्र सिमटे होते हैं जिनके द्वारा समाज को प्रेरित किया जा सकता है। राजनीतिक व्यवस्था उन चरित्रों को अपनी सुविधानुसार प्रयोग करती हैं। इस सुविधानुसार के कारण ही विवाद होते हैं। अगर राजनीतिक व्यवस्था नायकों को जाति और धर्म के बंधन से ऊपर उठकर स्वीकार करना शुरू कर दे तो इसका संदेश बड़ा होगा। किन्तु राजनीतिक व्यवस्था वही कार्य करती है जैसा जनता चाहती है। जब जनता अपने जन नायकों का जाति और धर्म से ऊपर उठकर सम्मान करना स्वीकार कर देगी, हमारी राजनीतिक व्यवस्था भी उसी व्यवस्था के अनुरूप कार्य करना शुरू कर देगी। जैसे राम मंदिर निर्माण का एक जन आंदोलन जनता के बीच से उठा और आज वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसके कारण अयोध्या और आस पास के क्षेत्रों में काफी रोजगार उपलब्ध होने लगा है। अयोध्या की दीपवाली एतेहासिक होने लगी है। धार्मिक पर्यटन के द्वारा समाज में सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और राजनीतिक शुचिता भी बढ़ती है।

● अमित त्यागी

उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले राजनीतिक घमासान काफी तेज चल रहा है। राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। लखीमपुर में किसान आंदोलन की घटना में केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री के

बेटे के बहाने ब्राह्मण अस्मिता से खिलवाड़ का घटनाक्रम भी काफी चर्चित हुआ। किसान आंदोलन के नाम पर पहले खालिस्तानी समर्थकों ने अपना कब्जा कर किसान का विषय पीछे करने का प्रयास किया इसके बाद किसान नेताओं की आड़ में राकेश टिकैत इसके मुखिया बन गए। लखीमपुर घटना के बाद ब्राह्मण

बनाम सिख बनाने के प्रयास भी हुये। उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल ब्राह्मणों की भाजपा से नाराजगी को लगातार भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समय दे रही हैं उसके बाद कांग्रेस का ग्राफ लगातार मजबूत हो रहा है। प्रियंका द्वारा 2022 के लिए की जा रही मेहनत का परिणाम 2022 से ज्यादा

2024 में दिखने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर प्रकरण के बाद विपक्षी हमलों से विचलित हुये बिना जिस तरह योगी सरकार ने संयम का परिचय दिया उससे ब्राह्मण तबका अब भाजपा से पहले से ज्यादा संतुष्ट है। अब वह भाजपा के साथ रहेगा या विपक्षी खेमे में मतदान करेगा इस पर अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। हालांकि, केन्द्रीय मंत्री के पुत्र पर सरकार ने कार्यवाही की और जेल भेज दिया किन्तु यह दर्शाता है कि सरकार में बड़े नामों को बचाया नहीं जाता है। सपा की सरकार में ऐसे किसी का नाम आता तो शायद ही कोई कार्यवाही की जाती।

पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या बढ़ती महंगाई है। तेल, गैस और आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसके आगे सारे विषय, सारे समीकरण और सारी बातें धरी रह जाती हैं। ऐसे में सरकार को बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने के ठोस प्रयास जमीन पर दिखाने होंगे। रोजगार के साधन भी उपलब्ध करने होंगे। इसके साथ ही समाज में नए नायक गढ़ने होंगे जिनसे प्रेरित होकर समाज सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कर सकें। धार्मिक पर्यटन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में रोजगार उपलब्ध करवाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। जिस तरह जम्मू में अमरनाथ और वैष्णो देवी की यात्रा में सभी हिन्दू मुस्लिम बराबर का योगदान करके सहयोग करते हैं और रोजगार पाते हैं ऐसा ही उत्तर प्रदेश में माहौल तैयार करना होगा। रोजगार के इस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्थानीय एवं क्षेत्रीय नायकों को हिन्दू और मुस्लिम दोनों धर्मों से चुनना होगा। खासतौर पर दोनों समुदायों के पिछड़े वर्ग से क्योंकि वह सबसे ज्यादा वंचित रहा है।

अभी पिछले कुछ समय में प्रतीको के माध्यम से कई क्षेत्रीय एवं स्थानीय नायकों के नाम चर्चा में आये। राजा सुहेलदेव, सम्राट मिहिर भोज, राजा महेंद्र प्रताप सिंह कुछ ऐसे नाम हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट रहे हैं। सांस्कृतिक राजनीति और रणनीति में यह एक नया आयाम जुड़ रहा है। यह एक नए तरह की राजनीति है जिसमें मध्यकालीन राजाओं और औपनिवेशिक दौर में आजादी की लड़ाई के प्रतीकों को सम्मान दिया जा रहा है। जब भी किसी दौर के नायकों को सम्मान दिया जाता है

तब एक गर्व की अनुभूति होती है जो उस समाज से जुड़े लोगों के लिए चेतना का कार्य करता है। यह समूह को जोड़ने का माध्यम बनता है। इसके साथ ही नायकों का सम्मान राष्ट्रिय स्वाभिमान के साथ जातीय सम्मान प्रस्फुटित करता है। अब यहां यह समझना महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक व्यवस्था तो जातीय समीकरण साधने के लिए इन नायकों का सम्मान करती है और यह उनकी मजबूरी भी कही जा सकती है किन्तु अगर जनता इन नायकों को जाति से ऊपर उठकर पूरे समाज की प्रेरणा मानना शुरू कर दे तो यह सकारात्मक ऊर्जा वाला विषय बन जाएगा।

राजनीतिक व्यवस्था द्वारा बहराइच के राजा सुहेलदेव के नाम पर सुहेलदेव एक्सप्रेस चलायी गयी है। सुहेलदेव ने सैयद सालार गाजी उर्फ गाजी मियां को परास्त किया था। इनकी एक आदमकद प्रतिमा भी लगाई गयी है। चितौरा नामक गांव में बने उनके मंदिर का पुनर्निर्माण करवाकर वहां पार्क और पर्यटकों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी हैं। अब इस क्षेत्र में इस नायक के इर्द गिर्द रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसी तरह अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह की स्मृति में एक विश्वविद्यालय का उदघाटन किया गया है। हाथरस के राजा महेंद्र प्रताप सिंह जाट राजपरिवार से जुड़े थे। स्वतन्त्रता आंदोलन में भी उनकी एक बड़ी भूमिका रही थी। इसके साथ साथ सम्राट मिहिर भोज की एक आदमकद प्रतिमा का अनावरण योगी आदित्यनाथ के द्वारा दादरी में किया गया। भगवान विष्णु के अनन्य उपासक माने जाने वाले सम्राट मिहिर भोज का शासन नौवीं शताब्दी में उज्जैन से कन्नौज तक था। हालांकि, यह प्रतीक जातिगत राजनीति को साधने के लिए

राजनीतिक व्यवस्था ने चुने हैं किन्तु यदि इनके कार्यों को आधार माना जाये तो यह सभी के लिए सर्वमान्य होने चाहिए। सुहेलदेव को उत्तर प्रदेश में पासी और राजभर दोनों अपना नायक मानते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बहुलता है तो वहां राजा महेंद्र प्रताप सिंह को अपना नायक माना जाता है। सम्राट मिहिर भोज को गुर्जर एवं राजपूत अपना नायक मानते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तक इनका विस्तार है।

प्रतीकात्मक राजनीति के बड़े आयाम

महंगाई और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रहे कृषि आंदोलन के द्वारा भाजपा को राजनीतिक नुकसान होता दिख रहा है। ऐसे में जाट, गुर्जर अस्मिता के नाम पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह एवं सम्राट मिहिर भोज के नाम को भाजपा ने भुनाने का प्रयास किया है। अब राजनीतिक व्यवस्था तो राजनीति करेगी किन्तु किसी भी समाज के नायक का सम्मान होना गर्व की अनुभूति देता है। नायकों की स्मृतियां वर्तमान एवं क्षणिक विषयों पर भारी पड़ती हैं। स्मृतियां जन गोलबंदी का शक्तिशाली माध्यम होती हैं। स्मृति से अस्मिता का उद्गम होता है। लोगों को विषय हेतु जागरूक किया जाता है। मूर्तियां प्रतीकात्मक होती हैं और वह स्मृतियों को दीर्घकाल के लिए स्थापित कर देती हैं। इसके बाद उस क्षेत्र के आसपास उससे संबन्धित व्यापार शुरू हो जाता है जहां से रोजगार मिलने शुरू हो जाते हैं। इस तरह से व्यक्ति से व्यक्तित्व बना विचार स्थापित हो जाता है। वर्तमान में समाज के बहुत से ऐसे समूह उपस्थित हैं जो इतिहास में वह स्थान पाने से वंचित हो गए हैं जैसा उनको मिलना चाहिए



लखीमपुर हत्याकांड की पृष्ठभूमि

योगी बाबा ने सांपों के बिल में तेजाब डाल दिया है। अतः सांप अब बिलबिलाते फुफकारते हुए बाहर निकल रहे हैं...

धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक तथ्यात्मक सवाल की चर्चा तो अब शुरू हो गयी है कि 1947 के बाद पाकिस्तान से आए हुए जिन सिक्ख शरणार्थियों को उत्तरप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने सहानुभूति दशाते हुए उत्तरप्रदेश के तराई इलाके में खाली पड़ी सरकारी जमीन में से 12.5 एकड़ (50 बीघा) जमीन प्रति परिवार प्रदान की थी। आज वो 12.5 एकड़ जमीन के टुकड़े 120 से 1250 एकड़ तक बढ़े कैसे हो गए हैं?

जमींदारी उन्मूलन कानून के बाद उत्तरप्रदेश में 1961 में लैंड सीलिंग एक्ट बनाकर 12.5 एकड़ से अधिक जमीन रखने पर कानूनी रोक भी लग गई थी। लेकिन इसके बावजूद तराई के इलाकों में 12.5 एकड़ की जमीन के टुकड़े 125 से 1250 एकड़ तक का फार्म कैसे बन गए ?

इस सवाल का जवाब खून से रंगे हुए हदसों का वह खतरनाक शर्मनाक इतिहास है जिसकी एक झलक को लखीमपुर में 3 अक्टूबर को लाठी डंडों तलवारों से पीट पीटकर मौत के घाट उतारे गए 4 लोगों की मौत के वीडियो के माध्यम से पूरे देश ने देखा है और आज भी देख रहा है। लेकिन लखीमपुर की हिंसा को भ्रष्टाचारी मंडी में जमकर बेंच रहे न्यूजचैनल इस सच को दिखाना बताना तो दूर, इसकी चर्चा तक नहीं कर रहे हैं। जबकि लखीमपुर हिंसा इसी सवाल के जवाब में ही छुपी हुई है।

उत्तरप्रदेश के भूराजस्व विभाग के दस्तावेजों में दर्ज आंकड़ें यह बताते हैं कि 1947 में उत्तरप्रदेश के इस तराई इलाके में धारू और बुक्स जनजाति का बाहुल्य था। इलाके की लगभग ढाई लाख एकड़ से अधिक जमीन के मालिक धारू और बुक्स जनजाति के लोग ही थे। आज यह आंकड़ा घटकर लगभग 15 हजार एकड़ से भी कम हो चुका है।

तराई की इस उपजाऊ जमीन पर मालिकाना हक के समीकरण को पूरी तरह बदल देने के लिए अनपढ़ अनजान धारू और बुक्स जनजाति के लोगों पर कैसा कहर बरसाया गया। इसके बहुत दर्दनाक हजारों किस्से इस इलाके के जर्नल में दर्ज हैं। 60 और 70 के दशक में अज्ञात हत्यारों द्वारा दोनों जनजातियों के लोगों की नृशंस हत्याओं की ऐसी आंधी इस इलाके में चली थी कि उन्होंने

जान बचाकर भागने में ही भलाई समझी थी। कानूनी लड़ाई लड़ने लायक धन और समझ उन अनपढ़ निर्धन धारूओं के पास ही नहीं। धारू बुक्स जनजाति के अनपढ़ ग्रामीणों वनवासियों को एक बोटल शराब देकर उनकी एक एकड़ भूमि का सौदा किस तरह किया गया, इसकी अनेक कहानियां उत्तरप्रदेश के तराई इलाके के लखीमपुर, पीलीभीत, उधमसिंह नगर के वरिष्ठ नागरिकों से सुनी जा सकती हैं। सदियों से उनके पास रही उनके पुरखों की भूमि उस दौरान किस दरिंदगी के साथ कैसे कब्जा की जा रही है, यह सच्चाई जब सामने आने लगी तो 1981 में उत्तरप्रदेश सरकार ने कानून बनाकर गैर जनजाति के लोगों द्वारा धारू और बुक्स जनजाति की जमीन खरीदने पर रोक लगा दी थी। अतीत में हुए ऐसे सौदों को भी रद्द करने की घोषणा की थी। लेकिन 1981-82 में भड़क चुकी खालिस्तानी आतंकवाद की आग से सहमी सरकार अकाली दल के हंगामे और हड़दंग के दबाव में आ गयी थी। फलस्वरूप उत्तरप्रदेश में यह कानून कभी लागू ही नहीं हो सका। लगभग यही स्थिति लैंड सीलिंग एक्ट की रही। दोनों कानून केवल कागजों तक सीमित रहे। आश्चर्य की बात यह है कि इन दोनों कानूनों का विरोध उत्तरप्रदेश के राजनीतिक दलों के बजाए पंजाब का अकाली दल कर रहा था।

इसी तरह वन विभाग की हजारों हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा कर के बनाए गए 100, 200, 500, हजार, दो हजार एकड़ तक के आलीशान फार्म हाउस उत्तरप्रदेश में 12.5 एकड़ की लैंड सीलिंग वाले एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए तराई के इन जिलों में दिख जायेंगे। फर्जी नामों वाले फर्जी सदस्यों के ट्रस्ट बना के सीलिंग एक्ट को धता बताने का गोरखधंधा भी तराई के इस इलाके में जमकर प्रचलन में है। पंजाब के बादल परिवार, उसके परिजनों परिचितों समेत अकाली दल व पंजाब कांग्रेस के कई विधायकों सांसदों मंत्रियों के फार्म हाउस भी यहां मौजूद हैं। फर्जी नामों और कंपनियों वाले आलीशान विशाल बेनामी फार्म हाउसों की बहुत बड़ी संख्या भी इस क्षेत्र में है। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने 1998 में इन अवैध कब्जों पर सरकारी शिकंजा कसने की कोशिश की थी। तब केंद्र की अटल सरकार को निर्णायक समर्थन दे रहा अकाली दल उस कार्रवाई के विरोध में खुलकर सामने आ गया था। परिणामस्वरूप कार्रवाई कागजों तक ही सीमित रही। लेकिन इसका एक लाभ अवश्य

हुआ है। जमीन पर नजर आने वाले सैकड़ों हजारों एकड़ वाले आलीशान फार्म हाउसों का आकार सरकारी दस्तावेजों में कई गुना छोटा है। यह कहानी बहुत लंबी है। लेकिन यह कहानी अब अपने सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है।

जनजातियों की जमीन की खरीद पर रोक के कानून और लैंड सीलिंग एक्ट को धता बताकर तथा वन विभाग की हजारों हेक्टेयर भूमि पर कब्जा कर के बने हजारों फार्महाउसों, फर्जी ट्रस्टों पर मुख्यमंत्री योगी ने सरकारी शिकंजा कसना शुरू किया है। उनको नोटिस भेज दिए गए हैं। 12.5 एकड़ से अधिक जमीन पर खेती पर रोक लगा दी है। वन विभाग की हजारों हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा कर के बने आलीशान फाइवस्टार फार्महाउसों पर बुलडोजर चलवा के जमीन वापस लेने की मुहिम शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री योगी की इस कार्रवाई से तराई के इस इलाके से ज्यादा हड़कंप पंजाब के राजनीतिक गिरोहों के बड़े बड़े अड्डों में मच गया है। ये गिरोह खुलकर इस कार्रवाई का विरोध कर नहीं सकते। वो अगर ऐसा करेंगे तो जनता के सामने पूरी तरह नंगे हो जाएंगे। राजनेता के बजाए गरीब धारूओं और वन विभाग की सरकारी जमीन लूटने वाले भूमाफिया डकैत का उनका चेहरा और चरित्र पूरी तरह बेनकाब हो जाएगा। इसलिए तथाकथित किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तानी गुंडे खूनी हत्यारे अपराधियों को बुलाकर लखीमपुर में खून की होली खेली गयी है ताकि मुख्यमंत्री योगी और उनकी सरकार पर दबाव डाल कर उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके।

अतः यह समझने की आवश्यकता है कि लखीमपुर में जो हुआ है उसका किसानों से कोई लेनादेना नहीं है। लखीमपुर हिंसा का उद्देश्य मुख्यमंत्री योगी पर दबाव बनाकर रोकना है, जो गरीब धारूओं और उनकी जमीन इस चुके, वन विभाग की जमीन हड़प चुके जहरीले भूमाफिया सांपों के बिल में सरकारी कार्रवाई का तेजाब डाल रहे हैं।

- सतीश चन्द्र मिश्रा



गोरखपुर में 6 पुलिसियों द्वारा एक निर्दोष व्यापारी के नृशंस कत्ल के सम्बंध में

1. न तो यह पहला कत्ल है और न आखिरी। यह होता आया है और होता रहेगा।
2. होता इसलिए रहेगा क्योंकि इस वारदात में दुनिया ने बहुत साफ तरीके से ये देखा कि पुलिस-प्रशासन का सारा सिस्टम शुरू से ही कातिलों के पक्ष में और पीड़ितों के खिलाफ जम कर मुखर और सक्रिय था। एसएसपी वही कहानी सुना रहे थे जो कातिल इंस्पेक्टर ने लिखी थी।
3. होता इसलिए भी रहेगा क्योंकि ऐसे कातिलों को सजा देने में शासन प्रशासन की दिलचस्पी तभी जागती है जब बदनामी की आंच बहुत बढ़ जाती है। ऐसा एक लाख मामलों (जी एक लाख) में एक बार होता है। प्रदेश में तकरीबन हर जिले में 99,999 पुलिसिया उत्पीड़न और बर्बरता के मामले तो अखबारों की रुचि का विषय नहीं बन पाते। पीड़ित पैसा देने, पिटने या जुल्म सहने को अभिशप्त होते हैं। इसमें निरीह जनता से लेकर ताकतवर व्यापारी और रसूखदार लोग सब शामिल हैं। कोई बरी नहीं।
4. होता इसलिए भी रहेगा क्योंकि हर मामले में गुहार लगाने वाली मीनाक्षी गुप्ता नहीं होती जो घंटों तक डीएम और एसएसपी की लीपापोती की गुहार-धमकियां झेलती रही पर डिगी नहीं।
5. होगा इसलिए भी क्योंकि जगत नारायण जैसों के पैरोकार उसके पक्ष में ईमानदारी से



6. लगे रहेंगे। बेलघाट और बांसगांव में उसके द्वारा की गई हत्याओं को जैसे मैनेज किया, आगे भी करते रहेंगे।
6. यह सिलसिला इसलिए भी जारी रहेगा क्योंकि इसके खिलाफ मुखरता से सड़क पर लड़ने कोई जनप्रतिनिधि नहीं उतरता। वे आपको हर जगह दिखेंगे। भ्रष्ट इंजीनियर का तबादला रुकवाते हुए, भ्रष्ट पुलिसियों को बचाते हुए पर आपकी किसी परेशानी पर कतई नहीं दिखेंगे विपक्षियों को जबरन निकलने नहीं दिया गया।
7. यह इसलिए भी नहीं रुकेगा क्योंकि हम सबने अपनी आत्माएं बेच दी हैं। कभी जाति के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर बनी अपनी सरकारों के खिलाफ सही मुद्दे पर बोलना भी हमें अपराध लगता है। मीनाक्षी गुप्ता के समर्थन में आंसू बहाने वाले खुशी दुबे पर चुप रहते हैं। किसी पीड़ित के दुख पर, किसी आदमी को

प्रताड़ित होते देख कर, जबरन जेल में ठूस दिए गए लोगों को देखकर, खुलेआम प्रशासन और पुलिस की सीनाजोरी देखकर, दिन भर खुद अपने साथ होती नाजायज जबर्दस्तियों को देखकर भी हम चुप हैं। हमारा बोल देना, सहानुभूति में रो देना कहीं मोदी जी, योगी जी, ठाकरे जी, अश्विनेश जी या किसी और जी के खिलाफ चला गया तो क्या मुंह दिखाएंगे तब ?

पूरा सिस्टम सड़ चुका है। वेलफेयर स्टेट की अवधारणा का फेंकरवेल हो चुका है। 10 दिसंबर को हर साल मानवाधिकार दिवस मनाने वाले या अपनी कार/बाइक पर नेशनल और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट दुकानों का बोर्ड लगाकर चलने वाले किसी धंधेबाज ने इस मसले पर कोई बयान नहीं दिया है और अखबार वालों ने भी उनसे पूछने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है।

हर जगह भैंस लाठी वाले के कब्जे में हैं। पीछे सत्ता, नेता, अफसर सब हाथ बांधे खड़े हैं। इस हालात को अकेले बदल सकने की ताकत रखने वाले अखबार भी अब सच देखना, बोलना, कहना नहीं चाहते क्योंकि रिपोर्टरों और संपादकों के लिए ऐसा करना अब सम्भव नहीं रहा।

था।

चूंकि, भारतीय समाज अनेक जातियों और उपजातियों का एक समूह है इसलिए अक्सर उनके बीच इन अवसरों की प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा दिखती रहती हैं। इनमें आपस में प्रतिस्पर्धी भागीदारी भी दिखाई देती है। दादरी में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर राजपूत और गुर्जर समुदाय में आपस में हुआ विवाद इसका उद्धारण है। ग्वालियर में तो मिहिर भोज की मूर्ति का विषय ग्वालियर उच्च न्यायालय तक भी पहुंच गया। इसके बाद उच्च न्यायालय को विषय विशेषज्ञों, दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों एवं प्रशासन के प्रतिनिधियों की

एक समिति बनाकर विषय के निवारण का प्रयास किया गया। यानि कि एक बात तो स्पष्ट है कि इसका फायदा राजनीतिक व्यवस्था सदा से उठाती रही है। पर इन सबके बीच समाज का भला होता रहना चाहिए। सामाजिक न्याय का विषय सिर्फ जातियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि विभिन्न समुदायों के अनादर विभक्त उपजातियों के आपसी सामंजस्य का विषय भी होना चाहिए।

पिछड़े मुस्लिम से विन्धित को राष्ट्रनायक

ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदु समाज जातियों में विभक्त समाज है। मुस्लिम समाज भी उंच नीच,

अगड़ा पिछड़ा, दलित और आदिवासी समाज में बंटा हुआ है। सामाजिक स्तर पर राजनीतिक हिस्सेदारी के समय जाति आधारित भागीदारी की बात होती रही है। मुस्लिम समाज में आदिवासी प्रजातियों में वन गूजर, भील, सेपिया, बकरवाल जातियां हैं। दलित मुस्लिमों में मेहतर, भक्नों, नट, धोबी, हलालखोर, गोरकन आदि जातियां प्रमुखता से हैं। मुस्लिमों की पिछड़ी जातियों में धुनकर, ढफाली, तेली, बुनकर, कोरी आदि जातियां आती हैं। इसके साथ ही शेख, सैयद और पठान को अगड़ी जातियां माना जाता है। मुस्लिम समाज के अध्ययन पर बनी कई समितियों जैसे काका कालेलकर आयोग,

पर्यटन रोजगार- श्रीराम के जीवन चरित्र से रामराज स्थापना तक

नए स्थान पर जाना और वहां जाकर आनंद प्राप्त करना पर्यटन है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं मूर्त रूप ले चुकी हैं। राम सिर्फ हिंदुओं के आराध्य रहे हैं ऐसा नहीं है। रामराज में सिर्फ हिंदुओं के लिए अवसर रहे हो ऐसा भी नहीं है। रामराज एक आदर्श राज्य की अवधारणा है। उस सामाजिक सद्भाव का उद्धारण है जिसमें नेतृत्व क्षमता विकसित करके लक्ष्य प्राप्ति का संदेश है। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि राम जब वन में गए तो वह चाहते तो अन्य राजाओं से संरक्षण प्राप्त कर सकते थे। किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। सीता का अपहरण होने पर उन्होंने वंचितों को इकट्ठा करके सेना बनाई और विजय प्राप्त की। शबरी के बेर खाए और केवट के द्वारा नदी पार की। हनुमान में नेतृत्व क्षमता विकसित की और उन पर सम्पूर्ण विश्वास किया। इस तरह से रामराज का विचार सिर्फ एक कल्पना नहीं है बल्कि यह जमीन पर लायी जा चुकी सच्ची धियारी है।

आज के समय में जब मां बाप दोनों नौकरी पेशा हो चुके हैं तब ऐसे में सबसे बड़ी समस्या उनके द्वारा अपने बच्चों को समय न दे पाना होता है। कम समय देने के कारण बच्चों में संस्कार का तत्व प्रस्फुटित नहीं हो पाता है। जब हम अक्सर समाचारों में अपराध की खबरें सुनते हैं तो वह हमारे अंदर नकारात्मकता का भाव भर देती है। हम यह सोचते हैं कि कब समाज से अपराध खत्म होंगे ? हम अपने बच्चों को लेकर चिंतित हो जाते हैं। चूंकि अभिभावक नौकरी पेशा होने के कारण

समयाभाव में जूझ रहे होते हैं इसलिए सकारात्मक सोच के लोगों के लिए ऐसी खबरें दुख देने वाली होती हैं। बच्चों में बढ़ रही अपराधिक प्रवृत्ति की एक बड़ी वजह उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी होता है। समाधान की प्रक्रिया में सोचने पर हमें धार्मिक पर्यटन का महत्व समझ आता है। उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा प्रदेश है जिसमें धार्मिक पर्यटन के



वह सभी तत्व उपस्थित हैं जिसमें पर्यटन के साथ आनंद भी है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थानों का धार्मिक पर्यटन न सिर्फ घूमने का आनंद देता है बल्कि परिवार को बांधे रखने में भी सहायक होता है। मथुरा, काशी, अयोध्या, गोला गोकर्णनाथ, नैमिषारण्य, प्रयागराज संगम, चित्रकूट जैसे अनेकों स्थान हैं जो उत्तर

प्रदेश को धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाते हैं।

उदारीकरण का दौर आने के बाद भारत का बाजार जैसे ही विश्व के लिए खुला वैसे ही भोगवादी प्रवृत्ति का पुष्प और ज्यादा पल्लवित हो गया। किसी भी व्यक्ति की 'कय-शक्ति' सफलता का मापदंड बन गयी। जब सफलता का मापदंड 'कय-शक्ति' हो तब 'नैतिक-आचरण' जैसी बातें किताबी और अप्रयोगिक होने लगी। जनता की सोच भी बाजार के हिसाब से चलने लगी। जनता की आवाज सरकार की आवाज बनने लगी। इस तरह बाजार के द्वारा सत्ता और जनता को हईजैक कर लिया गया। जो बातें सामाजिक दृष्टि से अस्वीकार थीं वह स्वीकार की जाने लगी। महिला अधिकार और सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं को उपभोग की वस्तु दिखाकर पेश किया जाने लगा। बाजार में बिकने वाले हर सामान की मोडेल कम कपड़ों की लड़की होने लगी चाहे उस उत्पाद का उस महिला से कुछ लेना देना हो या न हो। सनी लियोने को एक वैश्विक अन्तराष्ट्रीय व्यापारिक षड्यंत्र के अंतर्गत भारत में प्रचारित एवं प्रसारित किया गया। पॉर्न बाजार भारत में एक बड़ा बाजार बन कर उभरा। इस तरह से भारत के पूरे सांस्कृतिक परिदृश्य को छिन्न-भिन्न करके योग से भोग की तरफ मोड़कर एक बड़ा बाजार पैदा हो गया।

-अमित त्यागी

मण्डल आयोग, रंगनाथ मिश्र आयोग एवं सच्चर समिति ने जातिगत विभेद को स्वीकार किया है। मण्डल आयोग के लागू होने के बाद मुस्लिम समाज की पिछड़ी जातियों के लोगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ मिला। परमान्दा मुस्लिम की स्थिति पहले से सुधर गयी। इस तरह से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को स्थापित किया गया। इस तरह से मुस्लिम समाज के नायकों को स्थापित करके उनको प्रोत्साहित किया जा सकता है। वीर अब्दुल हमीद, डॉ कलाम, दारा शिकोह जैसे अनेक व्यक्तित्व रहे हैं जिनके नाम पर प्रतिमा आदि लगाकर समाज को

प्रेरित किया जा सकता है। इनके नाम पर रोजगार पैदा किया जा सकता है।

ऐसा करने से हर गली चौराहे पर कुकरमुत्तों की तरह उगने वाली मजार प्रवृत्ति से भी छुटकारा मिलेगा और मुस्लिम समाज के लोगों को उनके बीच से प्रभावी नेतृत्व भी मिलेगा। अभी तक मुस्लिम समाज के पास स्वयं का नेतृत्व करने वालों का नहीं बल्कि उनका तुष्टीकरण करने वालों का कब्जा रहा है। मुस्लिमों की संस्थाएं जैसे मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड, जमाते इस्लामी, जमीयत उलेमा, मिस्ली काउंसिल, वक्फ बोर्ड, मदरसों आदि में आदिवासी, दलित और पिछड़े मुसलमानों की

भागीदारी लगभग शून्य है। ऐसी संस्थाएं अशराफ़ मुसलमान या यूँ कहें शासक वर्ग द्वारा संचालित हैं। यह समाज सामाजिक न्याय के प्रश्न पर खामोश हो जाता है। इसकी अनदेखी कर देता है। अब सवाल यह है कि क्यों मुस्लिम समाज अपने अंदर के सामाजिक प्रतीकों को बाहर नहीं ला रहा है। ऐसा करने से किसके हितों को नुकसान हो सकता है। कौन हैं जो मुस्लिम समाज के पिछड़ों को आगे बढ़ने से रोकना चाहता है? मुस्लिम समाज की मौजूदा स्थिति न उनके हित में है न देश के। जब तक हिन्दू समाज के पिछड़े वर्ग की तरह मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन पर काम नहीं होगा तब तक

दीपावली - आध्यात्मिक तीर्थ और सप्तपुरी में से एक है अयोध्या धाम

भारत भूमि पर अयोध्या ऐसा पुण्य स्थान है जहाँ का आध्यात्मिक पक्ष बहुत समृद्ध है। सनातन, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बीच अयोध्या बेहद चर्चित स्थान है। सनातन धर्म के अनुयायियों की आस्था जिन सात पुरियों में है, अयोध्या उनमें से एक है। प्राचीन काल में सरयू नदी के किनारे पर बसे अयोध्या को कौशल धाम भी कहा जाता था। अयोध्या में कई महान योद्धा, ऋषि-मुनि और अवतारी पुरुषों के जन्म होने के कारण इसका आध्यात्मिक महत्व बढ़ जाता है। जैन मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ सहित 5 तीर्थकरों का जन्म हुआ था। जैन परंपरा के अनुसार 24 तीर्थकरों में से 22 इक्ष्वाकु वंश के

थे। इन 24 तीर्थकरों में से सर्वप्रथम तीर्थकर आदिनाथ (ऋषभदेव जी) के साथ चार अन्य

मान्यताओं के अनुसार बुद्ध देव ने अयोध्या अथवा साकेत में 16 वर्षों तक निवास किया था। सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर की स्थापना विवस्वान (सूर्य) के पुत्र वैवस्वत मनु महाराज द्वारा की गई थी। वैवस्वत मनु लगभग 6673 ईसा पूर्व हुए थे। ब्रह्माजी के पुत्र मरीचि से कश्यप का जन्म हुआ। कश्यप से विवस्वान और विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु का जन्म माना जाता है। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र माने जाते हैं। जिनके नाम इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यन्त, करुष, महबली, शर्याति और पृषध थे। इसमें इक्ष्वाकु कुल का ही ज्यादा विस्तार हुआ। इक्ष्वाकु कुल में ही आगे चलकर प्रभु श्रीराम हुए। अयोध्या पर महाभारत काल तक इसी वंश के लोगों का शासन रहा।



तीर्थकरों का जन्मस्थान भी अयोध्या है। बौद्ध

तक इसी वंश के लोगों का शासन रहा।

देश को एकजुट रखने का स्वप्न स्वप्न ही रहेगा। इसके लिए मुस्लिम समाज से सीको को चिन्हित करके आगे लाना ही आवश्यक समाधान दिखता है।

यूरोप की पर्यटन अर्थव्यवस्था प्रेरणास्रोत

पर्यटन और रोजगार का गहरा संबंध है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को रोजगार का प्रमुख उत्पादक बनाया जा सकता है। इसके लिए समाज को एकजुट रखना पहली शर्त है। जाति और धर्म की सीमाओं को व्यापार में संतुलित रखना दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है। यूरोप के कई देश सिर्फ पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था पर आश्रित हैं। स्विट्जरलैंड जैसे छोटे देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार पर्यटन है। अर्थव्यवस्था का आधार बनाने के लिए इन देशों ने मेहनत भी की है। उन्होंने न सिर्फ अपने यहां के प्राकृतिक सौन्दर्य को संरक्षित किया बल्कि नागरिकों को प्रशिक्षित किया ताकि वह पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग बन सकें। उत्तर प्रदेश में भी धार्मिक पर्यटकों के लिए कुशल गाइड तैयार करने की आवश्यकता है। पर्यटकों के आने पर होटल व्यवसाय, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय, टुरिस्ट गाइड सहित अनेकों क्षेत्र में रोजगार सृजित होने लगते हैं। इस रोजगार सृजन का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि यह उसी स्थान

पर सृजित होते हैं जिस स्थान पर व्यक्ति निवास करता है।

यह बड़े शहरों में रोजगार की तलाश करने जाने वाले नौजवानों के कारण बढ़ती शहरी आबादी को भी नियंत्रित करता है। कोरोना के बाद वापस गांव लौटें लाखों लोगों के लिए पर्यटन सरकार को बहुत सी समस्याओं का हल प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन का राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय बड़ा बाजार मौजूद है। विश्व में बौद्ध धर्म को मानने वाले एक बड़े वर्ग के लिए सारनाथ एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। अन्तराष्ट्रिय पर्यटकों के आगमन को यदि हम सुलभ बना देते हैं तो यह उत्तर प्रदेश की वैश्विक पहचान का माध्यम बन जायेगा। उत्तर प्रदेश में भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या एवं भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा एक बड़े पर्यटक स्थल हैं। बनारस के घाट अगर आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर हैं तो लखनऊ अपनी नक्काशी के लिए। आगरा में स्थित ताजमहल तो विश्व की धरोहर है ही। दुधवा और जिम कार्बेट जैसे नेशनल पार्क भी उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। अब उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी भी बन रही है। धार्मिक पर्यटन के इन क्षेत्रों को जितना ज्यादा प्रचारित और प्रसारित किया जायेगा उतना ही ज्यादा इन क्षेत्रों में रोजगार सृजन संभव होता जायेगा और सामाजिक सद्भाव बढ़ेगा।

चार साल की सनातन चेतना का असर -

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के चार साल से ज्यादा के कार्यकाल में उन्होंने सनातन चेतना जागृत करने का एक बड़ा कार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज एवं फैजाबाद का नाम अयोध्या करने का धार्मिक पर्यटन पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। ऋग्वेद में कहा गया है कि किसी पदार्थ का नाम रखकर उसे पहचानना ज्ञान का प्रथम चरण है। शब्द और उसके अर्थ ही दीर्घ काल में बोध सम्पदा बन जाया करते हैं। पूरी दुनिया में सांस्कृतिक आधार पर नामों में परिवर्तन होते रहे हैं। पर्शिया का नया नाम आज ईरान है। आज जो म्यांमार है वह पहले बर्मा था। आज का जॉर्डन पहले ट्रंसजार्डन था। श्रीलंका का पूर्व नाम सीलोन था। इस तरह से वह पूरा परिक्षेत्र जिसमें भारतीय संस्कृति निवास करती थी उसका नाम आर्यावर्त था। नाम परिवर्तन मात्र बाजार और चर्च की अवधारणा से लोहा लेते हुये सांस्कृतिक पुनर्स्थापना की शुरुआत था। इन सबका असर आम आदमी के मनमस्तिष्क पर आज भी विराजमान है। अब योगी सरकार को सबसे महत्वपूर्ण विषय महंगाई, किसान पर अपना ध्यान केन्द्रित करना है क्योंकि यही वह सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं जहां से पानी रिस सकता है।

बेहतर भविष्य का द्योतक है खाद्य सुरक्षा

• डॉ.शंकर सुवन सिंह

विश्व भर में, हर वर्ष 60 करोड़ लोग अस्वच्छ और असुरक्षित भोजन के सेवन से बीमारी का शिकार होते हैं और चार लाख से अधिक लोगों की मौत होती है। स्वच्छ एवं सुरक्षित भोजन, बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और भुखमरी का अन्त करने के लिये अहम है। हम जो भोजन चुनते हैं और जिस तरह से हम उसका सेवन करते हैं, वह हमारे स्वास्थ्य और हमारे ग्रह के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। कृषि-खाद्य प्रणालियों के काम करने के तरीके पर इसका प्रभाव पड़ता है। जीवन जीने के लिए खाद्य पदार्थों की मूलभूत आवश्यकता होती है। वर्ष 2021 विश्व खाद्य दिवस की थीम है- 'स्वस्थ कल के लिए अब सुरक्षित भोजन' (सेफ फूड नाउ फॉर ए हेल्थी टुमरो)। आहार शुद्ध और पौष्टिक होना चाहिए। सुरक्षा का तात्पर्य है खतरे की चिंता से मुक्ति। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है- खाद्य की कमी के खतरे की चिंता से मुक्ति। खाद्य सुरक्षा का मतलब है समाज के सभी नागरिकों के लिए जीवन चक्र में पूरे समय पर्याप्त मात्रा में ऐसे विविधतापूर्ण भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित होना, यह भोजन सांस्कृतिक तौर पर सभी को मान्य हो और उन्हें हासिल करने के समुचित माध्यम गरिमामय हों। खाद्य सुरक्षा की इकाई देश भी हो सकता है, राज्य भी और गांव भी। खाद्य सुरक्षा की अवधारणा व्यक्ति के मूलभूत अधिकार को परिभाषित करती है। अपने जीवन के लिये हर किसी को निर्धारित पोषक तत्वों से परिपूर्ण भोजन की जरूरत होती है। महत्वपूर्ण यह भी है कि भोजन की जरूरत नियत समय पर पूरी हो। किसी क्या खूब कहा है- भूखे भजन न होए गोपाला! पहले अपनी कंठी माला। भूखे पेट तो ईश्वर का भजन भी नहीं होता है। फिर विकास की बात सोचना अपने को अंधेरे में रखने के सामान है। इसका एक पक्ष यह भी है कि आने वाले समय की अनिश्चितता को देखते हुए हमारे भण्डारों में पर्याप्त मात्रा में अनाज सुरक्षित हों, जिसे जरूरत पड़ने पर तत्काल जरूरतमंद लोगों तक सुव्यवस्थित तरीके से पहुंचाया जाये। भोजन का



अधिकार एक व्यक्ति का बुनियादी अधिकार है। केवल अनाज से हमारी थाली पूरी नहीं बनती है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें विविधतापूर्ण भोजन (अनाज, दालें, खाने का तेल, सब्जियां, फल, अंडे, दूध, फलियां, गुड़ और कंदमूलों) की हर रोज जरूरत होती है ताकि कार्बोहायड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा किया जा सके। भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने में सरकार की सीधी भूमिका है क्योंकि अधिकारों का संरक्षण नीति बना कर ही किया जाता है और सरकार ही नीति बनाने की जिम्मेदारी निभाती है। यदि यह विविधता न हो तो हमारा पेट तो भर सकता है, परन्तु पोषण की जरूरत पूरी न हो पाएगी। सामान्यतः केवल गरीबी ही भोजन के अधिकार को सीमित नहीं करती है; लैंगिक भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार के कारण भी लोगों के भोजन के अधिकार का हनन हो सकता है। पीने के साफ पानी, स्वच्छता और सम्मान भी भोजन के अधिकार के हिस्से हैं। हाल के अनुभवों ने सिखाया है कि राज्य के अनाज गोदाम इसलिये भरे हुए नहीं होना चाहिए कि लोग उसे खरीद पाने में सक्षम नहीं हैं। इसका अर्थ है कि सामाजिक सुरक्षा के नजरिये से अनाज आपूर्ति की सुनियोजित व्यवस्था होना चाहिए। यदि समाज की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित रहेगी तो लोग

अन्य रचनात्मक प्रक्रियाओं में अपनी भूमिका निभा पायेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार का दायित्व है कि बेहतर उत्पादन का वातावरण बनाये और खाद्यान्न के बाजार मूल्यों को समुदाय के हितों के अनुरूप बनाये रखे। खाद्य सुरक्षा रूपी मकान के चार प्रमुख स्तम्भ हैं- 1. भोजन की उपलब्धता, 2. भोजन की पहुंच, 3. भोजन का सदुपयोग, 4. भोजन की स्थिरता। यह स्तम्भ खाद्य सुरक्षा को गति और सही दिशा देते हैं। मकान और स्तम्भ दोनों का आधार पोषण है। कहने का तात्पर्य बिना पोषण के खाद्य सुरक्षा का कोई मतलब नहीं है। पोषण की सुरक्षा एक ऐसी स्थिति है जब सभी लोग हर समय पर्याप्त और जरूरी मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन का वास्तव में उपभोग कर पाते हों। जीवन को सक्रीय और स्वस्थ रूप से जीने के लिए जरूरी इस भोजन में विभिन्नता, विविधता, पोषण तत्वों मौजूदगी और सुरक्षा भी निहित हो। खाद्य सुरक्षा के व्यावहारिक पहलू निम्नवत हैं- उत्पादन- यह माना जाता है कि खाद्य आत्मनिर्भरता के लिए उत्पादन में वृद्धि करने के निरन्तर प्रयास होते रहना चाहिए। इसके अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप नई तकनीकों का उपयोग करने के साथ-साथ सरकार को कृषि व्यवस्था की बेहतर के लिये पुनर्निर्माण की नीति अपनाना

चाहिए। वितरण- उत्पादन की जो भी स्थिति हो राज्य के समाज के सभी वर्गों को उनकी जरूरत के अनुरूप अनाज का अधिकार मिलना चाहिए। जो सक्षम है उसकी क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए आजीविका के साधन उपलब्ध होना चाहिए और जो वंचित एवं उपेक्षित समुदाय हैं (जैसे- विकलांग, वृद्ध, विधवा महिलायें, पिछड़ी हुई आदिम जनजातियां आदि) उन्हें सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा करवाना राज्य का अधिकार है। आपातकालीन व्यवस्था में खाद्य सुरक्षा समय की अनिश्चितता उसके चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक आपदायें समाज के अस्तित्व के सामने अक्सर चुनौतियां खड़ी करती हैं। ऐसे में राज्य यह व्यवस्था करता है कि आपात कालीन अवस्था (जैसे- सूखा, बाढ़ या चक्रवात) में प्रभावित लोगों को भुखमरी का सामना न करना पड़े। खाद्य सुरक्षा के तत्व- उपलब्धता-प्राकृतिक संसाधनों से खाद्य पदार्थ हासिल करना- सुसंगठित वितरण व्यवस्था, पोषण आवश्यकता को पूरा करना, पारम्परिक खाद्य व्यवहार के अनुरूप होना, सुरक्षित होना, उसकी गुणवत्ता का मानक स्तर का होना।

आर्थिक पहुंच

यह सुनिश्चित होना चाहिए कि खाद्यान्न की कीमत इतनी अधिक न हो कि व्यक्ति या परिवार अपनी जरूरत के अनुरूप मात्रा एवं पोषण पदार्थ का उपभोग न कर सके। स्वाभाविक है कि समाज के उपेक्षित और वंचित वर्गों के लिये सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के जरिये खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जाना चाहिए।

भौतिक पहुंच

इसका अर्थ यह है कि पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न हर व्यक्ति के लिये उसकी पहुंच में उपलब्ध होना चाहिए। इस सम्बन्ध में शारीरिक-मानसिक विकालांगों एवं निराश्रित लोगों के लिए पहुंच को सुगम बनाना जरूरी है। मानव अधिकारों की वैश्विक घोषणा(1948)का अनुच्छेद 25(1)कहता है कि हर व्यक्ति को अपने और अपने परिवार को बेहतर जीवन स्तर बनाने, स्वास्थ्य की स्थिति प्राप्त करने का अधिकार है जिसमें भोजन, कपड़े और आवास की सुरक्षा शामिल है। खाद्य एवं कृषि संगठन(एफ.ए.ओ.)ने 1965 में अपने संविधान की प्रस्तावना में घोषणा की कि मानवीय समाज की भूख से मुक्ति सुनिश्चित करना उनके बुनियादी उद्देश्यों में से एक है। समानता और सम्मानजनक व्यवहार एक बुनियादी शर्त है। जब रिश्ते बेहतर होते हैं तो समस्याओं को हल करना बहुत आसान हो जाता है।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून, नियम एवं संगठन कुछ इस प्रकार हैं -

1. अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम(आई.एच.आर, 2005),
2. इन्फोसानडू यह एफएओ और डब्ल्यूएचओ द्वारा सूचना विनिमय और सहयोग के लिए संयुक्त रूप से बनाया गया खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नेटवर्क है।
3. कोडेक्स अलीमेंटेरियस कमीशन(सी.ए.सी.)- यह स्वास्थ्य संबंधी और पौष्टिक भोजन की गुणवत्ता(डब्ल्यू.एच.ओ और

एफ.ए.ओ संयुक्त कार्यक्रम)से संबंधित वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर स्थापित वैश्विक मानक है।

4. हार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट सिस्टम (एच. ए. सी. सी. पी.)- यह एक प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम है जो खाद्य उत्पादन प्रक्रिया में संभावित खतरों को पहचानता है और खतरों को होने से रोकने के लिए हरसंभव विकल्प बतलाता है।

5. गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज/अच्छा निर्माण अभ्यास (जी.एम.पी.)- यह सुरक्षित और पौष्टिक भोजन का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सेनेटरी और प्रसंस्करण आवश्यकताओं को दर्शाता है।

6. फूड रि कॉल- फूड रि कॉल को आपूर्ति श्रृंखला से खाद्य पदार्थों(जो उपभोक्ताओं के लिए बिक्री, वितरण या उपभोग के दौरान सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकते हैं) को हटाने के लिए की गई कार्रवाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह खाद्य श्रृंखला के किसी भी स्तर पर बाजार से खाद्य पदार्थों को हटा सकता है, भले ही खाद्य पदार्थ उपभोक्ताओं तक पहुंच चुका हो। शब्द 'वापसी' का उपयोग व्यापक रूप से 'फूड रि कॉल' के संबंध में किया जाता है।

7. यूज बाय डेट / उपयोग-दर-दिनांक(सुझाई गई अंतिम उपभोग की तारीख या समाप्ति की तिथि)डू यह वह अनुमानित अवधि है जिसके उपरांत उत्पाद की गुणवत्ता या तो नष्ट हो जाती है या काफी कम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि उत्पाद की गुणवत्ता एवं उपभोक्ता के लिए उसकी उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए 'यूज बाय डेट' से पहले-पहले उत्पाद को प्रयोग में ले आना चाहिए।

8. एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण एवं खाद्य सुरक्षा / वन हेल्थ एंड फूड सेफ्टी- खाद्य सुरक्षा के लिए एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण अपनाकर मानव और पशु चिकित्सा सहित वन्यजीव और जलीय स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी समुदायों के साथ पोषे रोग विज्ञान समुदायों सहित कई स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों से विशेषज्ञों और संसाधनों को एकीकृत कर उनके विचारों का समावेश करना एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण एवं खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आता है (आई ओ एम, 2012),

9. एफ.एस.एस.ए.आई - भारत में खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और मानकों का निरीक्षण करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण



(एफ. एस. एस. ए. आई.) को 2006 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित किया गया था।

10. आई.एस.ओ. 22000 - आई.एस.ओ. 22000 एक मानक है जिसे खाद्य सुरक्षा के मानकीकरण के लिए गठित अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा विकसित किया गया है।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ उपाय इस प्रकार हैं -

अ) नीति निर्माताओं द्वारा अनुसरण किये जाने वाले प्रयास- i) पर्याप्त भोजन प्रणाली और बुनियादी ढांचे का निर्माण और रखरखाव, ii) बहु-क्षेत्रीय सहयोग एवं सहकार्यता (विशेष रूप से पशुपालन और कृषि क्षेत्रों में), iii) खाद्य सुरक्षा को व्यापक खाद्य नीतियों और कार्यक्रमों में एकीकृत करना (विशेष रूप से पोषण और खाद्य सुरक्षा), iv) विश्व स्तर पर सोचें एवं स्थानीय रूप से कार्य करें- घरेलू स्तर पर निर्मित भोजन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा को सुनिश्चित करना।

ब. खाद्य संचालकों और उपभोक्ताओं द्वारा अनुसरण किये जाने वाले प्रयास-i) भोजन की पर्याप्त जानकारी एवं खराब भोजन द्वारा होने वाली आम बीमारियों की पर्याप्त सूचना रखें, ii) डब्ल्यूएचओ द्वारा दी गयी पांच कुंजीयों का अभ्यास करते हुए भोजन को सुरक्षित बनाएं, iii) उपभोक्ता खरीद हुई सामग्री की जानकारी प्राप्त करने के लिए सामग्री के साथ लगे हुए लेबल को पढ़ें।

स) विश्व खाद्य संगठन (डब्ल्यू. एच. ओ) द्वारा सुरक्षित भोजन के लिए दी गयी पांच कुंजियां (डब्ल्यू. एच. ओ., 2015) -

1. खाद्य सामग्री की सफाई- i) नल के पानी के साथ कच्चे फल और सब्जियां पूरी तरह



धो लें, ii) हमेशा अपने हाथों एवं रसोई को साफ रखें, सब्जी काटने के लिए सब्जी काटने वाले बोर्ड का प्रयोग करें।

2. पके हुए और कच्चे भोजन को अलग रखना - i) कच्चे भोजन और खाने-पीने के लिए तैयार भोजन को मिलाये ना, ii) कच्चे मांस, मछली और कच्ची सब्जियां को भी साथ में न रखें।

3. अच्छी तरह से पकाना - i) मांस, मुर्गी, झींगा और समुद्री भोजन को अच्छी तरह से पकाए, ii) जब तक भोजन से गरम भाप ना आये भोजन को पाकते रहे।

4. सुरक्षित तापमान पर भोजन रखें : i) पके हुए भोजन को दो घंटे के अंदर फ्रिज में रख दे, ii) जमे हुए भोजन को डीफ्रॉस्ट करने के लिए कमरे के तापमान पर न रखे बल्कि रेफ्रिजरेटर या माइक्रोवेव का उपयोग करें।

5. सुरक्षित पानी और कच्चे खाद्य प्रदूषण का प्रयोग करें : i) भोजन की तैयारी के लिए सुरक्षित पेयजल का उपयोग करें, ii) पैक किए गए भोजन को खरीदने के दौरान 'यूज बाय डेट' / उपयोग-दर-दिनांक' और लेबल की जांच

करें।

समाज का एक हिस्सा अपनी जरूरत का खाद्यान्न बाजार से नहीं खरीदता था। वह या तो पैदा करता था या संग्रहित करता था। परन्तु अब हर कोई बाजार के हवाले है। आर्थिक लाभ कमाने के लिये छोटे-छोटे किसानों ने भी खाद्यान्न की फसलों को छोड़कर नकद आर्थिक लाभ देने वाली फसलों पर ध्यान केन्द्रित किया और विपरीत परिस्थितियों में बमुश्किल अपना अस्तित्व बचा पाये। क्या एक बार फिर खाद्य सुरक्षा की पारम्परिक व्यवस्था पुर्नजीवित हो पायेगी।

खाद्य सुरक्षा से खाद्यान्न में कमी नहीं होगी तो राष्ट्र के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। वैश्विक महामारी से विश्व में आपात काल जैसी अवस्था हो जाती है। आपात काल की स्थिति में रोजमर्रा की वस्तुओं में कमी आने लगती है। खाद्यान्न में कमी का होना आपात काल की सबसे बड़ी बीमारी है। भोजन की कमी के कारण मानव त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगता है। खाद्यान्न में कमी को पूरा करने का सबसे अच्छा और कारगर उपाय है 'खाद्य सुरक्षा'। भारत को खाद्य सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना होगा। जिन लोगों की इम्युनिटी कमजोर है, उनको पोषण की आवश्यकता है। शारीरिक रूप से कमजोर लोग ही कोरोना जैसी बीमारी का सामना नहीं कर पाते। शरीर पोषण से मजबूत बनता है। यह कहने में आश्चर्य नहीं होगा की समुदाय का स्वास्थ्य ही राष्ट्र की सम्पदा है। अतएव हम कह सकते हैं कि सुरक्षित भोजन के बिना स्वास्थ्य भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती।

लेखक - असिस्टेंट प्रोफेसर व प्रोक्टर
खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
शुएट्स, नैनी, प्रयागराज (यूपी)



designing
printing
colour print

All types of advt. booking
(Newspapers, Magazines, Invites, Tips, Menu Design)



Office : B-2, 3-4, Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi. Contact : 011-43572907, 9968748460, 7503951103/06
Press : G-123, Near MCD Office, Gazipur, Delhi - 110096, Contact : 9968748460, 8700235930

संगीत और सन्तुलन का मार्ग

● तपेश आर पंवार

इस शीर्षक का ध्यान आते ही मन में विचार आया की इसे जनमानस तक पहुंचाना आवश्यक है। क्योंकि ये विषय वे ही लोग समझ पाएंगे जो कलात्मक होने के साथ साथ बेहद सरल और सहज भी हैं। मैंने अपने अनुभव के आधार पर पाया की संगीत का रचनात्मक स्तर इतना गहरा है की कोई भी इंसानी दिमाग सरलता से इस पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित ध्वनि तरंगों को आसानी से समझ सकता है। किन्तु इसके कुछ स्वाभाविक चरण हैं जिनको बिना समझे इस आयाम को टटोलने में शोधार्थियों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है जैसे की हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति में एक सन्तुलन होना तथा हमे हमारे अहंकार तत्व की पूरी जानकारी व आभास होना।

भारतीय संगीत में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत हो या दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत हो दोनों में ही संगीत के दो दर्शन प्राप्त होते हैं और वो हैं देशी संगीत और मार्गी संगीत। देशी संगीत जिसमें हम संगीत अभिव्यक्ति का प्रदर्शन या कार्य दूसरों के लिए, दूसरों के हिसाब से तथा दूसरों से प्रभावित होकर करते हैं। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारा आज का मनोरंजन जगत बाजार जिससे आप सभी भलीभांति परिचित हैं। इसके विपरीत मार्गी संगीत या दर्शन की परिभाषा है की जो संगीत

केवल आप और आपके भीतर तक ही सीमित है तथा असीमित होने का आभास रखता है, निरन्तर घटता व बढ़ता है एवं आपके जीवन के प्रभाव से उत्पन्न अभिव्यक्ति को लिए हुए संगीत के बीजरूप में आपमें स्थित है। मार्गी संगीत में केवल आप ही श्रोता हैं, आप ही गायक हैं, वादक हैं, आप ही उत्पन्न कर रहे हैं और आप ही उत्पत्ति देख

चूंकि आज तक हुए संगीत प्रयोगों में अधिकांश प्रयोग देशी संगीत ध्वनियों पर ही किया गया है और इसका प्रभाव चाहे थोड़ी देर का हो पर हर बार दिखाई पड़ता है फिर चाहे सामने श्रोता कोई व्यक्ति हो, पशु पक्षी या वनस्पति हो। इसके विपरीत मार्गी संगीत में आप केवल होने के एहसास में होते हैं। एसी स्थिति में आपका प्रभाव और संवेदनशीलता बढ़ जाती है तथा आप एक अतिसूक्ष्म आण्विक स्तर पर चेतना के स्पन्दन को समझने व उसका अनुभव करने लगते हैं। यह अनुभव केवल एक सरल, सहज, दयालु एवं प्रेमी दिमाग ही सहन कर सकता है। मार्गी संगीत में आपका अहंकार एक महान सन्तुलन को खोजते हुए उसमें स्थापित होने की प्रबल चेष्टा करता है तथा निरन्तर अभ्यास के बाद एक बेहतर, निर्भय और निराकार जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करता है।



रहे हैं। मार्गी संगीत में आपको नाद स्वरूप का सटीक साक्षात्कार होने लगता है। मार्गी संगीत में आप समय के बेहद बारीक हिस्सों को छूने का प्रयास करते हैं और इससे एक विशिष्ट संभावना पैदा होती है तथा एक क्षण ऐसा आता है जब ध्वनि की उत्पत्ति, कारण, क्रिया, स्थान आदि कारकों का अनुभव होने लगता है जिससे फलस्वरूप आपको एक समय ऐसा प्रतीत होता है की आप वर्तमान में ही भविष्य एवं भूतकाल को अनुभव करते हैं जिसमे केवल आपके होने की अनुभूति है।

जिसके फलस्वरूप सहज रूप से आपका दृश्य जगत का ज्ञान बढ़ने लगता है और आपके सभी सवालियों का जवाब आपको मिलने लगता है। इसलिए मार्गी संगीत या दर्शन के विद्यार्थी अथवा शोधार्थी न के बराबर होते हैं। क्योंकि ये क्रियान्वयन की दृष्टि से उतना ही कठिन प्रतीत होता है जितना अनाहत नाद को सुनना या समझना।

लेखक - तपेश आर पंवार (शोधार्थी - कला, साहित्य एवं मनोविज्ञान)

स्व. डॉ. मदन मोहन अग्रवाल जी की मूर्ति का अनावरण

विद्या भारती से संबद्ध सरस्वती विद्या मंदिर, ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद) के सभी प्रबंध समिति के सदस्य शिक्षक गण बाहर से पधारे अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति के साथ अपने विद्यालय के संस्थापकों में से एक व प्रखर राष्ट्रवादी, समाजसेवी एवं राम मंदिर आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय डॉक्टर मदन मोहन अग्रवाल जी की मूर्ति के विद्यालय परिसर में अनावरण के अवसर पर विद्यालय और विद्यालय में अध्ययन करने वाले सभी भैया

बहनों के उज्वल भविष्य के लिए अनेक योजनाओं की घोषणा की गई।

- 1) डॉ मदन मोहन अग्रवाल स्मृति खेल परिसर का लोकार्पण किया गया
- 2) स्वर्गीय डॉ मदन मोहन अग्रवाल जी की भव्य मूर्ति का अनावरण किया गया
- 3) श्रद्धांजलि सभा व स्वर्गीय डॉक्टर साहब के सनातन धर्म व समाज में योगदान पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथि द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया।

- 4) स्वर्गीय डॉ मदन मोहन अग्रवाल के कार्यों व जीवन वृत्त को रेखांकित करती स्मारिका का भव्य रूप से विमोचन किया गया।
- 5) विद्यालय के 10 होनहार(वित्तीय स्थिति में कमजोर) भैया बहनों की छात्रवृत्ति नीरजा गुप्ता सुपुत्री स्व. डॉक्टर मदन मोहन अग्रवाल जी(गुड़गांव) के द्वारा जोकि 500 रूपये प्रति माह प्रति छात्र रहेगी
- 6) ठाकुरद्वारा नगर पालिका के वर्तमान चेयरमैन श्री महान हाजी लियाकत जी के





स्वर्गीय डॉ मदन मोहन अग्रवाल जी के कार्यों व जीवन वृत्त को रेखांकित करता डायलॉग इंडिया के विशेषांक का विमोचन भी डा साहब की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर किया गया।



- द्वारा 51000 रुपये की आर्थिक सहायता
- 7) विद्यालय के प्रत्येक भैया बहन को 100 रुपये का नगद पुरस्कार एवं पेन पेंसिल चॉकलेट तथा एक breakfast packet का वितरण
- समारोह में कुं. सर्वेश सिंह- पूर्व सांसद, मुरादाबाद , श्री गुरु (डॉ) पवन सिन्हा, आध्यात्मिक चिंतक व संस्थापक - पावन चिंतन धारा आश्रम , वीरेंद्र कुमार, राष्ट्रीय संगठन मंत्री - भारतीय मजदूर संघ, नीरज गुप्ता , प्रांत प्रमुख धर्म प्रसार विभाग, विश्व हिंदू परिषद, प.उ. प्र, स्वर्गीय डॉ साहब की धर्मपत्नी सत्यभामा अग्रवाल व पूरा परिवार विद्यालय के प्रबंधक श्री आशुतोष अग्रवाल जी बाढ़ प्रबंधक समिति के अन्य अधिकारीगण श्रीमान संजय सिंघल जी सुनील अग्रवाल जी अनुराग सिंघल जी मुदित अग्रवाल जी मोहित अग्रवाल जी पूर्व प्रधानाचार्य श्रीमान गजेंद्र जी आदि प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित रहे

बड़े संकेत छोड़ गया स्व. मदन मोहन जी की मूर्ति का अनावरण

ठाकुरद्वारा में पहली बार धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से सक्रिय व अत्यंत लोकप्रिय रहे स्वर्गीय डा मदन मोहन जी की मूर्ति की स्थापना कुछ अच्छे संकेत, मायने व मापदंड छोड़ गयी है।

समारोह में कुं. सर्वेश सिंह- पूर्व सांसद, मुरादाबाद, श्री गुरु (डा) पवन सिन्हा, आध्यात्मिक चिंतक व संस्थापक -पावन चिंतन धारा आश्रम, वीरेंद्र कुमार, राष्ट्रीय संगठन मंत्री - भारतीय मजदूर संघ, नीरज गुप्ता, प्रांत प्रमुख - धर्म प्रसार विभाग, विश्व हिंदू परिषद, प. उ. प्र, मूर्तिकार सुशांक कुमार, स्वर्गीय डा साहब की धर्मपत्नी सत्यभामा अग्रवाल व पूरा परिवार, देशभर व क्षेत्र से आए दर्जनों प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों, विद्यालय के प्रबंधक श्री आशुतोष अग्रवाल जी व प्रबंध समिति के अन्य अधिकारीगण श्रीमान संजय सिंघल जी सुनील अग्रवाल जी अनुराग सिंघल जी मुदित अग्रवाल जी मोहित अग्रवाल जी पूर्व प्रधानाचार्य श्रीमान गजेंद्र जी आदि प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

संघ परिवार से जुड़ी देश व क्षेत्र की प्रसिद्ध राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक व व्यावसायिक व्यक्तियों का जुड़ना भी इस बात का संकेत है कि डा साहब की स्वीकार्यता व सम्मान बहुत व्यापक था। डा साहब की धर्मपत्नी व पुत्र-पुत्रियों ने किसी चौराहे या पार्क के स्थान पर डा साहब की सहायता से खड़े किए गए सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में उनकी मूर्ति की स्थापना करवाई। उद्देश्य स्पष्ट है कि नई पीढ़ी में बचपन से ही डा साहब की सोच व विचारों को गढ़ना व उसी के अनुरूप सनातनी, सेवाभावी व राष्ट्रभक्त पीढ़ी का निर्माण करना। इस अवसर पर डॉ साहब की जीवनी का विमोचन व वितरण भी किया गया। यह पुस्तक भी नई पीढ़ी व वर्तमान पीढ़ी दोनों को ही समान रूप से प्रेरित करेगी। डा साहब के परिजनों ने यह स्पष्ट भी किया कि वे विद्यालय के विकास में आगे भी क्षेत्र के लोगों व प्रबंध समिति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। क्षेत्र के लोगों के लिए 'परिवार' का यह उपक्रम प्रेरणा व ऊर्जा का काम करेगा और अनेकोनेक लोग अब शिक्षा से

सेवा के इस अत्यंत आवश्यक प्रकल्प से जुड़ेंगे। डा साहब के परिवार ने पिछले कुछ महीनों में लगातार विद्यालय के आधारभूत ढांचे को सुधारने, संवारने, खेल परिसर के विकास व सौंदर्यीकरण के लिए भरपूर सहायता की है व आगे भी करते रहने की बात कही है। इसी क्रम में विद्यालय के 10 होनहार (वित्तीय स्थिति में कमजोर) भैया बहनों की मासिक छात्रवृत्ति 'स्वर्गीय डा मदन मोहन स्मृति छात्रवृत्ति' चलाने की घोषणा नीरजा गुप्ता पुत्री स्व. डॉक्टर मदन मोहन अग्रवाल जी (गुड़गांव) के द्वारा जो की गई। यह छात्रवृत्ति 500/- रूपये प्रति माह प्रति छात्र रहेगी। यह छात्रवृत्ति क्षेत्र के लोगों को अपने बच्चों का प्रवेश इस विद्यालय में कराने के लिए प्रेरित करेगी। डॉ साहब द्वारा दान दी गयी जमीन पर शहर के सबसे बड़े खेल परिसर का लोकार्पण इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बच्चों के शारीरिक व बौद्धिक विकास के लिए सबसे आवश्यक खेल का मैदान होता है और शहर में ये न के बराबर हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति की योजना इस परिसर



क्षेत्र में अति लोकप्रिय रहे स्वर्गीय डॉक्टर मदन मोहन अग्रवाल जी की मूर्ति के विद्यालय परिसर में अनावरण के अवसर पर हुई संगोष्ठी में व्यापक जनसहभागिता ने कार्य को नया स्तर प्रदान किया ।



प्रखर राष्ट्रवादी, समाजसेवी एवं राम मंदिर आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर मदन मोहन अग्रवाल जी की मूर्ति के हमारे ग्रह नगर ठाकुरद्वारा स्थित सरस्वती विद्या मंदिर विद्यालय परिसर में अनावरण के अवसर पर आकर्षण का केंद्र रहे मुख्य वक्ता श्री गुरु (डा) पवन सिन्हा, आध्यात्मिक चिंतक व संस्थापक -पावन चिंतन धारा आश्रम। पवन जी ने थोड़ा समय शहर के तहसील परिसर में नवनिर्मित हनुमान धाम में भी व्यतीत किया व प्रवचन दिए।



यह हमारी माँ सत्यभामा जी की ही संकल्प शक्ति थी जिसके कारण कोरोना महामारी की मार के बीच भी सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में तमाम अवरोधों के उपरांत भी पिताजी की मूर्ति स्थापित हुए व विद्यालय का विकास व नई ऊर्जा का संचार हुआ व पिताजी का एक अधूरा स्वप्न पूर्ण होने की ओर अग्रसर हुआ। माँ के ही संकल्प से हनुमान धाम में अधूरा पड़ा राधा-कृष्ण मंदिर का निर्माण भी पिछले वर्ष पूर्ण ही पाया था। पिताजी के विचारों व सोच को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सदैव हमें प्रेरित किया। ऐसी माँ को पाकर हम धन्य हुए। शत-शत नमन



संख्या की दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सबसे बड़े आनुषंगिक संगठन भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री वीरेंद्र जी का हमारे परिवार से विशिष्ट संबंध व जुड़ाव है। स्वर्गीय पिताजी के क्षेत्र के संघचालक होते हुए वीरेंद्र जी पहली बार प्रचारक बनकर ठाकुरद्वारा ही आए थे और पिताजी के स्नेह व मार्गदर्शन के कारण परिवार का हिस्सा बनते गए। स्नेह, अपनत्व व समान संघ दृष्टि का यह रिश्ता आज भी उतना ही मजबूत है। हम भाइयों को संघ से जोड़ने व शाखा में ले जाने में वीरेंद्र जी की ही मुख्य भूमिका थी। पिताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए वे विशेष रूप से सुदूर रायपुर से आए और पिताजी के कार्यों, संघ दृष्टि, समर्पण व कार्यशैली के अनेक अपूर्व प्रसंग अपने उद्घोषण में बताए। सबसे महत्वपूर्ण राम जन्मभूमि आंदोलन को शुरू कराने में पिताजी की विशद भूमिका को बहुत गहराई से उन्होंने रेखांकित किया। नई पीढ़ी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी।



पिताजी की मूर्ति का उद्देश्य और मूर्तिकार सुशांक

जब हमारे परिवार ने यह निर्णय लिया कि स्वर्गीय पिताजी के कार्यों व विरासत को आगे बढ़ाया जाए तो अनेक स्तर पर सेवा कार्य करने का निश्चय किया गया। पिताजी के व्यक्तित्व और कार्यों से नई पीढ़ी को परिचित करवाना और वे उससे प्रेरणा ले सकें इसके लिए पिताजी के मन में हमेशा घर किए रहने वाले हमारे ग्रह नगर के सरस्वती विद्या मंदिर में पिताजी की मूर्ति लगाने का संकल्प लिया गया। कार्य कुछ अलग था व मूर्ति के विषय में ज्ञान शून्य तो अनेक परिजनों व मित्रों की सहायता से मूर्तिकार व मूर्तियों के प्रकार पर खोज, शोध व पड़ताल शुरू हुई। अंततः खोज छोटे भाई आशीष मिश्रा के माध्यम से सुशांक जी पर जाकर खत्म हुई। सुशांक जी से जब मूर्ति के दर्शन, विविध आराम, प्रकार व उद्देश्यों की गहराई जानी तो दिमाग ही चकरा गया। कई मुलाकातों के बीच कला के विविध रूपों में पारंगत सुशांक समझ चुके थे कि अनुज जी किसी कारपोरेट या लाला टाइप के व्यक्ति नहीं हैं और अपने पिता की मूर्ति बनवाने की उनकी सोच के पीछे एक समग्र दर्शन छिपा है और मूर्ति उस समग्रता का एक पहलू मात्र है। हम तो पिताजी की मूर्ति के माध्यम से नई पीढ़ी को सनातन संस्कृति के ढांचे में पल्लवित पुष्पित करने की चाह रखते थे जिसके साक्षात् प्रतीक हमारे पिताजी थे। मेरी गंभीरता को देख वे भी ख़ासे गंभीर हो चुके थे और पूरी लगन से मूर्ति निर्माण में लग गए। इस बीच पिताजी के अच्छी गुणवत्ता व विविध आरामों वाले फोटो न होना, कोविड के कारण बार बार होने वाला लॉकडाउन और पूरी तरह नकारात्मक माहौल काम बिगाड़ता रहा, जिस कारण दो महीने में पूरा जो सकने वाले इस प्रोजेक्ट में कई महीने लग गए। सुशांक ने इस बीच पिताजी की मूर्ति के बहुत से डमी बनाए और मुझे भी कई बार पूरे पूरे दिन साथ बैठाया मगर मैं व परिवार में कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ। सुशांक को लगा ऐन कुछ अलग व हटकर ही करना पड़ेगा ताकि पिताजी के वास्तविक स्वरूप के भाव मूर्ति में आ सकें। अंततः उन्होंने मूर्तिकला की किसी गूढ़ तकनीक का प्रयोग किया और पिताजी के चेहरे के हर भाग को चावल के दाने जितना बना बना काम आगे बढ़ाया और फिर कुछ ही दिनों में मुझे मूर्ति में पिताजी के साक्षात् दर्शन होने लगे। सुशांक तो अपने काम में ऐसे खो गए कि अक्सर पिताजी से साक्षात्कार तक करने लगे। पिताजी की जीवंत प्रतिमा का आकर्षण उसके लोकार्पण समारोह में सभी को खींच रहा था। काम के प्रति उनका ज्ञान, लगन, सनातनता के प्रति उनके विश्वास व उनके सहज व्यक्तित्व ने मुझे बहुत प्रभावित किया। आज वे अपने क्षेत्र में एक सफल नाम हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि वे शीघ्र ही शीर्ष पर पहुँचेंगे।



में विभिन्न खेल गतिविधियाँ प्रारंभ करने की है। इससे भी निकट भविष्य में विद्यालय का आकर्षण नई पीढ़ी में बढ़ना तय है। महत्वपूर्ण यह भी है कि कार्यक्रम में आने वाले सभी विशिष्ट अतिथियों ने आगे भी विद्यालय के विकास से जुड़े रहने की इच्छा व्यक्त की है।

विद्यालय प्रबंध समिति शीघ्र ही इन राष्ट्रीय स्तर के व्यक्तित्वों को जोड़कर कर एक सलाहकार समिति का गठन करने जा रही है। यह समिति लगातार विद्यालय विद्यार्थियों के समग्र विकास पर नजर रखेगी। यह कदम क्षेत्र में उच्च स्तरीय स्कूली शिक्षा की उपलब्धता की दिशा में एक

महत्वपूर्ण कदम होगा।

उम्मीद है कि निकट भविष्य में गुणवत्तापूर्ण व रोजगारपरक शिक्षा के लिए शहर व क्षेत्र के बच्चों को निकट के दूसरे शहर में पढ़ने जाना नहीं पड़ेगा और माता पिताओं की ऊर्जा व संसाधनों की बर्बादी रुकेगी। ■



मौलिक भारत विचार श्रृंखला-3

देश की उन्नति के लिए लाल फीता नहीं सुस्वागतम करते अधिकारी

● अजय सिंह 'एकल'



देश जब अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ माना रहा है तब यह आवश्यक है कि देश की मौजूदा व्यवस्थाओं का पुनरावलोकन किया जाए और जो अच्छा हो रहा है उसे और अच्छा करने का प्रयास और जो ठीक नहीं हो रहा या जिन व्यवस्थाओं के अपेक्षित परिणाम नहीं दिख रहे हैं उनकारणों की समीक्षा करके उसे कैसे ठीक किया जाए इसकी योजना बना कर इसे सुधारा जाए ताकि बेहतर परिणाम मिल सके और देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सके। यह किसी से छुपा नहीं है कि वर्तमान व्यवस्थाओं में जो एक व्यवस्था जिसे देश की उन्नति में वृद्धि का कारक बनना चाहिये वह ही बाधा बन रही है। यह गहरी चिंता का विषय है कि जिस देश की आबादी दुनिया में दूसरे नंबर पर है अर्थ व्यवस्था छठे नंबर पर है, उस देश की ईज आफ डूइंग बिजनेसकी रैंकिंग वर्ष 2020 में 63वे नंबर पर थी। यानि दुनिया में 62 देश ऐसे हैं जहां काम थंधा करना भारत के मुकाबले में आसान है। मजे की बात है कि दुनिया के अनेक छोटे और पिछड़े देश जैसे केनिया, स्लोवेनिया, सर्बिया, हंगरी और बेलारूस इत्यादि भी हमसे काफी बेहतर हैं। इसका एक बड़ा कारण देश में प्रचलित अनावश्यक कानून तथा निर्धारित प्रक्रियाओं में जटिलता है। लेकिन यह परिणाम है इसका मूल कारण है उच्च अधिकारियों की मानसिकता जो साधारण कामों को भी इतना जटिल बना देती है कि जनता के समय और श्रम की बर्बादी तो करती ही है देश की उन्नति में भी बाधा बनती



है।

स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने 21 अप्रैल 1947 को पहले सिविल सर्विस दिवस पर भाषण करते हुए कहा था "We salute our civil servants, the steel frame of India, for their significant contribution and dedication towards nation building". तब शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि सिविल सर्वेन्ट्स के संवर्ग को जिसे वह इतना सम्मान दे रहे हैं और देश निर्माण के लिए भरोसा कर रहे हैं उसमें नितेश ठाकुर, नीरा यादव, बाबू लाल अग्रवाल या टीना जोशी जैसे लोग भी आएंगे जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजा पड़ेगा। यह तो कुछ वह नाम हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो गए हैं। ज्यादातर लोगों के बारे में सब जानते हैं, लेकिन आरोप सिद्ध न होने या राजनैतिक संरक्षण के कारण प्रशासन भी लाचार

दिखाई देने लगता है। यही नहीं पुलिस सेवा के लोग जिन्हें जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी निर्वाहन का दायित्व है उसमें मणिलाल पाटीदार और हाल ही में मुम्बई पुलिस कमिश्नर रहे परमवीर सिंह जैसे लोगों को फरार अपराधी घोषित करना पड़ेगा और इन्हे पकड़वाने वाले के लिए इनाम देना पड़ेगा। यानि जब मेड़ खेत को खाने की कोशिश में लगी तो चिंता होना स्वाभाविक है।

यह आनंद का विषय है कि एक अत्यंत पिछड़े राज्य छत्तीसगढ़ के जिला सूरजपुर में डी.एम.के पद पर तैनात डा. गौरव सिंह के द्वारा किए जा रहे जनसेवा के कामों की गूँज देश भर में सुनाई पड़ रही है। डॉ. गौरव प्रत्येक शनिवार को एक बस में अपनी प्रशासनिक अधिकारियों की टीम लेकर प्रवास करते हैं जो लोगों की समस्याओं का निदान वही पर करती है। डॉ. गौरव का मानना है कि गांव वालों को

लगना चाहिये की प्रशासन उनके साथ है। लिहाजा इस मुहिम का नाम 'प्रशासन आपके द्वारे' रखा गया है। इस मुहिम के माध्यम से पेंशन हो या मनरेगा अथवा खाद्य संबंधी समस्या सभी का हल मौके पर करने की कोशिश की जाती है। यह अधिकारी सही मायने में सरदार पटेल के स्वप्न 'स्वराज को सूरज' में बदलने रूपांतरित करने का प्रयास कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश के 1996 बैच के आईएएस उमा कान्त उमराओ ने आईआईटी रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग पास करने के बाद प्रशासनिक सेवा में आये और विलक्षण प्रतिभा का उपयोग देवास जिला जो पानी की कमी से जूझ रहा था उसे सौ प्रतिशत सिंचित करवाया। आज देवास के 1067 गांवों में 10 हजार से भी ज्यादा तालाब हैं। सयुक्त राष्ट्र संघ ने भी 2012 में देवास में जल संरक्षण के लिए तालाब की संस्कृति को जीवित किए जाने पर इसे दुनिया का तीसरा उदाहरण माना है। देवास जिले में उमराव को जलाधीश यानी पानी का भगवान माना जाता है। इन्हे देश के 10 सबसे अच्छे आईएएस की सूची में भी रखा गया है। सिक्किम के राज यादव, तमिलनाडू के संदीप नन्ददोरी जैसे अनेक अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा, देश सेवा, और जनता की सेवा के अनुपम उदाहरण देश के सामने रखे हैं।

लेकिन ऐसे प्रशासनिक अधिकारी अपवाद ही हैं जो पूरी संवेदनशीलता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते दिखाई देते हैं। देश में ज्यादातर अधिकारी भ्रष्ट और निकम्मे हैं। इस बारे में राजनीतिज्ञों को भी पता है। बल्कि यह कहा जाए की राजनीतिज्ञों और अधिकारियों

का एक नेक्सस देश में काम कर रहा है तो अतिशयोक्ति न होगी। ऐसा नहीं है की इस समस्या को ठीक करने के लिए प्रयास नहीं हुए, लेकिन जो प्रयास हुए वह दृढ़ राजनैतिक इच्छा शक्ति की कमी और 30 वर्षों तक बनी गठबंधन सरकारों की मजबूरीयों के कारण अच्छे परिणाम नहीं दे सके। मोदी सरकार आने के बाद इस दिशा में कई तरह की योजनाएं शुरू हुई हैं, जिनका उद्देश्य प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना और अधिकारियों को जनता की समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाना है।

इस लक्ष्य को समय बद्ध तरीके से प्राप्त करने हेतु मोदी सरकार 2 ने एक बहुप्रतीक्षित उच्च महत्वाकांक्षी योजना मिशन कर्म योगी के नाम से शुरू की है। मिशन कर्म योगी के द्वारा केन्द्रीय सरकार के 46 लाख उच्च स्तरीय लोक सेवक जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईईएस इत्यादि भी शामिल हैं, के काम करने के तौर तरीके और सोच बदलने का लक्ष्य है। इसमें मुख्य रूप से छै विषय शामिल किया गए हैं। यह विषय हैं लोक नीतियों की संरचना, संस्थागत नीतियों की संरचना, कार्य क्षमता बढ़ाने संबंधी युक्ति और नीतियों की संरचना, आधुनिक तकनीक के अधिकतम प्रभावकारी उपयोग हेतु नीतियों की संरचना और क्रियान्वयन, तकनीक आधारित मानव संसाधन विकास एवं प्रबंधन, प्रभावी निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए नीतियों की संरचना और क्रियान्वयन। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उच्च अधिकारियों की कई समितियां और कार्य दल भी निर्धारित हुए हैं। सरकार का मानना है

इस मिशन के सफलता पूर्वक लागू होने से भारतीय लोक सेवक अधिक रचनात्मक, उन्नतशील, अग्रसक्रिय, पेशेवर, प्रगतिशील, पारदर्शी एवं तकनीक के प्रयोग में निपुण होकर कार्य को ज्यादा कुशलता पूर्वक करने में समर्थ हो जाएंगे।

ऐसा नहीं है की हमारे देश में इसके पहले अच्छी, प्रगतिशील लोकहित की नीतियां नहीं बनी हैं लेकिन इनका कार्यान्वयन ठीक न होने के कारण ज्यादातर नीतियों के अपेक्षित परिणाम नहीं आये हैं। देश की वर्तमान स्थितियों को देख कर किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के लिए इसे नकारना असंभव है। अगले पांच वर्षों में मिशन कर्म योगी पूरी तरह से लागू हो जाएगा। इससे सबकुछ ठीक हो जाएगा यह मानने के कारण हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकेगा इसे मानने के भी पर्याप्त कारण हैं। पहला तो यह की इन नीतियों को बनाने वाले और लागू करने वाले जिम्मेदार वही ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके कार्यों को इस मिशन के द्वारा परिवर्तन कर प्रभावी बनाने का लक्ष्य है। साधारणतया पुरानी कार्य प्रणाली को छोड़ना और नई को अंगीकार करना कठिन होता है और फिर जब जवाबदेही भी उसी को करनी है जो खुद भी इसी प्रवृत्ति का है तो काम और भी आसान हो जाता है। यानि दोनों एक ही नाव में सवार, और साथ ही पार करने की कोशिश कर रहे हों, तब न तू मेरी कहे और न मैं तेरी कहूँ, वाली स्थिति में मुश्किल और ज्यादा हो जाती है। इस बात की प्रशंसा करनी होगी की मोदी सरकार ने 31 ज्वाइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी ऐसे पेशेवरों को बनाया है जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्टपहचान बनाई है। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो ऐसे नियुक्त किए गए लोगों की राह भी बहुत आसान नहीं दिखाई देती है। प्रयोग अच्छा है, लेकिन समय बताएगा की इसके परिणाम कैसे आ रहे हैं। यहां एक प्रश्न यह है की करे क्या? इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए विकल्प क्या क्या है? अब इस मूल विषय की चर्चा करते हैं।

पहला विकल्प यह है की अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई सिविल सेवा व्यवस्था के मौजूदा स्वरूप को समाप्त करके देश की आवश्यकता के अनुरूप नई सेवा बने। यह सिस्टम अंग्रेजों ने इस लिए बनाया था की उनकी शुरुवात ही काफी ऊपर से हो। सिविल सेवा का उद्देश्य है की इसमें सबसे मेधावी लोग आ सकें, लेकिन

MISSION KARMAYOGI: RULES-BASED TO ROLES-BASED
National Programme for Civil Services Capacity Building (NPCSCB)

- Shift from 'Rules-based' to a 'Roles-based' human resource management
- Emphasise role of "On-Site learning" in complementing "Off-Site learning"
- Linking training and development of competencies of civil servants
- Transforming training institutions into Centres of Excellence
- Ministries to directly invest and co-create a common learning ecosystem
- Focus on massive scale training on e-learning

यह उद्देश्य पूरा होता नहीं दिखता है। कारण कम मेधावी छात्र भी लाखों रुपये खर्च करके वर्षों कोचिंग करके इसमें चयनित हो जाते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा मेधावी पैसे के अभाव में चयनित नहीं हो पाते। इससे दो तरफा नुकसान होता है। एक तो सरकार को सबसे मेधावी व्यक्ति नहीं मिलते, दूसरे कम मेधावी जब बास् बन कर आ जाते हैं तो निम्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों में निराशा और हताशा भर जाती है। फिर वे भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। इसका समाधान है की भर्ती निचले स्तर पर हो। फिर कार्य कुशलता एवं विभागीय परीक्षाओं द्वारा उन्हें आगे बढ़ने के अवसर दिए जाए। इस स्तर पर भी इसका नाम भारतीय सिविल सेवा और भारतीय पुलिस सेवा आदि ही रखा जाए। जब एक लिपिक जानेगा की वह मुख्य सचिव बन सकता है या एक सिपाही जानेगा की उसे भी एसपी या आइ जी या डीआईजी बनने के चांस मिल सकता है तो काम के प्रति उसका नजरिया बदल जाएगा। सरकार की सारी कार्य पद्धति और सरकारी कार्यालयों का वातावरण भी बदल जाएगा। उच्च पदों पर बैठने वाले लोगों का आम आदमी जिसका काम कर रहे हैं और जो कार्यालय के सहयोगी हैं उनके प्रति भाव बदल जाएगा। पदोन्नति में विभागीय परीक्षा, वरिष्ठ अधिकारियों की राय के साथ ही जनता के प्रति उनके भाव जानने के लिए जनता की राय को भी शामिल किया जाना चाहिये। यह विकल्प कई देशों जैसे आस्ट्रेलिया जो गुड गवर्ननेस के जाने जाते हैं व्यवहार में है।

दूसरे विकल्प के रूप में सभी कैडर में सेवाओं के लिए एक परीक्षा हो। लिखित और साक्षात्कार परीक्षा में प्रासांक और रुचि के अनुसार विभाग में तैनाती केवल मिडिल लेवल पर हो। प्रत्येक पांच सालों में कार्य का मूल्यांकन हो तत्पश्चात पदोन्नति के साथ ही खराब काम करने वालों की पद अवनिता का भी प्रविधान किया जाए। पदोन्नति के लिए मूल्यांकन करते समय समाज के प्रतिष्ठित लोगों की समित जिला, प्रदेश और देश के स्तर पर बनाई जाए जिनकी राय को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिये। यह विभागों में स्थानांतरण, पोस्टिंग और पददोन्ती में होने वाले होने वाले भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएगा तथा अच्छे और ईमानदार अधिकारियों को विभाग में भ्रष्ट एवं निकम्मे बड़े अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले अपमान और

निरादर से मुक्ति में भी मदद करेगा।

प्रशासनिक सेवाओं में आने वाले काफी लोग इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट इत्यादि की डिग्री लेकर आते हैं जिसका उपयोग प्रशासनिक कार्यों में उपयोग बहुत कम होता है। अतः मेरा सुझाव है इस समवर्ग में बीस वर्षों की सेवा के बाद जिन अधिकारियों का सेवावृत्त अच्छा रहा है और उनकी रुचि भी हो उन्हें देश एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण विभाग जैसे छोटी और मझोले उद्यमों और कृषि जैसे विभागों में जिला या जिलों के समूह बना कर उसकी संवृद्धि की जिम्मेदारी दे दी जाए। तथा काम करने वाले अधिकारियों को उनके



अच्छे और कुशल नेत्रत्व के कारण होने वाली वृद्धि का कुछ हिस्सा दिया जाए ताकि किसान, उद्यमी और अधिकारी दोनों मेज के आमने-सामने बैठने के बजाय एक ही तरफ बैठे और उनकी भलाई में ही अपनी भलाई देख सके। इस तरह उद्योग धंधों के बढ़ने से सरकार को ज्यादा कर प्राप्त होगा, और जिन प्रशासनिक लोगों की कुशलता, दक्षता के कारण यह संभव हुआ है उन्हें इसका अतिरिक्त लाभ मिले तो अपने बुद्धि और कौशल से उन्हें इतना धन लाभ हो सकता है जितना भ्रष्ट लोग भी नहीं कर पाते। इस व्यवस्था में अधिकारी उद्योगों और कृषि की उन्नति में अपना हित भी देख पाएंगे और उद्यमों में जितनी मेहनत उद्यमी इसे चलाने के लिए करते हैं करते हैं यह अधिकारी भी उन्हें जब सहयोग करेंगे तो यह दोनों के लिए तो लाभकारी होगा ही सरकार के लिए भी लाभकारी होगा। अधिकारी एन केन पैसे कमाने के बजाय अपनी बुद्धि और मेहनत के दम पर सम्मान सहित देश प्रथम मान कर जनता की सेवा कर सकेंगे।

इसके साथ ही सेवा से मुक्त हुए लोगों की

जिन्हें सरकार द्वारा पेंशन दी जा रही है उन्हें अगले 10 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष कम से कम हर महीने 50 घंटे यानि साल में 600 घंटे आवश्यक रूप से रुचि अनुसार समाज सेवा में लगाया जाए। ताकि समाज से जो मिला है उसका कुछ भाग अपनी सेवा देकर समाज को वापस भी करे। ऐसे लोग समाज सेवा के दौरान यदि गांव में ही रहे तो इन्हें विशेष सम्मान देने की व्यवस्था कर गांव का विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा।

सरकारी कार्यालयों को लाल फीता शाही और विभागीय भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले बिना आत्म निर्भर भारत, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, गुड गवर्ननेस इत्यादि की बातें केवल सतही रहेंगी। पिछले दो सालों में कोरोना ने दुनिया के उद्यमियों का मोह चीन से भंग कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के कारण चीन के बिजली घर अपनी आधी से भी कम क्षमता पर काम कर रहे हैं इससे चीन के उद्यम बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। भारत अपनी विशेषताओं, ओजस्वी राजनैतिक नेत्रत्व और कुशल कारीगरों की उपलब्धता के कारण चीन का विकल्प बन के उभर रहा है। विदेशी निवेश बढ़ा है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने भारत में उद्यमों को शिफ्ट करने और नया उद्यम स्थापित करने में अपनी रुचि दिखाई है। विदेशों से आने वाले उद्यमियों के मन में यह विश्वास उत्पन्न करना आवश्यक है की यह देश कानून का पालन करने वाले लोगों और उद्यमियों का स्वागत करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा की सरकारी कामों में होने वाली अनावश्यक देरी की सभी बाधाओं को भी दूर करेगा। हमारे अधिकारी काम क्यों नहीं होगा बताने की बजाए काम कैसे होगा की राह प्रशस्त करेंगे तो देश की आर्थिक और सामाजिक उन्नति तो होगी ही साथ ही रोजगार के नए अवसरों की भरमार हो जाएगी। इतना होने पर 5 ट्रिलियन डालर इकॉनमी का लक्ष्य भी आसानी से हासिल हो जाएगा। अमृत महोत्सव एक अवसर है आमूल चूल परिवर्तन का, आईये हम यह तय करते हैं की हमने पिछले 75 साल जैसे बिताए हैं अगले 75 वर्ष वैसे नहीं बिताएंगे बल्कि कार्यप्रणालियों में गुणोत्तर परिवर्तन करके देश की उन्नति को पंख लगाएंगे। क्योंकि हम देश से और देश हमसे बनता है। देश और समाज की उन्नति में ही हमारी उन्नति समाहित है।

मौलिक जन संवाद के मंथन के उपरांत मौलिक भारत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजे सुझाव - बिल्डर प्राजेक्ट्स के लिए एक राज्य नीति बनायी जानी चाहिए

रेरा के पास पर्याप्त न्यायिक शक्तियां हों व प्राधिकरणों, शीर्ष राजनेताओं, नौकरशाही, बिल्डर, ठेकेदार, बिचोलिया फर्मों आदि की जवाबदेही स्पष्ट रूप से निर्धारित हो

सम्मानित बंधुवर

सादर वंदे !

मौलिक भारत नेताओं-सरकारी बाबुओं-बिल्डरों के गठजोड़ के खिलाफ व आम निवेशकों के हित में लगातार आवाज उठा रहा है। जिला गौतमबुद्ध नगर देश में इस भ्रष्ट व्यवस्था का सबसे बड़ा शिकार रहा है। मौलिक भारत की पहल पर नेताओं-सरकारी बाबुओं-बिल्डरों के गठजोड़ के खिलाफ व आम निवेशकों के हित में समस्याओं के समाधान के लिए कुछ रचनात्मक व सकारात्मक उपाय ढूंढने के लिए दिल्ली एनसीआर की प्रमुख संस्थाओं (गौतमबुद्ध नगर सहित दिल्ली एनसीआर के स्ट्रेस प्रोजेक्ट (लटके हुए बिल्डर प्रोजेक्ट) से जुड़े निवेशकों के संगठनों जो बायर्स के हितों के लिए प्रभावी कार्य कर रहीं हैं) व अन्य प्रमुख सामाजिक संस्थाओं के अनुभव व सुझावों को साझा करने व सम्मिलित कार्ययोजना बनाने के लिए 26/9/2021 , रविवार को अग्रसेन भवन, नोएडा में दोपहर 2 बजे से सायं 6 बजे के बीच मौलिक जन संवाद का आयोजन किया था। इस जनसंवाद व उसके बाद के मंथन के उपरांत गौतमबुद्ध नगर सहित दिल्ली एनसीआर के स्ट्रेस प्रोजेक्ट (लटके हुए बिल्डर प्रोजेक्ट) की समस्या को सुलझाने के लिए मौलिक भारत ने निम्न सुझाव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भेजे हैं। सुझावों की प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय व शहरी विकास मंत्री भारत सरकार को भी भेजी गई हैं। अनुज अग्रवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मौलिक भारत , पंकज सरावगी, राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार, मौलिक भारत व अनिल गर्ग, राष्ट्रीय सचिव, मौलिक भारत ने विस्तार से बताते हुए स्पष्ट किया की मौलिक भारत ने

मांग की है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यीडा प्राधिकरणों के लिए आवश्यक है कि-

a) प्राधिकरण फंसे हुए प्राजेक्ट्स की निम्न प्रकार की सूची बनायें -

1) वे प्रोजेक्ट जो समाधान के लिए CIRP (IBC (b) के अंतर्गत आ गए हैं।

2) जिन प्रोजेक्ट की भूमि बिल्डर ने PSP के अंतर्गत वापस कर दी है और अभी तक फ्लैट देने में असमर्थ है।

3) जिन बिल्डरों ने प्राधिकरणों को देय किशत का पिछले दो वर्षों से भुगतान नहीं किया है।

4) जिस प्रोजेक्ट की RERA (Real Estate Regulatory Authority) के पास बहुत अधिक शिकायतें हैं।

5) वे प्रोजेक्ट जिनको प्राधिकरणों ने तीन सौ करोड़ रुपए से अधिक के ऋण के बदले प्रोजेक्ट को गिरवी रखने की अनुमति दी हुई है।

b) प्राधिकरण प्रोजेक्ट की जमीन आवंटन रद्द करने के स्थान पर 'बेस रेजलूशन प्लान' लेकर आए, जिससे यह स्पष्ट हो सके की फंसे हुए प्रोजेक्ट को शुरू किया जा सकता है या नहीं और उसमें फंसे/डूबे हुए धन की वापसी संभव है या नहीं इस लचीले रवैए व प्रक्रिया से अनेक बिल्डर समाधान के लिए सामने आ सकते हैं और प्राधिकरण को फंसा हुआ धन व निवेशक को प्लैट मिलना संभव हो सकेगा।

c) प्राधिकरणों की हाथ झाड़ने की जगह हमेशा के लिए 'एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन ओरगेनाइजेशन' के रूप में सक्रिय भूमिका अपेक्षित है क्योंकि वे इसीलिए बिल्डर को उदार शर्तों पर भूमि उपलब्ध कराती हैं ताकि निवेशक को सस्ता मकान मिल सके। निवेशक भी इसी भरोसे से इन प्राजेक्ट्स में निवेश करता है क्योंकि उसको यह भरोसा होता है कि इन प्राजेक्ट्स के पीछे प्राधिकरण के रूप में सरकार मौजूद है। यह प्राधिकरण व सरकारों की जिम्मेदारी व जवाबदेही भी है कि यह भरोसा न टूटे।

d) यह प्राधिकरणों की जिम्मेदारी है कि वे ऐसा मेकेनिज्म विकसित करें कि मौजूदा विवादों का समाधान हो व आगे किसी भी प्रोजेक्ट में यह स्थिति आने पर निवेशक का कोई भी नुकसान हुए बिना, उसके तुरंत समाधान का मार्ग प्रशस्त रहे।

e) प्राधिकरण एक 'स्ट्रेस रेजलूशन फंड' का गठन करें जो अटके हुए प्राजेक्ट्स को जिनको कु-प्रबंधन के कारण अस्थायी रूप से फंड की कमी है, को तुरंत अंतरिम/ब्रिज फंडिंग उपलब्ध करवा सके।

f) प्राधिकरणों को अपनी लीगल टीम में ऐसे पेशेवर विशेषज्ञ रखने होंगे जो अटके हुए मामलों को निपटाने में पारंगत हों।

प्राधिकरणों को सभी अटके हुए प्राजेक्ट्स के मामलों में संबंधित बिल्डरों के विरुद्ध सीआईआरपी में भाग लेते हुए एक स्थायी नीति बनानी होगी।

g) जिन प्राजेक्ट्स का आवंटन प्राधिकरणों ने रद्द किया है उनके फिर से शुरू होने की स्थिति बनने पर पुनरावंटन शुल्क माफ होना चाहिए।

h) अटके हुए बिल्डर की कंपनी में जो सीआईपीआर के समाधान से गुजर रही है की शेयरहोल्डिंग बदलने पर सभी प्रकार का ट्रांसफर चार्ज व संविधान में परिवर्तन का शुल्क माफ होना चाहिए। इससे अटके हुए प्रोजेक्ट को पुनः शुरू करना आसान होगा।

i) जिन प्राजेक्ट्स में निर्धारित मात्रा में ग्रांड कवरेज नहीं हुई थी, समाधान प्रक्रिया में बचे हुए एफएआर (वाणिज्यिक) को रियायती दरों पर उपयोग करने की अनुमति दी जाए ताकि वह प्रोजेक्ट फिर से व्यावहारिक बन सके।

j) उन मामलों में जिनमें आबंटी किसी अन्य कंपनी के साथ छूट कर चुका है और आबंटी दिवालिया हो गया हो या डेवलपर दिवालिया हो गया हो, ऐसे मामले व्यावहारिकता पूर्ण तरीके से हल किए जाने चाहिए



Dear Sir/Madam,
Please find attached/forwarded, for appropriate attention, an e-mail petition addressed to the President/President's Secretariat which is self explanatory. Action Taken on the petition may please be communicated to the petitioner directly.

Regards

(R.K.Sharma)
(OSD)
President's Secretariat
Rashtrapati Bhavan, New Delhi

विजिलेंस जांच में बेनामी संपत्ति के मालिकों के नाम होंगे उजागर

गुप्त जांच में

दुर्लभ पत्तों में तलाश के तहत नए विजिलेंस में 34 अधिकांशों के खिलाफ मुकदमा चला दिया है। इनमें विजिलेंस जांच शुरू हो चुकी है। जांच के तहत नए पत्तों को भी शामिल कर लिया है। 34-35 अधिकांशों को शामिल करने में काम चल रहा है। अगले चरण में विजिलेंस में पुराने पत्तों को शामिल करने का काम शुरू किया जा रहा है। इनमें विजिलेंस जांच शुरू कर दी जा रही है। अगले चरण में नए पत्तों को शामिल करने का काम शुरू किया जा रहा है। अगले चरण में नए पत्तों को शामिल करने का काम शुरू किया जा रहा है।

विकास अधिकारी/प्लानिंग आयोग	संबंधित विभाग
विजिलेंस	संबंधित विभाग
प्लानिंग आयोग	संबंधित विभाग
नगरपालिका	संबंधित विभाग
ग्राम पंचायत	संबंधित विभाग
सिटी म्यूनिसिपालिटी	संबंधित विभाग
मिशनरिया	संबंधित विभाग
अन्य	संबंधित विभाग

विकास अधिकारी/प्लानिंग आयोग	संबंधित विभाग
विजिलेंस	संबंधित विभाग
प्लानिंग आयोग	संबंधित विभाग
नगरपालिका	संबंधित विभाग
ग्राम पंचायत	संबंधित विभाग
सिटी म्यूनिसिपालिटी	संबंधित विभाग
मिशनरिया	संबंधित विभाग
अन्य	संबंधित विभाग

देश में बिल्डर-खरीदार करारनामे में एकरूपता जरूरी

सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस, कम्प्लेक्स एस्टेट क्षेत्र में आदर्श करारनामा उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए जरूरी

अपराध-आलस राज्यों में अलग-अलग करारनामे

सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डरों को कम्प्लेक्स एस्टेट क्षेत्र में आदर्श करारनामा उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए जरूरी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने बिल्डरों को नोटिस देकर कहा है कि देश भर में एक ही तरह के करारनामे बनाने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग करारनामे बनाने से उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग करारनामे बनाने से उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए जरूरी है।

रियल एस्टेट में आणखी पारदर्शिता

सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डरों को नोटिस देकर कहा है कि देश भर में एक ही तरह के करारनामे बनाने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग करारनामे बनाने से उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग करारनामे बनाने से उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए जरूरी है।

Click on Sign to add text and place signature on a PDF File.

Grievance/Communication Details

Inward No.	89176/SC/PI/L(E)/2021
Letter Date	10-09-2021
Received On	06-10-2021
Applicant Name	ANUJ AGARWAL NATIONAL PRESIDENT MOLIK BHARAT & ORS
Address	306A 37-38-39 ANSAL BUILDING COMMERCIAL COMPLEX DR MUKHERJEE NAGAR
State	DELHI
Status Information	UNDER PROCESS

Wednesday, October 06, 2021-07:03:42

बिल्डर - बायर समस्या के समाधान के लिए मौलिक भारत के प्रतिवेदन को महामहिम राष्ट्रपति जी ने उचित कार्यवाही के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव को फॉरवर्ड किया

मित्रों,

जैसा कि आप जानते हैं कि 'मौलिक भारत' संगठन चुनाव सुधार, सुशासन, पारदर्शिता एवं हिंदुस्तान के विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों की जनता के प्रति जवाबदेही के लिए 8 सालों से कार्यरत हैं।

मौलिक भारत ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को चुनाव सुधारों पर संस्था के लंबे अनुभवों के आधार पर 10/09/2021 को महत्वपूर्ण सुझाव भेजे हैं। सुझावों की प्रति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि एवं कानून मंत्री, भारत सरकार, अध्यक्ष विधि आयोग, भारत सरकार को भी भेजी गयी थी। यह सुखद है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने मौलिक भारत सुझाव को संज्ञान में लेते हुए उनको 'लेटर पिटीशन' के रूप में स्वीकार कर लिया-

Your Grievance/Communication has been given Inward No. 89176/SCI/PIL/w@wv For status, kindly logon to <http://sci.gov.in> and go to Grievance Management option in Case Information Tab. - Supreme Court of India

बदलाव के लगभग हर पहलू को समेटे हुए ये सुझाव अगर मान लिए गए तो भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना पूर्णरूपेण सत्य हो जाएगी। मूल प्रतिवेदन का लिंक -

<http://maulikbharat.co.in/press-release-subject.../>

बड़ी सफलता- मौलिक भारत ने अभी कुछ दिन पहले बिल्डर प्रोजेक्ट के लिए राष्ट्रीय नीति की मांग की थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सहमति जता दी।

पहले 1% अपराधियों पर कार्यवाही के लिए यूपी सरकार का धन्यवाद - अनुज अग्रवाल, अध्यक्ष, मौलिक भारत

अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अपराधी तो 2600 से भी ज्यादा हैं नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों में और सुपरटेक टिवन टावर घोटाले में यूपी सरकार द्वारा बनाई गई एसआईटी की जांच में 26 अपराधी चिन्हित हुए व उन पर कार्यवाही शुरू की गयी है। सुखद यह है कि अभी तक कानून के पंजे से बच रहे सुपरटेक के मालिक आर के अरोड़ा को दोषी माना गया। ये तो मात्र 1% अपराधी ही चिन्हित किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इन प्राधिकरणों का आंख नाक सबसे भ्रष्टाचार टपक रहा है। मगर पहली बार सुप्रीम कोर्ट के दबाव में हुई इस बड़ी कार्यवाही का मौलिक भारत स्वागत करता है। साथ ही वादा करता है कि एक एक अपराधी को चुन चुन कर सजा दिलवाने व निवेशकों को उनका हक दिलाने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगा और जब तक सबको सजा नहीं मिलेगी चैन से नहीं बैठेगा।

जब नोएडा, ग्रेटर नोएडा व रीडा तीनों प्राधिकरणों के आंख, नाक, कान व हाथ मुंह सब भ्रष्टाचार में सने हैं तो मात्र 24 कर्मचारियों के खलाफ ही विजिलेंस की जांच क्यों - मौलिक भारत

अनुज अग्रवाल
अध्यक्ष, मौलिक भारत

1) जो जेडीए हो उसकी मान्यता व देय सब लीज पर लगने वाली स्टॉप ड्यूटी स्थगित रखी जाए।

2) भूमि के उस विशेष हिस्से की भूमि बकाया राशि की गणना जेडीए द्वारा भूमि बकाया के लिए किए गए वास्तविक भुगतान को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।

k) जिन परियोजनाओं में आरडब्ल्यूए या फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन ने अपने नियंत्रण में ले लिया है और व्यवसाय प्रमाण पत्र के लंबित हो फ्लैटों का पंजीकरण अभी भी नहीं है परियोजनाओं को दी जाने वाली कंपाउंडिंग फीस की माफी दी जानी चाहिए।

l) स्ट्रेम प्रोजेक्ट्स की वित्तीय व्यवहार्यता के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्राधिकरणों को 8वें ब्याज लगाने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेहिचक बिना किसी पूर्वाग्रह के अटके प्रोजेक्ट की वित्तीय व्यवहार्यता के लिए स्वीकार करना चाहिए।

m) CIRP के अंतर्गत आने वाली सभी दबावग्रस्त परियोजनाओं पर 'देर से निर्माण

दंड' की छूट होनी चाहिए।

n) ऐसे मामले जहां प्राधिकरणों ने लीज डीड को रद्द कर दिया है, उसे ऐसा तंत्र बनाना होगा जो पीड़ित घर खरीदारों को बड़े हुए भूमि मूल्य मुआवजा दें यह धन प्राधिकरणों को नए आवंटन से वसूलना होगा।

o) दबावग्रस्त परियोजनाओं के फ्लैटों/दुकानों की बिक्री पर स्थानांतरण शुल्क में छूट मिलनी चाहिए। यहां तक कि ऐसे फ्लैटों और दुकानों के पूर्व-रजिस्ट्री हस्तांतरण की एक निर्धारित अवधि के लिए अनुमति दी जाए।

p) प्राधिकरणों, वित्तीय संस्थानों और यूपी-आरईआरए के बीच घनिष्ठ कार्य संबंध होने बहुत आवश्यक हैं।

इसलिए प्राधिकरणों की यह जिम्मेदारी है कि वह न केवल तनावग्रस्त परियोजनाओं की समस्या का वास्तविक समाधान प्रस्तुत करें बल्कि एक स्थायी तंत्र बनाने के लिए भी आगे आएं जिसमें परियोजनाएं जो

भविष्य में तनावग्रस्त हो जाते हैं, उनमें हितधारकों के किसी नुकसान के तुरंत समस्या का समाधान हो सके। संस्था ने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि उसके सुझावों के अनुरूप बिल्डर प्राजेक्ट्स के लिए एक राज्य नीति बनायी जानी चाहिए ताकि समयबद्ध रूप से अटके हुए प्रोजेक्ट की समस्या का निवारण हो व भविष्य में इस प्रकार की समस्या फिर से न उत्पन्न हो। सुप्रीम कोर्ट के सुझावों के अनुरूप बिल्डर-बायर अग्रिमेंट में एकरूपता हो। जिसमें रेरा के पास पर्याप्त न्यायिक शक्तियां हों व प्राधिकरणों, शीर्ष रजनेताओ, नौकरशाही, बिल्डर, ठेकेदार, बिचोलिया फर्मों आदि की जवाबदेही स्पष्ट रूप से निर्धारित हो। साथ ही यह भी अनुरोध किया गया है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से भी इसी प्रकार का केंद्रीय कानून बनाने की सिफारिश भी करे।

अनुज अग्रवाल
राष्ट्रीय अध्यक्ष, मौलिक भारत

मक्कार हरियाणा सरकार और मोदी जी की स्मार्ट सिटी योजना

दिल्ली एनसीआर में प्राधिकरण व नगर निगम ही नहीं सरकारें भी उतनी ही बेईमान, भ्रष्ट व निकम्मी हैं पूरा दिल्ली और एनसीआर अवैध बस्तियों व निर्माण से अटे पड़े हैं और यह क्षेत्र एक 'शहरी देहात' में बदल कर बड़ी प्रदूषण व पर्यावरण समस्या को जन्म दे चुका है। ताजा उदाहरण हरियाणा के फरीदाबाद का है जहां के दिल्ली से लगे सूरजकुंड क्षेत्र में अवैध बस्तियां, फार्म हाउस, सोसाइटी स्कूल, कॉलेज और होटलों की भरमार है। अरावली की पहाड़ियों के वन क्षेत्र में ये निर्माण पिछले तीन दशकों में अवैध रूप से राज्य सरकारों के इशारे पर, राजनेताओं, नौकरशाहों व दबंगो को वन विभाग व नगर निगमों की मिलीभगत से कब्जा करने दिए जाते रहे और देखते ही देखते लाखों लोग फरीदाबाद से गुरुग्राम तक के इस वन क्षेत्र में बसते गए वो भी बिना किसी कागज के। आज यहां जगह की कीमत एक लाख रुपए वर्ग मीटर है और सैकड़ों लोगों के पास सौ सौ करोड़ तक की जमीन कब्जे में है वो भी बिना किसी कागजी कार्यवाही के। आप अंदाजा लगा सकते हो की कितने लाख करोड़ रुपयों का यह घोटाला चल रहा है और क्या क्या बंदरबांट रोज होती होगी। कितनी मजेदार बात है कि बिना रजिस्ट्री व कागज के भी ये सभी निर्माण सरकार वैध मान रही है और यहां बिजली, पानी, सड़क, सीवर, पार्क व अन्य सभी सुविधाएं दे रही है। भारत में शहरीकरण एक अभिशाप की तरह है। सरकार, निगम व प्राधिकरण अपनी काली कमाई के लिए अवैध निर्माण को शह देते हैं और बेतरतीब, अराजक और लूट के प्रतीक शहर बस जाते हैं, भगवान भरोसे। ताजा मामला इसलिए प्रकाश में आया क्योंकि एक एनजीओ सूरजकुंड के राजहंस होटल से लगे खोरी गांव में बनी अवैध बस्ती को हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय गयी थी और न्यायालय के आदेश पर दस हजार अवैध मकान निगम को तोड़ने भी पड़े। बताया जा रहा है कि एक बड़े कारपोरेट समूह ने राजहंस होटल खरीद लिया है और इसलिए उसकी रुचि उस अवैध बस्ती को हटाने में थी। चूंकि अवैध बस्ती हट चुकी है तो राज्य सरकार मामला रफा दफा करने की कोशिश कर रही है और मक्कार सरकार कोर्ट में अजीबोगरीब तर्क दे रही है। जानकर यह भी बता रहे हैं कि भू माफियाओं ने सैकड़ों करोड़ की जमीन कब्जा की हुई है, ने बहुत मोटी रकम नीचे से ऊपर तक खिला दी है और बड़ी बात नहीं कि न्यायालय भी कान में रई डाल कर न सो जाए। क्योंकि बाजार अर्थव्यवस्थाओं में न्याय पैसे वालो का गुलाम होता है।

ऐसे में प्रधानमंत्री जी किन 'स्मार्ट सिटी' योजना एक मजाक बन कर ही रह जानी है। मौलिक भारत पूछता है कि क्या मोदी जी इस महा घोटाले का संज्ञान लेंगे ?

अनुज अग्रवाल
अध्यक्ष, मौलिक भारत

[HARYANA GOVT ON FOREST LAND]

'Entire Gurugram will have to be demolished'

The 'forest' land issue

Abraham Thomas
t@hmail.com

NEW DELHI Every building in 11 districts of Haryana, including Gurugram and Faridabad, will have to be demolished if the authorities were to remove all structures from 'forest land' as defined and mandated by a 2018 Supreme Court judgement, the state government said on Friday, cautioning that such an exercise could create a "serious and unparallelled law-and-order problem".

Expressing its inability to implement a July order by the top court to raze structures from forest land, the Manohar Lal Khattar government said that "the task is beyond its capacity" because nearly 90% of land in the state is considered 'forest land' in the terms of the Supreme Court's 2018 judgment.

Therefore, carrying out this exercise, the state said, will lead to a mass-scale demolition of buildings, schools, colleges, government offices and residential buildings in 11 districts, which includes all of Gurugram and Faridabad.

On July 21 a bench of Justices AM Khanwilkar and Dinesh Dikshitkar, decided the Haryana government to ensure that all unauthorised structures standing on Aravalli forest land should be cleared. "Our direction to remove structures on forest land applies to all structures without any exception," stated the directive.

Adding with this direction, state authorities demolished the sham colony of Khari Gera, and issued show-cause notices to owners.

WHAT WAS THE ORDER?
In the 2018 case, Justice Dikshitkar said that all unauthorised structures standing on forest land should be demolished "without any exception".

WHAT HARYANA GOVT SAID
Haryana govt said that all land under PUA can't be treated as "forest land" as it covers 11 whole districts including Gurugram and Faridabad.

1.7 million hectares of land is notified under PUA, according to the 2017 Act of PUA.

The directive required an "absolute state and beyond the capacity of the state government" and is bound to create serious and unparallelled law-and-order problem.

— Haryana Govt (2018)

खोरी में अवैध निर्माण गिराने पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना क्षमता में नहीं: हरियाणा सरकार

राजीव शिन्हा

नई दिल्ली। हरियाणा सरकार ने अरावली वन भूमि के अवैध निर्माण हटाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हथ खड़े कर दिए हैं। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को शेष अरावली में हलचलनास दखल कराने का आदेश का पालन किया गया, तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला सहित 11 जिलों में झुलने, पारोलेजो, साफ्टी कम्प्लेक्सों और अत्यधिक धनार्थ कर्तित अन्य इमारतों को ध्वस्त करना पड़ना। दूसरी कानून-व्यवस्था की गांधी समस्य होती। यह हमारी शक्त से बाहर है।

इस वर्ष 23 जिलों को पर्यावरण के खोरी में अवैध निर्माण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट को सूचना दी गई थी कि वन भूमि पर कितने कितने अवैध के खम्बे खड़ा होगा। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के की

बड़े निर्माणों पर असमंजस

खोरी वन में 129 परमिट, 11 नंबर होल न्यूरो परमिट 1000 को ध्वस्त करने का मामला अभी बची है। इन्हें को लेकर हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के खम्बे अपना पक्ष रखा है।

एक अन्य फैसले का शिफ्ट करती हुए आरोहों को लाना करने में असमर्थता जाहिर है। राज्य सरकार का कहना है, सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले के अंतर्गत व वन भूमि की करीब 40 फीसदी जमीन को वन भूमि बन चला।

>> संविधानिक अधिकार का भी मुद्दा। पृष्ठ 2

भूमि संरक्षण अधिनियम के तहत जमीन वन भूमि

सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2018 के फैसले में कहा था कि परमिट पूरा संरक्षण अधिनियम (बीएनएर), 1900 के तहत जमीन गरीब जमीन को वन भूमि बना कराना। इस इकाई के अन्तर्गत पर कोर्ट ने 2018 में फरीदाबाद में अवैधता को लेकर बांध एम्प्लोय में सभी इमारतों को गिराने का आदेश दिया था।

17,39,907 हेक्टेयर भूमि पारोलेजों के तहत

इस अधिनियम के तहत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, अंबाला, पण्डित शंकरानंद, खोरी, फिरोज, पारोलेज, सहेरवाड़ा व नेशनल राजमार्ग हैं।

A Premium Institute for

One Day Competitive Examinations

SSC

BANK PO

Class by competent and well experts Specialists faculty for each disciplines.
Complete approach with special emphasis on conceptual clarity, presentation & strategy.

SSC (CGL + CPO + CHSL + MTS)

BANK (PO+CLERK), All COMPETITIVE EXAMS)

Special Features

Live Lectures

Recording of Live Lectures

Doubt Sessions

Regular Mock Tests

Very Impressive Results

Fully updated Assignment

One to One Mentoring Sessions

English / हिन्दी
Medium
Hostel Facility

Study
Material &
Test Series

New ONLINE/OFFLINE Batches in English/Hindi medium

starts from 12th Nov.2021 & 26th Nov-2021

Catch your dreams
**Career
Dream**

Powered By:



EDUCATIONAL SOCIETY

A Legacy of 25 Years

H.O. : 301/A,37,38,39, Ansal Building, Behind Safal Dairy, Commercial Complex, Mukherjee Nagar, Delhi-9

Contact : 9891186435, 9811069629, 9015912244, 011-27654588

Website : www.careerpluseonline.com / www.careerplusgroup.com

Career Plus People - Born to Lead

2
0
2
2

IAS/PCS

2
0
2
3

PRELIMS • MAINS • PRELIMS CUM MAINS

New **ONLINE/OFFLINE** Batches in English/Hindi Medium

Starts from 12th Nov. 2021 & 26th Nov. 2021

SUBJECTS AVAILABLE

GENERAL STUDIES (for Prelims/Mains), **CSAT & ESSAY**

HISTORY | **GEOGRAPHY** | **SOCIOLOGY** | **PUB. ADMIN.**

POL. SCIENCE | **SANSKRIT "LITT"** | **HINDI "LITT"**



By Most Renowned & Competent Facilities
under the Leadership & Direction of
Mr Anuj Agarwal & Niraj Kushwaha



Silver Jubilee Year
(Since 1997)



English / हिन्दी
Medium
Hostel Facility

EDUCATIONAL SOCIETY

A Legacy of 25 Years

Study
Material &
Test Series

■■■■■ **44 SELECTIONS IN IAS 2020** ■■■■■

H.O. : 301/A,37,38,39, Ansal Building, Behind Safal Dairy, Commercial Complex, Mukherjee Nagar, Delhi-9

Contact : 9891186435, 9811069629, 9015912244, 011-27654588

Website : www.careerplsonline.com / www.careerplusgroup.com